EDU TERIA

करेंट कॉन्सेप्ट

फरवरी 2026

संस्करण - फरवरी 2026

प्रकाशक
EDU TERIA PUBLICATIONS
Avadh Market, Rajiv Nagar Chowk
Near Atal Path, Patna-800013

मुद्रक
B.B. Printers

Composer : *Vishnu Jee*

Cover Design : *Shushil Kumar*

Marketing Representative

☎ 9431216685

Email ID – **eduteriapublication@gmail.com**
Website – **eduteria.live**
Telegram – **eduteriatestseries**

NOT FOR SALE

विधिक घोषणाएँ

- इस पुस्तक में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान, एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुंचे क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
- © Copyright – Eduteria Publication- सभी अधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन का कोई भी भाग प्रकाशक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में या किसी भी तरह से या फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग, या अन्य इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक तरीकों सहित, किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से प्रेषित, वितरित या प्रसारित नहीं किया जा सकता है।

विषय सूची

अध्याय | पृष्ठ संख्या

1. राष्ट्रीय घटनाक्रम.....07 - 26

1. पेन्नैयार नदी
2. पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) 2.0 में त्रिपुरा शीर्ष पर
3. प्लास्टइंडिया 2026 (PLASTINDIA 2026)
4. 'ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026' (Black Swan Summit India)
5. भारत के पहले सहकारी-आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म 'भारत टैक्सी' का शुभारंभ
6. शत् प्रतिशत बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बना अलवर
7. बस्तर पंडुम (Bastar Pandum)
8. राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन
9. उत्तराखण्ड में शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास
10. लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव
11. गुजरात सरकार का स्टारलिंक के साथ आशय पत्र (Letter of Intent – LoI) हस्ताक्षर
12. ADB ने असम में बाढ़ प्रबंधन के लिए 182 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी।
13. दिल्ली 'लखपति बिटिया योजना'
14. भगवान बुद्ध के पवित्र देवनीमोरी अवशेष
15. राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के संदर्भ में गृह मंत्रालय का नया प्रोटोकॉल
16. औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026
17. राइट टू रिकॉल (Right to Recall)
18. मध्य प्रदेश के बालाघाट, WLGSP के अंतर्गत एक पायलट जिला चुना गया
19. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन किया
20. केरल सरकार का "स्त्री सुरक्षा योजना"
21. असम के 'मोरान बाईपास' पर पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन
22. प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र पर बने "कुमार भास्कर वर्मा सेतु" का किया उद्घाटन
23. 'पीएम राहत' (PM RAHAT) योजना
24. इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट 2026
25. गोहपुर से नुमालीगढ़ तक 4-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मंजूरी
26. केरल, व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने और उसे मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना।
27. NHAI द्वारा 'मधुमक्खी गलियारा' (Bee Corridor) पहल विकसित करने की घोषणा
28. 'ओल चिकी' लिपि का शताब्दी समारोह
29. 'ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) परियोजना'
30. केरल ने भारत की पहली "ग्राफीन नीति" को मंजूरी दी
31. "भारत-विस्तार (Bharat-VISTAAR) पहल"
32. 'SAHI' और 'BODH' पहल
33. BioAsia 2026 का 23वां संस्करण 'हैदराबाद' में आयोजित हुआ
34. दुनिया का पहला 'ह्यूमैनिटी-फर्स्ट' AI शहर बनाएगा बेंगलुरु का स्टार्टअप Bharat1.AI
35. पश्चिम बंगाल की "मातिर सृष्टि" (Matir Srishti) पहल
36. नमो भारत (RRTS) कॉरिडोर
37. राष्ट्रपति भवन में सी. राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण
38. पलामू टाइगर रिज़र्व ने 'वनजीवी दीदी' पहल शुरू की
39. पर्यटन नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2026 (Tourism Leadership Summit 2026)
40. केरल का आधिकारिक नाम बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी
41. 'ई-बाइक दीदी योजना' (E-Bike Didi Scheme)
42. विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026
43. बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट-जीरो पंचायत
44. राष्ट्रीय घटनाक्रम (To The Point)

2. अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम.....27 - 38

1. 'कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026' (Cost of Living Index 2026)
2. सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी भारत की पहली राजकीय यात्रा पर
3. ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स 2025
4. भारत और अमेरिका के अंतरिम व्यापार समझौता फ्रेमवर्क की घोषणा की
5. प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय मलेशिया यात्रा
6. भारत-GCC मुक्त व्यापार समझौता (FTA) हेतु 'संदर्भ शर्तों' (Terms of Reference - ToR) पर हस्ताक्षर

7. "भारत-कनाडा : साइबर सुरक्षा और कानून प्रवर्तन पर बनी सहमति।"
8. संसदीय चुनावों में प्रधानमंत्री साने ताकाइची के नेतृत्व वाले गठबंधन की शानदार जीत
9. नई दिल्ली में भारत द्वारा पहली BRICS शेरपा और सू-शेरपा बैठक की मेज़बानी
10. बायोफैच (BIOFACH) 2026
11. भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025
12. भारत-ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता
13. नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स (NRI) 2025
14. म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026 (MSC 2026)
15. भारत ने किंबर्ले प्रोसेस (KP) की अध्यक्षता संभाली
16. अंतर्राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा सम्मेलन (ICDS) 2026
17. 39वां अफ्रीकी संघ (AU) शिखर सम्मेलन 2026
18. 'पैक्स सिलिका घोषणापत्र' (Pax Silica Declaration)
19. FCI ने वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के साथ चावल आपूर्ति के लिए समझौता किया
20. वेस्ट बैंक
21. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का तीन दिवसीय भारत दौरा
22. भारत और ब्राजील ने डाक क्षेत्र में सहयोग पर एक MoU साइन किया
23. अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम (To The Point)

3. रक्षा प्रौद्योगिकी ..... 39 - 47

1. रक्षा क्षेत्र को अब तक का सर्वाधिक 7.85 लाख करोड़ रुपए का आवंटन
2. ठोस ईंधन आधारित डक्टेड रैमजेट (SFDR) तकनीक
3. 'ऑपरेशन शास्त्र'
4. 'बड़ी स्क्वाड्रन (Buddy Squadron) संयुक्त हवाई अभ्यास
5. स्कैल्प (SCALP) मिसाइल (स्टॉर्म शैडो)
6. भारतीय वायु सेना (IAF) और रॉयल थाई वायु सेना (RTAF) के बीच इन-सीटू संयुक्त अभ्यास
7. असम राइफल्स के डॉग स्क्वाड में शामिल होंगे स्वदेशी नस्ल के 'तांगखुल हुई' और 'कोंबई'
8. भारतीय तटरक्षक बल द्वारा गोवा में अत्याधुनिक वाटरजेट प्रोडक्शन एवं टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन
9. बेंगलुरु में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) की नई मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी और ए आई पुश का उद्घाटन
10. 'हैमर' (AASM HAMMER) मिसाइल
11. खोर्रमशहर-4 (Khorramshahr-4)
12. भारतीय नौसेना द्वारा कैडेट प्रशिक्षण जहाज (CTS) 'कृष्णा' की लॉन्चिंग
13. मिलन 2026 (MILAN 2026)
14. DRDO ने गगनयान मिशन के ड्रोग पैराशूट का परीक्षण किया
15. आईएनएस अंजदीप (INS Anjadip)
16. भारत की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति, 'प्रहार' (PRAHAAR) का अनावरण
17. 'अग्नि वर्षा' (Agni Varsha)
18. सैन्य अभ्यास खंजर (Exercise KHANJAR) का 13वाँ संस्करण
19. अभ्यास 'वज्र प्रहार' (Vajra Prahar) 2026
20. वायु शक्ति 2026
21. रक्षा प्रौद्योगिकी (To The Point)

4. विज्ञान प्रौद्योगिकी ..... 48 - 56

1. स्टेम सेल थेरेपी
2. सौर चक्र (Solar Cycles)
3. LNG और डीजल-आधारित दोहरी-ईंधन वाली 1400 HP DEMU ट्रेन का सफल परीक्षण
4. हेवन-1 (Haven-1)
5. फुट एंड माउथ रोग (FMD)
6. वी. ओ. चिदंबरनार बंदरगाह(VOC): उन्नत एंटी-ड्रोन सिस्टम वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह
7. भारत-नीदरलैंड हाइड्रोजन फैलोशिप कार्यक्रम
8. 'पर्पल ब्लिस' (Purple Bliss) टमाटर
9. AI हेल्थकेयर इकोसिस्टम "I Live Connect"
10. चंद्रयान-4 के लिए सुरक्षित लैंडिंग साइट
11. "लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर (LSDs) पर शोध के लिए देश का पहला समर्पित बायोबैंक स्थापित"
12. इंडिया AI स्टैक
13. अंटार्कटिका में टेली-रोबोटिक (Tele-robotic) अल्ट्रासाउंड का सफल परीक्षण
14. आंध्र प्रदेश में स्थापित होगी भारत की सबसे बड़ी एकीकृत लिथियम-आयन बैटरी गीगाफैक्ट्री
15. लेनाकापाविर (Lenacapavir)
16. अमरावती में भारत की पहली क्वांटम वैली (Quantum Valley) की आधारशिला
17. ISRO का युवा विज्ञानी कार्यक्रम 'युविका 2026'
18. मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल वैन
19. "सुजविका" (AI-संचालित बायोटेक उत्पाद डेटा पोर्टल)
20. विज्ञान प्रौद्योगिकी (To The Point)

5. आर्थिक घटनाक्रम ..... 57 - 67

1. "बायो-फार्मा शक्ति" योजना (Biopharma SHAKTI)
2. केंद्रीय बजट में जल जीवन मिशन और नमामि गंगे मिशन
3. यंत्र इंडिया लिमिटेड (YIL) को मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जे को मंजूरी
4. 'वरिष्ठ बजट' (Elderly Budget)
5. 2026-31 के लिए 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें
6. वॉलमार्ट (Walmart) 'ट्रिलियन-डॉलर क्लब' में शामिल होने वाली पहली पारंपरिक रिटेल कंपनी बनी
7. Axis Bank ने लॉन्च 'रूफटॉप सोलर फाइनेंस' (Rooftop Solar Finance)
8. कोटक महिंद्रा बैंक ने देश का पहला पूर्णतः डिजिटल FPI लाइसेंस जारी किया
9. उत्तर प्रदेश बजट 2026-27
10. CPI का आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 हुआ
11. एक लाख करोड़ रुपये के शहरी चुनौती कोष (UCF) को मंत्रीमंडल की स्वीकृति
12. SBI दस लाख करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी बनी
13. "भारत की पहली CBDC आधारित PDS पहल
14. शहरी चुनौती कोष (Urban Challenge Fund - UCF)
15. मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का आधार वर्ष (Base Year) अब 2022-23
16. "पावरग्रिड की वित्तीय स्वायत्तता में विस्तार: CCEA ने निवेश सीमा को ₹5,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹7,500 करोड़ किया"
17. ओड़िशा में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 'हाई - सिक्योरिटी डाटा सेंटर' स्थापित
18. केंद्रीय बजट 2026-27
19. एशिया आर्थिक संवाद (AED) 2026
20. आर्थिक घटनाक्रम (To The Point)

6. पर्यावरण पारिस्थितिकी ..... 68 - 73

1. केरल के कंथल्लूर-मरायूर में खोजी गई सुगंधित ऑर्किड की प्रजाति "डिप्लोज़ेंट्रम पैपिलोसम"
2. 'इबू बैरन' (Ibu Baron)
3. राज्य-स्तरीय बर्ड एटलस (State-level Bird Atlas)
4. केरल में ड्रैगनफ्लाई की नई प्रजाति लिरियोथेमिस कैरलेंसिस (Lyriothemis keralensis) की खोज
5. उत्तराखण्ड के दारमा घाटी के उच्च हिमालयी क्षेत्र में दिखा दुर्लभ "हिम तेंदुआ" और विलुप्तप्राय "स्नो कॉक"
6. भागलपुर के अगरपुट-कुरपट वेटलैंड में पहली बार दिखा 'हाइब्रिड रीफ हेरॉन'
7. भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने तटीय जल से समुद्री कृमि की दो नई प्रजातियों की खोज की
8. 'लेइओगैलाथिया समुद्रगिरि', नामक स्क्वाट लॉबस्टर
9. टैट्राटेनियम पैकाडे
10. पिस्टल श्रिम्प की एक नई प्रजाति "अल्फियस मधुसूदनई"
11. चमेली को नुकसान पहुँचाने वाली ब्लॉसम मिज की एक नये प्रजाति 'Contarinia icardiflores' की खोज
12. भारत और नेपाल में वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता के लिए समझौता
13. पर्यावरण पारिस्थितिकी (To The Point)

7. नियुक्ति ..... 74 - 77

1. निवेदिता दुबे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की पहली महिला सदस्य बनीं
2. मणिपुर में युमनाम खेमचंद सिंह के नेतृत्व में नयी सरकार का गठन
3. पुर्तगाल में एंटोनियो जोस सेगुरो ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता
4. थन्या नाथन सी. केरल की पहली पूर्ण दृष्टिहीन महिला न्यायाधीश बनीं।
5. "मिया अमोर मोटली" लगातार तीसरी बार बारबाडोस की प्रधानमंत्री बनीं
6. जोस मारिया बाल्काजर (José María Balcázar) पेरू के नये अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त हुए
7. तारिक रहमान, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने
8. रॉब जेटन, नीदरलैंड के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने।
9. निधि छिब्बर को मिला नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार
10. नियुक्ति (To The Point)

8. खेल घटनाक्रम ..... 78 - 88

1. ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026
2. देविका सिहाग ने थाईलैंड मास्टर्स 2026 का महिला एकल खिताब जीता
3. एशियाई राइफल और पिस्टल निशानेबाजी चैंपियनशिप 2026
4. महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026
5. भारत छठी बार अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का विजेता

6. 'खेलो दिल्ली-दिल्ली खेल महाकुंभ' 2026
7. अबू धाबी (UAE) में आयोजित "ओपन मास्टर्स गेम्स 2026" के पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर
8. अंतरराष्ट्रीय मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप (IMACC) 2026
9. छठी राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026
10. मिलानो-कॉर्टिना, शीतकालीन ओलंपिक 2026
11. अर्जेंटीना के टेनिस खिलाड़ी 'टोमस मार्टिन एचेवेरी' ने अपना पहला ATP टूर खिताब जीता
12. खेल घटनाक्रम (To The Point)

9. पुरस्कार एवं सम्मान ..... 83 - 89

1. दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड 2026
2. 68वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स 2026
3. प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को 2026 का क्रैफोर्ड पुरस्कार
4. विंग्स इंडिया 2026 पुरस्कार: दिल्ली एयरपोर्ट सर्वश्रेष्ठ
5. भूटान की राजमाता को उपेंद्र नाथ ब्रह्मा 'मानवता के सिपाही' पुरस्कार 2025
6. पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार
7. रुबल नागी को प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचर प्राइज 2026
8. चांग-क्रैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड 2026
9. बी बी सी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर 2025
10. "भव्य भारत भूषण पुरस्कार" (2026)
11. आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल, वसई (पालघर)
12. मणिपुरी फिल्म 'Boong' (बूंग) को सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का BAFTA अवार्ड
13. 'स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल'
14. पुरस्कार एवं सम्मान (To The Point)

10. भारत में एआई का युग और पर्यावरण संरक्षण ..... 90 - 92
(नवाचार से स्थिरता तक एक नई दिशा)

11. भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 ..... 93 - 96

12. विविध समसामयिकी ..... 97 - 100

1. माउंट अकांकागुआ (Mount Aconcagua)
2. आदित्य पंड्या बने भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री
3. 'म्यूजिकल रोड' (Musical Road)
4. समर्थ पोर्टल (SAMARTH Portal)
5. सौंदला : भारत का पहला 'जाति-मुक्त' गांव
6. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजरायल दौरा
7. विविध समसामयिकी (To The Point)

13. बिहार समसामयिकी ..... 101 - 107

1. बिहार बजट 2026-27
2. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण (2025-26)
3. बिहार 'नक्सल-मुक्त' राज्य घोषित
4. ISRO, पश्चिम चंपारण और भागलपुर में अत्याधुनिक डॉप्लर वेदर रडार (DWR) स्थापित करेगा।
5. बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2026
6. बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026
7. सोनपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रस्ताव को बिहार कैबिनेट की मंजूरी
8. बिहार कैंसर कॉन्क्लेव 2026
9. कंबोडिया सरकार की पर्यटन गतिविधियों में मदद करेगा बिहार
10. बिहार की पहली 'ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी' को अंतिम रूप देने में जुटा 'BREDA'
11. 'जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना'
12. एशियन वॉटरबर्ड सेंसस 2026 (Asian Waterbird Census - AWC) 2026
13. बिहार समसामयिकी (To The Point)

14. अभ्यास प्रश्न ..... 108 - 119

NOT FOR SALE

राष्ट्रीय घटनाक्रम

01 पेन्नैयार नदी

❑ चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को पेन्नैयार नदी जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच लंबित विवाद के निपटारे के लिए एक न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है।

मुख्य बिंदु

- पेन्नैयार नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक अंतर्राज्यीय नदी विवाद है, जो कर्नाटक द्वारा पेन्नैयार की सहायक मार्कण्डेय नदी पर बांध और चेक डैम बनाने से उपजा है।
- तमिलनाडु ने 2018 में शिकायत की थी कि कर्नाटक ने ऊपरी हिस्से में एकतरफा निर्माण किया है। जो 1892 के एक समझौते का उल्लंघन है, जो तमिलनाडु के कृषि और पीने के पानी को प्रभावित करता है।
- कर्नाटक का कहना है कि 1892 का समझौता पुराना है और स्वतंत्र भारत में अब प्रासंगिक नहीं है।

❑ नदी जल विवाद न्यायधिकरण के बारे में

भारत में नदी जल विवाद न्यायाधिकरण (River Water Disputes Tribunals) का गठन तब किया जाता है जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न होता है और आपसी बातचीत से समाधान नहीं निकल पाता।

➲ संवैधानिक और कानूनी आधार :

भारतीय संविधान के अनुसार, जल मुख्य रूप से 'राज्य सूची' का विषय है, लेकिन अंतर-राज्यीय नदियों के मामले में केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

- → अनुच्छेद 262: यह संसद को अंतर-राज्यीय नदी विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है।
- → अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956: इसी कानून के तहत केंद्र सरकार न्यायाधिकरणों का गठन करती है।

➲ कार्य प्रणाली:

जब कोई राज्य सरकार केंद्र से शिकायत करती है कि किसी दूसरे राज्य के कार्यों (जैसे बांध बनाना) से उनके जल हितों को नुकसान हो रहा है, तो:

- → केंद्र सरकार पहले बातचीत (Negotiation) के माध्यम से विवाद सुलझाने की कोशिश करती है।
- → यदि बातचीत विफल रहती है, तो केंद्र सरकार एक न्यायाधिकरण (Tribunal) का गठन करती है।
- → न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं, जो अक्सर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज होते हैं।

➲ अब तक गठित कुछ प्रमुख न्यायाधिकरण:

भारत में अब तक कई न्यायाधिकरण बने हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख ये हैं:

- → कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण: तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच।
- → कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण: महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच।
- → नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण: राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच।
- → महादयी/मांडवी जल विवाद न्यायाधिकरण: गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच।

❑ पेन्नैयार नदी के बारे में:-

- पेन्नैयार नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है जो मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है।
- यह नदी कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर जिले में नंदी पहाड़ियों (Nandi Hills) से निकलती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 432 किलोमीटर है।
- यह कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु के कृष्णागिरी, धर्मपुरी, तिरुवन्नामलाई और विल्लुपुरम जिलों में बहते हुए अंत में कडलूर के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
- इसे दक्षिण भारत की पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। इसका "पिनाकिनी" नाम भगवान शिव के धनुष 'पिनाक' से जुड़ा है।
- इस नदी पर बना कृष्णगिरि बांध और साथानूर बांध खेती और सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।
- पेन्नैयार की प्रमुख सहायक नदियाँ चिन्नार, वनियार, पाम्बार और मार्कण्डेय हैं।

02 पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) 2.0 में त्रिपुरा शीर्ष पर

❑ चर्चा में क्यों?

त्रिपुरा ने पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) 2.0 में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्थानीय शासन में एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है।

❑ त्रिपुरा की इस सफलता के मुख्य स्तंभ :-

त्रिपुरा ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिसके कारण उसे यह गौरव प्राप्त हुआ:

- संसाधन प्रबंधन: स्थानीय स्तर पर राजस्व जुटाने और उपलब्ध संसाधनों का पारदर्शी तरीके से उपयोग करने में कुशलता।
- डिजिटलीकरण: 'ई-पंचायत' मिशन के तहत सेवाओं को डिजिटल बनाना, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आई और जवाबदेही बढ़ी।

- सामाजिक समावेशन: योजनाओं के क्रियान्वयन में महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
- बुनियादी ढांचा: गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाओं का बेहतर प्रबंधन।

❑ PAI 2.0 क्या है?

पंचायत उन्नति सूचकांक (Panchayat Abhyudaya Index) एक वैज्ञानिक ढांचा है जो विभिन्न मापदंडों पर पंचायतों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है:

- गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका वाले गांव
- स्वस्थ गांव
- बाल सुलभ पंचायत
- जल पर्याप्त गांव
- स्वच्छ और हरित गांव

❑ PAI 2.0 का महत्व :-

पंचायत उन्नति सूचकांक राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा (Competitive Federalism) को बढ़ावा देता है। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- स्व-मूल्यांकन: राज्यों को अपनी कमियों को पहचानने और उनमें सुधार करने का अवसर मिलता है।
- डेटा-आधारित नीति: सरकार को यह समझने में मदद मिलती है कि किन क्षेत्रों में अधिक निवेश या सुधार की आवश्यकता है।
- प्रेरणा: त्रिपुरा की सफलता अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों और बाकी भारत के लिए एक रोल मॉडल का काम करेगी।

त्रिपुरा ने पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) 2.0 में शीर्ष स्थान प्राप्त कर न केवल पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए स्थानीय स्वशासन (Local Governance) का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है।

03 प्लास्टइंडिया 2026 (PLASTINDIA 2026)

प्लास्टइंडिया 2026 (Plastindia 2026) का 12वाँ संस्करण हाल ही में 5 से 10 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। यह दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक है, जो हर तीन साल में आयोजित की जाती है।

मुख्य बिंदु

- तिथि : 5 फरवरी से 10 फरवरी, 2026
- स्थान: भारत मंडपम (प्रगति मैदान), नई दिल्ली
- थीम (विषय): "भारत नेक्स्ट" (Bharat Next)
- उद्देश्य: आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।

❑ प्रदर्शनी की मुख्य विशेषताएं:

इस कार्यक्रम ने भारतीय प्लास्टिक उद्योग की वैश्विक ताकत को प्रदर्शित किया:

- विशाल भागीदारी: इसमें 2,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शकों (Exhibitors) ने हिस्सा लिया और लगभग 6 लाख दर्शकों के आने का अनुमान लगाया गया।
- शून्य-अपशिष्ट (Zero-Waste): यह दुनिया की पहली ऐसी प्रदर्शनी रही जिसे पूरी तरह से 'जीरो वेस्ट' के रूप में आयोजित किया गया। यहाँ पैदा होने वाले सभी कचरे को अलग कर उसे रिसाइकिल किया गया।
- प्रमुख फोकस: इसमें मुख्य रूप से सर्कुलर इकोनॉमी, टिकाऊ (Sustainable) प्लास्टिक समाधान, और ए आई संचालित उन्नत मशीनरी पर जोर दिया गया।
- पांच रणनीतिक स्तंभ: यह आयोजन व्यापार, प्रौद्योगिकी, प्रतिभा, परंपरा और पर्यटन (Trade, Technology, Talent, Tradition, and Tourism) पर आधारित था।

❑ प्लास्टिक उद्योग का महत्व:

भारतीय प्लास्टिक उद्योग वर्तमान में लगभग ₹3–3.5 लाख करोड़ का है। प्लास्टइंडिया जैसे मंचों के माध्यम से भारत खुद को प्लास्टिक विनिर्माण और निर्यात के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। विशेष नोट: इस प्रदर्शनी में स्टार्टअप्स और युवाओं के लिए एक समर्पित स्थान बनाया गया था ताकि वे प्लास्टिक क्षेत्र में अपने नए और पर्यावरण के अनुकूल आइडिया पेश कर सकें।

04 'ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026' (Black Swan Summit India)

❑ चर्चा में क्यों?

ओडिशा सरकार ने हाल ही में भुवनेश्वर में 'ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026' (Black Swan Summit India) का सफल आयोजन किया। यह दो दिवसीय शिखर सम्मेलन 'भारतनेत्र' (BharatNetra) पहल के तहत आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य को डिजिटल फाइनेंस, AI और फिनटेक के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

❑ आयोजन और साझेदारी

- स्थान: भुवनेश्वर, ओडिशा
- समय: 5-6 फरवरी, 2026
- साझेदारी: यह सम्मेलन ओडिशा सरकार और सिंगापुर स्थित ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क (GFTN) के बीच एक रणनीतिक सहयोग का परिणाम था।

❑ मुख्य अतिथि और उपस्थिति

- भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इस शिखर सम्मेलन की शोभा बढ़ाई।
- ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और अन्य वरिष्ठ नीति निर्माता, निवेशक और वैश्विक उद्यमी भी इसमें शामिल हुए।
- सम्मेलन में 24 देशों के लगभग 1,700 प्रतिनिधियों और 100 से अधिक वक्ताओं ने भाग लिया।

❑ 'भारतनेत्र' (BharatNetra) पहल क्या है?

भारतनेत्र ओडिशा सरकार की एक महत्वाकांक्षी रणनीति है जिसका लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को "माइनिंग इकोनॉमी" (Mining Economy) से "माइंड इकोनॉमी" (Mind Economy) में बदलना है। इसके प्रमुख स्तंभ हैं:

- भविष्य के लिए तैयार कार्यबल: युवाओं को AI, फिनटेक और डिजिटल वित्त में कौशल प्रदान करना।

- ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCCs): ओडिशा को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के लिए एक पसंदीदा निवेश स्थल बनाना।
- नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र: फिनटेक और इंश्योरटेक (InsurTech) क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना।

❑ समिट के प्रमुख विषय

- आर्थिक समावेश: राष्ट्रपति मुर्मु ने जोर दिया कि तकनीक का उपयोग सामाजिक न्याय और वित्तीय समावेशन (विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में) के लिए होना चाहिए।
- लैंगिक न्याय: भारत की फिनटेक क्रांति को केवल तकनीकी सफलता नहीं, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण और लैंगिक न्याय की कहानी के रूप में भी देखा गया।
- चुनौतियां: सम्मेलन में साइबर अपराध, डीपफेक और डिजिटल धोखाधड़ी जैसे जोखिमों पर भी चर्चा हुई और इनके समाधान के लिए सतर्कता बढ़ाने का आह्वान किया गया।

❑ महत्व: यह पहली बार है जब भारत में 'ब्लैक स्वान समिट' का आयोजन किया गया है। इससे पहले इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ था। यह समिट ओडिशा के 'विज़न 2036-2047' को हकीकत में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

05 भारत के पहले सहकारी-आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म 'भारत टैक्सी' का शुभारंभ

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में भारत के पहले सहकारी-आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म 'भारत टैक्सी' का शुभारंभ किया। यह प्लेटफ़ॉर्म ड्राइवरों (सारथी) को कमीशन-आधारित एग्रीगेटर्स से मुक्ति दिलाकर उन्हें मालिकाना हक देता है, जिसका मुख्य उद्देश्य शून्य कमीशन और निष्पक्ष मूल्य निर्धारण के साथ 'सहकार से समृद्धि' को बढ़ावा देना है।

❑ 'भारत टैक्सी' की मुख्य विशेषताएं :-

यह प्लेटफॉर्म "सहकार से समृद्धि" के विजन पर आधारित है और इसके प्रमुख आकर्षण निम्नलिखित हैं:

- सारथी ही मालिक (Sarathi Hi Malik): यह दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइवर-स्वामित्व वाला मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है। इसमें ड्राइवर केवल कर्मचारी नहीं, बल्कि सहकारी समिति के सदस्य और हिस्सेदार हैं।
- जीरो-कमीशन मॉडल: निजी कंपनियों के विपरीत, यह प्लेटफॉर्म ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं लेता है। ड्राइवर अपनी कमाई का 100% हिस्सा (या कुछ मॉडल्स में 80% सीधा बैंक खाते में) प्राप्त करते हैं। कुछ परिचालन खर्चों के लिए केवल एक मामूली दैनिक शुल्क (लगभग ₹30) लिया जाता है।
- नो सर्ज प्राइसिंग (No Surge Pricing): यात्रियों के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि इसमें मांग बढ़ने पर किराया नहीं बढ़ाया जाएगा (सर्ज फ्री)। इससे यात्रियों को किफायती और पारदर्शी किराया मिलता है।
- बहु-विकल्प सेवा: इस ऐप के जरिए यात्री कार, ऑटो-रिक्शा (थ्री-व्हीलर) और बाइक (टू-व्हीलर) बुक कर सकते हैं।
- कल्याणकारी योजनाएं: ड्राइवरों के लिए ₹5 लाख का दुर्घटना बीमा और ₹5 लाख का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

❑ सुरक्षा और सशक्तिकरण:

- सारथी दीदी (Sarathi Didi): महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए महिला यात्रियों के लिए महिला ड्राइवरों का विकल्प दिया गया है।
- पुलिस एकीकरण: सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर विशेष बूथ और सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार किया गया है।

06 शत् प्रतिशत बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बना अलवर

राजस्थान का अलवर जिला केंद्र सरकार और IRDAI की '2047 तक सभी के लिए बीमा' (Insurance for All by 2047) पहल के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है।

मुख्य बिंदु

- लक्ष्य: 2047 तक भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक सभी के लिए बीमा सुनिश्चित करना।
- प्रक्रिया: अलवर जिले के 9 गांवों (जैसे- भूला का बास, देसूला) में 10 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को बीमा के दायरे में लाया गया।
- बीमा प्रदाता: यह पहल यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से लागू की गई।
- महत्व: यह पहल वित्तीय समावेशन को बढ़ाती है और ग्रामीणों को स्वास्थ्य, जीवन और संपत्ति संबंधी बीमा कवर देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।
- पहला पूर्ण बीमित गांव: 15 अगस्त 2025 को अलवर के देसूला ग्राम को देश का प्रथम 100% बीमित गांव घोषित किया गया था।

❑ सफलता के प्रमुख कारक:-

- राज्य और केंद्र का तालमेल: केंद्र की 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति' और 'सुरक्षा बीमा योजना' को राज्य की 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना' (पूर्व में चिरंजीवी) के साथ जोड़कर व्यापक स्तर पर कवरेज सुनिश्चित किया गया।
- बीमा सखी और स्थानीय एजेंट: ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और स्थानीय प्रतिनिधियों को 'बीमा सखी' के रूप में प्रशिक्षित किया गया, जिससे बीमा के प्रति झिझक खत्म हुई।
- डिजिटल पैठ: 'बीमा सुगम' प्लेटफॉर्म के माध्यम से दावों (Claims) और पॉलिसी खरीदने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया।

❑ '2047 तक सभी के लिए बीमा' का लक्ष्य :-

IRDAI ने आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक हर भारतीय को बीमा के दायरे में लाने के लिए एक त्रि-स्तरीय ढांचा तैयार किया है:

- बीमा सुगम - एक 'वन-स्टॉप शॉप' पोर्टल जहाँ पॉलिसी खरीदना, सर्विसिंग और क्लेम निपटान सब कुछ एक जगह होता है।
- बीमा विस्तार - एक किफायती, समग्र (All-in-one) बीमा उत्पाद जो जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति को एक साथ कवर करता है।
- बीमा वाहक - ग्राम स्तर पर कार्यबल (Workforce), जो घर-घर

जाकर बीमा वितरण और जागरूकता बढ़ाते हैं।

नोट: अलवर की इस उपलब्धि ने न केवल राजस्थान को "मॉडल स्टेट" के रूप में स्थापित किया है, बल्कि यह देश की GDP में बीमा पैठ (Insurance Penetration) को बढ़ाने में भी मील का पत्थर साबित होगा।

07 बस्तर पंडुम (Bastar Pandum)

❑ चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू ने छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग स्थित जगदलपुर में 'बस्तर पंडुम' का शुभारंभ किया। यह उत्सव जनजातीय विरासत को संरक्षित करने के लिए आयोजित किया जाता रहा है।

❑ बस्तर पंडुम 2026 के मुख्य विवरण:

- उद्घाटन: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 7-9 फरवरी, 2026 के मध्य इस महोत्सव का उद्घाटन जगदलपुर में किया।
- उद्देश्य: जनजातीय संस्कृति, कला, पारंपरिक वेशभूषा, व्यंजन और हस्तशिल्प (जैसे ढोकरा शिल्प, बांस शिल्प) का प्रदर्शन करना।
- भागीदारी: इस बार सात जिलों, 1885 ग्राम पंचायतों और 32 जनपद मुख्यालयों से 12 विधाओं में 55 हजार प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
- महत्व: यह महोत्सव बस्तर की नई पहचान , विकास और सांस्कृतिक गौरव को दर्शाता है, जो पहले केवल नक्सलवाद से जुड़ा था।
- समापन: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लालबाग मैदान में इसके समापन समारोह में हिस्सा लिया।

❑ बस्तर पंडुम के बारे में -

- बस्तर पंडुम, छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग का प्रमुख सांस्कृतिक महोत्सव है, जो जनजातीय परंपराओं, कला, लोक संगीत और नृत्य का जश्न मनाता है।
- गोंडी भाषा में 'पंडुम' का अर्थ 'उत्सव' या 'पर्व' है।
- यह आयोजन बस्तर की समृद्ध आदिवासी संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने और उसे संरक्षित करने के लिए आयोजित किया जाता है।
- बस्तर की इस समृद्ध आदिवासी कला और संस्कृति को पुनर्जीवित करने और इसे देश-विदेश के सामने लाने के लिये बस्तर पण्डुम का आयोजन 2025 में पहली बार किया गया।
- बस्तर पंडुम जनजातीय समाज की जीवनशैली से जुड़ी उन विधाओं को सामने लाता है, जिनमें लोककला, शिल्प, तीज-त्योहार, खानपान, बोली-भाषा, रीति-रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, पारंपरिक वाद्य यंत्र, नृत्य, गीत-संगीत, नाट्य, व्यंजन एवं पेय पदार्थ, आंचलिक साहित्य तथा वन औषधियों का समृद्ध संसार समाहित है।

08 राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन

❑ चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा में स्थित अनुसंधान केंद्र में आयोजित 'राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' के अंतर्गत राष्ट्र-स्तरीय परामर्श एवं रणनीति सम्मेलन में 2030-31 तक दलहन उत्पादन 350 लाख टन करने और आयात पर निर्भरता खत्म करने के रोडमैप को अंतिम रूप दिया गया।

❑ मुख्य उद्देश्य

- आत्मनिर्भरता (Self-sufficiency): वर्ष 2027 तक दालों के उत्पादन में भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना।
- आयात में कमी: हर साल दालों के आयात पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपयों की बचत करना।
- किसानों की आय में वृद्धि: दालों के लाभकारी मूल्य और उन्नत तकनीक के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारना।

❑ मिशन की प्रमुख रणनीतियाँ

- उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना: प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ाने के लिए उच्च उपज वाली किस्मों (High-yielding varieties) पर ध्यान केंद्रित करना।
- क्षेत्र विस्तार (Area Expansion): ऐसी ज़मीन पर दालें उगाना जहाँ वर्तमान में खेती कम हो रही है, विशेषकर चावल की कटाई के बाद खाली पड़े खेतों (Rice Fallows) का उपयोग करना।
- बीज केंद्रों (Seed Hubs) की स्थापना: गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए देश भर में बीज केंद्रों का जाल बिछाना।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद: सरकार ने अरहर (तुअर), उड़द और मसूर के लिए 'बंपर' खरीद का आश्वासन दिया है ताकि किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाया जा सके।
- ई-समृद्धि पोर्टल: भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) और NCCF के माध्यम से किसानों का पंजीकरण करना ताकि वे अपनी उपज सीधे सरकार को बेच सकें।

❑ मुख्य चुनौतियाँ

- मानसून पर निर्भरता: भारत में अधिकांश दालें असिंचित (बिना सिंचाई वाली) भूमि पर उगाई जाती हैं, जिससे उत्पादन अस्थिर रहता है।
- भंडारण की कमी: दालों के सुरक्षित भंडारण और प्रसंस्करण (Processing) की सुविधाओं में अभी भी सुधार की गुंजाइश है।
- कम उत्पादकता: प्रति हेक्टेयर उपज के मामले में हम अभी भी वैश्विक औसत से पीछे हैं।

❑ वर्तमान स्थिति और महत्व

- भारत का स्थान: भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है।
- चुनौती: मांग और आपूर्ति के बीच अंतर के कारण हमें अभी भी अरहर और उड़द जैसी दालें मोजाम्बिक, म्यांमार और अन्य देशों से आयात करनी पड़ती हैं।
- पोषण: दालें प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं, इसलिए खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ पोषण सुरक्षा के लिए भी यह मिशन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

09 उत्तराखण्ड में शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के टनकपुर में लगभग ₹3,300 करोड़ की लागत वाली महत्वाकांक्षी शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया। 200 वर्ग किलोमीटर

में फैली यह परियोजना, जिसका उद्देश्य पर्यटन, बुनियादी ढांचे और रोजगार को बढ़ावा देना है, इसमें शारदा घाट का पुनर्विकास, जल निकासी प्रणाली, हेलीपैड और साहसिक पर्यटन (राफ्टिंग/पैराग्लाइडिंग) सुविधाएं शामिल हैं।

❑ परियोजना के मुख्य विवरण:

- उद्देश्य: धार्मिक पर्यटन (पूर्णगिरी मेला), साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था व रोजगार को सशक्त करना।
- क्षेत्रफल: यह परियोजना चंपावत जिले के लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करती है, जो बनबसा से लेकर माता रणकोची तक फैली है।
- निवेश: इस बड़े पैमाने की परियोजना के लिए लगभग ₹3,300 करोड़ प्रस्तावित हैं।

❑ प्रमुख घटक:

- शारदा घाट पुनर्विकास: घाटों का सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास।
- बुनियादी ढांचा: टनकपुर शहर की जल निकासी व्यवस्था में सुधार, हेलीपैड और बहुमंजिला पार्किंग।
- पर्यटन गतिविधियां: शारदा नदी में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और अन्य साहसिक खेल।
- सांस्कृतिक/धार्मिक पर्यटन: प्रसिद्ध पूर्णागिरी मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार और विकास।
- इस परियोजना का उद्देश्य न केवल पर्यटन को बढ़ाना है, बल्कि बाढ़ प्रतिरोधी संरचनाओं के माध्यम से नदी के प्रवाह को नियंत्रित कर पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है।

❑ शारदा नदी के बारे में:-

- शारदा नदी, जिसे नेपाल में महाकाली और ऊपरी क्षेत्रों में काली नदी के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में कालापानी (लिपुलेख दर्रा) क्षेत्र से निकलती है।
- बनबसा बैराज के बाद मैदानी इलाकों में प्रवेश करने पर यह शारदा नदी के नाम से जानी जाती है।
- यह नदी भारत और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है, फिर उत्तर प्रदेश में बहते हुए बहराइच के पास घाघरा नदी में मिल जाती है।
- इसकी कुल लंबाई लगभग 480 किमी. (300 मील) है।
- धौलीगंगा, गौरीगंगा, और लधिया इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं।
- भारत और नेपाल इस नदी पर 'पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना' (Pancheshwar Dam) पर काम कर रहे हैं, जो बिजली उत्पादन और सिंचाई के लिए बेहद अहम है।
- टनकपुर के पास बना शारदा बैराज सिंचाई के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ से उत्तर प्रदेश की कई नहरें निकलती हैं।

10 लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

❑ चर्चा में क्यों?

फरवरी 2026 में लोकसभा में विपक्ष ने अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और वामपंथी दलों सहित विपक्षी दलों ने महासचिव को सौंपे गए नोटिस पर हस्ताक्षर किए, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने इस हस्ताक्षर नहीं किया।

❑ अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया -

- लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना संसदीय लोकतंत्र में एक बड़ा कदम है। भारत में अध्यक्ष का पद निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उन्हें हटाने की प्रक्रिया को काफी विशिष्ट रखा गया है।

➲ संवैधानिक आधार

- संविधान के अनुच्छेद 94(c) के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से एक संकल्प (Resolution) पारित करके हटाया जा सकता है।

➲ आवश्यक शर्तें और प्रक्रिया

- लोकसभा के नियमों (विशेषकर नियम 200-203) के तहत यह प्रक्रिया चलती है:
  - → पूर्व सूचना: प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिनों का लिखित नोटिस देना अनिवार्य है।
  - → समर्थन: प्रस्ताव को सदन में पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए।
  - → अध्यक्ष की भूमिका: जब उनके खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा हो रही हो, तो वे सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। उनकी जगह उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) या पैनल का कोई अन्य सदस्य सदन चलाता है।
  - → बोलने का अधिकार: अध्यक्ष को अपने बचाव में सदन में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का पूरा अधिकार होता है, लेकिन वे केवल पहली बार में मत (Vote) दे सकते हैं, निर्णायक मत (Casting Vote) नहीं।

➲ बहुमत का गणित

- अध्यक्ष को हटाने के लिए 'प्रभावी बहुमत' (Effective Majority) की आवश्यकता होती है।
- सदन की कुल सदस्य संख्या में से रिक्तियों (Vacancies) को घटाने के बाद जो संख्या बचती है, उसका 50% से अधिक।
- यह सामान्य विधायी कार्यों के लिए आवश्यक 'साधारण बहुमत' से अधिक कठिन होता है।

❑ ऐतिहासिक संदर्भ

- भारत में अब तक किसी भी लोकसभा अध्यक्ष को इस प्रस्ताव के जरिए पद से नहीं हटाया जा सका है। हालांकि जी.वी. मावलंकर (1954) और कुछ अन्य अध्यक्षों के खिलाफ ऐसे नोटिस लाए गए थे, लेकिन वे सफल नहीं हुए या उन पर चर्चा नहीं हुई।

11 गुजरात सरकार का स्टारलिंक के साथ आशय पत्र (Letter of Intent - LoI) हस्ताक्षर

'डिजिटल इंडिया' के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, गुजरात सरकार ने एलन मस्क की स्पेसएक्स की सैटेलाइट इंटरनेट सहायक कंपनी स्टारलिंक के साथ आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किया।

❑ मुख्य बिंदु:

- यह दस्तावेज़ गांधीनगर में राज्य उद्योग आयुक्त पी. स्वरूप और स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख प्रभाकर जयकुमार के बीच आदान-प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी उपस्थित रहे।

- इस समझौते का उद्देश्य राज्य के दूरस्थ, आदिवासी, सीमावर्ती और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में हाई-स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना है। यह पहल शिक्षा, स्वास्थ्य, ई-गवर्नेंस और आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देगी।
- गुजरात सरकार की पायलट परियोजना का दायरा:
  - → शिक्षा (स्मार्ट स्कूल) : उपग्रह इंटरनेट से उन स्कूलों में भी डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा मिलेगी जहाँ बिजली या केबल की पहुँच सीमित है।
  - → स्वास्थ्य (टेलीमेडिसिन) : ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) को बड़े अस्पतालों से जोड़ा जाएगा, जिससे गाँव के मरीज को विशेषज्ञ डॉक्टरों से वीडियो कॉल पर परामर्श मिल सकेगा।
  - → तटीय सुरक्षा: गुजरात की लंबी तटरेखा की सुरक्षा के लिए पुलिस चौकियों को निर्बाध इंटरनेट मिलेगा, जिससे निगरानी तंत्र मजबूत होगा।
  - → कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs): सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ग्रामीणों को अब शहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ग्रामीण केंद्रों पर हाई-स्पीड कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी।
  - → GIDC और बंदरगाह: औद्योगिक पार्कों में लॉजिस्टिक्स को ट्रैक करने और डेटा साझा करने के लिए तेज़ नेटवर्क का उपयोग होगा।
  - → वन्यजीव अभयारण्य: गिर जैसे अभयारण्यों में वन्यजीवों की निगरानी और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए 'सेंसर' और 'कैमरा ट्रैप' को उपग्रह से कनेक्ट किया जा सकता है।
- पायलट आकलन की निगरानी एवं क्रियान्वयन के समन्वय हेतु गुजरात सरकार और स्टारलिंक के प्रतिनिधियों का एक संयुक्त कार्यदल गठित किया जाएगा।

❑ स्टारलिंक के बारे में:-

- स्टारलिंक (Starlink) एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) द्वारा विकसित एक क्रांतिकारी उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवा है।
- यह पारंपरिक भू-स्थिर उपग्रहों की तुलना में बहुत नीचे, लगभग 550 किमी की ऊंचाई पर उपग्रहों को तैनात करता है, जिससे इंटरनेट की गति तेज (150-500 Mbit/s) होती है।
- उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट प्राप्त करने के लिए एक 'डिश एंटीना', जिसे "डिशी" कहा जाता है और वाई-फाई राउटर की एक किट इंस्टॉल करनी होती है।
- यह ग्रामीण इलाकों, पहाड़ी क्षेत्रों, समुद्र और विमान जैसे स्थानों के लिए आदर्श है।
- भारत में, सेवा के लिए लगभग ₹34,000 की हार्डवेयर लागत और ₹8,600 का मासिक शुल्क अपेक्षित है, जिसके लिए प्रोविजनल लाइसेंस और ट्रायल चल रहे हैं।
- स्टारशील्ड, स्टारलिंक का एक विशेष संस्करण है जो रक्षा और सैन्य उद्देश्यों के लिए काम करता है।

EDU TERIA Telegram Channel
link : https://eduteria.live

12 ADB ने असम में बाढ़ प्रबंधन के लिए 182 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी।

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने फरवरी, 2026 में असम में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाए गए बाढ़ और नदी तट कटाव (riverbank erosion) के प्रबंधन के लिए 182 मिलियन डॉलर (लगभग ₹1,500 करोड़ से अधिक) के अतिरिक्त ऋण को मंजूरी दी है। यह कदम असम को आपदा-प्रतिरोधी राज्य बनाने और वहां के समुदायों की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा निवेश है।

मुख्य बिंदु

- उद्देश्य: ब्रह्मपुत्र नदी के कारण होने वाली भीषण बाढ़ और मिट्टी के कटाव को रोकना, जिससे ग्रामीण गरीबी और विस्थापन में कमी आए।
- अतिरिक्त वित्त पोषण: यह 182 मिलियन डॉलर का ऋण, अक्टूबर 2023 में स्वीकृत 200 मिलियन डॉलर की मौजूदा परियोजना के अतिरिक्त है।
- प्रमुख कार्य: लगभग 63.5 किलोमीटर लंबी नदी तट सुरक्षा दीवार का निर्माण।
  - → मौजूदा तटबंधों (embankments) को मजबूत करना।
  - → आधुनिक 'बाढ़ पूर्वानुमान' और 'प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली' को बेहतर बनाना।
- लाभार्थी: इस परियोजना से सीधे तौर पर असम के करीब 6 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है, विशेषकर उन गरीब परिवारों और महिलाओं को जो नदी के किनारे जोखिम में रहते हैं।
- क्षेत्र: इसके तहत ब्रह्मपुत्र के चार अतिरिक्त उच्च-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (high-priority reaches) को कवर किया जाएगा।

❑ ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में:-

- ब्रह्मपुत्र नदी, एशिया की सबसे प्रमुख और लंबी नदियों में से एक है। इसकी लम्बाई लगभग 2,900 किमी है।
- यह तिब्बत के मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में स्थित 'चेमायुंगडुंग ग्लेशियर' से उद्गमित होकर , भारत के अरुणाचल और असम राज्य में प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में पा (गंगा) के साथ मिलकर अंत में बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है।
- अपने मुहाने पर गंगा और ब्रह्मपुत्र, सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करते हैं जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है।
- इसे तिब्बत में 'त्सांगपो', अरुणाचल में 'दिहांग' और बांग्लादेश में 'जमुना' कहा जाता है। यह असम में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, माजुली, बनाती है।
- दिबांग, लोहित, धनश्री, सुबनसिरी, जियाभरेली, पगलादिया, मानस, तिस्ता, पिथुमारी और संकोश आदि ब्रम्हपुत्र की सहायक नदियां हैं।

❑ एशियाई विकास बैंक के बारे में:-

- एशियाई विकास बैंक (ADB) एक प्रमुख बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन, समावेशी आर्थिक विकास और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है।
- भारत ADB का एक संस्थापक सदस्य है और बैंक का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है।

13 दिल्ली 'लखपति बिटिया योजना'

❑ चर्चा में क्यों?

दिल्ली सरकार ने हाल ही में बालिकाओं की शिक्षा को मजबूत करने के लिए लखपति बिटिया योजना शुरू की है। यह योजना 2008 की पुरानी लाड़ली योजना का उन्नत रूप है और 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी।

मुख्य बिंदु

- मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'लखपति बिटिया योजना' की घोषणा की और यह 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगी। यह योजना वर्ष 2008 में शुरू की गई पुरानी 'लाड़ली योजना' का स्थान लेगी।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की समस्या को रोकना तथा उनकी शैक्षिक निरंतरता, वित्तीय सुरक्षा और सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है।
- सरकार कुल ₹56,000 की राशि अलग-अलग किस्तों में जमा करेगी, जो ब्याज सहित मैच्योरिटी पर ₹1 लाख से अधिक हो जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थी बेटी के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- पैसा एक साथ देने के बजाय पढ़ाई के महत्वपूर्ण चरणों (जैसे दाखिला, 10वीं पास, ग्रेजुएशन) पर दिया जाएगा -

चरण	मिलने वाली राशि (किस्त)
जन्म के समय	₹11,000
कक्षा 1 में प्रवेश	₹5,000
कक्षा 6 में प्रवेश	₹5,000
कक्षा 9 में प्रवेश	₹5,000
कक्षा 10 पास करने पर	₹5,000
कक्षा 12 में प्रवेश	₹5,000
ग्रेजुएशन या डिप्लोमा	₹20,000 (चरणों में)

❑ पात्रता और शर्तें :-

- परिवार पिछले कम से कम 3 वर्षों से दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  - → बेटी का जन्म दिल्ली में होना अनिवार्य है।
  - → परिवार की कुल वार्षिक आय ₹1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- यह लाभ एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों तक ही सीमित है।
  - → यदि लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले कर दी जाती है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

14 भगवान बुद्ध के पवित्र देवनीमोरी अवशेष

❑ चर्चा में क्यों?

भगवान बुद्ध के पवित्र देवनीमोरी अवशेष श्रीलंका में एक सप्ताह (4 से 11 फरवरी 2026) के ऐतिहासिक सार्वजनिक प्रदर्शन के बाद भारत लौट आए हैं। कोलंबो के गंगारामया मंदिर में आयोजित इस प्रदर्शनी में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यह पहली बार था जब गुजरात के देवनीमोरी से प्राप्त अवशेष विदेश में प्रदर्शित किए गए थे, जो भारत-श्रीलंका के गहरे आध्यात्मिक संबंधों को दर्शाता है।

मुख्य बिंदु

- ये पवित्र अवशेष मूल रूप से गुजरात के शामलाजी के पास स्थित 'देवनीमोरी' स्तूप की खुदाई के दौरान मिले थे।
  - → ऐतिहासिक साक्ष्य: पुरातात्विक खुदाई में एक पत्थर का संदूक (Casket) मिला था जिस पर खुदे लेखों से इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि होती है।
  - → समय काल: यह स्तूप लगभग चौथी शताब्दी (क्षत्रप काल) का माना जाता है।
- श्रीलंका की यात्रा

  श्रीलंका की सरकार और वहां के बौद्ध समुदाय के विशेष अनुरोध पर भारत सरकार ने इन अवशेषों को प्रदर्शन के लिए भेजा था।
  - → आस्था का केंद्र: श्रीलंका में लाखों श्रद्धालुओं ने इन अवशेषों के दर्शन किए, जो भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' (पड़ोसी पहले) और साझा सांस्कृतिक विरासत की नीति को मजबूत करता है।
  - → राजनयिक संबंध: इस तरह के 'अवशेष कूटनीति' (Relic Diplomacy) के माध्यम से भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव को बढ़ावा देता है।
- सुरक्षित वापसी
  - → प्रदर्शन के बाद इन अवशेषों को पूरी सुरक्षा और सम्मान के साथ भारत वापस लाया गया है। इन्हें आमतौर पर बड़ौदा (वडोदरा) के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय (MSU) के संग्रहालय में संरक्षित रखा जाता है।
- नोट: देवनीमोरी के स्तूप से मिला यह संदूक न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि कला की दृष्टि से भी यह 'गांधार शैली' और स्थानीय भारतीय कला के अद्भुत संगम को दर्शाता है।

15 राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के संदर्भ में गृह मंत्रालय का नया प्रोटोकॉल

❑ चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और सरकारी निकायों को नई एडवाइजरी जारी की है, इसके अनुसार जब भी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान एक साथ गाए जाएं, तो राष्ट्रीय गीत को पहले गाया या बजाया जाए। साथ ही राष्ट्रगीत के पहले सभी छह छंद का गायन भी अनिवार्य होगा।

❑ नया प्रोटोकॉल क्या है?

- यह नया प्रोटोकॉल संविधान के अनुच्छेद 51A(a) के अंतर्गत निहित मूल कर्त्तव्य राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान एवं अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध है।
- जब एक ही कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों बजाए जाते हैं, तो 'वंदे मातरम्' पहले बजाया या गाया जाना चाहिये, उसके बाद 'जन गण मन' गाया जाना चाहिये।
- जब राष्ट्रीय गीत का सरकारी संस्करण (लगभग 3 मिनट 10 सेकंड लंबा) गाया या बजाया जाता है, तो श्रोताओं को खड़े होकर सम्मान व्यक्त करना अनिवार्य है।
- अब राष्ट्रीय गीत को विशेष उच्च स्तरीय सरकारी कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से बजाया या गाया जाना तय किया गया है।

→ राष्ट्रपति या राज्यपाल/उप-राज्यपाल के आगमन और प्रस्थान पर औपचारिक राज्य समारोहों में
→ राष्ट्रपति के देश को संबोधित करने से तुरंत पहले और बाद में, चाहे वह ऑल इंडिया रेडियो या टीवी पर हो।
→ जब राष्ट्रीय ध्वज परेड में लाया जाता है।
→ सांस्कृतिक या औपचारिक समारोहों में (परेड के अलावा) राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर।

❑ राष्ट्रगीत "वन्दे मातरम्" के बारे में -

भारत का राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' न केवल एक गीत है, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक शक्तिशाली प्रतीक भी रहा है।

➲ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- रचनाकार: इसकी रचना प्रसिद्ध बंगाली लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी।
- स्रोत: यह गीत उनके प्रसिद्ध उपन्यास 'आनंदमठ' (1882) से लिया गया है।
- भाषा: मूल रूप से यह संस्कृत और बांग्ला भाषा का मिश्रण है।
- महत्व: स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 'वंदे मातरम' क्रांतिकारियों का प्रेरणा मंत्र बन गया था। 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार गाया था।
- इसके वर्तमान प्रसिद्ध धुन के लिए यदुनाथ भट्टाचार्य को श्रेय दिया जाता है।
- श्री अरबिंदो ने इसका अंग्रेजी में गद्य अनुवाद (Prose translation) किया था।

➲ राष्ट्रगीत का दर्जा

- 24 जनवरी, 1950 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा ने इसे 'राष्ट्रगीत' के रूप में स्वीकार किया। इसे भारत के राष्ट्रगान (जन गण मन) के समान दर्जा प्राप्त है।

➲ राष्ट्रगान 'जन गण मन' के बारे में -

- भारत का राष्ट्रगान 'जन गण मन' न केवल एक राष्ट्रगान है, बल्कि यह देश की एकता, संप्रभुता और गौरव का प्रतीक है।
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि -
  → इसकी रचना विश्वविख्यात कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर ने की थी।
  → यह मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा गया था।
  → इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था।
- राष्ट्रगान का दर्जा
  → भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रगान के रूप में अपनाया।
  → राष्ट्रगान की पूरी धुन गाने में निर्धारित समय 52 सेकंड है।
  → कुछ विशेष अवसरों पर इसका संक्षिप्त रूप (पहली और अंतिम पंक्ति) गाया जाता है, जिसमें लगभग 20 सेकंड का समय लगता है।
- नोट: रवींद्रनाथ ठाकुर ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रीय गान की रचना की, भारत के लिये "जन गण मन" तथा बांग्लादेश के लिये "आमार सोनार बांग्ला"।

16 औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026

❑ चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया है, जिसका उद्देश्य 2020 के कानून के तहत पुराने श्रम कानूनों को निरस्त करने से संबंधित अस्पष्टता को दूर करना है।

मुख्य बिंदु

- यह संशोधन 2020 की संहिता के तहत तीन पुराने कानूनों (ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926; औद्योगिक रोजगार अधिनियम, 1946; और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) के निरसन (repeal) के संबंध में कानूनी स्पष्टता और निश्चितता लाता है।
- श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा प्रस्तुत यह विधेयक 21 नवंबर, 2025 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा, जो ट्रेड यूनियन, औद्योगिक रोजगार और विवाद अधिनियमों को प्रतिस्थापित करता है।
- यह संशोधन मुख्य रूप से "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" और श्रमिकों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। इसके कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हो सकते हैं:
  → विवाद समाधान प्रक्रिया (Dispute Resolution): औद्योगिक विवादों को सुलझाने के लिए ट्रिब्यूनल की प्रक्रियाओं को और अधिक डिजिटल और समयबद्ध (Time-bound) बनाने का प्रस्ताव।
  → छंटनी और क्लोजर के नियम: कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में छंटनी (Retrenchment) के लिए अनुमति की सीमा में बदलाव की चर्चा है, ताकि कंपनियां बाजार की स्थिति के अनुसार तेजी से ढल सकें।
  → निश्चित अवधि का रोजगार (Fixed-term Employment): कॉन्ट्रैक्ट लेबर और परमानेंट स्टाफ के बीच के अंतर को कम करने और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को अधिक स्पष्ट करने पर जोर।
  → यूनियन मान्यता: ट्रेड यूनियनों की मान्यता के लिए वोटिंग और सदस्यता सत्यापन के नियमों को सरल बनाना।

❑ संशोधन की आवश्यकता क्यों?

- सरकार अक्सर इन बदलावों के पीछे निम्नलिखित तर्क देती है:
  → निवेश को बढ़ावा: श्रम कानूनों को लचीला बनाकर विदेशी और घरेलू निवेश (FDI) को आकर्षित करना।
  → डिजिटलीकरण: पुराने कागजी कामकाज को पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना ताकि पारदर्शिता बढ़े।
  → बदलती अर्थव्यवस्था: गिग इकोनॉमी (Gig Economy) और नए जमाने के स्टार्टअप्स की जरूरतों को देखते हुए पुराने नियमों में सुधार की जरूरत महसूस की जा रही थी।

❑ विपक्ष और श्रमिक संगठनों की प्रतिक्रिया -

- आमतौर पर ऐसे संशोधनों पर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। जहाँ उद्योग जगत इसका स्वागत करता है, वहीं कुछ श्रमिक संगठन 'हायर एंड फायर' (Hire and Fire) नीति के बढ़ते प्रभाव और जॉब सिक्योरिटी को लेकर चिंता जताते हैं।

17 राइट टू रिकॉल (Right to Recall)

❑ चर्चा में क्यों?

हाल ही में सांसद राघव चड्ढा ने संसद में राइट टू रिकॉल का मुद्दा उठाया। राइट टू रिकॉल (Right to Recall) या 'वापस बुलाने का अधिकार' एक ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसके तहत मतदाता अपने चुने हुए प्रतिनिधि (जैसे विधायक या सांसद) को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पद से हटा सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो, अगर जनता अपने प्रतिनिधि के काम से खुश नहीं है, तो उसे 5 साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वे एक तय प्रक्रिया के जरिए उसे वापस बुला सकते हैं।

❑ कार्य प्रक्रिया :

- याचिका (Petition): क्षेत्र के मतदाताओं का एक निश्चित प्रतिशत (जैसे 25% या 50%) हस्ताक्षर करके प्रतिनिधि को हटाने की मांग करता है।
- मतदान (Voting): यदि याचिका वैध पाई जाती है, तो उस निर्वाचन क्षेत्र में विशेष मतदान कराया जाता है।
- परिणाम: यदि बहुमत प्रतिनिधि के खिलाफ वोट देता है, तो उसे पद छोड़ना पड़ता है और उस सीट पर फिर से चुनाव होते हैं।

❑ भारत में वर्तमान स्थिति:

- भारत में राष्ट्रीय स्तर (लोकसभा या राज्यसभा) पर फिलहाल 'राइट टू रिकॉल' का कानून नहीं है। हालांकि, कुछ राज्यों में स्थानीय निकायों (पंचायती राज और नगर निकायों) में यह व्यवस्था लागू है:
  - → मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और हरियाणा जैसे राज्यों में सरपंचों या स्थानीय पार्षदों के खिलाफ 'राइट टू रिकॉल' के प्रावधान मौजूद हैं।
  - → हरियाणा में हाल ही में (2020) ग्राम पंचायतों के लिए इसे कानूनी रूप दिया गया है।

❑ भारत में इसके सबसे बड़े पैरोकार:

- भारत में इस अधिकार की मांग नई नहीं है। समय-समय पर कई दिग्गजों ने इसकी वकालत की है:
  - → वी.के. कृष्ण मेनन: उन्होंने 1950 के दशक में ही लोकसभा में इसकी वकालत की थी।
  - → जयप्रकाश नारायण (JP): 1974 के छात्र आंदोलन के दौरान उन्होंने इसे "सच्चे लोकतंत्र" की नींव बताया था।
  - → अन्ना हजारे: 2011 के लोकपाल आंदोलन के दौरान उन्होंने 'राइट टू रिकॉल' और 'राइट टू रिजेक्ट' (नोटा) को चुनावी सुधारों के लिए अनिवार्य बताया था।

18 मध्य प्रदेश के बालाघाट, WLGSP के अंतर्गत एक पायलट जिला चुना गया

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना (WLGSP) के अंतर्गत एक पायलट जिले के रूप में चुना गया है। बालाघाट जिले के परसवाड़ा में 500 मीट्रिक टन क्षमता के एक गोदाम का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2024 में किया गया। यह परियोजना स्थानीय स्तर पर अनाज भंडारण को बढ़ावा देती है।

❑ बालाघाट ही क्यों?

- बालाघाट अपनी धान (चावल) की पैदावार विशेषकर 'चिन्नौर' चावल जिसे GI टैग प्राप्त है, के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ उत्पादन अधिक होने के कारण भंडारण की आधुनिक सुविधाओं की आवश्यकता सबसे अधिक महसूस की जा रही थी।

❑ योजना की प्रमुख विशेषताएं और विवरण:

- उद्देश्य: छोटे और सीमांत किसानों को फसल बेचने की मजबूरी (distress sale) से बचाना और उन्हें स्थानीय स्तर पर भंडारण क्षमता प्रदान करना।
- पायलट परियोजना: बालाघाट जिले की बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी मर्यादित (PACS) परसवाड़ा में 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम का निर्माण किया गया है, जो अब पूरी तरह चालू है।
- गोदाम का उपयोग: निर्मित गोदाम का उपयोग मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन (MPWLC) द्वारा किया जा रहा है।
- कार्यान्वयन: यह योजना कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना (AMI) जैसी कई योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से PACS स्तर पर लागू की जा रही है।
- सब्सिडी: इस योजना के तहत पैक्स के लिए सब्सिडी को 25% से बढ़ाकर 33.33% कर दिया गया है।

यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता को बढ़ाकर फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

19 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन किया

फरवरी, 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 'सेवा तीर्थ' (नया PMO) और कर्तव्य भवन-1 व 2 का उद्घाटन किया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत निर्मित यह अत्याधुनिक परिसर अब प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSCS) और कैबिनेट सचिवालय का केंद्र होगा। इसका उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को एकीकृत और आधुनिक बनाना है।

❑ सेवा तीर्थ के उद्घाटन की मुख्य विशेषताएं:

- उद्घाटन और स्थान: प्रधानमंत्री मोदी ने दारा शिकोह रोड पर 2.26 लाख वर्ग फुट में बने 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन किया।
- उद्देश्य: यह परिसर बिखरे हुए कार्यालयों को एक छत के नीचे लाकर कार्यकुशलता और समन्वय (coordination) को बढ़ाएगा।
- ऐतिहासिक महत्व: 13 फरवरी, 1931 को नई दिल्ली को राजधानी घोषित किए जाने के 95 वर्ष पूरे होने पर यह उद्घाटन किया गया।
- विशेषताएं: यह परिसर 4-स्टार GRIHA मानकों पर आधारित है, जो ऊर्जा-कुशल (energy-efficient), वाटर-कंजर्वेशन (water conservation), और उच्च-स्तरीय सुरक्षा (smart access control) से युक्त है।
- सत्ता से सेवा: पीएम मोदी ने इसे 'सत्ता की मानसिकता' से 'सेवा की भावना' की ओर बदलाव का प्रतीक बताया।

- सेवा तीर्थ स्मारक: अवसर पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया।

सेवा तीर्थ के उद्घाटन के साथ, अब प्रमुख मंत्रालय और प्रशासनिक विभाग अधिक सुव्यवस्थित तरीके से कार्य कर सकेंगे।

20 केरल सरकार का "स्त्री सुरक्षा योजना"

हाल ही में केरल सरकार ने राज्य में बेरोज़गार महिलाओं और ट्रांसवुमन (ट्रांसजेंडर महिलाओं) को एक हजार रुपए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है।

मुख्य बिंदु

- लॉन्च और कार्यान्वयन:
  - → मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आधिकारिक तौर पर फरवरी 2026 में इस योजना की शुरुआत की।
  - → पहले चरण में ही लगभग 10.18 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से राशि ट्रांसफर की गई है।
- उद्देश्य: इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की वित्तीय निर्भरता को कम करना और समाज में 'जेंडर जस्टिस' (Gender Justice) को बढ़ावा देना है। यह योजना विशेष रूप से उन बेरोजगार महिलाओं और ट्रांस-महिलाओं के लिए है जो किसी अन्य सामाजिक कल्याण पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हैं।
- वित्तीय सहायता: पात्र लाभार्थियों को ₹1,000 प्रति माह की वित्तीय सहायता (पेंशन के रूप में) दी जाएगी।
- आवेदन प्रक्रिया: इच्छुक महिलाएं KSMART पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
- आयु सीमा: इसके लिए आवेदन करने वाली महिलाओं की आयु 35 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- पात्रता (राशन कार्ड): केवल वे ही इसके पात्र हैं जिनके पास अंत्योदय अन्न योजना (पीला कार्ड) या प्राथमिकता वाले परिवार (गुलाबी कार्ड) श्रेणी का राशन कार्ड है।

21 असम के 'मोरान बाईपास' पर पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ में 'मोरान बाईपास' पर पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (Emergency Landing Facility -ELF) का उद्घाटन किया। यह परियोजना न केवल परिवहन के लिए, बल्कि भारत की रणनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है।

❑ मुख्य विशेषताएं और महत्व

- रणनीतिक स्थान: डिब्रूगढ़ में इसकी स्थिति चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के करीब होने के कारण सैन्य दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- बहुउद्देशीय उपयोग: यह सुविधा सामान्य समय में राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में कार्य करेगी, लेकिन युद्ध या आपातकाल के दौरान इसे लड़ाकू विमानों और मालवाहक विमानों के लिए रनवे के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।
- कनेक्टिविटी: यह पूर्वोत्तर भारत में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और संकट के समय त्वरित मानवीय सहायता (HADR) पहुँचाने में मदद करेगी।
- लंबाई और क्षमता: यह लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी है, जो बड़े मालवाहक और लड़ाकू विमानों को सुरक्षित उतारने में सक्षम है।
- तकनीकी विवरण: इस तरह की स्ट्रिप्स को विशेष रूप से भारी विमानों के भार को सहने के लिए बनाया जाता है और इनमें हवाई यातायात नियंत्रण (ATC) की बुनियादी सुविधाएं भी शामिल होती हैं।

❑ भारत में अन्य ELF स्थल

- भारत के पास पहले से ही कुछ अन्य स्थानों पर ऐसी सुविधाएं हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - → राजस्थान: बाड़मेर (NH-925A)
  - → उत्तर प्रदेश: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
  - → आंध्र प्रदेश: बापटला (NH-16)
- नोट: भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो अपने राष्ट्रीय राजमार्गों को रनवे के रूप में उपयोग करने की क्षमता विकसित कर रहे हैं।

22 प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र पर बने "कुमार भास्कर वर्मा सेतु" का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने आधुनिक कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। यह पुल गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ता है और क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई गति देगा।

मुख्य बिंदु

- इस पुल के बनने से गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के बीच यात्रा का समय 45-60 मिनट से घटकर मात्र 7 से 10 मिनट रह जाएगा।
- लगभग 2.86 किलोमीटर लंबा यह 6-लेन एक्स्ट्राडोज्ड प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट (पीएससी) पुल लगभग 3,030 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। यह पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्स्ट्राडोज्ड पुल है।
- भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए पुल में बेस आइसोलेशन तकनीक का उपयोग किया गया है, जिसमें फ्रिक्शन पेंडुलम बेयरिंग्स लगाए गए हैं।
- हाई-परफॉर्मेंस स्टे केबल्स और ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम (बीएचएमएस) पुल की मजबूती और दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। बीएचएमएस रियल-टाइम निगरानी और शुरुआती क्षति पहचान में मदद करता है।
  - → इसका नाम महान कामरूप राजा कुमार भास्कर वर्मा के नाम पर रखा गया है, जो प्राचीन असम के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे।

❑ राजा कुमार भास्कर वर्मा के बारे में

- राजा कुमार भास्कर वर्मा, प्राचीन असम (कामरूप) के वर्मन राजवंश के सबसे प्रतापी राजा थे। उनके शासनकाल (594-650 ईस्वी) को असम का स्वर्ण युग माना जाता है।

- प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन सांग (Xuanzang) उन्हीं के बुलावे पर असम आए थे। उन्होंने राजा भास्कर वर्मा की खेती, सिंचाई और शिक्षा के प्रति प्रेम की तारीफ की थी।
- उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन के साथ उनके बहुत मजबूत रिश्ते थे।
- उनके पास 30,000 नावों की विशाल नौसेना और 20,000 हाथियों की सेना थी।
- वे जीवन भर अविवाहित रहे, इसलिए उन्हें 'कुमार राजा' कहा जाता है। असमिया कैलेंडर (भास्कराब्द) की शुरुआत भी उन्हीं के राज्याभिषेक से मानी जाती है।

23 'पीएम राहत' (PM RAHAT) योजना

❑ चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की जान बचाने और उन्हें तुरंत आर्थिक मदद देने के लिए 'पीएम राहत' (PM RAHAT) योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 'गोल्डन आवर' (दुर्घटना के बाद का पहला घंटा) में बिना किसी वित्तीय बाधा के बेहतर इलाज सुनिश्चित करना है।

❑ पीएम राहत योजना की मुख्य विशेषताएं:-

- कैशलेस इलाज: दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होते समय कोई पैसा जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- उपचार सीमा: प्रति व्यक्ति ₹1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार मुफ्त दिया जाएगा।
- समय सीमा: यह कवर दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों तक के लिए वैध है।
- हर सड़क पर लागू: यह योजना देश की सभी श्रेणियों की सड़कों (नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या स्थानीय सड़कें) पर होने वाली दुर्घटनाओं के लिए लागू है।
- अस्पताल: इसके तहत 'आयुष्मान भारत' (AB PM-JAY) से जुड़े सभी अस्पतालों को 'नामित अस्पताल' माना गया है, जहाँ पीड़ित अपना इलाज करा सकते हैं।
- नोट:- 'पीएम राहत' (PM RAHAT) में RAHAT का पूर्ण रूप 'Road Accident Health Assistance Treatment' है।

24 इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट 2026

❑ चर्चा में क्यों?

नई दिल्ली में इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 (India-AI Impact Summit 2026) का आयोजन फरवरी, 2026 में नई दिल्ली में किया गया। यह ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) में आयोजित होने वाला अपनी तरह का पहला बड़ा वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन रहा। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य एआई (AI) के व्यावहारिक उपयोग और उसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर चर्चा करना था, न कि केवल इसके तकनीकी पहलुओं पर।

मुख्य बिंदु

- तिथि: 16–21 फरवरी, 2026
- स्थान: भारत मंडपम, नई दिल्ली (मुख्य केंद्र), साथ ही सुषमा स्वराज भवन और विज्ञान भवन।
- आयोजक: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
- थीम: "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" (सभी का कल्याण, सभी की खुशी)।
- प्रमुख स्तंभ (Sutras): यह तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित था—People (लोग), Planet (ग्रह), और Progress (प्रगति)।

❑ शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं -

- ग्लोबल डिक्लेरेशन: सम्मेलन के दौरान "इंडिया एआई इम्पैक्ट डिक्लेरेशन" को 92 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने अपनाया। यह एआई के जिम्मेदार और समावेशी उपयोग पर जोर देता है।
- भारी निवेश: इस आयोजन के माध्यम से एआई बुनियादी ढांचे और अनुसंधान में लगभग 200 बिलियन डॉलर से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई।
- दिग्गज वक्ताओं की भागीदारी: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी को मुख्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसमें सुंदर पिचाई (Google), सत्य नडेला (Microsoft), और सैम ऑल्टमैन (OpenAI) जैसे दिग्गजों के साथ-साथ कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों (जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा) ने हिस्सा लिया।

❑ सात चक्र (7 Chakras): चर्चा के लिए सात कार्य समूहों (Working Groups) का गठन किया गया था:

- मानव पूंजी (Human Capital)
- सामाजिक सशक्तिकरण के लिए समावेश (Inclusion)
- सुरक्षित और विश्वसनीय एआई (Safe & Trusted AI)
- विज्ञान (Science)
- एआई संसाधनों का लोकतंत्रीकरण (Democratizing AI)
- आर्थिक विकास (Economic Growth)
- लचीलापन और दक्षता (Resilience & Efficiency)

❑ प्रमुख उपलब्धियां:-

- Equitable AI Transition Playbook: श्रमिकों को एआई के दौर में तैयार करने के लिए ILO के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया गया।
- Guinness World Record: 24 घंटों के भीतर एआई जिम्मेदारी अभियान के लिए 2.5 लाख से अधिक प्रतिज्ञाएं (pledges) प्राप्त करने का विश्व रिकॉर्ड बना।
- एआई इम्पैक्ट एक्सपो: इसमें 850 से अधिक प्रदर्शकों ने अपनी एआई तकनीकों का प्रदर्शन किया, जिसमें रिलायंस जियो और गूगल जैसे बड़े नाम शामिल थे।

❑ महत्व:-

- सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहा कि भारत ने खुद को 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) के नेता के रूप में स्थापित किया। समिट में यह संदेश स्पष्ट था कि एआई तकनीक केवल विकसित देशों के पास ही केंद्रित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसका लाभ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों को भी मिलना चाहिए।

25 गोहपुर से नुमालीगढ़ तक 4-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मंजूरी

❑ चर्चा में क्यों?

कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) ने हाल ही में असम में गोहपुर से नुमालीगढ़ तक 4-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इसकी कुल लागत 18,662 करोड़ रुपये है।

❑ परियोजना की मुख्य विशेषताएं:-

- लंबाई: कुल 33.7 किलोमीटर लंबा 4-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर।
- कनेक्टिविटी: यह ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में स्थित गोहपुर (NH-15) को दक्षिण में स्थित नुमालीगढ़ (NH-715) से जोड़ेगा।
- अंडरवाटर टनल: इस प्रोजेक्ट का सबसे रोमांचक हिस्सा ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनने वाली 15.79 किमी लंबी ट्विन-ट्यूब सुरंग है।

❑ महत्व:-

- समय की भारी बचत: वर्तमान में इन दो शहरों के बीच की दूरी लगभग 220 किमी है, जिसे तय करने में 5-6 घंटे लगते हैं। इस कॉरिडोर के बाद यह सफर महज 20-30 मिनट का रह जाएगा।
- भारत की पहली रेल-सह-सड़क टनल: यह भारत की पहली ऐसी अंडरवाटर टनल होगी जिसमें सड़क के साथ-साथ रेल के लिए भी प्रावधान होगा।
- सामरिक और आर्थिक महत्व: यह अरुणाचल प्रदेश और उत्तर-असम के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए सेना की आवाजाही को आसान बनाएगा। साथ ही, यह 11 आर्थिक केंद्रों, 2 हवाई अड्डों और काजीरंगा जैसे पर्यटन स्थलों को भी जोड़ेगा।
- पर्यावरण का ध्यान: क्योंकि यह क्षेत्र काजीरंगा नेशनल पार्क के करीब है, इसलिए नदी के नीचे सुरंग बनाने का निर्णय लिया गया ताकि सतह पर वन्यजीवों को कोई परेशानी न हो।

26 केरल, व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने और उसे मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना।

केरल 2050 तक 80% शहरीकरण के अनुमान के साथ, एक व्यापक शहरी नीति (Comprehensive Urban Policy) का मसौदा तैयार करने और उसे मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा तैयार की गई यह 25 वर्षीय नीति, जलवायु-स्मार्ट शहरों, वैज्ञानिक योजना, विकेंद्रीकृत शासन, और समावेशी विकास पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य राज्य के शहरी परिदृश्य को व्यवस्थित करना है।

❑ मुख्य विशेषताएं:

- लक्ष्य (2050 तक): केरल खुद को जलवायु-संवेदनशील, वैज्ञानिक रूप से नियोजित, और टिकाऊ शहरों के नेटवर्क के रूप में बदलने का लक्ष्य रख रहा है।
- पृष्ठभूमि: इस नीति की घोषणा 2023-24 के राज्य बजट में की गई थी, और इसे विकसित करने के लिए एक विशेषज्ञ आयोग का गठन किया गया था।
  - → दिसंबर 2023 में गठित 'केरल शहरी नीति आयोग' ने मार्च 2025 में रिपोर्ट सौंपी।
- प्रमुख क्षेत्र: इसमें शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार, असमानता को कम करना, अपशिष्ट प्रबंधन (चक्रीय अर्थव्यवस्था), और लोगों के अनुकूल सेवाओं को प्राथमिकता दी गई है।
- स्थायी विकास: यह नीति Public Private People Partnership को बढ़ावा देती है और शहरीकरण के माध्यम से राज्य के आर्थिक विकास को समर्थन देने का प्रयास करती है।

27 NHAI द्वारा 'मधुमक्खी गलियारा' (Bee Corridor) पहल विकसित करने की घोषणा

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा शुरू की गई 'मधुमक्खी गलियारा' (Bee Corridor) पहल का उद्देश्य राजमार्गों के किनारे फूलदार पेड़ों, झाड़ियों और घासों की एक श्रृंखला लगाकर मधुमक्खियों और अन्य परागणकों (pollinators) के लिए साल भर भोजन और प्राकृतिक आवास सुरक्षित करना है। यह एक पर्यावरणीय पहल है, जिसके तहत 2026-27 तक लगभग 40 लाख पौधे लगाए जाने की योजना है, जिससे जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा मिलेगा।

❑ 'मधुमक्खी गलियारा' पहल के मुख्य उद्देश्य-

- जैव विविधता का संरक्षण: राजमार्गों के निर्माण से अक्सर प्राकृतिक आवास खंडित हो जाते हैं। यह गलियारा मधुमक्खियों, तितलियों और अन्य परागणकों को एक सुरक्षित मार्ग और घर प्रदान करता है।
- पौधों का चयन: स्थानीय और मौसम के अनुकूल फूलदार पौधों (जैसे सूरजमुखी, सरसों, नीम, करंज, महुआ, पलाश, जामुन और बबूल जैसे देशी पौधे) का चयन इस तरह किया जाता है कि परागणकों को हर मौसम में 'नेक्टर' (अमृत) और पराग मिलता रहे।
- कृषि उत्पादकता में वृद्धि: राजमार्ग अक्सर खेतों के बीच से गुजरते हैं। यदि राजमार्गों के किनारे मधुमक्खियाँ फलती-फूलती हैं, तो वे पास के खेतों में भी परागण करेंगी, जिससे किसानों की फसल की पैदावार बढ़ सकती है।
- कार्बन अवशोषण: सघन वृक्षारोपण और झाड़ियाँ न केवल धूल को रोकती हैं, बल्कि वाहनों से निकलने वाले कार्बन उत्सर्जन को सोखने में भी मदद करती हैं।

❑ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के बारे में -

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत 1988 के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है, जो फरवरी 1995 से सक्रिय है।
- इसका उद्देश्य भारत में विश्व स्तरीय राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना का निर्माण और प्रबंधन करना है।
- इसका प्रमुख कार्य राजमार्ग निर्माण, टोल शुल्क (Toll fee) संग्रह, और राजमार्गों का रखरखाव है।
- NHAI 'नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट' (NHDP) और 'भारतमाला परियोजना' जैसी प्रमुख परियोजनाओं को लागू करता है।

- यह टोल की समस्याओं को कम करने के लिए फास्टैग (FASTag) और कैमरा-आधारित ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) तकनीक का उपयोग करता है।

28 'ओल चिकी' लिपि का शताब्दी समारोह

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'ओल चिकी' लिपि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। 'ओल चिकी' (Ol Chiki) लिपि के 100 वर्ष पूरे होने का यह समारोह न केवल संथाली भाषा के लिए, बल्कि भारत की भाषाई विविधता के संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा मील का पत्थर है।

मुख्य बिंदु

- लिपि का इतिहास: 'ओल चिकी' लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने वर्ष 1925 में किया था। इसका उद्देश्य संथाली भाषा को उसकी अपनी विशिष्ट पहचान और लेखन शैली प्रदान करना था।
- संवैधानिक महत्व: संथाली भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम (2003) के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था।
- सांस्कृतिक गौरव: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो स्वयं संताल समुदाय से आती हैं, द्वारा इसका उद्घाटन करना इस लिपि के वैश्विक और राष्ट्रीय सम्मान को दर्शाता है।
- आयोजन का उद्देश्य: इस शताब्दी समारोह का मुख्य लक्ष्य जनजातीय भाषाओं के संरक्षण को बढ़ावा देना और आने वाली पीढ़ियों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना है।

❑ प्रमुख गतिविधियाँ:-

- कार्यक्रम का आयोजन डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में हुआ।
- समारोह में स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किए गए।
- संताल समुदाय के 10 विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया गया।

❑ लिपि की विशेषताएं:-

- 'ओल चिकी' में 'ओल' का अर्थ है 'लिखना' और 'चिकी' का अर्थ है 'लिपि'।
- यह लिपि ध्वन्यात्मक (Phonetic) है और इसमें 30 अक्षर होते हैं।
- इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह प्रकृति से प्रेरित है। इसके अक्षरों के आकार पहाड़ियों, नदियों और मिट्टी के बर्तनों जैसे प्राकृतिक और दैनिक जीवन के दृश्यों पर आधारित हैं।
- यह बाएँ से दाएँ (Left to Right) लिखी जाती है।
- नोट:- पंडित रघुनाथ मुर्मू को 'गुरु गोमके' की उपाधि से जाना जाता है।

29 'ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) परियोजना'

❑ चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने फरवरी 2026 में ₹81,000 करोड़ की 'ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) परियोजना' को हरी झंडी दे दी है। ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए तय शर्तों के अनुरूप इसे मान्यता प्रदान किया है।

❑ परियोजना के मुख्य स्तंभ:-

- यह एक "होलिस्टिक डेवलपमेंट" प्रोजेक्ट है जिसके चार प्रमुख घटक हैं:
  - → गलाथिया खाड़ी (Galathea Bay) में एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT)।
  - → एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (ना नागरिक और सैन्य दोनों उपयोग के लिए)।
  - → एक एकीकृत टाउनशिप (Integrated Township)।
  - → एक 450 MVA का गैस और सौर आधारित हाइब्रिड पावर प्लांट।

❑ सामरिक और आर्थिक महत्व:-

- मलक्का जलडमरूमध्य (Strait of Malacca): यह द्वीप वैश्विक व्यापार मार्ग के अत्यंत करीब है। यह परियोजना कोलंबो, सिंगापुर और पोर्ट क्लैंग जैसे विदेशी पोर्ट्स पर भारत की निर्भरता कम करेगी।
- हिंद महासागर क्षेत्र (IOR): सैन्य और नागरिक हवाई अड्डे के साथ यह भारत की समुद्री सुरक्षा और निगरानी क्षमताओं को मजबूत करेगा।
- ब्लू इकोनॉमी: यह 'मैरीटाइम इंडिया विजन 2030' और 'अमृत काल विजन 2047' का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

❑ पर्यावरणीय चिंताएं और NGT की शर्तें :-

- NGT ने कुछ कड़ी शर्तों के साथ अनुमति दी है, क्योंकि इस परियोजना के कारण लगभग 130 वर्ग किमी वन भूमि का उपयोग होगा और करीब 10 लाख पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है।
  - → कोरल सुरक्षा: Zoological Survey of India (ZSI) के मार्गदर्शन में कोरल कॉलोनियों को सुरक्षित रूप से दूसरी जगह स्थानांतरित (Translocation) करना होगा।
  - → लुप्तप्राय प्रजातियां: लेदरबैक कछुए (Leatherback Turtles), निकोबार मेगापोड और खारे पानी के मगरमच्छों के संरक्षण के लिए विशेष उपाय करने होंगे।
  - → रेतीले तटों का संरक्षण: NGT ने स्पष्ट किया है कि कछुओं के प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण रेतीले तटों (Sandy Beaches) को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।

30 केरल ने भारत की पहली "ग्राफीन नीति" को मंजूरी दी

फरवरी 2026 में केरल भारत का पहला राज्य बना जिसने अपनी समर्पित ग्रैफीन नीति (Graphene Policy) को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य राज्य को उच्च-तकनीकी अनुसंधान और विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। यह नीति पलक्कड़ में एक ग्रेफाइन पार्क और डिजिटल इनोवेशन सेंटर के माध्यम से 200 करोड़ रुपये के निवेश से शुरू की गई है।

❑ नीति के प्रमुख उद्देश्य -

- औद्योगिक हब: केरल को ग्रैफीन आधारित उद्योगों और अनुसंधान के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना।

- निवेश प्रोत्साहन: निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए सब्सिडी और विशेष वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना।
- उत्पादन इकाइयाँ: राज्य में ग्रैफीन के उत्पादन और प्रसंस्करण (processing) के लिए विशेष क्लस्टर विकसित करना।

❑ केरल को ही चुनने का कारण:-

- केरल ने पिछले कुछ वर्षों में ग्रैफीन के क्षेत्र में एक मजबूत आधार तैयार किया है:
  - → इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्रैफीन (IICG): यह कोच्चि में स्थित देश का पहला ग्रैफीन अनुसंधान केंद्र है।
  - → डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल: यहाँ ग्रैफीन पर उच्च स्तरीय शोध पहले से ही चल रहा है।
  - → करुप्पुपुर (Karuppuppur): केरल में ग्रेफाइट के भंडार मौजूद हैं, जो ग्रैफीन के उत्पादन के लिए कच्चा माल है।

❑ ग्रैफीन का महत्व:-

- ग्रैफीन एक परमाणु की मोटाई वाली कार्बन की परत है, जो स्टील से 200 गुना अधिक मजबूत और तांबे से कहीं बेहतर बिजली का संवाहक है। इसका उपयोग इन क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है:
  - → रक्षा: बुलेटप्रूफ जैकेट और रडार सिस्टम में।
  - → इलेक्ट्रॉनिक्स: तेजी से चार्ज होने वाली बैटरी और लचीले स्क्रीन।
  - → स्वास्थ्य: बायो-सेंसर्स और सटीक दवा वितरण (targeted drug delivery)।
- नोट:- ग्रैफीन को इसकी मजबूती और विद्युत चालकता के कारण "भविष्य का पदार्थ" (Wonder Material) माना जाता है।

31 "भारत-विस्तार (Bharat-VISTAAR) पहल"

भारत-विस्तार (Bharat-VISTAAR) केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा फरवरी 2026 में जयपुर से किसानों के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण डिजिटल सहयोगी कार्यक्रम है। यह कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका पूरा नाम Virtually Integrated System to Access Agricultural Resources (कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए आभासी एकीकृत प्रणाली) है।

मुख्य बिंदु

- इसके मुख्य उद्देश्य हैं:-
  - → डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI): इसे कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल आधार के रूप में विकसित किया गया है, जो विभिन्न सरकारी सेवाओं को एक ही मंच पर लाता है।
  - → एआई-संचालित परामर्श: यह किसानों को मौसम, मंडी भाव, कीट नियंत्रण और मृदा (मिट्टी) स्वास्थ्य के बारे में सटीक और रीयल-टाइम जानकारी प्रदान करता है।
- प्रमुख विशेषताएं:-
  - → भारती (Bharati) एआई असिस्टेंट: यह एक एआई-पावर्ड वॉयस असिस्टेंट है जो किसानों से उनकी मातृभाषा में बात कर सकता है।
  - → बहुभाषी समर्थन: इसे भारत की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है ताकि भाषा की बाधा दूर हो सके।
  - → एकीकृत प्लेटफार्म: यह AgriStack, ICAR (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद), और भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) जैसे महत्वपूर्ण डेटा स्रोतों को आपस में जोड़ता है।
  - → सरकारी योजनाओं तक पहुंच: किसान इस प्लेटफार्म के जरिए 10 से अधिक केंद्रीय योजनाओं (जैसे PM-KISAN) की पात्रता जांच सकते हैं और लाभों को ट्रैक कर सकते हैं।
- किसानों को लाभ:-
  - → बिचौलियों की समाप्ति: किसानों को सीधे सटीक जानकारी मिलती है, जिससे वे बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहते।
  - → त्वरित समाधान: टोल-फ्री नंबर (155261) या चैटबॉट के माध्यम से किसान अपनी खेती से जुड़ी समस्याओं का तुरंत समाधान पा सकते हैं।
  - → उत्पादकता में वृद्धि: वैज्ञानिक सलाह और समय पर अलर्ट मिलने से फसल की बर्बादी कम होती है और उत्पादन बढ़ता है।

32 'SAHI' और 'BODH' पहल

❑ चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने फरवरी 2026 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया ए आई समिट में भारत के ए आई स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य को नया रूप देने के लिए दो महत्वपूर्ण पहल 'SAHI' और 'BODH' का शुभारम्भ किया। SAHI का उद्देश्य एआई को नैतिक और साक्ष्य-आधारित बनाना है, जबकि BODH एक डेटा प्लेटफॉर्म है जो स्वास्थ्य डेटा की गोपनीयता बनाए रखते हुए एआई मॉडल्स का परीक्षण और मूल्यांकन करता है।

मुख्य बिंदु

- SAHI (Strategy for Artificial Intelligence in Healthcare for India -भारत में स्वास्थ्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की रणनीति):
  - → उद्देश्य: भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में AI के सुरक्षित, नैतिक, और समावेशी रूप से अपनाने के लिए राष्ट्रीय मार्गदर्शन प्रदान करना।
  - → कार्य: राज्यों और संस्थानों को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के अनुरूप AI के जिम्मेदार उपयोग में सहायता करना।
- BODH (Benchmarking Open Data Platform for Health AI - स्वास्थ्य AI के लिए बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म):
  - → विकास: इसे IIT कानपुर द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के सहयोग से विकसित किया गया है।
  - → विशेषता: यह एक गोपनीयता-सुरक्षित (Privacy-pre-serving) मंच है, जो अंतर्निहित डेटासेट को साझा किए बिना एआई मॉडल के सटीक मूल्यांकन को सक्षम बनाता है।
  - → महत्व: ये पहल भारत के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वास, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करती हैं।

→ लक्ष्य: एआई के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को आम नागरिक के लिए अधिक सुलभ और डेटा-आधारित बनाना।

33 BioAsia 2026 का 23वां संस्करण 'हैदराबाद' में आयोजित हुआ

हैदराबाद में BioAsia 2026 का 23वां संस्करण फरवरी, 2026 में आयोजित किया गया। यह एशिया का सबसे बड़ा लाइफ साइंसेज और हेल्थ-टेक फोरम है। इसका उद्घाटन तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने 17 फरवरी को हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (HICC) और HITEX प्रदर्शनी केंद्र में किया। इस दौरान उद्योग मंत्री डी. श्रीधर बाबू भी उपस्थित थे।

मुख्य बिंदु

- मुख्य विषय (Theme): इस वर्ष की थीम "TechBio Unleashed: AI, Automation & the Biology Revolution" रखी गई थी। यह मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित था कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटोमेशन दवा की खोज (drug discovery) और स्वास्थ्य सेवाओं को बदल रहे हैं।
- विस्तार: इस बार यह आयोजन 9,000 वर्ग मीटर के बड़े क्षेत्र में किया गया, जिसमें 500 से अधिक कंपनियों और 4,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

❑ सम्मेलन के प्रमुख आकर्षण:-

- जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड: कैंसर जीन थेरेपी में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ब्रूस एल. लेविन को प्रतिष्ठित 'जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड' से सम्मानित किया गया।
- प्रमुख वक्ता: सम्मेलन में गूगल डीपमाइंड के वीपी पुष्मीत कोहली, एमजेन (Amgen) के मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. हावर्ड वाई. चांग और नोवार्टिस व सनोफी जैसी वैश्विक कंपनियों के नेतृत्व ने हिस्सा लिया।
- नेक्स्ट-जेन लाइफ साइंसेज पॉलिसी: मुख्यमंत्री ने तेलंगाना की "नेक्स्ट-जेन लाइफ साइंसेज पॉलिसी 2026-30" पर जोर दिया, जिसका लक्ष्य 2030 तक 25 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करना है।
- नवाचार (Innovation): इसमें एक स्टार्टअप पैवेलियन बनाया गया जिसमें 40 उभरते स्टार्टअप्स ने अपनी अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया।

❑ महत्वपूर्ण घोषणाएं:-

- वैश्विक निवेश: फ्रांस (Opella Healthcare), इंडोनेशिया (Vaksindo) और अमेरिका की प्रमुख कंपनियों ने तेलंगाना में महत्वपूर्ण निवेश की घोषणाएं कीं।
- लक्ष्य: राज्य सरकार का लक्ष्य तेलंगाना को 2047 तक लाइफ साइंसेज का वैश्विक इकोसिस्टम बनाना है।

34 दुनिया का पहला 'ह्यूमैनिटी-फर्स्ट' AI शहर बनाएगा बेंगलुरु का स्टार्टअप Bharat1.AI

भारत मंडपम, नई दिल्ली में हाल ही में संपन्न हुए India AI Impact Summit 2026 के दौरान, बेंगलुरु के स्टार्टअप Bharat1.AI ने दुनिया का पहला 'ह्यूमैनिटी-फर्स्ट' AI शहर बनाने के प्लान की घोषणा की।

❑ प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य (B1 AI City)

- Bharat1 का लक्ष्य एक ऐसा शहर जैसा 'सिमुलेशन' तैयार करना है जहाँ AI एजेंट्स और फिजिकल रोबोट्स को असली दुनिया के माहौल में टेस्ट किया जा सके।
  - → इसे 'Humanity-First' इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका फोकस AI को केवल शक्तिशाली बनाने पर नहीं, बल्कि उसे इंसानी मूल्यों और सुरक्षा के साथ जोड़ने पर है।
  - → यह इंटरनेट के पुराने डेटा के बजाय रीयल-टाइम 4D डेटा (लगभग 1 एक्सबाइट प्रति वर्ष) का उपयोग करेगा।

❑ पहला चरण: B1 AI सुपरपार्क

- इस विजन का पहला कदम बेंगलुरु के सरजापुर (Sarjapura) में 5 लाख वर्ग फुट का एक रिसर्च कैंपस होगा।
  - → क्षमता: यहाँ 10,000 से अधिक AI शोधकर्ता और स्टार्टअप्स एक साथ काम कर सकेंगे।
  - → पार्टनरशिप: इस प्रोजेक्ट में NVIDIA के साथ-साथ IIT कानपुर (Airawat Foundation), IISc (SPARC), और BITS पिलानी जैसे संस्थान भी शामिल हैं।
  - → कनेक्टिविटी: कैंपस में 400 Gbps की सुपर-फास्ट कनेक्टिविटी होगी ताकि बड़े मॉडल की ट्रेनिंग में कोई बाधा न आए।

❑ 'आधार' (Aadhaar) के साथ जुड़ाव

- इस विजन की एक अनूठी बात यह है कि Bharat1.AI अपने AI सिस्टम को डिजिटल पहचान प्रणालियों (जैसे आधार) के साथ जोड़ने की योजना बना रहा है, ताकि AI सिस्टम इंसानी पहचान और जवाबदेही के प्रति जागरूक रह सकें।

❑ इस प्रोजेक्ट की भविष्य की रूपरेखा:

- Phase 1 - 2026 के अंत तक - सरजापुर में सुपरपार्क का उद्घाटन और 10,000+ शोधकर्ताओं का आगमन।
- Phase 2 - अगले 36 महीने - सुपरपार्क को एक बड़े 'AI सिटी टेस्टबेड' में बदलना।

35 पश्चिम बंगाल की "मातिर सृष्टि" (Matir Srishti) पहल

❑ चर्चा में क्यों?

पश्चिम बंगाल की मातिर सृष्टि (Matir Srishti) पहल को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा अंतरराष्ट्रीय मान्यता और प्रमाणपत्र मिला है। 2020 में शुरू की गई यह पहल 6 पश्चिमी जिलों में बंजर भूमि को बागवानी, मछली पालन और पशुपालन के माध्यम से उपजाऊ बनाकर 2.5 लाख से अधिक लोगों के लिए आजीविका और आय बढ़ा रही है।

❑ 'मातिर सृष्टि' पहल का उद्देश्य:-

- यह योजना मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा, पुरुलिया, बीरभूम, झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर और पश्चिम बर्धमान जैसे जिलों में शुरू की गई थी। इन क्षेत्रों की विशेषता यह है कि यहाँ की जमीन तुलनात्मक रूप से कम उपजाऊ और शुष्क (Laterite soil) है।

→ बंजर भूमि का रूपांतरण: इस पहल का मुख्य लक्ष्य बंजर पड़ी जमीन को उपजाऊ बनाकर उसे बागवानी, मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए उपयोग में लाना है।

→ आय के स्रोत: इसके माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों और विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को रोजगार और आय के नए साधन प्रदान किए गए हैं।

→ सतत विकास: प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हुए सूक्ष्म सिंचाई (Micro-irrigation) और वर्षा जल संचयन का उपयोग करके खेती को बढ़ावा देना।

❑ **FAO की मान्यता का महत्व:-**

- संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने इसे एक "सफल मॉडल" के रूप में स्वीकार किया है क्योंकि:
  - → खाद्य सुरक्षा: यह मॉडल खराब प्राकृतिक परिस्थितियों में भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का तरीका बताता है।
  - → जलवायु अनुकूलन (Climate Adaptation): बदलती जलवायु के बीच बंजर भूमि का प्रबंधन कैसे किया जाए, इसमें यह योजना एक मिसाल है।
  - → सामुदायिक भागीदारी: इसमें स्थानीय समुदायों की सक्रिय भूमिका को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है।

36 नमो भारत (RRTS) कॉरिडोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ RRTS कॉरिडोर के महत्वपूर्ण खंडों का उद्घाटन किया है। यह भारत की पहली सेमी-हाई-स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है।

मुख्य बिंदु

- कुल कॉरिडोर: दिल्ली से मेरठ के बीच इस पूरे कॉरिडोर की लंबाई लगभग 82 किलोमीटर है।
- गति: इन ट्रेनों की डिजाइन गति 180 किमी/घंटा है, जबकि परिचालन गति 160 किमी/घंटा तक रहती है।
- उद्देश्य: इसका मुख्य लक्ष्य दिल्ली और एनसीआर (NCR) के बीच यात्रा के समय को कम करना और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है।
- तकनीक: इसमें यूरोपीय ट्रेन नियंत्रण प्रणाली (ETCS) लेवल-2 सिग्नलिंग का उपयोग किया गया है, जो इसे बेहद सुरक्षित और आधुनिक बनाता है।

37 राष्ट्रपति भवन में सी. राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फरवरी 2026 में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय प्रांगण में सी. राजगोपालाचारी (राजाजी) की प्रतिमा का अनावरण किया, जो ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा के स्थान पर स्थापित की गई है।

मुख्य बिंदु

- नई प्रतिमा को राजा जी उत्सव के दौरान 'अशोक मंडप' के पास ग्रैंड ओपन सीढ़ी पर स्थापित किया गया है।
- यह पहल भारत के औपनिवेशिक अतीत (लुटियंस की दिल्ली) से विमुख होने और 'गुलामी की मानसिकता' को छोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- सी. राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर-जनरल थे, जिन्हें इस प्रतिमा के माध्यम से राष्ट्र-निर्माण में उनके योगदान के लिए सम्मान दिया गया है।
- राजाजी की प्रतिमा को महात्मा गांधी की प्रतिमा के ठीक सामने स्थापित किया गया है, जो उनके बीच के विश्वास और मित्रता को रेखांकित करता है।

❑ **चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में -**

- चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (1878–1972), जिन्हें 'राजाजी' के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख स्तंभ, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे। उन्हें उनकी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण 'आधुनिक भारत का चाणक्य' भी कहा जाता है।

➲ **राजनैतिक करियर और उपलब्धियाँ**

- अंतिम गवर्नर जनरल: वह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल (1948-1950) और इस पद को संभालने वाले एकमात्र भारतीय थे।
- मुख्यमंत्री: उन्होंने मद्रास प्रेसीडेंसी के मुख्यमंत्री (1937-39) और बाद में मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री (1952-54) के रूप में कार्य किया।
- स्वतंत्र पार्टी की स्थापना: 1959 में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी नीतियों के विरोध में 'स्वतंत्र पार्टी' की स्थापना की, जो मुक्त बाजार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वकालत करती थी।

➲ **स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका**

- वह महात्मा गांधी के बेहद करीबी सहयोगी थे, गांधीजी उन्हें अपनी "अंतरात्मा का रक्षक" मानते थे।
- वेदारण्यम नमक सत्याग्रह: दांडी मार्च के दौरान, उन्होंने तमिलनाडु के वेदारण्यम में नमक कानून तोड़ने के लिए मार्च का नेतृत्व किया था।

➲ **साहित्य और दर्शन**

- भारत रत्न: 1954 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया (वह इसके पहले तीन प्राप्तकर्ताओं में से एक थे)।
- साहित्य अकादमी पुरस्कार: उन्होंने रामायण और महाभारत का तमिल और अंग्रेजी में अनुवाद किया। उनकी पुस्तक 'चक्रवर्ती थिरुमगन' (रामायण का पुनर्कथन) के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।

➲ **'सी.आर. फार्मूला' (1944)**

- भारत के विभाजन की बहस के दौरान, उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध को सुलझाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसे 'राजाजी फार्मूला' कहा जाता है।
- इसमें उन्होंने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जनमत संग्रह (Plebiscite) के आधार पर विभाजन की संभावना को स्वीकार करने की बात कही थी, ताकि स्वतंत्रता की राह आसान हो सके।

❑ एडविन लुटियंस के बारे में -

- एडविन लुटियंस (Edwin Lutyens) 20वीं सदी के एक ब्रिटिश वास्तुकार (Architect) थे, जिन्हें मुख्य रूप से नई दिल्ली के निर्माण और उसकी डिजाइनिंग के लिए जाना जाता है।

➲ **लुटियंस ने भारत में कई प्रतिष्ठित इमारतों का डिजाइन तैयार किया:**

- राष्ट्रपति भवन (Viceroy's House): यह लुटियंस की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसमें उन्होंने यूरोपीय क्लासिकवाद और भारतीय स्थापत्य कला (जैसे सांची स्तूप जैसा गुंबद और जाली का काम) का बेहतरीन संगम किया।
- इंडिया गेट (All India War Memorial): प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों की याद में बनाया गया यह स्मारक भी उन्हीं की देन है।
- हैदराबाद हाउस: दिल्ली में स्थित यह भव्य इमारत भी उन्हीं के द्वारा डिजाइन की गई थी।
- नोट: लुटियंस की शैली को 'एडवर्डियन क्लासिकवाद' (Edwardian Classicism) कहा जाता है।

38 पलामू टाइगर रिज़र्व ने 'वनजीवी दीदी' पहल शुरू की

झारखंड स्थित पलामू टाइगर रिज़र्व ने आसपास के 17 चयनित किए गए गाँवों में 'वनजीवी दीदी' नामक एक नई समुदाय-आधारित पहल शुरू की है, जिसके तहत स्थानीय महिलाओं को पर्यावरण शिक्षिका और संरक्षण सहायक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।

❑ मुख्य विशेषताएँ:

- नाम का अर्थ: 'वनजीवी' का तात्पर्य वनवासी या वन जीवन से है, जबकि 'दीदी' महिलाओं को समुदाय की नेता के रूप में दर्शाता है।
- लक्षित महिलाएँ: प्रत्येक गाँव (जैसे हेनार, सुरकुमी, कोटम) से 18 शिक्षित महिलाएँ चुनी गईं (कुल लगभग 306)। इनमें से अधिकांश कॉलेज स्नातक हैं या उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं।
- मुख्य उद्देश्य: ये दीदियाँ वन विभाग और स्थानीय लोगों के बीच पुल का काम करेंगी, ताकि शिकार व अवैध लकड़ी कटाई रोकी जा सके।

❑ प्रशिक्षण और भूमिकाएँ :-

- चयनित महिलाओं को निम्नलिखित के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है:
  - → वन्यजीव संरक्षण की जागरूकता फैलाना।
  - → मानव-वन्यजीव संघर्ष के समाधान सिखाना।
  - → वन विभाग व निवासियों के बीच मध्यस्थता।
  - → सतत आजीविका व जिम्मेदार वन उपयोग को बढ़ावा देना।
- प्रत्येक को ₹3,000 मासिक मानदेय मिलेगा। यह 17 फरवरी 2026 से शुरू दो माह का पायलट प्रोजेक्ट है, जिसका विस्तार प्रदर्शन पर आधारित होगा।

❑ पलामू टाइगर रिज़र्व के बारे में

- पलामू टाइगर रिजर्व, झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है और भारत के वन्यजीव संरक्षण इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
- यह झारखंड के लातेहार और गढ़वा जिलों में छोटानागपुर पठार पर स्थित है। यह लगभग 1,129.93 वर्ग किमी (बेतला राष्ट्रीय उद्यान शामिल) है।
- यहां की मुख्य वनस्पति और जीव मुख्य रूप से साल और बांस के वन, बाघ, हाथी, तेंदुआ, गौर, सांभर, और चित्तीदार हिरण आदि हैं।
- उत्तरी कोयल, औरंगा, और बुरहा आदि नदियां, इस रिजर्व से होकर बहती हैं।
- यह 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत स्थापित नौ मूल टाइगर रिजर्वों में से एक है।
- 1932 में दुनिया की पहली बाघ गणना (Tiger Census) यहीं के तत्कालीन वन संरक्षक जे.डब्ल्यू. निकोलसन द्वारा पग-मार्क (Pug-mark) पद्धति के आधार पर की गई थी।

39 पर्यटन नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2026 (Tourism Leadership Summit 2026)

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने 24 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में 'पर्यटन नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2026' (Tourism Leadership Summit 2026) का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु

- यह शिखर सम्मेलन U.S.-India Strategic Partnership Forum (USISPF) द्वारा सांकला फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया था।
- इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 'भारत में पर्यटन की स्थिति 2026' (State of Tourism in India 2026) नामक रिपोर्ट जारी की।
- टूरिज्म विजन 2029 के तहत् भारत का लक्ष्य प्रत्येक राज्य में कम से कम एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल विकसित करना है, जिसमें स्मार्ट सुविधाएं और टिकाऊ (sustainable) प्रथाएं शामिल हों।
- उपराष्ट्रपति ने पर्यटन को केवल एक उद्योग नहीं, बल्कि संस्कृतियों के बीच एक सेतु (bridge) और सॉफ्ट डिप्लोमेसी का एक शक्तिशाली साधन बताया।
- सम्मेलन में पर्यटन अनुभव को बेहतर बनाने के लिए AI-आधारित समाधानों, बहुभाषी डिजिटल गाइड और प्रेडिक्टिव क्राउड मैनेजमेंट को एकीकृत करने पर जोर दिया गया।

40 केरल का आधिकारिक नाम बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 फरवरी 2026 को केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर 'केरलम' (Keralam) करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह निर्णय राज्य की भाषाई, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को मान्यता देने के लिए लिया गया है, जो मलयालम भाषा में राज्य का मूल नाम है।

मुख्य बिंदु

- केरल के नाम परिवर्तन की यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत आती है, जो केंद्र सरकार को राज्यों के नाम, सीमाओं या क्षेत्रों में परिवर्तन करने की शक्ति देता है।

❑ प्रक्रिया के मुख्य चरण:-

- राज्य की पहल: केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र से यह आग्रह किया था कि संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में राज्य का नाम 'केरलम' किया जाए।
- कैबिनेट की मंजूरी: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अब इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।
- राष्ट्रपति की भूमिका: अब राष्ट्रपति इस विधेयक को केरल विधानसभा को भेजेंगे ताकि राज्य अपने विचार साझा कर सके। हालांकि, संसद राज्य के विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है।
- संसद में विधेयक: राज्य के विचार मिलने के बाद, केंद्र सरकार राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 पेश करेगी।

❑ 'केरलम' का महत्व -

- मलयालम भाषा में राज्य को हमेशा से 'केरलम' कहा जाता रहा है। 'केरल' शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में किया जाता है। राज्य सरकार का तर्क है कि नाम को उसकी भाषाई और सांस्कृतिक जड़ों के अनुरूप होना चाहिए।

❑ केरल के बारे में:-

- इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 हुई थी।
- इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में पश्चिमी घाट की पहाड़ियां (अनामुड़ी सबसे ऊंची चोटी) हैं।
- राज्य की प्रमुख परंपराओं में कथकली नृत्य, कलारीपयट्टू (मार्शल आर्ट) और ओणम/विशु त्योहार शामिल हैं।
- प्रमुख स्थलों में मुन्नार (हिल स्टेशन), अलेप्पी (बैकवाटर), कोवलम तट, और वायनाड शामिल हैं।
- मसाला उत्पादन (काली मिर्च), रबर, नारियल और पर्यटन राज्य के मुख्य आधार हैं।
- यह भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य है और यहाँ शिशु मृत्यु दर सबसे कम है।
- पिनारयी विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। तथा राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर केरल के वर्तमान राज्यपाल हैं।

41 'ई-बाइक दीदी योजना' (E-Bike Didi Scheme)

दिल्ली सरकार ने महिला सशक्तिकरण और प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से 'ई-बाइक दीदी योजना' शुरू की है। इस योजना के तहत, प्रशिक्षित महिलाएं इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर चलाकर मुख्य रूप से महिला यात्रियों को टूरिस्ट स्थलों, मेट्रो स्टेशनों और बसों के लिए सुरक्षित 'लास्ट-माइल कनेक्टिविटी' प्रदान करेंगी। यह एक महिला-संचालित टैक्सी सेवा होगी।

मुख्य बिंदु

- उद्देश्य: महिलाओं के लिए रोजगार (Income) पैदा करना और महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- पात्रता: 18-40 वर्ष की महिलाएं, जो दिल्ली की निवासी हैं और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस (लर्नर भी मान्य) है।
- सहायता: सरकार ई-बाइक खरीदने के लिए सब्सिडी या प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है।
- प्रशिक्षण: चयनित महिलाओं को इलेक्ट्रिक बाइक चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- सुरक्षा: सभी ई-बाइक्स में जीपीएस (GPS) ट्रैकिंग सुविधा होगी।
- साझेदारी: यह सेवा ओला/रैपिडो जैसी कंपनियों की तरह ही ऐप-आधारित होगी।

42 विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026

❑ चर्चा में क्यों?

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हाल ही में डोना पाउला में विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 का शुभारंभ किया। महासागर स्वास्थ्य और सतत भविष्य विषय पर आधारित इस विज्ञान कांग्रेस में महासागर स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता, समुद्री इको-सिस्टम और सतत नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

मुख्य बिंदु

- आयोजन - 23–26 फरवरी, 2026 के मध्य चौथा विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस- 2026 गोवा में आयोजित किया गया।
- मुख्य विषय – स्वस्थ महासागर: सुरक्षित और सतत् भविश्य की आधारशिला (Ocean Health & Sustainable Future) है।
- इसे विज्ञान भारती, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (NIO), नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च (NCPOR) तथा गोवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया है।
- यह एक द्विवार्षिक (Biannual) अंतरराष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है जिसमें भारत और उसके आसपास के समुद्री देशों की भागीदारी हुई।
- इसका उद्देश्य महासागर क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों को एक साझा मंच प्रदान करना है।

❑ सम्मेलन के प्रमुख आकर्षण (मुख्य स्तंभ):-

- महासागर स्वास्थ्य और प्लास्टिक प्रदूषण: समुद्री प्रदूषण (खासकर माइक्रो-प्लास्टिक) को रोकने के लिए नई तकनीकों और नीतियों पर चर्चा।
- जलवायु लचीलापन (Climate Resilience): बढ़ते समुद्र स्तर और तटवर्ती इलाकों में आने वाले चक्रवातों से निपटने के लिए वैज्ञानिक समाधान।
- इको-सिस्टम संरक्षण: मैंग्रोव और कोरल रीफ (मूंगा चट्टानों) को बचाने के प्रयासों पर जोर, जो समुद्री जैव विविधता के रक्षक हैं।
- सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी: समुद्र से मिलने वाले संसाधनों का ऐसा दोहन जो पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाए।

43 बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट-जीरो पंचायत

महाराष्ट्र के भंडारा जिले की बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट-जीरो (कार्बन-न्यूट्रल) पंचायत बनी है, जिसने वृक्षारोपण, सौर ऊर्जा, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को शून्य कर दिया है। यह मान्यता 2026 के मुंबई जलवायु सप्ताह में दी गई, जो 2070 के राष्ट्रीय लक्ष्य से पहले स्थानीय जलवायु कार्रवाई का एक प्रमुख उदाहरण है।

मुख्य बिंदु

- भारत की पहली नेट-जीरो पंचायत: महाराष्ट्र के भंडारा जिले का बेलाग्राम (सरपंच: शारदा गायधाने) भारत की पहली ऐसी पंचायत है, जो 2070 से पहले ही कार्बन-न्यूट्रल हो गई है।
- प्रमुख पहल: गांव में 90,000 से अधिक पेड़ लगाए गए, सार्वजनिक भवनों पर सौर पैनल स्थापित किए गए, सिंगल-यूज़ प्लास्टिक को बंद किया गया, और घर-घर जाकर वेस्ट सेग्रेगेशन (कचरा पृथक्करण) किया गया।
- अन्य पुरस्कृत पंचायतें (2024): राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में, बेला (महाराष्ट्र) पहले स्थान पर, केंड्रिकेला (ओडिशा) दूसरे और मिलक अमावती (उत्तर प्रदेश) तीसरे स्थान पर रहीं।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर हरित ऊर्जा अपनाना, पारंपरिक ईंधन की जगह बायोगैस/सौर ऊर्जा लाना और पर्यावरण की रक्षा करना है।

❑ नेट-जीरो क्या है?

- नेट जीरो (Net Zero) का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन और सोखने के बीच संतुलन बनाना। इसका मतलब यह नहीं है कि उत्सर्जन शून्य हो जाएगा, बल्कि यह है कि जितना कार्बन उत्सर्जित होगा, उतना ही तकनीक या प्रकृति (पेड़-पौधों) द्वारा अवशोषित किया जाएगा।

44 राष्ट्रीय घटनाक्रम (To The Point)

- आंध्रप्रदेश के चित्तूर जिले ने सतत परिवहन और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए सबसे बड़े 'ई- साइकिल वितरण' के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड हासिल किया।
  - → 24 घंटे में 5555 ई-साइकिल वितरण का रिकार्ड हासिल किया गया।
- जम्मू कश्मीर के कटरा में श्री माता वैष्णव देवी साइन बोर्ड द्वारा देश का पहला देवी संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई।
- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को पेन्नैयार नदी के जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद का निपटारा करने के लिए एक न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा कर दिया और लुधियाना के हलवारा में नए सिविल टर्मिनल का उद्घाटन किया।
- हाल ही में केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने अलग 'वरिष्ठ नागरिक बजट' पेश किया, केरल ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना।
- मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र में 'दलहन आत्मनिर्भता मिशन' के रोडमैप को अंतिम रूप दिया गया।
- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बारथिन में बिलासपुर जिला प्रशासन की अभिनव डिजिटल शिक्षा पहल 'पढ़ाई विद ए आई' का औपचारिक रूप से शुभारम्भ किया।
- 'भारत टैक्सी' के सहकारी कैब मॉडल से जुड़ने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश बन गया।
- कर्नाटक सरकार ने राज्य भर में भूमि और संपत्ति लेनदेन की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए स्वचालित संपत्ति म्यूटेशन प्रणाली (Auto-Mutation System) की शुरुआत की है।
- भारत की अध्यक्षता में पहली BRICS Sherpas और Sous Sherpas की बैठक 9-10 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हुई।
- एलन मस्क की स्टारलिंक ने गुजरात सरकार के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) पर हस्ताक्षर किए हैं।
  - → उद्देश्य :- राज्य के दूर दराज, सीमावर्ती और आदिवासी क्षेत्रों में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करना है।
- सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया, इससे सोशल मिडिया प्लेटफार्म का AI से तैयार फेक कंटेंट को तीन घंटे के अंदर हटाने का दिशा निर्देश मिला।
- केंद्र सरकार ने लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत निरस्त किए गए पूर्व श्रम कानूनों की कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना है।
- मध्य प्रदेश का बालाघाट ज़िला सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना (WLGSP) के अंतर्गत पायलट ज़िले के रूप में चयनित किया गया है।
- भारत आधिकारिक तौर पर वैश्विक स्तर पर सक्रिय स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है।
- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹1 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता के साथ 'शहरी चुनौती कोष' (Urban Challenge Fund - UCF) शुरू करने को मंजूरी दी है।
- केरल सरकार ने बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसवुमन के लिए ₹1,000 मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 'स्त्री सुरक्षा योजना' शुरू की।
- हाल ही में नई दिल्ली में इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 आयोजित हुआ। पांच दिवसीय यह शिखर सम्मेलन वैश्विक दक्षिण में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन रहा, जो 'पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस' के तीन मुख्य स्तंभों पर केंद्रित रहा।
- उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की पहल पर देश का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्राहालय मथुरा स्थित पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित किया जाएगा।
- केरल, व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने और उसे मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना।
- हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू ने नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'ओल चिकी' लिपि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया।
  - → पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा 1925 में सृजित ओलचिकी लिपि की शताब्दी संथाल समुदाय के सांस्कृतिक और बौद्धिक इतिहास के लिए काफी महत्वपूर्ण है।

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के कोलार जिले के वेमागल में स्थित एयरबस H 125 हेलीकॉप्टरों के लिए भारत की पहली निजी क्षेत्र की असेंबली लाइन का उद्घाटन किया।
- केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भारत मंडपम में आयोजित इंडिया ए आई समिट में भारत के ए आई स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य को नया रूप देने के लिए दो महत्वपूर्ण पहलों 'SAHI' और 'BODH' का शुभारम्भ किया।
- हाल ही में असम मंत्रिमंडल ने प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में चाय बागान जनजातियों और आदिवासी समुदायों के लिए 3% आरक्षण कोटा को मंजूरी दी है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किया।
  - → उद्घाटन समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल रहे।
- इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नैतिक और समावेशी ए आई के लिए भारत के व्यापक "मानव विजन" (MANAV) का अनावरण किया।
  - → M – Moral and Ethical Systems
  - → A – Accountable Governance
  - → N – National Sovernity
  - → A – Accessible and Inclusive
  - → V – Valid and Legitimate
- इंडिया एआई और इंटेल इंडिया ने एआई जिम्मेदारी अभियान के तहत 24 घंटों में सबसे अधिक प्रतिज्ञाएं (25 लाख से अधिक) प्राप्त करने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है।
- हाल ही में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में "मेरी परंपरा - मेरी विरासत" विषय पर एक दिवसीय सेशन का आयोजन किया गया।
- तटीय समुदायों पर गंभीर प्रभावों के कारण केरल ने 'ज्वारीय बाढ़' को "राज्य-विशिष्ट आपदा" घोषित किया। ऐसा करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया।
- हाल ही में पंजाब सरकार ने गरीब परिवारों के लिये 'मेरी रसोई' योजना की घोषणा की। इसके तहत अप्रैल 2026 से राज्य के 40 लाख परिवारों को तिमाही आधार पर मुफ्त खाद्य किट प्रदान की जाएंगी।
- भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में राष्ट्रीय घोषणा 2026 को सर्वसम्मति से अपनाकर संपन्न हुआ।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के बुलढ़ाणा जिले के शेगांव में 'राष्ट्रीय आरोग्य मेले 2026' का उद्घाटन किया। यह मेला आयुष मंत्रालय की पहल है।
- पश्चिम बंगाल ने बेरोजगार युवाओं के लिए हाल ही में 'बांग्लार युवा साथी' योजना शुरू की। 21 से 40 वर्ष तक की आयु के बेरोजगार युवाओं को हर माह 1500 रुपये मदद देगी।
- हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वी.के. सक्सेना ने दिल्ली खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (DKVIB) के माध्यम से 'मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना' (MMKVY) के तहत कारीगरों के प्रशिक्षण और सशक्तिकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

NOT FOR SALE

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

01 'कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026' (Cost of Living Index 2026)

'कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026' के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष भी स्विट्ज़रलैंड के शहरों का दबदबा कायम है, जबकि भारत के कई शहर दुनिया के सबसे किफायती शहरों में शुमार हैं। रिपोर्ट के अनुसार मुम्बई, भारत का सबसे महंगा शहर है।

मुख्य बिंदु

- 'कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026' एक सांख्यिकीय उपकरण है जो यह मापता है कि किसी विशिष्ट स्थान पर एक निश्चित जीवन स्तर (Standard of Living) बनाए रखने के लिए कितने धन की आवश्यकता है।
- यह सर्बिया के एक कंपनी नंबियो द्वारा जारी किया जाता है।
- मुंबई, भारत का सबसे महंगा शहर है, जो वैश्विक में 445वें स्थान पर है। इस सूचकांक में दिल्ली, देशका दुसरा सबसे महंगा शहर है।

❑ दुनिया के 5 सबसे महंगे शहर -

1. ज्यूरिख (स्विट्ज़रलैंड)
2. जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड)
3. बासेल (स्विट्ज़रलैंड)
4. बरमूडा (बरमूडा)
5. सिंगापुर (सिंगापुर)

02 सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी भारत की पहली राजकीय यात्रा पर

सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी ने हाल ही में 5 से 10 फरवरी 2026 तक भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पूरी की है। अक्टूबर 2025 में कार्यभार संभालने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा था, जो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुआ।

मुख्य बिंदु

- राष्ट्रपति हर्मिनी ने अपनी 6 दिवसीय यात्रा के दौरान चेन्नई, मुंबई और नई दिल्ली का दौरा किया। उन्होंने चेन्नई और मुंबई में व्यापारिक समुदायों और स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों से मुलाकात की।
- नई दिल्ली में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राष्ट्रपति मुर्मू ने उनके सम्मान में 'राजकीय भोज' (State Banquet) का भी आयोजन किया।
- दोनों देशों ने 'Shared Vision for Sustainability, Economic Growth and Security (SESEL)' को अपनाया। यह विजन हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास (SAGAR और MAHASAGAR विजन) पर केंद्रित है।

❑ प्रमुख समझौते और घोषणाएं:-

- आर्थिक सहायता: भारत ने सेशेल्स के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। इसमें 125 मिलियन डॉलर की 'लाइन ऑफ क्रेडिट' और 50 मिलियन डॉलर की अनुदान सहायता शामिल है।
- रक्षा सहयोग: दोनों देशों ने हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। 'लैमिटी-2026' (LAMITYE-2026) संयुक्त सैन्य अभ्यास को लेकर भी चर्चा हुई।
- खाद्य सहायता: राष्ट्रपति हर्मिनी ने 1,000 मीट्रिक टन अनाज दान करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया।
- अन्य क्षेत्र: फिनटेक (Fintech), स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी।

➢ "सेशेल्स" के बारे में :-

- सेशेल्स, हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों का एक सुरम्य द्वीपसमूह राष्ट्र है, जो अफ्रीका के पूर्वी तट और मेडागास्कर के उत्तर-पूर्व में स्थित है।
- यह अफ्रीका का सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला देश है।
- इसकी राजधानी विक्टोरिया है, जो माहे (Mahé) द्वीप पर स्थित है। यह दुनिया की सबसे छोटी राजधानियों में से एक है।
- यहां की मुद्रा सेशेलियाई रुपया है।
- माहे (Mahé), प्रालिन (Praslin) और ला डिग (La Digue) यहाँ के सबसे लोकप्रिय द्वीप हैं।
- Vallee de Mai यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जहाँ दुर्लभ कोको डी मेर (Coco de Mer) के पेड़ पाए जाते हैं। इसके फल का आकार दुनिया में सबसे बड़ा होता है।
- यहाँ विशालकाय कछुए (Giant Tortoises) पाए जाते हैं, जो 100 साल से अधिक जीते हैं।
- भारतीय नागरिकों के लिए यह वीजा-मुक्त (Visa-free) प्रवेश की सुविधा देता है।

03 ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स 2025

❑ चर्चा में क्यों?

ग्लोबल फायरपावर (GFP) 2025 रैंकिंग में भारत 145 देशों में 0.1184 के पावर इंडेक्स स्कोर के साथ चौथे स्थान पर बना हुआ है जो भारत की निरंतर मजबूत वैश्विक सैन्य स्थिति को दर्शाता है। इस सूचकांक में अमेरिका पहले, रूस दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर है।

❑ शीर्ष 10 सैन्य शक्तियाँ (2025) :-

ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स में 'पावर इंडेक्स' (PwrIndx) स्कोर जितना कम होता है, देश उतना ही शक्तिशाली माना जाता है।

रैंक	देश	पावर इंडेक्स स्कोर
1.	संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)	0.0744
2.	रूस (Russia)	0.0788
3.	चीन (China)	0.0788
4.	भारत (India)	0.1184
5.	दक्षिण कोरिया	0.1656
6.	यूनाइटेड किंगडम (UK)	0.1785
7.	फ्रांस	0.1878
8.	जापान	0.1839
9.	तुर्की (Türkiye)	0.1902
10.	इटली	0.2164

भारत के लिए मुख्य बिंदु

- स्थिर रैंकिंग: भारत पिछले कई वर्षों की तरह इस बार भी चौथे स्थान पर है।
- ताकत के क्षेत्र: भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र सेना (manpower) है। इसके अलावा, भारत का रक्षा बजट (लगभग $75 बिलियन) और आधुनिक होती मिसाइल तकनीक (ब्रह्मोस, अग्नि) इसकी रैंकिंग को मजबूती प्रदान करती है।
- कमजोरियाँ: रिपोर्ट के अनुसार, भारत 'हेलीकॉप्टर कैरियर' और 'समुद्री माइन वारफेयर' जैसी कुछ श्रेणियों में वैश्विक स्तर पर अभी भी पीछे है।

❑ पड़ोसी देशों की स्थिति -

- चीन: तीसरे स्थान पर रहते हुए भारत से आगे है और अपनी नौसेना का तेजी से विस्तार कर रहा है।
- पाकिस्तान: 2025 की रैंकिंग में पाकिस्तान की स्थिति में गिरावट देखी गई है और वह 12वें स्थान पर खिसक गया है (जो 2024 में 9वें स्थान पर था)।
- भूटान: इस सूची में सबसे निचले पायदान (145वें स्थान) पर है।

❑ यह इंडेक्स कैसे तैयार होता है?

यह रैंकिंग 60 से अधिक मानकों के आधार पर तय की जाती है, जिनमें शामिल हैं:

- सैन्य संसाधन: सैनिकों की संख्या, टैंक, विमान और जहाजों की तादाद।
- वित्तीय स्थिति: रक्षा बजट और विदेशी मुद्रा भंडार।
- लॉजिस्टिक्स: रेलवे, पोर्ट्स और परिवहन की सुविधा।
- भूगोल: प्राकृतिक संसाधन और देश की सीमाएँ।

नोट: इस रैंकिंग में देशों की 'परमाणु क्षमता' को सीधे तौर पर स्कोर में नहीं जोड़ा जाता, बल्कि पारंपरिक सैन्य क्षमताओं पर ध्यान दिया जाता है।

EDU TERIA Telegram Channel
link : https://eduteria.live

04 भारत और अमेरिका के अंतरिम व्यापार समझौता फ्रेमवर्क की घोषणा की

भारत और अमेरिका ने फरवरी 2026 की शुरुआत में एक ऐतिहासिक अंतरिम व्यापार समझौता (Interim Trade Agreement Framework) की घोषणा की है। यह समझौता दोनों देशों के बीच पिछले कुछ समय से चल रहे व्यापारिक तनाव को कम करने और आर्थिक संबंधों को एक नई दिशा देने के उद्देश्य से किया गया है।

❑ टैरिफ (शुल्क) में भारी कटौती

- अमेरिका की ओर से: अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाले कुल प्रभावी शुल्क को लगभग 50% से घटाकर 18% कर दिया है।
- इसमें वह 25% का दंडात्मक टैरिफ (Penalty Tariff) हटाना शामिल है जो अमेरिका ने भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने के कारण लगाया था।
- भारतीय वस्त्र (Textiles), चमड़ा, जूते, और कुछ मशीनरी जैसे उत्पादों पर अब कम शुल्क लगेगा।
- भारत की ओर से: भारत ने सभी अमेरिकी औद्योगिक सामानों और कई कृषि उत्पादों (जैसे सूखे मेवे, ताजे फल, सोयाबीन तेल, और वाइन) पर टैरिफ कम करने या हटाने पर सहमति दी है।

❑ रणनीतिक और ऊर्जा सहयोग

- रूसी तेल पर प्रतिबद्धता: भारत ने रूसी कच्चे तेल की खरीद को रोकने या काफी कम करने की प्रतिबद्धता जताई है और अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अमेरिका की ओर रुख करने का निर्णय लिया है।
- बड़ी खरीदारी का लक्ष्य: भारत अगले 5 वर्षों में अमेरिका से लगभग $500 बिलियन मूल्य के ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, और औद्योगिक उत्पादों को खरीदने की योजना बना रहा है।

❑ अन्य प्रमुख क्षेत्र

- प्रौद्योगिकी और डेटा: दोनों देश ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPUs) और डेटा सेंटर उपकरणों जैसे उच्च-तकनीकी उत्पादों के व्यापार को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं।
- डिजिटल व्यापार: भविष्य में एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के लिए डिजिटल व्यापार नियमों और गैर-टैरिफ बाधाओं को हल करने पर भी चर्चा हुई है।
- क्षेत्रीय प्रभाव: यह समझौता हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव के बीच भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करता है।

❑ भविष्य की राह-

यह एक 'अंतरिम' यानी शुरुआती समझौता है। दोनों देशों का लक्ष्य आने वाले समय में एक पूर्ण द्विपक्षीय व्यापार समझौता (Bilateral Trade Agreement - BTA) करना है, जिससे व्यापार के और भी रास्ते खुलेंगे।

05 प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय मलेशिया यात्रा

❑ चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 और 8 फरवरी 2026 को मलेशिया की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सफल दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा संपन्न की। यह 2024 में दोनों देशों के बीच 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' (Comprehensive Strategic Partnership) स्थापित होने के बाद उनकी पहली उच्च स्तरीय यात्रा थी।

❑ द्विपक्षीय वार्ता और रणनीतिक सहयोग

प्रधानमंत्री मोदी और मलेशियाई प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम के बीच कुआलालंपुर और पुत्रजया में विस्तृत चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, रक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के साथ-साथ भविष्य की तकनीकों पर जोर दिया।

❑ प्रमुख समझौते (MoUs)

यात्रा के दौरान कुल 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें प्रमुख हैं:

- सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम: दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) में सहयोग के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया।
- डिजिटल भुगतान: भारत के UPI और मलेशिया के PayNet को जोड़ने पर सहमति बनी, जिससे दोनों देशों के बीच लेनदेन आसान होगा।
- डिजिटल काउंसिल (MIDC): 'मलेशिया-भारत डिजिटल काउंसिल' का गठन किया गया, जो AI, फिनटेक और साइबर सुरक्षा पर काम करेगी।
- अन्य क्षेत्र: आपदा प्रबंधन, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, श्रम सहयोग और आयुर्वेद (यूनिवर्सिटी ऑफ साइबरजया और भारत के आयुर्वेद संस्थान के बीच) में भी समझौते हुए।

❑ भारतीय समुदाय और 'जीवंत सेतु'

- "सेलामत दातंग मोदी जी": प्रधानमंत्री ने कुआलालंपुर में लगभग 15,000 भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय मूल के लोगों को दोनों देशों के बीच एक "जीवंत सेतु" बताया।
- सांस्कृतिक पहल: मलेशिया में एक 'तिरुवल्लुवर केंद्र' और मलेशियाई नागरिकों के लिए 'तिरुवल्लुवर छात्रवृत्ति' शुरू करने की घोषणा की गई।
- OCI कार्ड: भारतीय मूल के मलेशियाई नागरिकों की छठी पीढ़ी तक ओसीआई (OCI) कार्ड की पात्रता बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।

❑ आर्थिक और वैश्विक संदर्भ

- द्विपक्षीय व्यापार: भारत और मलेशिया के बीच व्यापार लगभग $20 अरब तक पहुँच गया है। दोनों नेताओं ने स्थानीय मुद्राओं (Local Currency) में व्यापार को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की।
- आतंकवाद पर कड़ा रुख: पीएम मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद के मुद्दे पर कोई "दोहरा मापदंड" नहीं चलेगा।

❑ महत्व

- चूँकि 2026 में मलेशिया आसियान (ASEAN) की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए मोदी जी की यह यात्रा भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और इंडो-पैसिफिक विजन को मजबूत करने के लिहाज से रणनीतिक रूप से बहुत सफल मानी जा रही है।

❑ मलेशिया के बारे में:-

- मलेशिया दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित एक विविध और उष्णकटिबंधीय देश है, जो अपनी आधुनिक संस्कृति, गगनचुंबी इमारतों और समृद्ध प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है।
- इसकी राजधानी कुआलालंपुर (आर्थिक) और पुत्रजया (प्रशासनिक) है। यहां की मुद्रा मलेशियन रिंगित (MYR) है।
- मलेशिया दो मुख्य भागों में विभाजित है, जो दक्षिण चीन सागर द्वारा अलग होते हैं।
  - → प्रायद्वीपीय मलेशिया (Peninsular Malaysia): यह थाईलैंड के साथ सीमा साझा करता है। राजधानी कुआलालंपुर इसी भाग में स्थित है।
  - → पूर्वी मलेशिया (East Malaysia): यह बोर्नियो द्वीप पर स्थित है और ब्रुनेई व इंडोनेशिया के साथ सीमा साझा करता है।
- मलेशिया में घूमने के लिए आधुनिक और प्राकृतिक दोनों तरह की जगहें मौजूद हैं:
  - → कुआलालंपुर (Kuala Lumpur): यहाँ के पेट्रोनास ट्विन टावर्स कभी दुनिया की सबसे ऊँची इमारत थे।
  - → बातु गुफाएं (Batu Caves): भगवान मुरुगन की विशाल प्रतिमा और चूना पत्थर की गुफाओं वाला एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल।
  - → लैंगकावी (Langkawi): अपने शानदार समुद्र तटों और 'ड्यूटी-फ्री' शॉपिंग के लिए प्रसिद्ध द्वीपों का समूह।
  - → कैमरून हाइलैंड्स: चाय के बागानों और ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है।
- 16 सितंबर, 1963 को स्थापित यह राष्ट्र, 1957 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाने वाले क्षेत्रों का विलय है।

06 भारत-GCC मुक्त व्यापार समझौता (FTA) हेतु 'संदर्भ शर्तों' (Terms of Reference - ToR) पर हस्ताक्षर

भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) ने फरवरी 2026 में एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए 'संदर्भ शर्तों' (Terms of Reference - ToR) पर हस्ताक्षर किए, जो औपचारिक वार्ताओं को शुरू करने की दिशा में एक प्रमुख कदम है। इस समझौते का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना, निवेश बढ़ाना और ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

मुख्य बिंदु

- भारत की ओर से अतिरिक्त सचिव अजय भादू और GCC की ओर से डॉ. राजा अल मरजूकी ने नई दिल्ली में इस पर हस्ताक्षर किए, जिसमें केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल उपस्थित थे।
- वित्त वर्ष 2024-25 में भारत-GCC व्यापार 178.56 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जो भारत के कुल वैश्विक व्यापार का 15.42% है।
  - → निर्यात-आयात: भारत का निर्यात लगभग $57 अरब रहा, जबकि मुख्य रूप से ऊर्जा (कच्चा तेल, गैस) के कारण आयात $121.7 अरब तक पहुंच गया।
  - → निवेश: सितंबर 2025 तक खाड़ी देशों ने भारत में लगभग 31.14 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) किया है।
- FTA का उद्देश्य इंजीनियरिंग, कपड़ा, रत्न और आभूषण के साथ-साथ पेट्रोकेमिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण और ICT क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ाना है।

- यह समझौता भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा और GCC देशों में काम कर रहे लगभग 1 करोड़ भारतीयों के लिए आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा।
- यह समझौता भारत की "एक्ट ईस्ट" और मध्य पूर्व की रणनीतिक आर्थिक भागीदारी का हिस्सा है।

❑ ToR क्या है?

संदर्भ शर्तें (ToR) वह दस्तावेज़ है जो प्रस्तावित समझौते के दायरे (Scope), संरचना और बातचीत के तौर-तरीकों को निर्धारित करता है। यह औपचारिक वार्ताओं की शुरुआत के लिए एक अनिवार्य कदम है।

- क्षेत्रीय गठबंधन: GCC में 6 देश शामिल हैं: सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। भारत पहले ही UAE (2022) और ओमान (2025) के साथ अलग से व्यापार समझौते कर चुका है।

❑ खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council - GCC)

- क्षेत्रीय गठबंधन: GCC में 6 देश शामिल हैं: सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। भारत पहले ही UAE (2022) और ओमान (2025) के साथ अलग से व्यापार समझौते कर चुका है।
- GCC मध्य पूर्व के छह अरब देशों का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है। इसकी स्थापना 25 मई, 1981 को रियाद, सऊदी अरब में हुई थी।
- इसमें कुल 6 देश शामिल हैं, जो भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं: सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन
- गठन के मुख्य उद्देश्य -
  - → आर्थिक एकीकरण: सदस्य देशों के बीच व्यापार, सीमा शुल्क और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में समानता लाना।
  - → सुरक्षा सहयोग: क्षेत्र की स्थिरता बनाए रखने के लिए सैन्य और सुरक्षा स्तर पर एक-दूसरे की मदद करना।
  - → साझा नीतियां: धर्म (इस्लाम), संस्कृति और सामाजिक संरचना के आधार पर समान नीतियां बनाना।
  - → साझा मुद्रा: लंबे समय से एक साझा मुद्रा (Common Currency) बनाने का लक्ष्य है, हालांकि यह अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हुआ है।
- संगठनात्मक संरचना -

  GCC का मुख्यालय रियाद, सऊदी अरब में स्थित है। यह मुख्य रूप से तीन स्तरों पर काम करता है:
  - → सर्वोच्च परिषद (Supreme Council): इसमें सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं। यह निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी संस्था है।
  - → मंत्रिस्तरीय परिषद (Ministerial Council): इसमें देशों के विदेश मंत्री शामिल होते हैं जो नीतियां तैयार करते हैं।
  - → सचिवालय (Secretariat General): यह प्रशासनिक कार्यों और नीतियों के कार्यान्वयन की देखरेख करता है।
- भारत के लिए महत्व

  भारत के लिए GCC सामरिक और आर्थिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है:
  - → ऊर्जा सुरक्षा: भारत अपनी तेल और प्राकृतिक गैस की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा इन देशों से आयात करता है।
  - → प्रवासी भारतीय: लगभग 80-90 लाख भारतीय इन देशों में रहते हैं और काम करते हैं।
  - → प्रेषण (Remittances): भारत को मिलने वाले कुल विदेशी धन का एक बड़ा हिस्सा GCC देशों से आता है।
  - → व्यापार: GCC भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है।

07 "भारत-कनाडा : साइबर सुरक्षा और कानून प्रवर्तन पर बनी सहमति।"

भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करते हुए फरवरी 2026 में ओटावा में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और कनाडा की NSA नताली ड्रोइन ने राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और साइबर सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त कार्य योजना पर सहमति जताई है। यह समझौता अंतरराष्ट्रीय अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और साइबर खतरों से निपटने के लिए सूचनाओं के आदान-प्रदान को बेहतर बनाएगा।

❑ सहयोग के मुख्य स्तंभ -

- राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद का मुकाबला

  दोनों देशों ने सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक साझा मंच तलाशने की कोशिश की है।
  - → इंटेलिजेंस शेयरिंग: कट्टरपंथ और सीमा पार अपराधों से जुड़े खतरों पर रीयल-टाइम सूचनाओं का आदान-प्रदान।
  - → चरमपंथ पर लगाम: भारत के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है ताकि कनाडा की धरती का उपयोग भारत-विरोधी गतिविधियों के लिए न हो सके।
- कानून प्रवर्तन (Law Enforcement)

  अपराधियों और संगठित गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई अब अधिक समन्वित होगी।
  - → संगठित अपराध: ड्रग तस्करी और मानव तस्करी जैसे नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस और जांच एजेंसियों (जैसे NIA और RCMP) के बीच बेहतर तालमेल।
  - → पारस्परिक कानूनी सहायता: अदालती मामलों और प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं में तेजी लाने की संभावना।
- साइबर सुरक्षा: डिजिटल दीवार को मजबूती

  साइबर स्पेस में बढ़ते खतरों को देखते हुए यह समझौता रणनीतिक रूप से बहुत अहम है।
  - → क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर: पावर ग्रिड, वित्तीय संस्थानों और सरकारी डेटा को साइबर हमलों से बचाने के लिए तकनीकी सहयोग।
  - → साइबर फॉरेंसिक: जटिल डिजिटल अपराधों को सुलझाने के लिए उन्नत उपकरणों और ट्रेनिंग का साझा उपयोग।

08 संसदीय चुनावों में प्रधानमंत्री साने ताकाइची के नेतृत्व वाले गठबंधन की शानदार जीत

जापान में हाल ही में संपन्न हुए संसदीय चुनावों में प्रधानमंत्री साने ताकाइची (Sanae Takaichi) के नेतृत्व वाले गठबंधन की यह जीत वाकई में ऐतिहासिक है। यह न केवल उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता का प्रमाण है, बल्कि जापान की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत भी मानी जा रही है।

मुख्य बिंदु

- 8 फरवरी 2026 को हुए निचले सदन (House of Representatives) के चुनावों में सत्तारूढ़ गठबंधन ने विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया:
  - → लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP): अकेले 316 सीटें जीतीं, जो 1955 में पार्टी की स्थापना के बाद से किसी भी एक पार्टी का सबसे शानदार प्रदर्शन है।
  - → सत्तारूढ़ गठबंधन (LDP + जापान इनोवेशन पार्टी - JIP): कुल 352 सीटें हासिल कर दो-तिहाई 'सुपरमैजॉरिटी' प्राप्त की।
  - → यह जीत ताकाइची के लिए इसलिए भी बड़ी है क्योंकि उन्होंने अक्टूबर 2025 में पद संभालने के मात्र चार महीने बाद यह "स्नैप इलेक्शन" (अचानक चुनाव) बुलाने का जोखिम लिया था।
- साने ताकाइची अक्टूबर 2025 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थीं। उन्होंने पद संभालने के कुछ ही महीनों बाद अपनी लोकप्रियता और नीतियों पर जनता का विश्वास परखने के लिए यह 'स्नैप इलेक्शन' कराने का फैसला किया, जो उनके लिए मास्टरस्ट्रोक साबित हुआ।
- "साना-मेनिया" और युवा मतदाता जापान में ताकाइची की लोकप्रियता को 'साना-मेनिया' या जापानी में 'सानाकात्सु' कहा जा रहा है।

❑ साने ताकाइची के बारे में -

- साने ताकाइची, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर अक्टूबर 2025 में चुनी गईं थीं।
- ताकाइची ने 1993 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और बाद में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो गईं।
- वह 10 बार सांसद चुनी गई हैं और पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की करीबी मानी जाती हैं।
- ताकाइची आर्थिक सुरक्षा, सामरिक अधिकारों और विदेश नीति पर अपने कठोर और स्पष्ट विचारों के लिए जानी जाती हैं। वह समलैंगिक विवाह का विरोध करती हैं और चीन के प्रति सख्त रुख रखती हैं।
- ताकाइची, एक शौकीन ड्रमर और बाइकर भी हैं। उन्हें 'आयरन लेडी' और 'लेडी ट्रम्प' के नाम से भी जाना जाता है।

EDU TERIA Telegram Channel
link : https://eduteria.live

09 नई दिल्ली में भारत द्वारा पहली BRICS शेरपा और सू-शेरपा बैठक की मेज़बानी

भारत द्वारा 2026 में BRICS की अध्यक्षता संभालने के बाद नई दिल्ली में पहली BRICS शेरपा और सू-शेरपा बैठक की मेज़बानी की गई। भारत द्वारा BRICS की अध्यक्षता संभालना वैश्विक मंच पर "ग्लोबल साउथ" की आवाज़ को और मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

मुख्य बिंदु

- अध्यक्षता: बैठक की अध्यक्षता भारत के BRICS शेरपा और सचिव (आर्थिक संबंध) सुधाकर दलेला ने की, जबकि शंभू एल. हक्की, भारत के BRICS सू-शेरपा भी इसमें शामिल रहे।
- थीम: प्राथमिकताओं को "अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिये निर्माण (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability)" थीम के तहत प्रस्तुत किया गया, जो BRICS नेतृत्व के प्रति भारत के जन-केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है।
- फोकस: इसमें स्वास्थ्य, कृषि, श्रम, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, नवाचार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT), सुरक्षा तथा आर्थिक और वित्तीय क्षेत्रों में सहयोग पर ज़ोर दिया गया।

❑ महत्व:-

- एजेंडा सेटिंग: नई दिल्ली में हुई इस पहली बैठक का मुख्य उद्देश्य पूरे वर्ष के लिए प्राथमिकताओं को निर्धारित करना है। इसमें आर्थिक सहयोग, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा (DPI), और वैश्विक दक्षिण (Global South) की आवाज को बुलंद करने जैसे मुद्दे शामिल रहने की संभावना है।
- विस्तारित BRICS: यह अध्यक्षता इसलिए भी खास है क्योंकि अब BRICS में नए सदस्य देश (जैसे मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात) शामिल हो चुके हैं। भारत की भूमिका इन सभी को एक साझा मंच पर लाने में महत्वपूर्ण होगी।
- रणनीतिक नेतृत्व: 2026 की अध्यक्षता भारत को "विश्व-मित्र" के रूप में अपनी छवि मजबूत करने और विकसित देशों व विकासशील देशों के बीच एक सेतु (Bridge) के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान करती है।

नोट: 'शेरपा' शब्द हिमालयी गाइडों से लिया गया है, जो पर्वतारोहियों को चोटी तक पहुँचाने में मदद करते हैं। कूटनीति में भी इनका काम शिखर सम्मेलन (Summit) को सफल बनाने के लिए कठिन वार्ताएं पूरी करना होता है।

10 बायोफैच (BIOFACH) 2026

❑ चर्चा में क्यों?

जैविक उत्पादों का दुनिया का सबसे बड़ा और प्रमुख व्यापार मेला "बायोफैच (BIOFACH) 2026", फरवरी 2026 में जर्मनी के नूरेमबर्ग में आयोजित किया गया। इस आयोजन में भारत को 'कंट्री ऑफ द ईयर' नामित किया गया।

मुख्य बिंदु

- उद्देश्य: इसका आयोजन जैविक खाद्य पदार्थों, टिकाऊ कृषि, और नवीन विनिर्माण के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से है।
- थीम: "ग्रोइंग टुमॉरो: यंग वॉइसेस, बोल्ड विज़न्स" (Growing Tomorrow: Young Voices, Bold Visions) - यह थीम ऑर्गेनिक उत्पादों के भविष्य पर ध्यान केंद्रित करती है।
- कंट्री ऑफ द ईयर: भारत को 'कंट्री ऑफ द ईयर' का सम्मान मिला, जो भारतीय जैविक उत्पादों की वैश्विक पहचान को मजबूत करता है।
- भारतीय भागीदारी (APEDA): कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने 20 से अधिक राज्यों के निर्यातकों, एफपीओ (FPOs) और सहकारी समितियों के साथ भारतीय मंडप (India Pavilion) का नेतृत्व किया।
- प्रदर्शित उत्पाद: भारतीय मंडप में चावल, मसाले, तिलहन, दालें, काजू, अदरक, हल्दी, आम की प्यूरी, चाय, कॉफी और बाजरा (millets) जैसे प्रमुख जैविक उत्पाद प्रदर्शित किए गए।

❑ APEDA के बारे में:-

- APEDA (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करने वाला एक प्रमुख संगठन है।
- इसकी स्थापना दिसंबर 1985 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी और इसने 1986 से काम करना शुरू किया।
- इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है, लेकिन इसके क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों में भी हैं।
- इसका मुख्य काम भारत से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात (Export) को बढ़ावा देना और उन्हें वैश्विक बाजारों तक पहुँचाना है।

11 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025

❑ चर्चा में क्यों?

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की स्थिति में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार देखा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र में कथित भ्रष्टाचार के आधार पर 182 देशों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें शून्य (अत्यधिक भ्रष्ट) से लेकर 100 (बहुत साफ) तक के पैमाने का उपयोग किया गया।

मुख्य बिंदु

- यह रिपोर्ट वैश्विक भ्रष्टाचार के रुझानों , उनके मूल कारणों, सामाजिक प्रभावों और कार्रवाई योग्य सिफारिशों का व्यापक मूल्यांकन प्रदान करती है।
- एक दशक से अधिक समय में पहली बार, वैश्विक सीपीआई औसत 100 में से घटकर मात्र 42 रह गया है। अधिकांश देशों (182 में से 122) का स्कोर 50 से नीचे है , जो विश्व स्तर पर भ्रष्टाचार की गंभीर समस्याओं को दर्शाता है।
- 80 से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले देशों की संख्या एक दशक पहले 12 से घटकर इस वर्ष केवल 5 रह गई है। (डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, नॉर्वे)

❑ भारत की स्थिति:-

- रैंक (Rank): 182 देशों में भारत 91वें स्थान पर है।
- स्कोर (Score): भारत का स्कोर 100 में से 39 रहा है।
- सुधार: 2024 की तुलना में भारत की रैंकिंग में 5 स्थानों का सुधार हुआ है (2024 में भारत 96वें स्थान पर था)।
- निष्कर्ष: हालांकि भारत की रैंक सुधरी है, लेकिन इसका स्कोर (39) अभी भी वैश्विक औसत (42) से कम है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की निरंतर चुनौतियों को दर्शाता है।

❑ वैश्विक प्रदर्शन: शीर्ष और निचले देश

- यह सूचकांक 0 (अत्यधिक भ्रष्ट) से 100 (बहुत स्वच्छ) के पैमाने पर देशों को मापता है।

श्रेणी	देश	स्कोर
1	(सबसे स्वच्छ) डेनमार्क	89
2	फिनलैंड	88
3	सिंगापुर	84
182 (सबसे भ्रष्ट)	सोमालिया और दक्षिण सूडान	9

❑ प्रमुख रुझान और कारण:

- डिजिटलीकरण का प्रभाव: भारत की रैंकिंग में सुधार का एक बड़ा श्रेय ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं को दिया गया है, जिससे सरकारी योजनाओं में बिचौलियों की भूमिका कम हुई है।
- वैश्विक गिरावट: रिपोर्ट में चिंता जताई गई है कि वैश्विक औसत स्कोर गिरकर 42 रह गया है, जो पिछले एक दशक का सबसे निचला स्तर है।

❑ पड़ोसी देशों की स्थिति:

- भूटान (18वीं रैंक): दक्षिण एशिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन।
- चीन (76वीं रैंक): भारत से बेहतर स्थिति में।
- पाकिस्तान (136वीं रैंक) और बांग्लादेश (150वीं रैंक): भारत की तुलना में अधिक भ्रष्ट माने गए हैं।

नोट:- रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत उन देशों में शामिल है जो भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए "खतरनाक" माने जाते हैं।

❑ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में -

- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (TI) 1993 में स्थापित एक प्रमुख वैश्विक गैर-सरकारी संगठन (NGO) है, जिसका मुख्यालय बर्लिन, जर्मनी में है।
- यह एक स्वतंत्र, गैर-पक्षपातपूर्ण संगठन है जो दुनिया भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है और सत्ता में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं ईमानदारी को बढ़ावा देता है।
- इसकी स्थापना 1993 में पीटर आइगेन (एक जर्मन वकील और विकास अर्थशास्त्री) द्वारा की गई थी।

- यह संस्था 1995 से प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (CPI) जारी करती है जो विभिन्न देशों को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके भ्रष्टाचार के स्तर (व्यापकता) के आधार पर रैंक प्रदान करती है।
- ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर, ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट और रिश्वतदाता सूचकांक (Bribe Payers Index) आदि भी इसी संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है।
- यह संस्था 100 से अधिक देशों में राष्ट्रीय शाखाओं के साथ भ्रष्टाचार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों को कम करने के लिए कार्य कर रही है।
- भारत में भी इसके सहयोगी संगठन जैसे "ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया" सक्रिय हैं, जो देश में पारदर्शिता के लिए काम करते हैं।

12 भारत-ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता

भारत ने ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान (Social Security Contributions) से संबंधित एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत दोनों देशों के नागरिकों के सामाजिक सुरक्षा योगदान और लाभ सुनिश्चित होंगे।

मुख्य बिंदु

- हस्ताक्षरकर्ता: विदेश सचिव विक्रम मिसरी और भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन ने नई दिल्ली में इस पर हस्ताक्षर किए।
- उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य उन कर्मचारियों को दोहरे सामाजिक सुरक्षा अंशदान से बचाना है जो एक-दूसरे के देशों में 36 महीने तक की अस्थायी नियुक्ति पर हैं।
- महत्व: यह समझौता अल्पकालिक विदेशी नियुक्तियों पर कर्मचारियों की गतिशीलता (Mobility) और निरंतर सामाजिक सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित करेगा।
- व्यापार का हिस्सा: यह ब्रिटेन के साथ भारत के व्यापार समझौते का हिस्सा है और व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते के साथ ही प्रभावी होगा।

13 नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स (NRI) 2025

❑ चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स (NRI) 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने डिजिटल अर्थव्यवस्था और तकनीकी बुनियादी ढांचे के मामले में अपनी स्थिति को काफी मजबूत करते हुए 127 अर्थव्यवस्थाओं में 45वां स्थान हासिल किया है। यह रिपोर्ट वॉशिंगटन डीसी स्थित पोर्टुलंस इंस्टीट्यूट (Portulans Institute) द्वारा जारी की गई है, जो यह मापती है कि कोई देश सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का लाभ उठाने के लिए कितना तैयार है।

❑ भारत की रैंकिंग और स्कोर

- वैश्विक रैंकिंग: भारत अब 45वें स्थान पर पहुँच गया है (2024 में यह 49वें स्थान पर था)। भारत ने अपनी रैंकिंग में 4 अंकों का सुधार किया है।
- आय श्रेणी में प्रदर्शन: 'निम्न-मध्यम आय' (Lower-middle-income) वाले देशों के समूह में भारत दूसरे स्थान पर बना हुआ है।
- कुल स्कोर: भारत का स्कोर पिछले वर्ष के 53.63 से बढ़कर 54.43 (100 में से) हो गया है।

❑ भारत की रैंकिंग और स्कोर

यह इंडेक्स 127 देशों का मूल्यांकन चार प्रमुख आधारों पर करता है। भारत का प्रदर्शन इन क्षेत्रों में इस प्रकार है:

- टेक्नोलॉजी (Technology): भारत यहाँ भविष्य की तकनीकों (AI, IoT) को अपनाने में अग्रणी है।
- लोग (People): इसमें व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सरकारी स्तर पर डिजिटल उपकरणों के उपयोग को देखा जाता है।
- गवर्नेंस (Governance): डिजिटल सुरक्षा, गोपनीयता और ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचे का मूल्यांकन।
- प्रभाव (Impact): अर्थव्यवस्था, जीवन स्तर और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) पर डिजिटल तकनीक का प्रभाव।

❑ वैश्विक शीर्ष देश

दुनिया के सबसे अधिक नेटवर्क-तैयार देशों की सूची में ये देश शीर्ष पर हैं:

- संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)
- फिनलैंड
- सिंगापुर

निष्कर्ष: भारत का प्रदर्शन यह दर्शाता है कि वह अपनी आर्थिक क्षमता (GDP) की तुलना में डिजिटल क्षेत्र में कहीं अधिक तेजी से निवेश और विकास कर रहा है। हालांकि, 'डिजिटल साक्षरता' और 'साइबर सुरक्षा' जैसे क्षेत्रों में सुधार की अब भी गुंजाइश है।

14 म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026 (MSC 2026)

❑ चर्चा में क्यों?

हाल ही में (फरवरी 2026) मे भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित "62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन" (MSC) में भागीदारी की, साथ ही इसके इत्तर जी4 (G4) देशों की साथ बैठक में भी भाग लिया।

मुख्य बिंदु

- थीम: इस वर्ष की रिपोर्ट और चर्चा का मुख्य शीर्षक "Under Destruction" रहा, जो वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के बिखराव और अस्थिरता को दर्शाता है।
- प्रमुख मुद्दे:
  - → वैश्विक व्यवस्था का संकट: अंतरराष्ट्रीय नियमों का टूटना और बड़ी शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा।
  - → क्षेत्रीय संघर्ष: मध्य पूर्व (Middle East) की सुरक्षा और रूस-यूक्रेन युद्ध के दीर्घकालिक प्रभाव।
  - → तकनीकी सुरक्षा: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर खतरे और अंतरिक्ष सुरक्षा।
- म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन (MSC) अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा नीति पर चर्चा करने के लिए दुनिया का सबसे प्रमुख और स्वतंत्र मंच है।
- इसे अक्सर "रक्षा क्षेत्र का दावोस" (Davos of Defence) भी कहा जाता है।

नोट:- म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की शुरुआत 1963 में 'एवाल्ड-हाइनरिच वॉन क्लेइस्ट' द्वारा की गई थी। उस समय इसका उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों के बीच संवाद बढ़ाना था।

❑ जी4 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ औपचारिक मुलाकात

- यह पहली बार था जब जी4 देशों के विदेश मंत्रियों ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के इतर (sidelines) औपचारिक मुलाकात की। आमतौर पर यह समूह संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मिलता है।
- बैठक में डॉ. एस. जयशंकर के साथ जापान, जर्मनी और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने भी भाग लिया।
- चर्चा का मुख्य केंद्र "रिफ़ॉर्मड मल्टीलेटरलिज्म" (Reformed Multilateralism) और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में जल्द से जल्द सुधार लाना था।
- चारों देशों ने एक-दूसरे की स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन किया और जोर दिया कि UNSC को 21वीं सदी की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप होना चाहिए।

❑ G4 समूह के बारे में-

- जी4 उन चार देशों का समूह है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पाने के लिए एक-दूसरे का समर्थन करते हैं। इसमें भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील शामिल हैं।
- इन देशों का तर्क है कि वर्तमान सुरक्षा परिषद (P5 - अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके) पुराने वैश्विक ढांचे का प्रतिनिधित्व करती है और इसमें सुधार की तत्काल आवश्यकता है।

15 भारत ने किंबर्ले प्रोसेस (KP) की अध्यक्षता संभाली

भारत ने वर्ष 2026 के लिए किंबर्ले प्रोसेस (KP) की अध्यक्षता ग्रहण की जो विश्व स्तर पर डायमंड गवर्नेंस के क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है। भारत की अध्यक्षता में इसमें डिजिटल सर्टिफिकेशन और पारदर्शिता पर जोर दिया जाएगा।

❑ किम्बर्ली प्रोसेस (KP) के बारे में -

- किम्बर्ली प्रोसेस (KP) एक अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन योजना है, जो 2003 से लागू है।
- किम्बर्ले प्रक्रिया सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय हीरा उद्योग और नागरिक समाज संगठनों की एक संयुक्त पहल है।
- इसका मुख्य उद्देश्य संघर्ष हीरों (Conflict Diamonds) या "खूनी हीरों" के व्यापार को रोकना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हीरों की बिक्री से होने वाले राजस्व का उपयोग हिंसा या अवैध गतिविधियों के लिए न हो।
- यह 99% से अधिक वैश्विक कच्चे हीरों के व्यापार को नियंत्रित करता है, जहाँ हर खेप के साथ एक Tamper-resistant (छेड़छाड़-मुक्त) प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।
- भारत KPCS के संस्थापक सदस्यों में से एक है, तथा इससे पहले 2008 और 2019 में भी अध्यक्षता की थी।
- किम्बर्ली प्रोसेस (KP) में 60 से अधिक भागीदार शामिल हैं, जो सभी नियमों का पालन करते हैं।

16 अंतर्राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा सम्मेलन (ICDS) 2026

❑ चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा सम्मेलन (ICDS) 2026 बेंगलुरु में आयोजित एक महत्वपूर्ण वैश्विक आयोजन था। यह दो-दिवसीय सम्मेलन 13-14 फरवरी 2026 को बेंगलूर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के जे.एन. टाटा ऑडिटोरियम में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

मुख्य बिंदु

- यह सम्मेलन संयुक्त रूप से जल शक्ति मंत्रालय (भारत सरकार), कर्नाटक सरकार, केंद्रीय जल आयोग (CWC), IISc बेंगलुरु और विश्व बैंक द्वारा आयोजित किया गया।
- सम्मेलन का उद्घाटन उच्च-स्तरीय समारोह के साथ 13 फरवरी को हुआ, जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया ने उद्बोधन दिया।
- यह DRIP (बाँध पुनर्वास और सुधार परियोजना) के चरण II और III के तहत आयोजित सम्मेलनों की श्रृंखला में दूसरा कार्यक्रम था।
- इसमें 12 देशों से 750 से अधिक प्रतिनिधि, इंजीनियर, नीति-निर्माता और विशेषज्ञों ने भाग लिया।
  - → सम्मेलन में बाँध सुरक्षा अधिनियम 2021, बाँध पुनर्वास, जलवायु लचीलापन, जोखिम मूल्यांकन, तलछट प्रबंधन, बाढ़ पूर्वानुमान और डायनामिक रूल कर्व्स जैसे विषयों पर चर्चा हुई।
- विशेषज्ञों ने रियल-टाइम डेटा शेयरिंग और बेसिन-स्तरीय जलाशय संचालन पर जोर दिया।
- वैश्विक अनुभवों और प्रौद्योगिकी नवाचारों के आदान-प्रदान ने भारत के बाँध सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में योगदान दिया।

❑ सम्मेलन के दौरान बाँधों की सुरक्षा और प्रबंधन को लेकर उठाए गए महत्वपूर्ण कदम:

- DAMCHAT (एआई प्लेटफॉर्म): आईआईटी रुड़की स्थित 'इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स' (ICED) द्वारा विकसित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। यह तकनीकी निर्णय लेने में सहायता करेगा।
- जल शक्ति डेटा प्रबंधन प्लेटफॉर्म: राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र (NWIC) द्वारा डेटा-संचालित बाँध प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए इसे जारी किया गया।

❑ उद्देश्य:-

- इसका मुख्य लक्ष्य बाँधों की संरचनात्मक मजबूती, निगरानी उपकरण स्थापना, आपदा तैयारी और संस्थागत क्षमता निर्माण था। सम्मेलन ने शासन सुधार, सामुदायिक तैयारी और सतत जल प्रबंधन को बढ़ावा दिया। यह भारत में बाँध सुरक्षा पारिस्थितिकी को सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

❑ बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के बारे में

- बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021, भारत में निर्दिष्ट बांधों (15 मीटर से ऊंचे, या 10-15 मीटर के विशिष्ट बांध) की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

- यह अधिनियम 30 दिसंबर 2021 से प्रभावी है। इसका मुख्य उद्देश्य बांध विफलता से जुड़ी आपदाओं को रोकना और राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर संस्थागत तंत्र स्थापित करना है।
  - → केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (NCDS) और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA), तथा राज्य स्तर पर राज्य बांध सुरक्षा समिति (SCDS) व राज्य बांध सुरक्षा संगठन (SDSO) का गठन।

17 39वां अफ्रीकी संघ (AU) शिखर सम्मेलन 2026

39वां अफ्रीकी संघ (AU) शिखर सम्मेलन 14-15 फरवरी 2026 को इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में आयोजित हुआ। यह अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों की वार्षिक बैठक है, जो महाद्वीप की प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करती है।

❑ मुख्य विषय (Theme)

- सम्मेलन का आधिकारिक विषय था: "एजेंडा 2063 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सुरक्षित जल और स्वच्छता प्रणालियों की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करना"।
- महत्व: अफ्रीका में लगभग 40 करोड़ लोगों के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है और 80 करोड़ से अधिक लोग बुनियादी स्वच्छता सेवाओं से वंचित हैं। इस विषय को चुनकर जल सुरक्षा को विकास, शांति और जलवायु लचीलेपन के एक स्तंभ के रूप में स्थापित किया गया है।

❑ प्रमुख नेतृत्व परिवर्तन

- नए अध्यक्ष: बुरुंडी के राष्ट्रपति एवेरिस्ट नदिशिमिने (Évariste Ndayishimiye) को वर्ष 2026 के लिए अफ्रीकी संघ का नया अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने मॉरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद ओल्ड गज़ौनी से कार्यभार संभाला।

❑ 'अफ्रीका वाटर विजन 2063' का शुभारंभ

- सम्मेलन में "Africa Water Vision 2063" और उससे संबंधित नीतियों को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया।
  - → WASH Compacts: सदस्य देशों ने 'नेशनल वॉश कॉम्पैक्ट्स' (National WASH Compacts) की शुरुआत की, जो 2035 तक सार्वभौमिक जल और स्वच्छता पहुंच सुनिश्चित करने के लिए देशों की औपचारिक प्रतिबद्धता है।

❑ अन्य महत्वपूर्ण एजेंडा और निर्णय

- शिखर सम्मेलन के दौरान केवल जल ही नहीं, बल्कि अन्य रणनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई:
  - → शांति और सुरक्षा: सूडान, पूर्वी कांगो (DRC) और साहेल क्षेत्र में चल रहे संघर्षों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। 'अफ्रीकन स्टैंडबाय फोर्स' (ASF) के उपयोग पर एक महत्वपूर्ण समझौते (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
  - → स्वास्थ्य संप्रभुता: 'CARMMA Plus' वेबसाइट और अफ्रीकी अनुसंधान इंजन लॉन्च किया गया ताकि टीकों और दवाओं के उत्पादन में अफ्रीका आत्मनिर्भर बन सके।
  - → आर्थिक एकीकरण: अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (AfCFTA) को कानूनी संधि से वाणिज्यिक वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया को तेज करने पर जोर दिया गया।

❑ अफ्रीकी संघ के बारे में -

- इसकी स्थापना 9 जुलाई 2002 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। इसकी रूपरेखा 9 सितंबर 1999 के सिरते घोषणापत्र में तैयार की गई थी।
- अफ्रीका महाद्वीप के सभी 55 देश इसके सदस्य हैं।
- इसका मुख्यालय अदीस अबाबा, इथियोपिया में स्थापित है।
- इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच एकता, सुरक्षा, मानवाधिकार, लोकतंत्र और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
- वर्ष 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में, अफ्रीकी संघ को समूह के 21वें सदस्य के रूप में आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया।
- इसके प्रमुख निकायों में अफ्रीकी संघ सभा (राष्ट्राध्यक्षों की बैठक) और अफ्रीकी संघ आयोग (सचिवालय) शामिल हैं।

18 'पैक्स सिलिका घोषणापत्र' (Pax Silica Declaration)

❑ चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' के दौरान 'पैक्स सिलिका घोषणापत्र' (Pax Silica Declaration) पर हस्ताक्षर किए।

❑ उद्देश्य :-

- केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और अमेरिकी अधिकारी जैकब हेलबर्ग (आर्थिक मामलों के अवर सचिव) की उपस्थिति में हुए इस समझौते का उद्देश्य सेमीकंडक्टर, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सुरक्षित, लचीली और चीन पर निर्भरता से मुक्त आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) का निर्माण करना है।

❑ 'पैक्स सिलिका घोषणापत्र' के मुख्य बिंदु:

- सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम: दोनों देश सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को मजबूत करने और अनुसंधान के लिए मिलकर काम करेंगे। यह भारत की 'सेमीकंडक्टर मिशन' (ISM) की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।
- AI सुरक्षा और नैतिकता: यह समझौता सुनिश्चित करता है कि AI का उपयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप हो और इसके जोखिमों (जैसे डेटा प्राइवेसी और गलत सूचना) को कम किया जा सके।
- तकनीकी सहयोग (iCET): यह पहल 'महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल' (initiative on Critical and Emerging Technology - iCET) के तहत सहयोग को और गहरा करती है।
- कौशल विकास: समिट में भारत के विशाल टैलेंट पूल को AI-रेडी बनाने के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर दिया गया।

❑ भारत के लिए लाभ:-

- तकनीकी हस्तांतरण: भारत को अत्याधुनिक चिप डिजाइन और निर्माण तकनीक (Fabrication) तक सीधी पहुंच मिलेगी।
- निवेश: सेमीकंडक्टर और AI क्षेत्रों में भारी विदेशी निवेश की संभावना बढ़ेगी

- आपूर्ति सुरक्षा: दुर्लभ खनिजों (Rare Earth Minerals) की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जो स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक के लिए जरूरी हैं।
- रक्षा तकनीकों में मददगार: यह समझौता भारत की रक्षा क्षमताओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस करने में मदद करेगा।
  - → ड्रोन तकनीक, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान में उन्नत AI का उपयोग भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा।

❑ क्या है 'पैक्स सिलिका'?

- 'पैक्स सिलिका' अमेरिका के नेतृत्व वाला एक नया रणनीतिक गठबंधन है।
- इसका मुख्य उद्देश्य चीन पर निर्भरता कम करना और सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), और महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) की एक सुरक्षित और विश्वसनीय वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) बनाना है।
- इस पहल में अमेरिका के साथ जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ब्रिटेन, नीदरलैंड, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) , कतर और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं।

19 FCI ने वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के साथ चावल आपूर्ति के लिए समझौता किया

भारतीय खाद्य निगम (FCI) और विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के बीच वर्ष 2031 तक के लिए वैश्विक भूख राहत अभियानों के समर्थन में चावल आपूर्ति हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता को मजबूत करना और वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदान देना है। यह समझौता भारत की "वसुधैव कुटुंबकम" की भावना और वैश्विक मानवीय सहायता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

❑ समझौते की मुख्य बिंदु:-

- आपूर्ति की मात्रा: इस समझौते के तहत FCI प्रति वर्ष 2 लाख मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) को करेगा।
- चावल की गुणवत्ता: इसमें अधिकतम 25% तक टूटे हुए चावल (broken rice) की आपूर्ति की जाएगी, जो अंतरराष्ट्रीय मानवीय वितरण मानकों के अनुरूप है।
- समय सीमा: यह समझौता 5 वर्षों (2026-2031) के लिए वैध है, जिसे आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है।
- निर्धारित मूल्य: वर्तमान आपूर्ति चक्र के लिए चावल की कीमत 2,800 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है, जो 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद कीमतों की वार्षिक समीक्षा की जाएगी।

❑ विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme - WFP) के बारे में:-

- विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख मानवीय संस्था है, जो दुनिया भर में भूख मिटाने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है।
  - → इसकी स्थापना 1961 में संयुक्त राष्ट्र महासभा और खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा की गई थी।
- इसका मुख्यालय रोम (इटली) में स्थित है।
- इसका लक्ष्य , सतत विकास लक्ष्य 2 (SDG 2) के तहत 2030 तक 'जीरो हंगर' प्राप्त करना है।
- यह दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय सहायता संस्था है जो आपात स्थितियों (युद्ध, अकाल, प्राकृतिक आपदा) में भोजन पहुँचाती है।
- WFP को "भूख से लड़ने, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए स्थितियों को बेहतर बनाने और युद्ध में भूख को हथियार के रूप में उपयोग किए जाने से रोकने" के प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार (2020) से सम्मानित किया गया।

❑ भारतीय खाद्य निगम (FCI) के बारे में:-

- FCI, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत एक प्रमुख वैधानिक संस्था है।
- इसकी स्थापना खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत 14 जनवरी 1965 को हुई थी।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- यह किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्यान्न (गेहूं, चावल) खरीदकर, भंडारण कर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से देशभर में सुनिश्चित और किफायती आपूर्ति बनाए रखता है, जो देश की खाद्य सुरक्षा का मुख्य स्तंभ है।

20 वेस्ट बैंक

❑ चर्चा में क्यों?

इजराइल की कैबिनेट ने वेस्ट बैंक (विशेषकर एरिया सी) में औपचारिक भूमि पंजीकरण (Land Registration) फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है। इस विवादास्पद कदम से, 1967 के बाद पहली बार, फिलिस्तीनी निवासियों के लिए जमीन का मालिकाना हक साबित करना अनिवार्य होगा; अन्यथा, दस्तावेज के अभाव में भूमि को 'राज्य संपत्ति' (State Land) घोषित कर दिया जाएगा।

मुख्य बिंदु

- एरिया सी पर फोकस: यह प्रक्रिया वेस्ट बैंक के 60% क्षेत्र 'एरिया सी' पर लागू होगी, जो पूरी तरह से इजरायली सेना के नियंत्रण में है।
- बस्ती विस्तार (Settlement Expansion): इस योजना का उद्देश्य इजरायली बस्तियों को बढ़ाना और उस भूमि पर अपना नियंत्रण मजबूत करना है, जिसे फिलिस्तीनी अपनी ऐतिहासिक भूमि मानते हैं।
- दस्तावेजीकरण की चुनौती: चूंकि वेस्ट बैंक की अधिकांश जमीन का पहले से आधिकारिक पंजीकरण नहीं है, इसलिए फिलिस्तीनियों को अपना स्वामित्व साबित करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
- अंतरराष्ट्रीय चिंता: इस फैसले को 'डी-फैक्टो विलय' (de facto annexation) और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया जा रहा है।

- प्रक्रिया और बजट: दक्षिणपंथी मंत्रियों (बेज़लेल स्मोट्रिच, यारिव लेविन, और इज़राइल काट्ज़) द्वारा प्रस्तावित, इस प्रक्रिया के लिए 2026-2030 के लिए लगभग 79 मिलियन डॉलर आवंटित किए गए हैं।

❑ 'वेस्ट बैंक' के बारे में -

- वेस्ट बैंक, जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर स्थित एक भू-आबद्ध (landlocked) क्षेत्र है, जो 1967 से इज़राइल के सैन्य कब्जे में है।
- यह फिलिस्तीन और इज़राइल के बीच एक मुख्य विवादित क्षेत्र है, जहां लगभग 26 लाख से अधिक फिलिस्तीनी और 7 लाख से ज्यादा इज़रायली सेटलर (बस्तियों में) रहते हैं।
- यह इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है और इसका दक्षिणी हिस्सा मृत सागर के तट को छूता है।
- 1948 के युद्ध के बाद इस पर जॉर्डन का कब्ज़ा था, लेकिन 1967 के छह-दिवसीय युद्ध (Six-Day War) में इज़राइल ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया।

21 फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का तीन दिवसीय भारत दौरा

❑ चर्चा में क्यों?

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने फरवरी 2026 में भारत का तीन दिवसीय दौरा किया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी ('होराइजन 2047' रोडमैप) को गहरा करना, रक्षा, अंतरिक्ष, और AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) में सहयोग बढ़ाना था। उन्होंने इस यात्रा की मुंबई से की, जहां उन्होंने टाटा एयरबस H125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन किया, इसके पश्चात दिल्ली में 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' में भाग लिया।

❑ मैक्रों के भारत दौरे के प्रमुख बिंदु:

- रणनीतिक संबंध: मैक्रों का यह चौथा दौरा था, जो भारत-फ्रांस 'होराइजन 2047' रोडमैप के तहत रक्षा, उच्च-तकनीक, और ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित था।
- रक्षा और रक्षा उत्पादन: भारत में हैमर मिसाइलों के उत्पादन के लिए BEL और सफ्रान के बीच संयुक्त उद्यम और रक्षा सहयोग पर जोर दिया गया।
- मुंबई और हेलीकॉप्टर प्लांट: मैक्रों और पीएम मोदी ने मुंबई में कर्नाटक के वेमगल में एयरबस H125 हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट का उद्घाटन किया, जहाँ अब भारत में ही हेलीकॉप्टर बनेंगे।
- डिजिटल पेमेंट (UPI): मैक्रों ने भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम (UPI) की प्रशंसा की और मुंबई के स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा इसका उपयोग करने की सराहना की।
- AI इम्पैक्ट समिट: उन्होंने नई दिल्ली में 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' में भाग लिया, जो ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला एआई शिखर सम्मेलन था।
- क्षेत्रीय मुद्दे: दोनों नेताओं ने इंडो-पैसिफिक में सहयोग और पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की।

EDU TERIA Telegram Channel
link : https://eduteria.live

- नोट:- फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15-17 जून 2026 को फ्रांस के एवियन-लेस-बैंस में आयोजित होने वाले 52वें जी-7 (G7) शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है।

22 भारत और ब्राजील ने डाक क्षेत्र में सहयोग पर एक MoU साइन किया

भारत और ब्राजील ने फरवरी 2026 में डाक क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो डाक सेवाओं में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य बिंदु

- केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फ्रेडरिको डी सिकेरा फिल्हो ने इस MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।
- यह समझौता 5 वर्षों के लिए लागू होगा, जिसका उद्देश्य डिजिटल सेवाओं, ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स और डाक सेवाओं का आधुनिकीकरण करना है।
- यह समझौता विशेष रूप से भारतीय MSME के लिए, जो ई-कॉमर्स और हस्तशिल्प में काम करते हैं, एशिया और लैटिन अमेरिका के बीच भरोसेमंद लॉजिस्टिक्स गलियारे बनाने में मदद करेगा।

❑ सहयोग के मुख्य क्षेत्र-

- डाक सेवाओं का आधुनिकीकरण: दोनों देश डाक संचालन में नई तकनीकों और डिजिटल समाधानों को साझा करेंगे।
- ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स: सीमा पार ई-कॉमर्स (Cross-border e-commerce) को बढ़ावा देने के लिए डाक वितरण प्रणाली को अधिक कुशल बनाया जाएगा।
- वित्तीय समावेशन: डाकघरों के माध्यम से दी जाने वाली वित्तीय सेवाओं (जैसे बचत खाते और प्रेषण) के क्षेत्र में अनुभव साझा करना।
- क्षमता निर्माण: दोनों देशों के डाक कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और तकनीकी विनिमय।

23 अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम (To The Point)

- 2025 में LEED- प्रमाणित हरित भवन क्षेत्र में भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए अमेरिका के बाहर विश्व का दूसर स्थान प्राप्त किया।
  - → चीन को पहला स्थान प्राप्त हुआ।
- वॉलमार्ट हाल ही में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार पूंजीकरण को शामिल करने वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी बन गई है।
- ग्लोबल फायर पावर की 2026 रैंकिंग के अनुसार भारत 0.1346 स्कोर के साथ चौथी बड़ी सैन्य शक्ति है।
- स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (जैसे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक) के उपयोग पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।

- केंद्रीय विज्ञान और प्रौधोगिकी विभाग - डी एस टी ने स्वच्छ ऊर्जा में भारत और नीदरलैंड के मध्य वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाते हुए भारत-नीदरलैंड हाइड्रोजन फैलोशिप कार्यक्रम आरम्भ किया।
- जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के सत्तारूढ़ गठबंधन ने संसदीय चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल की।
- नई दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी के मध्य वार्ता संपन्न।
  - → भारत और सेशेल्स ने स्वास्थ्य, मौसम विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौधोगिकी तथा सुशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
  - → सोशल हाउसिंग, रक्षा और समुद्री सुरक्षा में सहयोग के लिए भारत द्वारा 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई।
- जर्मनी के नूर्नबर्ग में फरवरी 2026 में आयोजित जैविक उत्पादों के विश्व के अग्रणी व्यापार मेले, "बायोफैच 2026" (BIOFACH 2026) में भारत को 'वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश' नामित किया गया है।
- भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत, 39 अंको के साथ 182 देशों और क्षेत्रों में 91वें स्थान पहुंच गया है।
  - → यह पिछले बार (96वें स्थान) के मुकाबले 5 अंको की सुधार दर्शाता है।
  - → यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी की जाती है।
- यूरोपीय संसद ने यूक्रेन के लिए 90 अरब यूरो के सहायता पैकेज को स्वीकृति दी।
- दक्षिण कोरिया ने दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कानून 'AI बेसिक एक्ट' लागू किया।
- सऊदी अरब 3-4 मई, 2026 को रियाद में तीसरे मानव क्षमता पहल (HCI) सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसका विषय "मानव संहिता" है।
  - → थीम (विषय):- मानव संहिता ('द ह्यूमन कोड')
  - → ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड को सम्मानित देश के रूप में शामिल किया जाएगा।
- भारत के विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने फरवरी 2026 में म्यूनिख सुरक्षा परिषद (एमएससी) 2026 के दौरान आयोजित G-4 बैठक में भाग लिया।
  - → G-4 में भारत के अलावा जापान, जर्मनी और ब्राजील शामिल हैं।
- भारत और न्यूजीलैंड ने हाल ही में बागवानी सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की। इसमें किवी व सेव जैसे फसलों पर विशेष ध्यान दिया गया।
- बांग्लादेश, भारत ए आई इम्पैक्ट समिट 2026 में अपनाई गई 'नई दिल्ली घोषणा पत्र' पर हस्ताक्षर करने वाला 89वां देश बना।
- फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने PM मोदी को 2026 में फ्रांस की अध्यक्षता में होने वाले 52 वें जी-7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया।
- 'ए आई इम्पैक्ट समिट' 2027 की मेजबानी स्विट्जरलैंड का जेनेवा शहर करेगा।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस और यूक्रेन के बीच बिना शर्त युद्धविराम का आह्वान करने वाले प्रस्ताव पर भारत ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। 107 देशों का समर्थन, 12 देशों का विरोध तथा भारत सहित 51 देश अनुपस्थित रहें।

रक्षा प्रौद्योगिकी

01 रक्षा क्षेत्र को अब तक का सर्वाधिक 7.85 लाख करोड़ रुपए का आवंटन

1 फरवरी 2026 को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को 7.85 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक आवंटन किया गया है। यह अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट है, जो पिछले वित्त वर्ष (2025-26) के 6.81 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले लगभग 15.19% अधिक है। इस भारी वृद्धि के पीछे 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) के बाद की सुरक्षा चुनौतियां और सेना के आधुनिकीकरण की आवश्यकताएं मुख्य कारण मानी जा रही हैं।

❑ रक्षा बजट 2026-27 की मुख्य बातें:

- कुल आवंटन: ₹7,84,678 करोड़ (लगभग 7.85 लाख करोड़)।
- आधुनिकीकरण (Capital Outlay): ₹2.19 लाख करोड़ से अधिक की राशि नए हथियारों, विमानों और युद्धपोतों की खरीद के लिए आवंटित की गई है, जो पिछले साल से करीब 22% अधिक है।
- घरेलू खरीद: रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत बजट का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 75%) घरेलू उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित रखा गया है।
- रक्षा पेंशन: पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन बजट को बढ़ाकर ₹1.71 लाख करोड़ कर दिया गया है।
- DRDO और नवाचार: रक्षा अनुसंधान (R&D) के लिए ₹29,100 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- सीमा बुनियादी ढांचा (BRO): सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिए BRO के बजट में भी बढ़ोतरी की गई है।

❑ बजट का महत्व:

- यह आवंटन भारत की कुल जीडीपी (GDP) का लगभग 2% है और केंद्र सरकार के कुल खर्च का 14.67% हिस्सा है, जो इसे सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक बजट वाला विभाग बनाता है।

02 ठोस ईंधन आधारित डक्टेड रैमजेट (SFDR) तकनीक

❑ चर्चा में क्यों?

हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) से ठोस ईंधन आधारित डक्टेड रैमजेट (SFDR) तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किया। इस सफल परीक्षण के साथ ही भारत उन विशिष्ट राष्ट्रों के समूह में सम्मिलित हो गया है, जिनके पास SFDR तकनीक उपलब्ध है। यह तकनीक लंबी दूरी की हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइलों के विकास के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

❑ सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (SFDR) टेक्नोलॉजी के बारे में -

- यह एक उन्नत एयर-ब्रीदिंग मिसाइल प्रणोदन प्रणाली है, जो पारंपरिक रॉकेटों के विपरीत, उड़ान के दौरान वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर ईंधन जलाती है। DRDO (डीआरडीओ) द्वारा विकसित यह तकनीक लंबी दूरी तक सुपरसोनिक गति (Mac 2 से अधिक) और अधिक पेलोड क्षमता प्रदान करती है, जो बियॉन्ड-विजुअल-रेंज (BVR) मिसाइलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

❑ SFDR की कार्यप्रणाली:-

- पारंपरिक मिसाइल इंजनों में ऑक्सीडाइज़र और ईंधन दोनों को साथ ले जाना पड़ता है, जिससे मिसाइल भारी हो जाती है। इसके विपरीत, SFDR तकनीक 'रैमजेट' सिद्धांत पर काम करती है।
  - → वायु-श्वसन प्रणाली (Air-breathing): यह मिसाइल उड़ान के दौरान वायुमंडल से ऑक्सीजन लेती है। इससे ऑक्सीडाइज़र ले जाने की ज़रूरत खत्म हो जाती है, जिससे मिसाइल हल्की होती है और उसमें अधिक ईंधन भरा जा सकता है।
  - → ठोस ईंधन (Solid Fuel): इसमें एक ठोस ईंधन थ्रस्ट ब्लॉक का उपयोग किया जाता है जो नोजल के माध्यम से ऊर्जा छोड़ता है।

❑ मुख्य प्रदर्शन संकेतक:-

- ऊँचाई की लचीलापन क्षमता: यह मिसाइल समुद्र तल से लेकर 20 किमी. की ऊँचाई तक प्रभावी रूप से संचालित हो सकती है।
- उच्च गतिशीलता: यह 10 किमी. तक के ऊर्ध्वाधर युद्धाभ्यास करने में सक्षम है।
- सटीक लक्ष्य निर्धारण: उच्च सटीकता सुनिश्चित करने के लिये इसमें रेडियो-फ्रीक्वेंसी सीकर, इनर्शियल नेविगेशन और जैम-प्रतिरोधी डेटा लिंक एकीकृत किये गए हैं।
- निरंतर सुपरसोनिक गति: सामान्य ठोस-ईंधन रॉकेटों के विपरीत, जो जल्दी ईंधन समाप्त कर लेते हैं, SFDR अधिक समय तक मैक 2 से मैक 3.8 की गति बनाए रखने में सक्षम होते हैं।
- विस्तारित मारक क्षमता: यह लड़ाकू विमानों को दृश्य सीमा से कहीं आगे स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम बनाता है, जिसकी परिचालन सीमा 50 किमी. से 340 किमी. के बीच है।
- घातक प्रभावशीलता: इसे उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों पर अधिकतम नुकसान पहुँचाने के लिये प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ से लैस विखंडन (फ्रैगमेंटेशन) वारहेड के साथ तैयार किया गया है।

❑ महत्त्व:

- विस्तृत नो-एस्केप ज़ोन: अंतिम चरण तक गति और ऊर्जा बनाए रखने के कारण यह एक बड़ा "नो-एस्केप ज़ोन" बनाता है, जिससे शत्रु विमानों के लिये बच निकलना मुश्किल हो जाता है।
- परिचालन बहुमुखी प्रतिभा: यह तकनीक हवा-से-हवा और सतह-से-हवा दोनों प्रकार की मिसाइल प्रणालियों में अपनाई जा सकती है, जिससे व्यापक वायु रक्षा क्षमताएँ और अधिक सुदृढ़ होती हैं।

- रणनीतिक बढ़त: यह तकनीक भारत की आगामी अस्त्र Mk-3 का आधार है, जो एक सीमा से परे हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल (BVRAAM) है और जिसे यूरोपीय मीटिओर मिसाइल तथा चीनी PL-15 के समकक्ष प्रतिस्पर्द्धी के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- सामरिक बढ़त: यह भारतीय वायु सेना (IAF) को "फर्स्ट लुक, फर्स्ट किल" की क्षमता प्रदान करती है, जिससे वह सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए शत्रुओं को निशाना बना सकती है।

❑ DRDO के बारे में:-

- इसकी स्थापना 1958 में हुई।(रक्षा विज्ञान संगठन और अन्य तकनीकी संस्थानों के विलय से)
  - → इसका मुख्यालय डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली में स्थित है।
  - → इसका आदर्श वाक्य "बलस्य मूलं विज्ञानम्" (शक्ति का आधार विज्ञान) है।
- वर्तमान में डॉ. समीर वी. कामत इसके अध्यक्ष हैं।

03 'ऑपरेशन शास्त्र'

❑ चर्चा में क्यों?

दिल्ली पुलिस ने हाल ही में 'ऑपरेशन शास्त्र' शुरू किया है, जो सोशल मीडिया पर हथियारों के महिमामंडन और गन कल्चर को रोकने के लिए लक्षित अभियान है।

मुख्य बिंदु

- अवैध हथियारों पर प्रहार: इसका प्राथमिक लक्ष्य उन गैंगस्टरों और अपराधियों को पकड़ना है जो अवैध आग्नेयास्त्र (firearms) की सप्लाई और इस्तेमाल में शामिल हैं।
- इंटेलिजेंस आधारित छापेमारी: पुलिस अपने खुफिया तंत्र और तकनीकी सर्विलांस का उपयोग कर उन 'हॉटस्पॉट्स' की पहचान कर रही है जहाँ अवैध हथियारों की खरीद-बिक्री अधिक होती है।
- गैंगवार पर लगाम: हाल के समय में दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में हुई गोलीबारी की घटनाओं को देखते हुए, पुलिस इस ऑपरेशन के जरिए गैंगस्टरों के नेटवर्क को तोड़ना चाहती है।
- व्यापक कार्रवाई: इसके तहत संदिग्धों की धरपकड़, वाहनों की चेकिंग और पहले से हथियार तस्करी में लिप्त अपराधियों की निगरानी बढ़ा दी गई है।
  - → लगभग 500 टीमें और 2,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी एक साथ इस काम में जुटे।
  - → पुलिस ने 6,000 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की।
  - → अब तक 83 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 16 नाबालिग भी शामिल हैं।
  - → इस दौरान 82 अवैध हथियार और 93 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं।

EDU TERIA Telegram Channel
link : https://eduteria.live

04 'बड़ी स्क्वाड्रन (Buddy Squadron) संयुक्त हवाई अभ्यास

दक्षिण कोरिया और अमेरिका की वायु सेनाओं ने 9-13 फरवरी, 2026 तक प्योंगटेक के ओसान एयर बेस पर 'बड़ी स्क्वाड्रन (Buddy Squadron) संयुक्त हवाई अभ्यास आयोजित किया। इसका उद्देश्य दोनों सहयोगी देशों के बीच अंतर-संचालनीयता और एकीकृत सामरिक क्षमताओं को बढ़ाना है।

मुख्य बिंदु

- 'बडी स्क्वाड्रन' अभ्यास की विशेषताएं:-
  - → फोकस: अन्य बड़े अभ्यासों के विपरीत, 'बडी स्क्वाड्रन' अक्सर Unit-level (इकाई-स्तर) पर होता है। इसका मुख्य उद्देश्य पायलटों और रखरखाव कर्मियों के बीच "कंधे से कंधा" मिलाकर काम करने की क्षमता विकसित करना है।
  - → रणनीति: इसमें लड़ाकू विमानों की डॉगफाइट (हवाई लड़ाई), दुश्मन के रडार से बचने की तकनीक और सटीक बमबारी का अभ्यास किया जाता है।
  - → विमान: इस अभ्यास में आमतौर पर दक्षिण कोरिया के F-15K या KF-16 और अमेरिका के F-16 Fighting Falcons जैसे चौथी और पांचवीं पीढ़ी के विमान हिस्सा लेते हैं।
- क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रभाव:-

  यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब उत्तर कोरिया अपनी मिसाइल तकनीक को लगातार उन्नत कर रहा है। 'बडी स्क्वाड्रन' जैसे छोटे लेकिन तकनीकी रूप से गहन अभ्यास यह सुनिश्चित करते हैं कि:
  - → त्वरित प्रतिक्रिया: किसी भी घुसपैठ की स्थिति में दोनों देशों की वायु सेनाएं बिना किसी देरी के एक ही फ्रीक्वेंसी पर काम कर सकें।
  - → मनोवैज्ञानिक दबाव: यह उत्तर कोरिया को स्पष्ट संदेश देता है कि गठबंधन की सैन्य तैयारी हर स्तर पर मजबूत है।
- ओसान एयर बेस का महत्व:-
  - → प्योंगटेक में स्थित ओसान एयर बेस कोरियाई प्रायद्वीप पर सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य ठिकानों में से एक है। यह उत्तर कोरियाई सीमा (DMZ) के काफी करीब है, जिससे यह किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है।

❑ दक्षिण कोरिया के बारे में:-

- दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित एक अत्यधिक विकसित और तकनीकी रूप से उन्नत देश है।
- इसकी राजधानी 'सियोल' और आधिकारिक मुद्रा 'वॉन' (Won) है।
- यह उत्तर में उत्तर कोरिया के साथ सीमा साझा करता है, जो दुनिया की सबसे अधिक सैन्यीकृत सीमाओं में से एक है। इसके पूर्व में जापान और पश्चिम में चीन है।
- 'शांत सुबह की भूमि' के रूप में प्रसिद्ध, यह देश अपने तीव्र आर्थिक विकास, के-पॉप (K-pop), टीवी ड्रामा, कॉस्मेटिक सर्जरी और सैमसंग व हुंडई जैसे ब्रांडों के लिए वैश्विक स्तर पर जाना जाता है।
- दक्षिण कोरिया 38वीं समानांतर रेखा (38th Parallel) के जरिए उत्तर कोरिया से अलग होता है।

05 स्कैल्प (SCALP) मिसाइल (स्टॉर्म शैडो)

❑ चर्चा में क्यों?

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-फ्रांस रक्षा साझेदारी को मजबूत करते हुए, भारत सरकार अपनी हवाई क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग €300 मिलियन की लागत से अतिरिक्त SCALP (स्टॉर्म शैडो) लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों की खरीद पर विचार कर रही है।

❑ SCALP के बारे में:-

- स्कैल्प (SCALP) मिसाइल (स्टॉर्म शैडो) फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा विकसित एक अत्यंत सटीक, लंबी दूरी की 'फायर एंड फॉरगेट' एयर-लॉन्च क्रूज मिसाइल है।
- ब्रिटेन में इसे 'स्टॉर्म शैडो' कहा जाता है, जबकि फ्रांस में इसे 'SCALP-EG' (Système de Croisière Autonome à Longue Portée – Emploi Général) के नाम से जाना जाता है।
- लगभग 1300 किलोग्राम वजनी यह मिसाइल 250-600 किमी की रेंज के साथ बंकरों, कमांड सेंटर और हवाई अड्डों जैसे मजबूत ठिकानों को तबाह करने में माहिर है।
- भारतीय राफेल लड़ाकू विमानों से लैस यह मिसाइल रडार से बचकर 0.8 मैक की गति से सटीक वार करती है।
- यह GPS, इंफ्रारेड (IR) सीकर और टेरेन प्रोफाइल मैचिंग (TERPROM) का उपयोग कर हर मौसम में उच्च परिशुद्धता से हमला करती है।
- इसमें एक विशेष प्रकार का 'ब्रोच' वॉरहेड होता है, जो पहले लक्ष्य की ऊपरी सतह को तोड़ता है और फिर अंदर जाकर विस्फोट करता है।

❑ महत्व:-

- यह मिसाइल दुश्मन के रडार से बचने के लिए बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती है, जिससे यह हवाई सुरक्षा को भेदने में अत्यधिक प्रभावी है। इसका उपयोग इराक, लीबिया और सीरिया जैसे संघर्षों में किया जा चुका है।

06 भारतीय वायु सेना (IAF) और रॉयल थाई वायु सेना (RTAF) के बीच इन-सीटू संयुक्त अभ्यास

भारतीय वायु सेना ने 9 से 12 फरवरी 2026 तक हिंद महासागर क्षेत्र में रॉयल थाई वायु सेना के साथ एक इन-सीटू संयुक्त अभ्यास आयोजित किया।

❑ अभ्यास का विवरण -

- यह अभ्यास दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करने और पारस्परिक समझ बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया।
- इसमें भारतीय वायु सेना के सु-30एमकेआई बहु-भूमिका लड़ाकू विमान, आईएल-78 मिड-एयर रिफ्यूलिंग टैंकर, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (AWACS) शामिल थे, जबकि थाई वायु सेना ने साब ग्रिपेन जेट्स का उपयोग किया।

❑ संचालन क्षेत्र -

- भारतीय विमान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एयरबेस से उड़े, जबकि थाई ग्रिपेन थाईलैंड के एयरबेस से संचालित हुए। • यह अभ्यास हिंद महासागर के ऊपर वायु युद्ध प्रशिक्षण पर केंद्रित रहा, जो 'एक्ट ईस्ट' नीति का हिस्सा है।
- महत्व - यह 2026 का भारतीय वायु सेना का पहला अंतरराष्ट्रीय अभ्यास था, जिसने क्षेत्रीय सुरक्षा, इंटरऑपरेबिलिटी और हिंद महासागर में साझा हितों को मजबूत किया।

❑ 'इन-सीटू' (In-Situ) अभ्यास का क्या मतलब है?

- 'इन-सीटू' का अर्थ है "उसी स्थान पर।" सैन्य संदर्भ में, इसका मतलब है कि यह अभ्यास किसी बनावटी ट्रेनिंग ग्राउंड के बजाय वास्तविक परिचालन क्षेत्र (Real-world operational area) में आयोजित किया गया।

07 असम राइफल्स के डॉग स्क्वाड में शामिल होंगे स्वदेशी नस्ल के 'तांगखुल हुई' और 'कोंबई'

असम राइफल्स ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अपने डॉग स्क्वाड में विदेशी नस्लों की जगह स्वदेशी नस्लों - तांगखुल हुई (मणिपुर) और कोंबई (तमिलनाडु) को चरणबद्ध तरीके से शामिल करने की योजना बनाई है।

मुख्य बिंदु

- उद्देश्य: सुरक्षा बलों में स्वदेशी कुत्तों को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भरता हासिल करना।
- लक्ष्य: 2050 तक विदेशी कुत्तों (जैसे जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर) को चरणबद्ध तरीके से बाहर करना।
- प्रशिक्षण: असम के जोरहाट स्थित असम राइफल्स डॉग ट्रेनिंग सेंटर (ARDTC) में इनका प्रशिक्षण चल रहा है।
- फायदे: ये नस्लें स्थानीय जलवायु और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों (पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर) के प्रति अधिक अनुकूल हैं और इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है।

❑ तांगबुल हुई (Tangkhul Hui) के बारे में -

- यह नस्ल मुख्य रूप से मणिपुर के उखरुल जिले की है।
  - → ये अपनी जबरदस्त वफादारी और शिकार करने की प्राकृतिक क्षमता के लिए जाने जाते हैं।
- पूर्वोत्तर भारत के कठिन और पहाड़ी इलाकों (Terrain) में रहने के कारण, ये असम राइफल्स के ऑपरेशंस के लिए शारीरिक रूप से पूरी तरह अनुकूल हैं। इन्हें "मणिपुरी तांगखुल डॉग" भी कहा जाता है।

❑ कोंबई (Kombai) के बारे में -

- इन्हें अक्सर "भारतीय टेरियर" कहा जाता है और ये तमिलनाडु से आते हैं।
  - → कोंबई बहुत ही साहसी और आक्रामक रक्षक होते हैं। इतिहास में इनका उपयोग शिकार और युद्धों में किया जाता रहा है।
  - → ये बेहद कम रखरखाव (Low maintenance) में रह सकते हैं और भारतीय जलवायु, विशेषकर गर्मी और उमस को सहन करने में विदेशी नस्लों (जैसे जर्मन शेफर्ड या लैब्राडोर) से कहीं बेहतर हैं।

08 भारतीय तटरक्षक बल द्वारा गोवा में अत्याधुनिक वाटरजेट प्रोडक्शन एवं टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन

हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिवमणि ने गोवा में एक अत्याधुनिक वाटरजेट प्रोडक्शन एवं टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया, यह भारतीय रक्षा और स्वदेशी विनिर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

मुख्य बिंदु

- साझेदार: यह सुविधा मेसर्स मरीन जेट पावर (MJP) इंडिया के साथ साझेदारी में स्थापित की गई है।
- वैश्विक क्लब में शामिल: भारत अब उन चुनिंदा देशों (अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बाद तीसरा) में शामिल हो गया है जिनके पास अपनी उन्नत वॉटरजेट टेस्टिंग सुविधा है। यह विदेशी परीक्षण केंद्रों पर हमारी निर्भरता को पूरी तरह खत्म कर देगा।
- रणनीतिक साझेदारी: मरीन जेट पावर (MJP) इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (ToT) यह सुनिश्चित करता है कि भविष्य में हम इन प्रणालियों का न केवल रखरखाव करेंगे, बल्कि इन्हें खुद विकसित भी कर सकेंगे।
- परिचालन क्षमता: चूंकि भारतीय तटरक्षक बल (ICG) पहले से ही 100 से अधिक ऐसे सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए स्थानीय स्तर पर सर्विसिंग और टेस्टिंग होने से जहाजों का 'डाउनटाइम' (मरम्मत में लगने वाला खाली समय) काफी कम हो जाएगा।
- आर्थिक और क्षेत्रीय लाभ:
  - → MSME को बढ़ावा: स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित होने से छोटे उद्योगों को काम मिलेगा।
  - → क्षेत्रीय हब: दक्षिण एशिया के अन्य देशों के लिए सर्विस सेंटर बनकर भारत 'मैरीटाइम इंजीनियरिंग' के क्षेत्र में एक लीडर के रूप में उभरेगा।

❑ वॉटरजेट प्रणोदन (Propulsion) क्या है?

- परंपरागत प्रोपेलर (पंखे) के विपरीत, वॉटरजेट सिस्टम पानी को अंदर खींचकर उसे तेज गति से पीछे की ओर फेंकता है। यह उथले पानी (Shallow water) में जहाजों को बेहतर गति और मोड़ने की जबरदस्त क्षमता (Maneuverability) प्रदान करता है, जो तटरक्षक बल के खोजी और बचाव अभियानों के लिए अत्यंत आवश्यक है।

09 बेंगलुरू में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) की नई मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी और ए आई पुश का उद्घाटन

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 फरवरी 2026 को बेंगलुरु में Bharat Electronics Limited (BEL) परिसर में एक अत्याधुनिक मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया। यह स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करने की दिशा में एक प्रमुख कदम है।

❑ मुख्य बिंदु और उपलब्धियाँ:

- मिसाइल फैसिलिटी: यह केंद्र विभिन्न मिसाइल प्रणालियों (जैसे QRSAM, MRSAM) के असेंबली और परीक्षण की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
- आकाश मिसाइल: उन्होंने आकाश तृतीय और चतुर्थ रेजिमेंट के कॉम्बैट सिस्टम्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
- AI पुश और पॉलिसी: रक्षा मंत्री ने BEL की AI नीति लॉन्च की और पुणे में AI उत्कृष्टता केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया, जो भारतीय हथियारों को AI से लैस करने पर केंद्रित है।
- अन्य अनावरण: उन्होंने माउंटेन फायर कंट्रोल रडार का अनावरण किया।

❑ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के बारे में:-

- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) भारत की एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (PSU) है, जो मुख्य रूप से रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाती है।
- यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और इसे भारत सरकार द्वारा 'नवरत्न' का दर्जा प्राप्त है।
- इसकी स्थापना 1954 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है।

10 'हैमर' (AASM HAMMER) मिसाइल

❑ चर्चा में क्यों?

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनकी फ्रांसीसी समकक्ष कैथरीन वाउटरिन के बीच बेंगलुरु में आयोजित छठे वार्षिक रक्षा संवाद की सह-अध्यक्षता के दौरान 10 वर्षों के लिए रक्षा सहयोग समझौते का नवीनीकरण किया, देश में फ्रांसीसी मूल की मिसाइलों के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और सेना अधिकारियों की पारस्परिक तैनाती के लिए एक समझौते की घोषणा की।

❑ समझौते के मुख्य बिंदु:-

- साझेदार: यह समझौता भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और फ्रांस की दिग्गज कंपनी सैफरान (Safran) इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के बीच हुआ है।
- उद्देश्य: इसका मुख्य लक्ष्य भारत में ही 'हैमर' (AASM HAMMER) मिसाइलों का निर्माण और विकास करना है।
- तकनीकी लाभ: यह केवल असेंबली तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें महत्वपूर्ण तकनीक का हस्तांतरण भी शामिल है, जिससे भविष्य में स्वदेशी मिसाइल तकनीक को मजबूती मिलेगी।

❑ 'हैमर' (HAMMER) मिसाइल की खासियत

- यह मिसाइल भारतीय वायु सेना की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है:
  - → सटीकता: यह एक 'प्रेसिजन गाइडेड' (सटीक निशाना लगाने वाली) मिसाइल है जिसे शुरू में राफेल (Rafale) विमानों के लिए लिया गया था।
  - → रेंज: यह लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के बंकरों और ठिकानों को तबाह कर सकती है।
  - → बहुमुखी उपयोग: इसे न केवल राफेल, बल्कि तेजस (LCA Tejas) जैसे अन्य लड़ाकू विमानों के साथ भी एकीकृत (Integrate) किया जा सकता है।

❑ रणनीतिक महत्व

- यह कदम न केवल भारत की वायु शक्ति को सशक्त बनाता है, बल्कि रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में फ्रांस के साथ हमारे गहरे भरोसे को भी दर्शाता है। इससे भविष्य में भारत के रक्षा निर्यात (Export) की संभावनाओं को भी बल मिलेगा।

11 खोर्रमशहर-4 (Khorramshahr-4)

❑ चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिका से बढ़ते तनावों के बीच ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) द्वारा अपनी नई लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 'खोर्रमशहर-4' को सैन्य अड्डे पर तैनात किए जाने से यह चर्चा में रहा।

- खोर्रमशहर-4 मिसाइल, जिसे 'खैबर' (Khaibar) के नाम से भी जाना जाता है, उनकी सबसे उन्नत और शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है। इसे मई 2023 में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया था।

❑ मिसाइल की मुख्य विशेषताएं और तकनीकी विवरण:

➲ मारक क्षमता और पेलोड

- दूरी (Range): इसकी मारक क्षमता लगभग 2,000 किलोमीटर है। यह दूरी इसे मध्य पूर्व के किसी भी लक्ष्य तक पहुँचने में सक्षम बनाती है।
- वारहेड (Warhead): यह 1,500 किलोग्राम तक का भारी विस्फोटक ले जा सकती है, जो इसे इरान की सबसे घातक मिसाइलों में से एक बनाता है।

➲ उन्नत तकनीकी खासियत

- ईंधन प्रणाली: यह तरल ईंधन (Liquid Fuel) का उपयोग करती है, लेकिन इसमें एक विशेष प्रकार का 'हाइपरगोलिक' (Hypergolic) ईंधन इस्तेमाल किया जाता है।
- त्वरित प्रहार: इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें ईंधन भरने के बाद इसे सालों तक स्टोर करके रखा जा सकता है। इससे युद्ध की स्थिति में इसे बहुत ही कम समय में लॉन्च किया जा सकता है।
- मिड-कोर्स सुधार: यह मिसाइल वायुमंडल के बाहर अपनी दिशा और गति को नियंत्रित करने के लिए इंजन का उपयोग कर सकती है, जिससे इसकी सटीकता (Accuracy) बढ़ जाती है।

➲ सुरक्षा प्रणालियों से बचाव

- इंटरसेप्शन से बचाव: खोर्रमशहर-4 की गति और वायुमंडल के बाहर पैंतरेबाज़ी (Maneuverability) करने की क्षमता इसे दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम (जैसे इजरायल के आयरन डोम या एरो सिस्टम) से बचने में मदद करती है।
- टर्मिनल फेज: लक्ष्य की ओर बढ़ते समय इसकी गति बहुत अधिक होती है, जिससे इसे ट्रैक करना और नष्ट करना कठिन हो जाता है।

12 भारतीय नौसेना द्वारा कैडेट प्रशिक्षण जहाज (CTS) 'कृष्णा' की लॉन्चिंग

भारतीय नौसेना ने 16 फरवरी 2026 को चेन्नई के कट्टुपल्ली स्थित एलएंडटी (L&T) शिपयार्ड में अपना पहला पूरी तरह से स्वदेश निर्मित और डिज़ाइन किया गया कैडेट प्रशिक्षण जहाज (CTS) 'कृष्णा' लॉन्च किया।

मुख्य बिंदु

- रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता'
  - → यह जहाज पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसका निर्माण L&T शिपयार्ड (कट्टुपल्ली, चेन्नई) में किया गया, जो निजी क्षेत्र की रक्षा विनिर्माण (Defense Manufacturing) में बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।
- विशिष्ट डिजाइन और क्षमता
  - → उद्देश्य: इसे मुख्य रूप से 'कैडेट प्रशिक्षण जहाज' (Cadet Training Ship - CTS) के रूप में तैयार किया गया है।
  - → प्रशिक्षण: यह जहाज भविष्य के नौसेना अधिकारियों को समुद्र में बुनियादी प्रशिक्षण, नेविगेशन और युद्ध कौशल सिखाने के लिए एक आधुनिक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा।
  - → सुविधाएं: इसमें प्रशिक्षुओं (Cadets) के लिए समर्पित कक्षाएं, अत्याधुनिक सिम्युलेटर और लंबे समुद्री अभियानों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा शामिल है।
- सामरिक महत्व
  - → स्वदेशी डिजाइन: वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो (Warship Design Bureau) द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया जाना भारत की इंजीनियरिंग विशेषज्ञता को प्रमाणित करता है।
  - → आयात पर निर्भरता में कमी: अब तक भारत को अक्सर प्रशिक्षण जहाजों के लिए अन्य प्लेटफार्मों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन 'कृष्णा' इस कमी को पूरा करेगा।
  - → निर्यात की संभावना: इस तरह के सफल प्रोजेक्ट्स से भारत भविष्य में अन्य मित्र देशों को भी ऐसे प्रशिक्षण जहाज निर्यात कर सकता है।
- नोट: भारतीय नौसेना के बेड़े में 'कृष्णा' नाम का पहले भी एक जहाज (INS Krishna - पूर्व HMS Andromeda) रहा है, जो एक ट्रेनिंग फ्रिगेट था। नए स्वदेशी 'कृष्णा' का लॉन्च होना उस विरासत को एक आधुनिक और मेड-इन-इंडिया स्वरूप में आगे बढ़ाना है।

13 मिलन 2026 (MILAN 2026)

भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित मिलन 2026 (MILAN 2026) अभ्यास विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ। यह इस अभ्यास का 13वां संस्करण था, जो अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बनकर उभरा है। यह अभ्यास मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच अंतर-संचालनीयता (interoperability), समुद्री सुरक्षा और आपसी तालमेल बढ़ाने पर केंद्रित है।

मुख्य बिंदु

- मेजबान:- भारतीय नौसेना (पूर्वी नौसेना कमान, विशाखापत्तनम)
- तिथि:- 15 से 25 फरवरी, 2026
- विषय (Theme):- 'सौहार्द (भाईचारा), सहयोग और सहभागिता' (Camaraderie, Cooperation, Collaboration)
- प्रतिभागी:- 70 से अधिक देश, 42 जहाज और पनडुब्बियां, तथा 29 विमान

- उद्घाटन:- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा
- भारतीय भागीदारी: स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत, 40 से अधिक जहाज और पनडुब्बियां शामिल।
- चरण: अभ्यास दो चरणों में आयोजित किया गया:
  - → हार्बर चरण (19-20 फरवरी): अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेमिनार, क्रॉस-डेक विज़िट, और सांस्कृतिक गतिविधियाँ।
  - → समुद्री चरण (21-25 फरवरी): बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी रोधी युद्ध (ASW), वायु रक्षा, और लाइव-फायरिंग अभ्यास।
  - → महत्व: यह भारत के 'सागर' (SAGAR - Security and Growth for All in the Region) विजन को आगे बढ़ाते हुए भारत को एक प्रमुख सुरक्षा भागीदार के रूप में स्थापित करता है।

❑ मिलन विलेज

- भारतीय नौसेना ने फरवरी 2026 में विशाखापत्तनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास 'मिलन 2026' के हिस्से के रूप में 'मिलन विलेज' का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु

- नौसेना का यह 'मिलन विलेज' ईएनसी सेलर्स इंस्टीट्यूट, विशाखापत्तनम में बनाया गया है।
- इसका उद्घाटन पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (FOC-in-C) वाइस एडमिरल संजय भल्ला द्वारा किया गया।
- नोट: मिलन अभ्यास 1995 में 4 देशों के साथ शुरू हुआ था और अब यह दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यासों में से एक बन गया।

14 DRDO ने गगनयान मिशन के ड्रोग पैराशूट का परीक्षण किया

भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए DRDO (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) ने हाल ही में (फरवरी 2026) को ड्रोग पैराशूट (Drogue Parachutes) का सफल 'क्वालिफिकेशन-लेवल लोड टेस्ट' पूरा किया है। यह परीक्षण चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी (TBRL) की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड (RTRS) सुविधा में आयोजित किया गया।

❑ परीक्षण की मुख्य विशेषताएं:

- अतिरिक्त सुरक्षा मार्जिन: इस परीक्षण में पैराशूट पर वास्तविक उड़ान के दौरान पड़ने वाले अधिकतम भार से भी अधिक भार (Qualification-level loads) डालकर इसकी मजबूती जांची गई।
- तकनीकी सहयोग: यह परीक्षण ISRO के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC) और DRDO की ADRDE (एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, आगरा) के संयुक्त प्रयासों से संपन्न हुआ।
- रिबन पैराशूट तकनीक: भारत ने इस मिशन के लिए उच्च शक्ति वाले 'रिबन पैराशूट' (High-strength ribbon parachutes) डिजाइन करने में अपनी महारत साबित की है।

❑ ड्रोग पैराशूट का महत्व:

- गगनयान के पूरे लैंडिंग सिस्टम में कुल 10 पैराशूट शामिल हैं। इनमें ड्रोग पैराशूट की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है:
  - → स्थिरता (Stabilization): अंतरिक्ष से वापस आते समय क्रू मॉड्यूल को हवा में स्थिर रखना।
  - → गति कम करना (Deceleration): मुख्य पैराशूट खुलने से पहले मॉड्यूल की गति को एक सुरक्षित स्तर तक नीचे लाना।

❑ गगनयान मिशन के बारे में

- यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसका उद्देश्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किमी. ऊँचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में 3 दिन के लिये भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है।
- इस मिशन में प्रमुख परीक्षण शामिल हैं जैसे कि इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट (IADT), पैड एबॉर्ट टेस्ट (PAT) और टेस्ट व्हीकल (TV) उड़ानें, जो मानवयुक्त मिशन से पहले सुरक्षा प्रणालियों की पुष्टि के लिये किये जाते हैं।
- इसमें पहले मानवरहित परीक्षण मिशन होंगे, जिसके बाद पहला मानवयुक्त मिशन लॉन्च किया जाएगा, जिसकी उम्मीद प्रारंभिक 2027 में है।

❑ DRDO के बारे में:-

- इसकी स्थापना 1958 में हुई।(रक्षा विज्ञान संगठन और अन्य तकनीकी संस्थानों के विलय से)
- इसका मुख्यालय डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली में स्थित है।
- इसका आदर्श वाक्य "बलस्य मूलं विज्ञानम्" (शक्ति का आधार विज्ञान) है।
- वर्तमान में डॉ. समीर वी. कामत इसके अध्यक्ष हैं।

15 आईएनएस अंजदीप (INS Anjadip)

❑ चर्चा में क्यों?

आईएनएस अंजदीप (INS Anjadip), जो एक अत्याधुनिक पनडुब्बी रोधी उथले जलयान (ASW-SWC) है, को 27 फरवरी 2026 को चेन्नई बंदरगाह पर पूर्वी नौसेना कमान में शामिल किया गया। इसे 'डॉल्फिन हंटर' के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें निष्क्रिय करना है। यह स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है।

मुख्य बिंदु

- श्रेणी: यह गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) द्वारा निर्मित एकीकृत पनडुब्बी रोधी उथले जलयान (ASW-SWC) परियोजना का एक हिस्सा है।
- क्षमता: यह लगभग 77 मीटर लंबा है और 1,400 टन विस्थापित करता है, जो तटीय क्षेत्रों (littoral zones) में काम करने में सक्षम है।
- हथियार: इसमें हल माउंटेड सोनार (Abhay), लाइटवेट टॉरपीडो और ASW रॉकेट जैसे आधुनिक सेंसर और हथियार शामिल हैं।

- महत्व: यह भारत के 'आत्मनिर्भर भारत' और रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- रणनीतिक भूमिका: इसे तटीय जल में पनडुब्बी रोधी अभियानों, कम तीव्रता वाले समुद्री कार्यों (LIMO) और खदान बिछाने की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है।
- नाम का इतिहास: इसका नाम कारवार के पास अंजदीप द्वीप के नाम पर रखा गया है, जिसने 1961 में 'ऑपरेशन विजय' (गोवा की मुक्ति) के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

16 भारत की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति, 'प्रहार' (PRAHAAR) का अनावरण

गृह मंत्रालय (MHA) ने 23 फरवरी 2026 को भारत की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति, 'प्रहार' (PRAHAAR) का अनावरण किया है। यह नीति भारत के आतंकवाद के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' (Zero Tolerance) के दृष्टिकोण को एक संस्थागत और रणनीतिक ढांचा प्रदान करती है। 'PRAHAAR' शब्द इसके सात मुख्य स्तंभों (Pillars) को दर्शाता है।

❑ प्रहार (PRAHAAR) के सात स्तंभ:

- P (Prevention): खुफिया जानकारी के आधार पर आतंकी हमलों की रोकथाम।
- R (Response): हमलों की स्थिति में त्वरित और आनुपातिक प्रतिक्रिया।
- A (Aggregation of Capacities): सुरक्षा एजेंसियों और संसाधनों की क्षमताओं का एकीकरण।
- H (Human Rights): मानवाधिकारों और कानून के शासन (Rule of Law) का पालन।
- A (Attenuation of Radicalisation): कट्टरपंथ को कम करना और युवाओं के पुनर्वास पर ध्यान देना।
- A (Aligning International Efforts): वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और संधियों को मजबूत करना।
- R (Recovery): समाज को आतंकी घटनाओं के प्रभाव से उबारने और लचीला बनाने (Resilience) पर जोर।

❑ इस नीति की प्रमुख विशेषताएं:

- हाइब्रिड खतरों से निपटना: यह नीति पारंपरिक आतंकवाद के साथ-साथ साइबर हमलों, ड्रोन आधारित खतरों, डार्क वेब और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए होने वाले टेरर फंडिंग जैसे आधुनिक खतरों पर भी ध्यान केंद्रित करती है।
- पूर्ण सरकार और पूर्ण समाज दृष्टिकोण: इसमें केवल सुरक्षा एजेंसियां ही नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को भी शामिल किया गया है।
- कानूनी सुदृढ़ता: जांच के हर स्तर (FIR से लेकर अभियोजन तक) पर कानूनी विशेषज्ञों को जोड़ने का प्रस्ताव है ताकि सजा की दर (Conviction Rate) बढ़ाई जा सके।
- शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance): आतंकवाद को किसी भी आधार पर उचित नहीं ठहराने और आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) को पूरी तरह नष्ट करने का लक्ष्य है।

17 'अग्नि वर्षा' (Agni Varsha)

भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने 24 फरवरी 2026 को राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 'अग्नि वर्षा' (Agni Varsha) नामक एक उच्च-तीव्रता वाला युद्धाभ्यास आयोजित किया। इस अभ्यास में टैंकों, ड्रोन और तोपखाने के माध्यम से रेगिस्तानी युद्ध क्षमता, आधुनिक तकनीक और स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन करते हुए परिचालन तत्परता को मजबूत किया गया।

मुख्य बिंदु

- उद्देश्य: कठिन थार मरुस्थल में शत्रु के ठिकानों पर सटीक हमले (Precision Strikes) और एकीकृत युद्ध क्षमता (Integrated Combat Power) का सत्यापन।
- प्रमुख हथियार: इसमें T-90 टैंक, K-9 वज्र होवित्जर, बोफोर्स तोपें, ALH और अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ-साथ निगरानी और स्ट्राइक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया।
- प्रदर्शन: भारतीय सेना ने अपनी युद्ध क्षमता को बढ़ाते हुए नेटवर्क-आधारित कमांड सिस्टम का उपयोग कर समन्वित हमले (Coordinated Attacks) किए।
- महत्व: यह अभ्यास पाकिस्तान सीमा के पास किया गया, जो भारत की तत्काल और त्वरित जवाबी कार्रवाई की शक्ति को दर्शाता है।
- तकनीकी फोकस: इस अभ्यास में आधुनिक ड्रोन और स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के एकीकरण पर जोर दिया गया।

18 सैन्य अभ्यास खंजर (Exercise KHANJAR) का 13वाँ संस्करण

भारत-किर्गिज़स्तान संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास 'खंजर' (Exercise KHANJAR) का 13वाँ संस्करण 4 से 17 फरवरी 2026 तक असम के मिसामारी मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया गया। यह द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास आतंकवाद-रोधी और शहरी युद्ध पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सामरिक समन्वय और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है।

मुख्य बिंदु

- पृष्ठभूमि: अभ्यास 'खंजर' की शुरुआत वर्ष 2011 में की गई थी और इसे प्रतिवर्ष भारत तथा किर्गिज़स्तान में क्रमशः आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के विशेष बलों के बीच पारस्परिक संचालन-क्षमता को सुदृढ़ करना है।
- भागीदार: भारतीय सेना की ओर से पैराशूट रेजिमेंट (विशेष बल) और किर्गिज़स्तान की ओर से इल्ब्रिस (Ilbris) विशेष बल ब्रिगेड इसमें भागीदारी करती है।
- प्रशिक्षण: आतंकवाद-रोधी और विशेष बल अभियानों में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान, शहरी तथा पर्वतीय भू-भाग में प्रशिक्षण, जिसमें स्नाइपिंग, भवनों में हस्तक्षेप तथा उच्च-ऊँचाई/पर्वतीय युद्धकौशल शामिल हैं।
- महत्त्व: यह रक्षा संबंधों को सुदृढ़ करता है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और अतिवाद से निपटने में सहयोग को बढ़ावा देता है तथा शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।

❑ किर्गिज़स्तान के बारे में -

- किर्गिज़स्तान मध्य एशिया का एक स्थलरुद्ध (Landlocked) देश है, जिसकी सीमाएँ कज़ाखस्तान, चीन, ताज़िकिस्तान और उज़्बेकिस्तान से लगती हैं।
- इसकी राजधानी बिश्केक और आधिकारिक मुद्रा किर्गिस्तानी सोम (Kyrgyzstani Som - KGS) है।
- यहां का 90% से अधिक भूभाग पर्वतीय है, जिसके कारण इसे "मध्य एशिया का स्विट्जरलैंड" भी कहा जाता है। यहां का सर्वोच्च "शिखर पोबेडी" (7,439 मीटर) है।
- किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण फरगाना घाटी साझा करता है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील मानी जाती है।
  - → फ़रगाना घाटी हाइड्रोकार्बन संसाधनों से समृद्ध है।
- उत्तर-पूर्वी तियानशान में स्थित इस्सिक-कुल झील , जिसे किर्गिज़ भाषा में यसिक-कोल कहते हैं , किर्गिस्तान की सबसे बड़ी झील है।
- किर्गिज़स्तान की प्रमुख नदी 'कारा दरिया' है, जो उज़्बेकिस्तान की सीमा पार कर 'किर्गिज़ और नारिन' नदियों से मिलती है। इन नदियों के संगम से सिर दरिया नदी बनती है, जो मूल रूप से अरल सागर में गिरती थी ।

19 अभ्यास 'वज्र प्रहार' (Vajra Prahar) 2026

❑ चर्चा में क्यों?

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास 'वज्र प्रहार' (Vajra Prahar) का 16 वाँ संस्करण 24 फरवरी, 2026 से हिमाचल प्रदेश के बकलोह स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल (SFTS) में शुरू हो गया है। यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास 16 मार्च 2026 तक चलेगा।

मुख्य बिंदु

- पृष्ठभूमि:पहली बार वर्ष 2010 में भारत में आयोजित यह अभ्यास बारी-बारी से भारत और अमेरिका में आयोजित किया जाता है। इसका पिछला संस्करण अमेरिका के इदाहो में आयोजित किया गया था।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य युद्ध रणनीतियों (Tactics), तकनीकी आदान-प्रदान और उन्नत विशेष अभियानों (Special Operations), के लिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर्संचालनीयता और संयुक्त परिचालन तत्परता को बढ़ाना है।
- प्रतिभागी: भारतीय सेना के विशेष बल के 45 जवान और अमेरिकी सेना के 'ग्रीन बेरेट्स' के 12 सैनिक शामिल हैं।
- महत्व: यह अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक और रक्षा सहयोग को मजबूत करता है।

❑ भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग

- भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग तेजी से एक रणनीतिक साझेदारी में बदल रहा है, जो मुख्य रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा, रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (जैसे GE F-414 इंजन), और 'मेक इन इंडिया' के तहत संयुक्त उत्पादन पर केंद्रित है।

➲ भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग के प्रमुख पहलू:

10-वर्षीय रक्षा ढांचा (10-Year Defense Framework)

→ हाल ही में भारत और अमेरिका ने 10 साल के नए रक्षा रोडमैप पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करने (Intelligence Sharing) और संयुक्त रक्षा उत्पादन के लिए अगले दशक की दिशा तय करता है।

महत्वपूर्ण रक्षा सौदे और 'मेक इन इंडिया'

→ GE F414 जेट इंजन: जनरल इलेक्ट्रिक (GE) और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के बीच F414 जेट इंजनों के सह-उत्पादन को लेकर समझौता महत्वपूर्ण चरण में है। इससे भारत लड़ाकू विमान इंजन बनाने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा।

→ MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन: भारत ने लगभग 32,000 करोड़ रुपये की लागत से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का सौदा अंतिम रूप दिया है। इनमें से 15 नौसेना को और बाकी वायुसेना व थल सेना को मिलेंगे। इनका रखरखाव और मरम्मत (MRO) भी भारत में ही होगा।

→ iCET पहल: 'क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी' (iCET) के तहत दोनों देश अंतरिक्ष, AI और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं।

सैन्य अभ्यास (Military Exercises)

दोनों देशों की सेनाएं अपनी अंतःक्रियाशीलता (Interoperability) बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास कर रही हैं:

→ वज्र प्रहार 2026: यह विशेष बलों (Special Forces) का अभ्यास मार्च 2026 में बकलोह, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया।

→ युद्ध अभ्यास 2025: इसका आयोजन अलास्का में किया गया था, जिसमें पर्वतीय और उप-आर्कटिक परिस्थितियों में प्रशिक्षण पर जोर दिया गया।

→ मालाबार अभ्यास: यह एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसमें क्वाड (Quad) के सदस्य देश शामिल होते हैं।

रणनीतिक और तकनीकी मंच

→ INDUS-X: यह मंच दोनों देशों के रक्षा स्टार्टअप्स को जोड़ने और नई तकनीकों के विकास के लिए एक 'इनोवेशन ब्रिज' का काम कर रहा है।

→ अंतरिक्ष सहयोग: मार्च 2026 में अमेरिकी स्पेस कमांड के प्रमुख ने भारत का दौरा किया, जो अंतरिक्ष सुरक्षा और उपग्रह निगरानी में बढ़ती साझेदारी को दर्शाता है।

मुख्य आधारभूत समझौते (Foundational Agreements)

भारत और अमेरिका ने चार प्रमुख रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं जो इस सहयोग की नींव हैं:

→ GSOMIA (2002): सैन्य खुफिया जानकारी की सुरक्षा के लिए।

→ LEMOA (2016): लॉजिस्टिक और रसद सहायता के लिए।
→ COMCASA (2018): सुरक्षित संचार और डेटा साझा करने के लिए।
→ BECA (2020): सटीक भू-स्थानिक (Geospatial) डेटा साझा करने के लिए।

20 वायु शक्ति 2026

भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति 2026 अभ्यास 27 फरवरी 2026 को राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज (जैसलमेर के पास) में सफलतापूर्वक आयोजित किया। यह भारतीय वायुसेना (IAF) की युद्धक क्षमता और मारक शक्ति का एक शानदार प्रदर्शन है। 'वायु शक्ति' अभ्यास हर तीन साल में एक बार आयोजित किया जाता है।

- थीम: "नभः स्पृशं दीप्तम्" (Touch the Sky with Glory) के आदर्श वाक्य के साथ वायु शक्ति का प्रदर्शन।

मुख्य बिंदु

- संयुक्त मारक क्षमता: इस अभ्यास में राफेल, सुखोई-30 MKI, तेजस, मिराज 2000 और मिग-29 जैसे लड़ाकू विमानों ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया।
- स्वदेशी ताकत: 'आत्मनिर्भर भारत' की झलक दिखाते हुए स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड और ध्रुव ने सटीक निशाना साधा।
- आकाश मिसाइल प्रणाली: सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों (SAM) जैसे 'आकाश' और 'समर' (SAMAR) ने हवा में आने वाले लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट करने का प्रदर्शन किया।
- चिनूक और अपाचे की भूमिका: भारी सामान ढोने वाले चिनूक हेलीकॉप्टरों ने तेजी से सैनिकों और हथियारों को तैनात करने की क्षमता दिखाई, जबकि अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने टैंक-रोधी मिसाइलों से प्रहार किया।

❑ रणनीतिक महत्व

- सटीक प्रहार (Precision Strikes): पोखरण की रेंज में सिम्युलेटेड (नकली) दुश्मन के ठिकानों, रडार साइटों और संचार केंद्रों पर गाइडेड बमों और मिसाइलों से हमला कर यह दिखाया गया कि IAF लंबी दूरी से भी पिन-पॉइंट सटीकता रखती है।
- नेटवर्क-केंद्रित युद्ध: यह अभ्यास केवल बमबारी तक सीमित नहीं है; इसमें AWACS (Netra और Phalcon) का उपयोग करके युद्ध क्षेत्र की पूरी निगरानी और वास्तविक समय में डेटा साझा करने का परीक्षण भी किया गया।
- रात का ऑपरेशन: 'वायु शक्ति' का एक बड़ा हिस्सा रात के अंधेरे में आयोजित किया जाता है, जो वायुसेना की 'आल वेदर' और '24x7' युद्ध लड़ने की क्षमता को प्रमाणित करता है।

21 रक्षा प्रौद्योगिकी (To The Point)

- भारतीय सेना और आईटीबीपी ने परिचालन समन्वय को बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल प्रदेश में छह दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास "अग्नि परीक्षा" का आयोजन किया।
- रक्षा मंत्रालय ने आयुध कारखाना बोर्ड के निगमीकरण के बाद गठित रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा देने की मंजूरी दी।
- हाल ही में भारत-किर्गिज़स्तान संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास खंजर (Exercise KHANJAR) का 13वाँ संस्करण असम के मिसामारी में आयोजित हुआ।
- भारतीय वायुसेना 27 फरवरी 2026 को राजस्थान के पोखरण एयर-टू-ग्राउंड रेंज में 'एक्सरसाइज वायुशक्ति-26' का आयोजन करेगी।
- हाल ही में पंजाब पुलिस ने वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए गैंगस्टरों के खिलाफ अभियान को और तेज करने के उद्देश्य से 'ऑपरेशन प्रहार' का दूसरा चरण शुरू किया।
- भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के महानिदेशक परमेश शिवमणि ने गोवा में वाटरजेट उत्पादन एवं परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया।
- साइबर क्षेत्र में सहयोग और रक्षा समझौतों के संदर्भ में तंजानिया पीपुल्स डिफेंस फोर्सेज (टीपीडीएफ) का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल फरवरी 2026 में तीन दिवसीय भारत दौरे पर रहा।
- भारतीय नौसेना ने फरवरी 2026 में विशाखापत्तनम में 'मिलन विलेज' का उद्घाटन किया।
  → यह उद्घाटन प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास 'मिलन 2026' (MILAN 2026) के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में किया गया।
- हाल ही में DRDO ने चंडीगढ़ में गगनयान कार्यक्रम के लिए ड्रोग पैराशूट (Drogue Parachute) का सफल योग्यता-स्तर भार परीक्षण (Qualification Level Load Test) संपन्न किया।
- हाल ही में जम्मू कश्मीर के किश्तवार में 'ऑपरेशन त्राशी-1' के तहत सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गए।
- 'डॉल्फिन हंटर' के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया युद्धपोत अंजदीप को 27 फरवरी 2026 को चेन्नई बंदरगाह पर पूर्वी नौसेना कमान में औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा।
- भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के सैनिकों के राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास 'अग्निवर्षा' को संचालित किया।
- 'सैय्यद-3 जी मिसाइल' ईरान द्वारा विकसित एक नौसैनिक सतह से हवा में मार करने वाली रक्षा मिसाइल है।
- भारत और जापान के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास 'धर्मा गार्जियन' का सातवां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में प्रारम्भ हुआ।
- भारतीय सेना की पश्चिमी कमान की प्रतिष्ठित 'खड़ग कोर' ने फरवरी 2026 में राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अपना विशाल सैन्य अभ्यास 'खड़ग शक्ति 2026' सफलतापूर्वक संपन्न किया।
- पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, ऑपरेशन गजब-लिल-हक के तहत काबुल सहित अन्य प्रांतों पर हवाई हमले किए।
- हाल ही में तेलंगना पुलिस द्वारा साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया गया।

विज्ञान प्रौद्योगिकी

01 स्टेम सेल थेरेपी

❑ चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी के नियमित या व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इसे अनैतिक, वैज्ञानिक रूप से अप्रमाणित और मरीजों के लिए खतरनाक बताया, क्योंकि इसकी सुरक्षा व प्रभावकारिता के ठोस प्रमाण नहीं हैं। WHO और ISSCR गाइडलाइंस के अनुरूप, इसे केवल स्वीकृत क्लिनिकल ट्रायल्स तक सीमित रखा गया है।

❑ मुख्य कारण :-

- वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी: वर्तमान में ऐसे कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण या क्लीनिकल डेटा मौजूद नहीं है जो यह साबित कर सके कि स्टेम सेल थेरेपी से ऑटिज़्म का प्रभावी इलाज संभव है।
- सुरक्षा की चिंता: इस थेरेपी के दीर्घकालिक दुष्प्रभावों और सुरक्षा को लेकर विशेषज्ञों ने गंभीर चिंताएँ जताई हैं।
- अनैतिक मार्केटिंग: कोर्ट ने पाया कि कई क्लीनिक इस थेरेपी को "चमत्कारी इलाज" के रूप में प्रचारित कर रहे थे, जिससे बच्चों के माता-पिता को झूठी उम्मीद दी जा रही थी और उनसे भारी रकम वसूली जा रही थी।

❑ स्टेम सेल थेरेपी (Stem Cell Therapy) क्या है?

- स्टेम सेल थेरेपी (Stem Cell Therapy) आधुनिक चिकित्सा की वह तकनीक है जिसमें शरीर की खराब या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को बदलने या उनकी मरम्मत करने के लिए स्टेम सेल्स का उपयोग किया जाता है। इसे अक्सर 'रीजेनरेटिव मेडिसिन' (पुनर्योजी चिकित्सा) भी कहा जाता है।
- हमारे शरीर में स्टेम सेल 'कच्चे माल' की तरह होते हैं। इनकी दो खास खूबियां इन्हें खास बनाती हैं:
  - → विभाजन: ये खुद को बार-बार विभाजित कर नई कोशिकाएं बना सकते हैं।
  - → परिवर्तन: ये शरीर की किसी भी विशिष्ट कोशिका (जैसे रक्त कोशिका, मस्तिष्क कोशिका, हृदय कोशिका या हड्डी की कोशिका) का रूप ले सकते हैं।

❑ यह थेरेपी कैसे काम करती है?

जब शरीर का कोई अंग या ऊतक (tissue) क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो डॉक्टर प्रयोगशाला में स्टेम सेल्स को खास कोशिकाओं में बदलने के लिए तैयार करते हैं। फिर इन्हें मरीज के शरीर में प्रत्यारोपित (transplant) कर दिया जाता है।

❑ स्टेम सेल के मुख्य स्रोत -

- भ्रूण स्टेम सेल (Embryonic Stem Cells): ये बहुत शुरुआती अवस्था के भ्रूण से लिए जाते हैं और शरीर की किसी भी कोशिका में बदल सकते हैं।
- वयस्क स्टेम सेल (Adult Stem Cells): ये हमारे अस्थि मज्जा (Bone Marrow) या वसा (Fat) में पाए जाते हैं।
- पेरिनाटल स्टेम सेल (Perinatal Stem Cells): ये बच्चे के जन्म के समय गर्भनाल (Umbilical Cord) के रक्त से मिलते हैं।

❑ किन बीमारियों में इसका उपयोग होता है?

अभी बहुत सी बीमारियों पर शोध चल रहा है, लेकिन मुख्य रूप से इनका उपयोग यहाँ होता है:

- कैंसर: विशेषकर ब्लड कैंसर (ल्यूकेमिया)।
- अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण: बोन मैरो ट्रांसप्लांट।
- हड्डियों की समस्या: खराब जोड़ों या रीढ़ की हड्डी के इलाज में।
- टाइप 1 डायबिटीज और पार्किंसंस: इन पर अभी बड़े स्तर पर रिसर्च जारी है।

❑ ऑटिज़्म क्या है?

ऑटिज़्म (Autism), जिसे वैज्ञानिक भाषा में ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) कहा जाता है, कोई बीमारी नहीं बल्कि मस्तिष्क के विकास में होने वाला एक अंतर है। यह व्यक्ति के बातचीत करने, दूसरों से जुड़ने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करता है।

नोट: स्टेम सेल थेरेपी के कई उपचार अभी भी प्रायोगिक (experimental) चरण में हैं। किसी भी क्लिनिक पर भरोसा करने से पहले उसकी वैज्ञानिक मान्यता की जांच जरूर करनी चाहिए।

02 सौर चक्र (Solar Cycles)

❑ चर्चा में क्यों?

IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक ऐसा गणितीय मॉडल विकसित किया है जो सौर चक्रों (Solar Cycles) की भविष्यवाणी करने में पहले के मॉडलों की तुलना में कहीं अधिक सटीक है।

❑ IIT कानपुर द्वारा विकसित मॉडल के बारे में -

प्रोफेसर महेंद्र वर्मा और उनकी टीम द्वारा विकसित यह मॉडल 'डाइनमो थ्योरी' (Dynamo Theory) पर आधारित है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं:

- सटीकता: यह मॉडल सूर्य के आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र के डेटा का उपयोग करता है ताकि यह बताया जा सके कि अगला चक्र कितना शक्तिशाली होगा।
- अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी: इसकी मदद से हम अंतरिक्ष में होने वाले तूफानों का पहले से अनुमान लगा सकते हैं, जिससे हमारे जीपीएस (GPS) और संचार प्रणालियों को सुरक्षित रखा जा सके।

❑ सौर चक्र क्या है?

सूर्य की चुंबकीय गतिविधि हर 11 साल में बदलती है। इस दौरान सूर्य पर सनस्पॉट (Sunspots) की संख्या बढ़ती और घटती है। जब यह गतिविधि चरम पर होती है, तो इसे 'सोलर मैक्सिमम' कहा जाता है, जिससे पृथ्वी पर उपग्रह (Satellites) और पावर ग्रिड प्रभावित हो सकते हैं।

❑ महत्त्व:-

अबतक सौर चक्रों की भविष्यवाणी करना काफी कठिन रहा है क्योंकि सूर्य की कार्यप्रणाली बहुत जटिल है। भारतीय शोधकर्ताओं का यह मॉडल न केवल भारत के आदित्य-L1 (Aditya-L1) मिशन के लिए मददगार साबित हो सकता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष विज्ञान में एक नया मानक स्थापित करता है।

03 LNG और डीजल-आधारित दोहरी-ईंधन वाली 1400 HP DEMU ट्रेन का सफल परीक्षण

पश्चिमी रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन ने भारत की पहली लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) और डीजल-आधारित दोहरी-ईंधन (Dual-Fuel) वाली 1400 HP DEMU ट्रेन का सफल परीक्षण पूरा कर लिया है।

❑ कार्य प्रणाली :-

यह एक Dual-Fuel प्रणाली है। इसका मतलब है कि इंजन मुख्य रूप से LNG (तरल प्राकृतिक गैस) का उपयोग करता है, जबकि डीजल का उपयोग केवल इग्निशन (दहन शुरू करने) और इंजन की स्थिरता बनाए रखने के लिए किया जाता है।

❑ मुख्य लाभ :-

- पर्यावरण अनुकूल: डीजल के मुकाबले LNG जलने पर बहुत कम कार्बन उत्सर्जन (CO_2), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) और पार्टिकुलेट मैटर छोड़ती है।
- लागत में कमी: LNG आमतौर पर डीजल की तुलना में सस्ती होती है, जिससे रेलवे के परिचालन खर्च में भारी बचत होगी।
- ऊर्जा दक्षता: LNG की ऊर्जा घनत्व अधिक होती है, जो इंजन को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करती है।

❑ भविष्य की राह :-

भारत ने 2030 तक 'नेट जीरो कार्बन एमिटर' (शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक) बनने का लक्ष्य रखा है। यह परीक्षण उस दिशा में एक बड़ा प्रोत्साहन है क्योंकि:

- यह पुरानी डीजल ट्रेनों को 'ग्रीन' ट्रेनों में बदलने का रास्ता खोलता है।
- इससे आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी।

04 हेवन-1 (Haven-1)

❑ चर्चा में क्यों?

वास्ट (Vast) स्पेस द्वारा विकसित हेवन-1 (Haven-1) दुनिया का पहला वाणिज्यिक (निजी) अंतरिक्ष स्टेशन है, जिसे 2027 की शुरुआत में स्पेसएक्स (SpaceX) के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। यह कैलिफोर्निया स्थित कंपनी द्वारा निर्मित एक छोटा, मानव-केंद्रित स्टेशन है, जिसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष पर्यटन के लिए किया जाएगा।

मुख्य बिंदु

- इसे कैलिफोर्निया स्थित एयरोस्पेस कंपनी वास्ट (Vast) द्वारा विकसित और निर्मित किया जा रहा है।
- वर्तमान योजना के अनुसार, इसे 2027 की पहली तिमाही (Q1 2027) में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले इसे 2025-26 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन तकनीकी एकीकरण और परीक्षणों के कारण इसमें थोड़ा बदलाव हुआ है।
- इसे स्पेसएक्स (SpaceX) के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए कक्षा में भेजा जाएगा।
- यह एक "सिंगल-मॉड्यूल" स्टेशन है, जिसमें एक बार में 4 अंतरिक्ष यात्री लगभग 30 दिनों तक रह सकेंगे।
- इस स्टेशन की एक बड़ी खूबी यह है कि यह अंतरिक्ष में घूमकर (Rotation) चंद्रमा जैसा गुरुत्वाकर्षण पैदा करने का परीक्षण करेगा।
- स्टेशन के परीक्षण NASA की तकनीकी सलाह के साथ, उनके "कमर्शियल लो अर्थ ऑर्बिट डेवलपमेंट" (CLD) प्रोग्राम के तहत किए जा रहे हैं।

❑ मिशन का उद्देश्य :-

जब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) 2030 तक रिटायर हो जाएगा, तब हेवन-1 जैसे निजी स्टेशन वैज्ञानिक अनुसंधान, विनिर्माण और अंतरिक्ष पर्यटन के लिए एक किफायती विकल्प प्रदान करेंगे। हेवन-1, वास्ट के बड़े लक्ष्य 'हेवन-2' की दिशा में पहला कदम है, जो आकार में और भी बड़ा होगा।

नोट:- वास्ट कंपनी के पीछे जेड मैककलेब (Jed McCaleb) का हाथ है, और वे इसे पूरी तरह से निजी निवेश से बना रहे हैं। यह स्टेशन पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने के बजाय शुरुआती दौर में SpaceX Dragon कैप्सूल पर निर्भर रहेगा (जैसे कि बिजली और लाइफ सपोर्ट के कुछ हिस्सों के लिए)।

05 फुट एंड माउथ रोग (FMD)

❑ चर्चा में क्यों?

दक्षिण अफ्रीका ने 20 वर्षों में पहली बार स्थानीय स्तर पर निर्मित फुट-एंड-माउथ डिजीज (FMD) वैक्सीन पेश की है, जिसका उद्देश्य देश के सबसे गंभीर प्रकोप से निपटना और टीकों के लिए आयात पर निर्भरता कम करना है।

मुख्य बिंदु

- यह वैक्सीन सरकारी एजेंसी एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल (ARC) द्वारा विकसित की गई है।
- इसका उद्देश्य देश के लगभग 1.2 करोड़ मवेशियों के 80% हिस्से को टीका लगाकर "वैक्सीन संप्रभुता" (vaccine sovereignty) प्राप्त करना है।
- दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में फुट-एंड-माउथ बीमारी के प्रकोप के कारण आपदा की स्थिति घोषित की थी।
- इससे पहले, दक्षिण अफ्रीका बोत्सवाना, अर्जेंटीना और तुर्की से टीके आयात कर रहा था।

❑ फुट एंड माउथ रोग के बारे में:-

फुट एंड माउथ रोग (FMD) या खुरपका-मुँहपका एक अत्यंत संक्रामक विषाणुजनित बीमारी है जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर जैसे दो खुर वाले पशुओं को प्रभावित करती है। यह एफएमडी वायरस (FMDV) द्वारा होती है।

❑ मुख्य विवरण:

- लक्षण: पशुओं को तेज बुखार (104-106°F), मुंह, जीभ, मसूड़ों और खुरों के बीच छाले होना, लंगड़ापन, दूध उत्पादन में अत्यधिक कमी और जुगाली न करना।
- प्रसार: यह वायरस संक्रमित पशुओं के सीधे संपर्क, लार, दूध, मूत्र, गोबर, या दूषित चारे से फैलता है।
- आर्थिक प्रभाव: इससे पशुओं की दुग्ध क्षमता और कार्यक्षमता कम हो जाती है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाता है।
- बचाव: सबसे अच्छा उपाय नियमित टीकाकरण है। संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग करना, चारे-पानी के बर्तनों को कीटाणुरहित करना, और संक्रमित फार्म में आने-जाने पर रोक लगाना आवश्यक है।
- उपचार: कोई विशिष्ट एंटीवायरल इलाज नहीं है, केवल छालों की सफाई और लक्षणों के आधार पर सहायक उपचार (एंटीबायोटिक्स) किया जाता है।

नोट: यह पशुओं का रोग है और मनुष्यों में होने वाले 'हाथ, पैर और मुंह के रोग' (HFMD) से बिल्कुल अलग है।

06 वी. ओ. चिदंबरनार बंदरगाह(VOC): उन्नत एंटी-ड्रोन सिस्टम वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह

तमिलनाडु स्थित वी. ओ. चिदंबरनार (VOC) बंदरगाह प्राधिकरण (थूथुकुडी) उन्नत एंटी-ड्रोन (ड्रोन-रोधी) सुरक्षा प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (CEL) के साथ साझेदारी में, यह 360-डिग्री रडार-आधारित प्रणाली 5 किलोमीटर के दायरे में संदिग्ध ड्रोन्स का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम है, जो समुद्री सुरक्षा को मजबूत करती है।

❑ प्रणाली की मुख्य विशेषताएं और क्षमताएं:-

- एकीकृत तकनीक: यह प्रणाली रडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) आधारित तकनीक का उपयोग करती है, जो बंदरगाह जैसे जटिल वातावरण के लिए विशेष रूप से बनाई गई है।
- 360-डिग्री कवरेज: यह सिस्टम चारों दिशाओं (Omnidirectional) में नज़र रखने और 360-डिग्री सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है।
- प्रभावी सीमा (Range): यह 5 किलोमीटर की दूरी तक अनाधिकृत ड्रोन का पता लगा सकता है, उन्हें ट्रैक कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें निष्क्रिय कर सकता है।
- दृष्टिकोण: यह पहल 'अमृत काल विजन 2047' और 'समुद्री भारत विजन 2030' के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य राष्ट्रीय सुरक्षा और तटीय रक्षा को मजबूत करना है।
- प्रमुख घटक: इसमें ड्रोन डिटेक्टर, डिटेक्शन रडार और 'मैन-पैक जैमर' (Man-pack Jammer) शामिल हैं, जिससे यह एक पूर्ण सुरक्षा समाधान बनता है।
- सुरक्षा का उद्देश्य: इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य बंदरगाह की महत्वपूर्ण बुनियादी संरचना, रणनीतिक संपत्तियों और कर्मियों को संभावित हवाई खतरों और जासूसी से बचाना है।

❑ वी. ओ. चिदंबरनार बंदरगाह के बारे में :-

- पुराना नाम: इसे पहले तूतीकोरिन पोर्ट के नाम से जाना जाता था (2011 में स्वतंत्रता सेनानी वी. ओ. चिदंबरनार के नाम पर बदला गया)।
- महत्व: यह भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है और मन्नार की खाड़ी में रणनीतिक रूप से स्थित है।
- ग्रीन हाइड्रोजन: सितंबर 2025 में, इसी बंदरगाह पर भारत की पहली बंदरगाह-आधारित 'ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना' की भी शुरुआत हुई थी।

07 भारत-नीदरलैंड हाइड्रोजन फैलोशिप कार्यक्रम

❑ चर्चा में क्यों?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने नीदरलैंड के साथ मिलकर भारत-नीदरलैंड हाइड्रोजन फैलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य शोधकर्ताओं को नीदरलैंड्स के उन्नत हाइड्रोजन इकोसिस्टम में प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह पहल भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और नेट-जीरो 2070 के लक्ष्यों के तहत स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान, क्षमता निर्माण और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देगी।

मुख्य बिंदु

- प्रमुख उद्देश्य: भारतीय डॉक्टरेट, पोस्टडॉक्टोरल और संकाय सदस्यों को नीदरलैंड के उन्नत तकनीकी ज्ञान का लाभ उठाकर हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के स्वदेशीकरण में सक्षम बनाना है।
- साझेदारी और सहयोग: ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय और 19 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs) के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत संयुक्त शोध और छात्र-संकाय विनिमय किया जाएगा।
- फैलोशिप के अंतर्गत शोधकर्ता निम्नलिखित विषयों पर ध्यान केंद्रित करेंगे:
  - → इलेक्ट्रोलाइजर तकनीक: पानी से हाइड्रोजन अलग करने की प्रक्रिया में सुधार।
  - → भंडारण और परिवहन: हाइड्रोजन को सुरक्षित रूप से स्टोर करना और लंबी दूरी तक पहुँचाना।
  - → लागत में कमी: ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को किफायती बनाना ताकि यह जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuels) का मुकाबला कर सके।
- रणनीतिक महत्व:
  - → नेट जीरो लक्ष्य: यह पहल भारत के 2070 तक 'नेट जीरो' उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी।
  - → औद्योगिक नवाचार: नीदरलैंड्स यूरोप में हाइड्रोजन हब के रूप में उभर रहा है, जिसका लाभ भारतीय शोधकर्ताओं को मिलेगा।

08 'पर्पल ब्लिस' (Purple Bliss) टमाटर

❑ चर्चा में क्यों?

ऑस्ट्रेलियाई नियामक (OGTR) ने हाल ही में आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) 'पर्पल ब्लिस' (Purple Bliss) टमाटरों की देश में

व्यावसायिक खेती और ताजा बिक्री को मंजूरी दे दी है। स्नैपड्रैगन के जीन से बने ये उच्च-एंटीऑक्सीडेंट बैंगनी टमाटर 2026 के अंत तक दुकानों में आ सकते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में बिक्री के लिए स्वीकृत पहली ताजी GM फसल है।

❑ क्या है 'पर्पल ब्लिस'?

- ये टमाटर बाहर और अंदर (गूदे) दोनों तरफ से गहरे बैंगनी रंग के होते हैं। आम तौर पर मिलने वाले बैंगनी टमाटरों (जैसे 'इंडिगो रोज़') का केवल छिलका बैंगनी होता है, लेकिन पर्पल ब्लिस अंदर से भी पूरी तरह बैंगनी है।
- इन्हें सामान्य चेरी टमाटरों की तुलना में अधिक मीठा और रसीला बताया गया है।
- इनमें एंथोसायनिन (Anthocyanin) की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो कि वही एंटीऑक्सीडेंट है जो ब्लूबेरी और ब्लैकबेरी में पाया जाता है।

❑ किसने विकसित किया ?

इन टमाटरों को नॉरफ़ॉक हेल्दी प्रोड्यूस (Norfolk Healthy Produce) द्वारा विकसित किया गया है। वैज्ञानिकों ने इसमें स्नैपड्रैगन (Snapdragon) फूल के दो जीन डाले हैं, जो टमाटर को पकने के साथ-साथ यह गहरा बैंगनी रंग और उच्च एंटीऑक्सीडेंट गुण प्रदान करते हैं।

❑ नियामक मंजूरी और सुरक्षा

- OGTR (Office of the Gene Technology Regulator): इन्होंने लाइसेंस (DIR 218) जारी करते हुए कहा है कि ये टमाटर पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए नगण्य (Negligible) जोखिम पैदा करते हैं।
- FSANZ (Food Standards Australia New Zealand): इन्होंने पुष्टि की है कि ये टमाटर खाने के लिए उतने ही सुरक्षित हैं जितने कि पारंपरिक टमाटर।
- लेबलिंग: नियमों के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया में बेचे जाने वाले इन टमाटरों पर स्पष्ट रूप से "Genetically Modified" लिखा होना अनिवार्य होगा ताकि उपभोक्ता सोच-समझकर चुनाव कर सकें।

उम्मीद है कि 2026 के अंत तक ये टमाटर ऑस्ट्रेलिया के चुनिंदा बाजारों और सुपरमार्केट्स में मिलने शुरू हो जाएंगे। इनका वितरण 'ऑल ऑसी फार्मर्स' (All Aussie Farmers) द्वारा किया जाएगा।

09 AI हेल्थकेयर इकोसिस्टम "I Live Connect"

❑ चर्चा में क्यों?

भारत ने फरवरी 2026 में 'iLive Connect' नाम से दुनिया का पहला डॉक्टर-नेतृत्व वाला AI हेल्थकेयर इकोसिस्टम लॉन्च किया है। यह डॉ. विवेका कुमार द्वारा विकसित एक अभिनव प्रणाली है, जो अस्पताल की सुविधाओं को सीधे मरीज के घर तक पहुँचाता है।

❑ iLive Connect की मुख्य विशेषताएं:-

- 24/7 रियल-टाइम मॉनिटरिंग: यह सिस्टम मरीजों की चौबीसों घंटे निगरानी करता है। इसमें एक छोटा वायरलेस बायोसेंसर पैच और रिस्टबैंड शामिल है, जो मरीज के शरीर से जुड़े रहते हैं।
- डॉक्टरों का नेतृत्व: अन्य फिटनेस ट्रैकर के विपरीत, यहाँ डेटा केवल एल्गोरिदम द्वारा नहीं, बल्कि एक सेंट्रल मेडिकल कमांड सेंटर में बैठे विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मॉनिटर किया जाता है।
- महत्वपूर्ण मापदंडों की ट्रैकिंग: यह टू-लीड ECG, हृदय गति (Heart Rate), ऑक्सीजन लेवल (SpO2), श्वसन दर, तापमान और रक्तचाप के रुझानों को ट्रैक करता है।
- भविष्यवाणी विश्लेषण (Predictive Analytics): AI की मदद से यह सिस्टम बीमारी के लक्षण दिखने से पहले ही शरीर में होने वाले सूक्ष्म बदलावों को पहचान लेता है और डॉक्टरों को अलर्ट भेजता है।
- अस्पताल में भर्ती होने की दर में कमी: एक शुरुआती अध्ययन के अनुसार, इस तकनीक के उपयोग से मरीजों के दोबारा अस्पताल में भर्ती होने की दर में 76% तक की कमी देखी गई है।

❑ लाभ:-

- यह विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, अकेले रहने वाले लोगों, और हृदय रोग या मधुमेह जैसी पुरानी बीमारियों (Chronic diseases) से जूझ रहे मरीजों के लिए डिज़ाइन किया गया है।

10 चंद्रयान-4 के लिए सुरक्षित लैंडिंग साइट

ISRO ने चंद्रयान-4 के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 'मॉन्स माउटन' (Mons Mouton) के पास 'MM-4' नामक एक सुरक्षित लैंडिंग साइट खोजी है। यह क्षेत्र 84° दक्षिण अक्षांश के पास है, जहाँ 5° से कम ढलान, पर्याप्त सूर्यप्रकाश और कम खतरों के कारण यह लैंडिंग के लिए सबसे उपयुक्त है।

❑ चंद्रयान-4 की लैंडिंग साइट (MM-4) की मुख्य विशेषताएं:

- स्थान: मॉन्स माउटन (Mons Mouton) क्षेत्र, जो दक्षिणी ध्रुव के पास एक ऊंचा पठारी इलाका है।
- सुरक्षा कारक: यह क्षेत्र कम ढलान, न्यूनतम चट्टानों (0.3 मीटर से छोटी) और बेहतर लैंडिंग ग्रिडों के कारण बेहद सुरक्षित है।
- वैज्ञानिक महत्व: यह साइट स्थायी रूप से छायादार क्रेटर्स के निकट है, जहाँ पानी की बर्फ मौजूद होने की उच्च संभावना है।
- अनुसंधान: यहां 3.7 अरब वर्ष से भी अधिक पुरानी सामग्री होने की उम्मीद है।
- लांच: चंद्रयान-4 (CH-4) का उद्देश्य चंद्रमा की सतह से मिट्टी और पत्थरों के नमूने वापस लाना है, जिसे 2028 तक लॉन्च करने की योजना है।

यह चयन चंद्रयान-2 ऑर्बिटर से प्राप्त हाई-रेजोल्यूशन चित्रों के गहन विश्लेषण के बाद किया गया है।

❑ भारत के चंद्रयान (Chandrayaan) के बारे में-

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का एक बेहद महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना और भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को दुनिया के सामने प्रदर्शित करना है। भारत ने अब तक तीन मुख्य चंद्रयान मिशन भेजे हैं:

➲ **चंद्रयान-1 (2008): जल की खोज**

- यह भारत का पहला मून मिशन था। इसने चंद्रमा के चक्कर लगाए लेकिन उसकी सतह पर उतरा नहीं।

- इसने चंद्रमा पर बर्फ (पानी के अणुओं) की खोज की, जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक क्रांतिकारी खोज थी।
- भारत चंद्रमा पर अपना झंडा (MIP) भेजने वाला चौथा देश बना।

➲ **चंद्रयान-2 (2019): एक आंशिक सफलता**

- इस मिशन में एक ऑर्बिटर, लैंडर (विक्रम) और रोवर (प्रज्ञान) शामिल थे।
- लैंडिंग के अंतिम क्षणों में तकनीकी खराबी के कारण 'विक्रम' लैंडर की क्रैश लैंडिंग हो गई।
- इसका ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा की कक्षा में काम कर रहा है और हाई-रेसोल्यूशन तस्वीरें भेज रहा है।

➲ **चंद्रयान-3 (2023): ऐतिहासिक सफलता**

- 23 अगस्त, 2023 को भारत ने वह कर दिखाया जो कोई और देश नहीं कर पाया था।
- भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना।
- प्रज्ञान रोवर ने सतह पर सल्फर और अन्य खनिजों की उपस्थिति की पुष्टि की।
- जिस स्थान पर लैंडर उतरा, उसे 'शिव शक्ति पॉइंट' नाम दिया गया।

11 "लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर (LSDs) पर शोध के लिए देश का पहला समर्पित बायोबैंक स्थापित"

भारत ने फरवरी 2026 में अहमदाबाद, गुजरात में फाउंडेशन फॉर रिसर्च इन जेनेटिक्स एंड एंडोक्रिनोलॉजी (FRIGE) में अपना पहला समर्पित नेशनल बायोबैंक for Lysosomal Storage Disorders (LSDs) (लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर) लॉन्च किया है।

मुख्य बिंदु

- Department of Biotechnology (DBT) द्वारा वित्तपोषित यह केंद्र 15 राज्यों के 530 मरीजों के डेटा और नमूनों को संग्रहित कर दुर्लभ बीमारियों के त्वरित निदान और उपचार विकसित करने का कार्य करेगा।
- यह केंद्र 8 LSD उपसमूहों के अंतर्गत 27 प्रकार के विकारों को कवर करता है, जिसमें गौचर रोग (Gaucher), टे-सैक्स (Tay-Sachs), म्यूकोलिपिडोसिस II/III, और मोरक्वियो-ए (Morquio-A) आदि प्रमुख हैं।

❑ भारत के लिए बायोबैंक का महत्व -

- अनुवांशिक डेटा का केंद्र: भारत में अनुवांशिक विविधता बहुत अधिक है। यह बायोबैंक भारतीय आबादी के विशिष्ट डेटा और जैविक नमूनों (जैसे रक्त, ऊतक, डीएनए) को सुरक्षित रखेगा।
- सटीक निदान (Precision Diagnosis): दुर्लभ बीमारियों का पता लगाने में अक्सर वर्षों लग जाते हैं। इस डेटाबेस की मदद से डॉक्टर और वैज्ञानिक बीमारियों को जल्दी और अधिक सटीक रूप से पहचान सकेंगे।
- स्वदेशी उपचार का विकास: वर्तमान में, LSDs के लिए एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी (ERT) अविश्वसनीय रूप से महंगी है। स्थानीय डेटा होने से भारतीय शोधकर्ता सस्ती, स्वदेशी दवाएं और जीन थेरेपी विकसित कर पाएंगे।
- क्लिनिकल ट्रायल में तेजी: शोधकर्ताओं को अब नमूनों के लिए विदेश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे नई दवाओं का परीक्षण और विकास तेज हो जाएगा।

चूंकि ये बीमारियां बहुत दुर्लभ हैं, इसलिए इनका डेटा जुटाना मुश्किल होता है। एक समर्पित 'बायोबैंक' होने का मतलब है कि अब एक दुर्लभ मामले से मिली जानकारी का उपयोग पूरे देश के मरीजों के इलाज के लिए किया जा सकता है।

12 इंडिया AI स्टैक

❑ चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने इंडिया AI स्टैक को AI को लोकतांत्रिक बनाने और स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, शासन जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए लॉन्च किया है। यह एक एकीकृत पाँच-लेयर ढांचा है जो AI को विश्वसनीय, किफायती और समावेशी बनाता है।

❑ स्टैक के मुख्य पांच लेयर

- एप्लीकेशन लेयर: स्वास्थ्य निदान, कृषि सलाह, भाषा अनुवाद जैसी सेवाएँ प्रदान करती है।
- AI मॉडल लेयर: इंडियाAI मिशन, भारतजेन, भाषिणी और इंडियाAI कोष के तहत भारतीय भाषाओं और प्राथमिकताओं पर आधारित मॉडल विकसित हो रहे हैं।
- कंप्यूटिंग लेयर: इंडियाAI कंप्यूट पोर्टल के जरिए सब्सिडी वाले GPU/TPU, राष्ट्रीय GPU क्लस्टर और सुपरकंप्यूटर उपलब्ध।
- डेटा सेंटर और नेटवर्क लेयर: 5G कवरेज, ऑप्टिकल फाइबर और डेटा सेंटरों (मुंबई, बेंगलुरु) पर आधारित।
- एनर्जी लेयर: 500+ GW क्षमता, 51% गैर-जीवाश्म ऊर्जा से समर्थित।

❑ महत्त्व:

- यह स्टैक समावेशी, सॉवरेन और किफायती AI को सक्षम बनाकर 'मानवता के लिये AI' को बढ़ावा देता है। यह विदेशी मॉडल और कंप्यूट पर निर्भरता कम करता है, साथ ही AI के विकास को स्थिरता, आत्मनिर्भरता और जन कल्याण के अनुरूप बनाता है।

नोट: यह स्टैक 'इंडिया स्टैक' (Aadhaar, UPI, DigiLocker) की अगली कड़ी है, जिसने वित्तीय समावेशन में क्रांति लाई थी। अब AI स्टैक का लक्ष्य 'बुद्धि का समावेशन' (Inclusion of Intelligence) करना है।

13 अंटार्कटिका में टेली-रोबोटिक (Tele-robotic) अल्ट्रासाउंड का सफल परीक्षण

अंटार्कटिका के 'मैत्री' (Maitri) स्टेशन पर मौजूद एक व्यक्ति का अल्ट्रासाउंड भारत (दिल्ली) में बैठे डॉक्टरों द्वारा नियंत्रित एक रोबोटिक आर्म के माध्यम से किया गया। यह दुनिया का पहला ऐसा मामला है जहाँ इतनी लंबी दूरी (लगभग 12,000 किलोमीटर) से अंटार्कटिका में इस तरह का जटिल मेडिकल प्रोसीजर पूरा किया गया। यह भारत के लिए वैज्ञानिक और चिकित्सा क्षेत्र में एक युगांतकारी उपलब्धि है।

मुख्य बिंदु

- यह सफलता एम्स (AIIMS), नई दिल्ली और IIT दिल्ली के साझा प्रयासों का परिणाम है।
  - → AIIMS: यहाँ के डॉक्टरों ने दिल्ली से रोबोटिक सिस्टम को दिशा-निर्देश दिए।
  - → IIT दिल्ली: संस्थान ने इस रिमोट-कंट्रोल्ड अल्ट्रासाउंड तकनीक और रोबोटिक आर्म को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - → NCPOR: नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ने अंटार्कटिका में रसद और तकनीकी सहायता प्रदान की।
- तकनीक कैसे काम करती है?

  यह सिस्टम टेली-ऑपरेशन (Tele-operation) पर आधारित है:
  - → डॉक्टर दिल्ली में एक जॉयस्टिक या सेंसर-युक्त डिवाइस का उपयोग करते हैं।
  - → उनके हाथों की गति को सैटेलाइट के माध्यम से अंटार्कटिका में लगी रोबोटिक आर्म तक भेजा जाता है।
  - → रोबोटिक आर्म मरीज के शरीर पर अल्ट्रासाउंड प्रोब को बिल्कुल वैसे ही घुमाती है जैसे डॉक्टर वहां मौजूद रहकर करते।
- इस सफलता का महत्व:
  - → दुर्गम क्षेत्रों के लिए वरदान: अंटार्कटिका, सियाचिन या गहरे समुद्र में तैनात कर्मियों को आपातकालीन स्थिति में विशेषज्ञ चिकित्सा सहायता मिल सकेगी।
  - → समय की बचत: मरीज को वापस लाने (Evacuation) के बजाय वहीं तुरंत निदान (Diagnosis) संभव होगा।
  - → भविष्य की अंतरिक्ष यात्रा: यह तकनीक भविष्य के मंगल या चंद्रमा मिशनों में अंतरिक्ष यात्रियों के इलाज के लिए आधार तैयार करती है।
- नोट: इस परीक्षण के दौरान डेटा ट्रांसमिशन के लिए उच्च गति वाले उपग्रह संचार का उपयोग किया गया, जो भारत की अंतरिक्ष संचार क्षमताओं (Space Communication) की मजबूती को भी प्रमाणित करता है।

14 आंध्र प्रदेश में स्थापित होगी भारत की सबसे बड़ी एकीकृत लिथियम-आयन बैटरी गीगाफैक्ट्री

हाल ही में वारी एनर्जीज (Waaree Energies) ने आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले के रामबिल्ली में भारत की सबसे बड़ी एकीकृत लिथियम-आयन बैटरी गीगाफैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है। यह भारत के ऊर्जा क्षेत्र (Energy Sector) के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा है।

मुख्य बिंदु

- कुल निवेश: ₹8,175 करोड़।
- स्थान: रामबिल्ली, अनाकापल्ली जिला, आंध्र प्रदेश।
- उत्पादन क्षमता: इसकी क्षमता 16 GWh होगी, जो इसे भारत की सबसे बड़ी एकीकृत (Integrated) लिथियम-आयन बैटरी गीगाफैक्ट्री बनाती है।
- रोजगार: इस प्रोजेक्ट से क्षेत्र में लगभग 3,000 प्रत्यक्ष नौकरियां (Direct Jobs) पैदा होने की उम्मीद है।
- विशेषता: यह एक ग्रीनफील्ड सुविधा होगी जो सेल निर्माण (Cell manufacturing) से लेकर बैटरी पैक और बड़े पैमाने पर 'बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली' (BESS) तक पूरी वैल्यू चेन को कवर करेगी।
- महत्व:
  - → आयात पर निर्भरता कम होगी: वर्तमान में भारत लिथियम-आयन सेल्स के लिए काफी हद तक चीन और अन्य पूर्वी एशियाई देशों पर निर्भर है। यह फैक्ट्री इस निर्भरता को कम करेगी।
  - → Clean Energy Ecosystem: यह परियोजना आंध्र प्रदेश की 'इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी' (ICE Policy) के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य राज्य को अक्षय ऊर्जा का केंद्र बनाना है।
  - → इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा: घरेलू स्तर पर बैटरी निर्माण से ईवी की लागत कम हो सकती है, जिससे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना आसान होगा।

❑ लिथियम-आयन बैटरी क्या है?

- यह एक प्रकार की रीचार्जेबल (Rechargeable) बैटरी है जिसमें लिथियम आयन डिस्चार्ज के दौरान 'एनोड' से 'कैथोड' की ओर और चार्जिंग के दौरान 'कैथोड' से 'एनोड' की ओर बढ़ते हैं।
- एक मानक लिथियम-आयन सेल में चार मुख्य भाग होते हैं:
  - → एनोड (Anode): आम तौर पर यह ग्रेफाइट का बना होता है।
  - → कैथोड (Cathode): यह लिथियम मेटल ऑक्साइड (जैसे $LiCoO_2$ या $LiFePO_4$) से बना होता है।
  - → इलेक्ट्रोलाइट (Electrolyte): एक तरल या जेल पदार्थ जो आयनों के प्रवाह में मदद करता है।
  - → सेपरेटर (Separator): एक पतली झिल्ली जो एनोड और कैथोड को आपस में जुड़ने (शॉर्ट सर्किट) से रोकती है।

15 लेनाकापाविर (Lenacapavir)

❑ चर्चा में क्यों?

जिम्बाब्वे ने 19 फरवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर दुनिया की पहली साल में दो बार ली जाने वाली HIV-AIDS निरोधक दवाई 'लेनाकापैरिव' (Lenacapavir) का वितरण शुरू कर दिया है।

❑ लेनाकापैरिव' के बारे में:-

- प्रकार: यह एक Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) इंजेक्शन है।
  - → यह एचआईवी-1 (HIV-1) के इलाज और रोकथाम के लिए एक क्रांतिकारी, लंबे समय तक असर करने वाली एंटीरेट्रोवायरल दवा है।
  - → यह एक "कैप्सिड इनहिबिटर" है जो वायरस के जीवन चक्र को बाधित करता है।
- अवधि: इसे साल में केवल दो बार (हर 6 महीने पर) लेना होता है, जो इसे रोज ली जाने वाली गोलियों की तुलना में अधिक सुविधाजनक बनाता है।

- प्रभावशीलता: क्लिनिकल ट्रायल्स में यह दवा HIV संक्रमण को रोकने में लगभग 100% प्रभावी पाई गई है।
- निर्माता: इसे अमेरिकी बायोफार्मास्युटिकल कंपनी गिलियड साइंसेज (Gilead Sciences) द्वारा विकसित किया गया है।

❑ जिम्बाब्वे में वितरण का महत्व:

- विश्व स्तर पर नेतृत्व: जिम्बाब्वे इस दवा को बड़े पैमाने पर लागू करने वाले दुनिया के पहले देशों में से एक बन गया है।
- लक्ष्य: कार्यक्रम के शुरुआती चरण में लगभग 46,000 से अधिक उच्च जोखिम वाले लोगों (जैसे युवा महिलाएं, सेक्स वर्कर्स और गर्भवती महिलाएं) को लक्षित किया गया है।
- सहयोग: इस पहल को यूएस प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी प्लान फॉर एड्स रिलीफ (PEPFAR) और ग्लोबल फंड द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे यह दवा लाभार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।
- स्वास्थ्य सुधार: जिम्बाब्वे पहले ही UNAIDS के 95-95-95 लक्ष्यों को प्राप्त कर चुका है और इस नई तकनीक से नए संक्रमणों को शून्य पर लाने की उम्मीद है।
- विशेष नोट: जिम्बाब्वे के साथ-साथ केन्या ने भी हाल ही में इस दवा की खेप प्राप्त की है और वहां भी मार्च 2026 से इसका वितरण शुरू होने की योजना है।

❑ जिम्बाब्वे के बारे में:-

- जिम्बाब्वे, आधिकारिक तौर पर जिम्बाब्वे गणराज्य, दक्षिण-पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक (भू-आबद्ध) देश है, जिसकी राजधानी हरारे है।
- यहाँ की मुद्रा 'जिम्बाब्वे डॉलर' है।
- यह देश ज़ाम्बेज़ी और लिम्पोपो नदियों के बीच स्थित है।
- इसके पड़ोसियों में दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, मोज़ाम्बिक और ज़ाम्बिया शामिल हैं।
- 1980 में स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले, यह देश दक्षिण रोडेशिया के रूप में ब्रिटिश शासन के अधीन था।
- प्रसिद्ध विक्टोरिया फॉल्स (Victoria Falls), यहीं स्थित है।
- एमर्सन म्नांगाग्वा (Emmerson Mnangagwa) यहां के वर्तमान राष्ट्रपति हैं।

16 अमरावती में भारत की पहली क्वांटम वैली (Quantum Valley) की आधारशिला

❑ चर्चा में क्यों?

आंध्र प्रदेश की आगामी राजधानी अमरावती में भारत की पहली क्वांटम वैली (Quantum Valley) स्थापित की जाएगी, जिसकी आधारशिला केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने रखी है। यह आईबीएम (IBM) की सहायता से निर्मित एक अत्याधुनिक हब होगा, जो दिसंबर 2026 तक 133-क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई (AI), और साइबर सुरक्षा पर शोध, नवाचार और विकास का केंद्र बनेगा।

मुख्य बिंदु

- उद्देश्य: अमरावती को वैश्विक क्वांटम केंद्र (जैसे बोस्टन, सिंगापुर) के समकक्ष लाना और डीप-टेक (Deep Tech) के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना।
- प्रमुख भागीदार: IBM, TCS, और L&T जैसी प्रमुख कंपनियां इस परियोजना में शामिल हैं।

❑ प्रमुख विशेषताएं

- अनुसंधान केंद्र: यहाँ क्वांटम एल्गोरिदम, क्वांटम संचार और क्वांटम सेंसर विकसित करने के लिए विश्व स्तरीय प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं।
- स्टार्टअप हब: क्वांटम और डीप-टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना।
- सहयोग: इसमें शैक्षणिक संस्थानों (IITs, IIITs) और निजी उद्योगों के बीच सहयोग को प्राथमिकता दी गई है।

❑ तकनीकी महत्व

- क्वांटम वैली निम्नलिखित क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती है:
  - → साइबर सुरक्षा: अधिक सुरक्षित 'क्वांटम क्रिप्टोग्राफी' विकसित करना।
  - → औषधि खोज (Drug Discovery): जटिल आणविक संरचनाओं का तेजी से विश्लेषण।
  - → आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI): AI की प्रसंस्करण शक्ति (Processing Power) को कई गुना बढ़ाना।

❑ राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) के साथ जुड़ाव

- अमरावती क्वांटम वैली भारत सरकार के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (National Quantum Mission) के लक्ष्यों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह मिशन भारत को क्वांटम क्षेत्र में अग्रणी देशों (जैसे अमेरिका और चीन) की श्रेणी में लाने के लिए लॉन्च किया गया है।

17 ISRO का युवा विज्ञानी कार्यक्रम 'युविका 2026'

ISRO ने कक्षा 9 के छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान, तकनीक और अनुप्रयोगों से रूबरू कराने के लिए 'युविका 2026' (युवा विज्ञानी कार्यक्रम) शुरू किया है। यह 2-सप्ताह का आवासीय कार्यक्रम 11-22 मई, 2026 तक चलेगा, जिसमें छात्रों को इसरो वैज्ञानिकों से मिलने, प्रयोगशालाओं का दौरा करने और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलेगा।

मुख्य बिंदु

- प्रमुख तिथियां-
  - → पंजीकरण शुरू (Registration Starts): 27 फरवरी 2026
  - → पंजीकरण की अंतिम तिथि (Last Date): 31 मार्च 2026
  - → प्रथम चयन सूची (First Selection List): 13 अप्रैल 2026
  - → प्रशिक्षण कार्यक्रम (Programme Dates): 11 मई से 22 मई 2026
- पात्रता और योग्यता (Eligibility)
  - → कक्षा: केवल वे छात्र जो 1 जनवरी 2026 तक भारत के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं, इसके पात्र हैं।

→ चयन का आधार: चयन प्रक्रिया में कक्षा 8 के अंकों (50% वेटेज), ऑनलाइन क्विज़ (10%), विज्ञान प्रतियोगिताओं, ओलंपियाड, खेलकूद और NCC/NSS गतिविधियों को महत्व दिया जाता है।

→ ग्रामीण छात्रों के लिए विशेष लाभ: पंचायत क्षेत्र (ग्रामीण) के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को चयन प्रक्रिया में 15% अतिरिक्त वेटेज दिया जाता है।

❑ ISRO के बारे में:-

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। यह एजेंसी डॉ. विक्रम साराभाई की दूरदर्शिता के साथ, अंतरिक्ष तकनीक के विकास, उपग्रह निर्माण, प्रक्षेपण यान (PSLV/GSLV), और चंद्रयान/मंगलयान जैसे ग्रहों के अन्वेषण के लिए जिम्मेदार है।

मुख्य बिंदु

- संस्थापक: डॉ. विक्रम साराभाई।
- मुख्यालय: बेंगलुरु, कर्नाटक।
- वर्तमान अध्यक्ष: डॉ. वी. नारायणन (Dr. V. Narayanan)

➲ प्रमुख उपलब्धियाँ:

- चंद्रयान-1 (2008): चंद्रमा पर पहला मिशन।
- मंगलयान (MOM - 2013): पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में सफल प्रवेश।
- चंद्रयान-3 (2023): चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश।

➲ प्रमुख केंद्र:

- विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC), तिरुवनंतपुरम: रॉकेट का विकास।
- यू.आर. राव उपग्रह केंद्र (URSC), बेंगलुरु: उपग्रहों का निर्माण।
- सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC), श्रीहरिकोटा: प्रक्षेपण सुविधा (Launch Pad)।

18 मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल वैन

❑ चर्चा में क्यों?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में विश्व स्तरीय गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल वैन (MQCV) या मोबाइल लैब की शुरुआत की है।

मुख्य बिंदु

- उद्देश्य: निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और जवाबदेही को बढ़ाना ताकि बिना सड़क उखाड़े या क्षतिग्रस्त किए उसकी जांच की जा सके।
- प्रौद्योगिकी: ये वैन अत्याधुनिक नॉन-डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग (NDT) उपकरणों से लैस हैं, जैसे कि अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मीटर, रिबाउंड हैमर, और एस्फाल्ट डेंसिटी गेज।
- परीक्षण: इन मोबाइल लैब के माध्यम से कंक्रीट और डामर (asphalt) की मजबूती का तुरंत पता लगाया जा सकता है।
- पायलट प्रोजेक्ट: यह पहल फिलहाल राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और ओडिशा में शुरू की गई है।
- निगरानी: इन वैन से प्राप्त रिपोर्टों की रियल-टाइम GPS ट्रैकिंग होगी, और इन डेटा को एक राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सीधे मंत्रालय के साथ साझा किया जाएगा।

19 "सुजविका" (AI-संचालित बायोटेक उत्पाद डेटा पोर्टल)

SUJVIKA (सुजविका) एक एआई (AI) आधारित Biotech Product Data Portal है, जिसे भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल भारतीय जैव अर्थव्यवस्था (Bioeconomy) को सशक्त बनाने और आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

मुख्य बिंदु

- इसका शुभारंभ 24 फरवरी, 2026 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और कार्मिक मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने किया।
- इसे ABLE (Association of Biotechnology Led Enterprises) के सहयोग से विकसित किया गया है।

❑ मुख्य उद्देश्य (Purpose)

- आयात डेटा का विश्लेषण: यह पोर्टल भारत में आयात होने वाले जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों (जैसे बायोकेमिकल्स, औद्योगिक एंजाइम आदि) का प्रमाणित और संरचित डेटा प्रदान करता है।
- आत्मनिर्भरता (Indigenisation): इसका मुख्य लक्ष्य यह पहचानना है कि भारत किन बायोटेक उत्पादों के लिए विदेशों पर निर्भर है, ताकि उन उत्पादों का निर्माण देश के भीतर (स्वदेशी स्तर पर) शुरू किया जा सके।
- रणनीतिक योजना: यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स को साक्ष्य-आधारित योजना बनाने में मदद करता है।

❑ प्रमुख विशेषताएं

- एआई-संचालित इंटेलिजेंस: यह जटिल व्यापार आंकड़ों को एआई (AI) के माध्यम से सरल और सुलभ प्रारूप में बदल देता है।
- क्षेत्र-वार अंतर्दृष्टि (Sector-wise Insights): पोर्टल बायोकेमिकल उत्पादों, औद्योगिक एंजाइमों और अन्य उच्च-मूल्य वाली बायोटेक सामग्रियों के बारे में विस्तृत जानकारी देता है।
- पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप: यह सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है ताकि घरेलू बायो-मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत किया जा सके।

❑ महत्व

- भारत का लक्ष्य 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था (Bioeconomy) बनने का है, जिसमें सुज्विका जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

20 विज्ञान प्रौद्योगिकी (To The Point)

- आई आई टी कानपुर के शोधकर्ताओं ने सौर्य चक्रों की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए एक नया मॉडल विकसित किया है।

- आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने छोटे व्यवसायों और MSMEs के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए 'पिल्लो एआई' (Pilloo AI) नामक वॉयस-बेस्ड (आवाज़-आधारित) अकाउंटिंग और बिलिंग ऐप लॉन्च किया है।
- दक्षिण अफ्रीका ने 20 वर्षों में पहली बार स्थानीय स्तर पर निर्मित फुट-एंड-माउथ डिजीज वैक्सीन पेश किया।
- दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन, हेवन-1 (Haven-1), अमेरिका में विकसित किया जा रहा है। इसे कैलिफोर्निया स्थित एयरोस्पेस कंपनी वास्ट (Vast) द्वारा विकसित किया जा रहा है।
- भारत ने विश्व का पहला डॉक्टर- नेतृत्व वाला AI हेल्थकेयर इकोसिस्टम "i Live Connect" लांच किया।
- ISRO ने चंद्रयान-4 के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मॉन्स माउटन (MM-4) नामक एक सुरक्षित लैंडिंग साइट खोजी है।
  → लक्ष्य- चंद्रमा की सतह से मिट्टी और पत्थरों के नमूने लाना है।
- भारत ने हाल ही में लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर (LSDs) नामक दुर्लभ अनुवांशिक बीमारियों के लिए अपना पहला समर्पित नेशनल बायोबैंक लॉन्च किया है।
- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली भारत का पहला संस्थान है जिसने फेस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है।
- MeitY ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में BHASHINI इंफ्रास्ट्रक्चर पर ओपन-सोर्स VoicERA वॉयस एआई स्टैक लॉन्च किया।
- बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप Sarvam AI द्वारा विकसित Sarvam Kaze भारत का पहला स्वदेशी (Indigenous) AI-पावर्ड स्मार्ट ग्लास है।
- NASA द्वारा 1972 के बाद पहली बार हाल ही में मानवयुक्त मिशन आर्टेमिस-II प्रक्षेपित करने की योजना बनायी है।
  → इस मिशन में चार अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे।
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग के 40 वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 'SUJVIKA' नामक AI-आधारित बायोटेक उत्पाद डेटा पोर्टल का शुभारम्भ किया।

NOT FOR SALE

आर्थिक घटनाक्रम

01 "बायो-फार्मा शक्ति" योजना (Biopharma SHAKTI)

❑ चर्चा में क्यों?

केंद्रीय बजट 2026-27 में केंद्र सरकार ने बायो-फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक हब बनाने के लिए "बायो-फार्मा शक्ति" योजना के तहत 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

मुख्य बिंदु

- उद्देश्य: देश के बायो-फार्मा इकोसिस्टम को मजबूत करना, अनुसंधान को बढ़ावा देना और जैव-समान दवाओं (Biosimilars) का घरेलू विनिर्माण।
- बुनियादी ढांचा: 3 नए NIPER (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च) की स्थापना और 7 मौजूदा संस्थानों का उन्नयन।
- क्लिनिकल ट्रायल: देशभर में 1,000 से अधिक क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का निर्माण करना।
- नियामक सुदृढ़ीकरण: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) को मजबूत करना।
- लक्ष्य: 2030 तक भारत की बायोइकोनॉमी को $165.7 बिलियन से बढ़ाकर $300 बिलियन तक पहुंचाना।

❑ "बायो-फार्मा शक्ति" योजना के बारे में:-

- बायो-फार्मा शक्ति (Bio-Pharma Shakti) योजना भारत सरकार की एक रणनीतिक पहल है, जिसे विशेष रूप से जैव-प्रौद्योगिकी (Biotechnology) और दवा निर्माण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- इसका लक्ष्य देश को "दुनिया की फार्मेसी" से आगे ले जाकर "नवाचार का केंद्र" बनाना है।
- इस योजना की नींव केंद्रीय बजट 2024-25 (अंतरिम बजट) के दौरान रखी गई थी।
- सितंबर 2024 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औपचारिक रूप से 'बायो-ई3' (Bio-E3 Policy) नीति को मंजूरी दी।

➲ योजना का विजन और उद्देश्य:-

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बल्कि ड्रग्स, बायोलॉजिक्स और वैक्सीन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है।

→ नवाचार को बढ़ावा: नई दवाओं की खोज (Drug Discovery) के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाना।

→ लागत में कमी: निर्माण प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाकर दवाओं की कीमतों को कम करना।

→ आयात पर निर्भरता कम करना: विशेष रूप से चीन और अन्य देशों से आने वाले कच्चे माल (API) पर निर्भरता घटाना।

➲ योजना के प्रमुख घटक:-

सरकार इस योजना को सफल बनाने के लिए चार मुख्य मोर्चों पर काम कर रही है:

→ बायो-मैन्युफैक्चरिंग हब: देश भर में समर्पित 'बायो-फार्मा पार्क' की स्थापना करना जहाँ साझा सुविधाएं उपलब्ध हों।

→ स्टार्टअप सहायता: जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र के नए उद्यमियों को शुरुआती फंडिंग और मेंटरशिप प्रदान करना।

→ नैदानिक परीक्षण (Clinical Trials): भारत में नैदानिक परीक्षणों के बुनियादी ढांचे को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपग्रेड करना।

→ तकनीकी हस्तांतरण: विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर अत्याधुनिक तकनीक को भारत लाना।

➲ लक्षित दवाएं और तकनीकें:-

यह योजना मुख्य रूप से भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों पर केंद्रित है:

→ जीन और सेल थेरेपी: आनुवंशिक रोगों के इलाज के लिए।

→ एमआरएनए (mRNA) तकनीक: तेजी से वैक्सीन विकसित करने के लिए।

→ बायोसिमिलर्स: महंगी जैविक दवाओं के किफायती विकल्प।

→ एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR): नई एंटीबायोटिक्स की खोज।

02 केंद्रीय बजट में जल जीवन मिशन और नमामि गंगे मिशन

केंद्रीय बजट 2026-27 में ग्रामीण जल सुरक्षा और नदी संरक्षण पर जोर देते हुए जल शक्ति मंत्रालय के तहत प्रमुख योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण धनराशि आवंटित की गई है। इसमें जल जीवन मिशन (JJM) के लिए 67,670 करोड़ रुपये और नमामि गंगे मिशन के लिए 3,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मुख्य बिंदु

जल जीवन मिशन (JJM) - ₹67,670 करोड़

- इस भारी-भरकम आवंटन का प्राथमिक लक्ष्य 'हर घर जल' के संकल्प को पूरा करना है।
  → ग्रामीण सशक्तिकरण: यह केवल पाइप बिछाने के बारे में नहीं है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को पानी लाने के कठिन श्रम से मुक्ति दिलाने और स्वास्थ्य में सुधार लाने के बारे में है।
  → स्थिरता: अब जोर केवल कनेक्शन देने पर नहीं, बल्कि पानी की नियमित आपूर्ति और जल स्रोतों के पुनर्भरण (Recharge) पर भी है।
- नोट:- जल जीवन मिशन (JJM) भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य देश के हर ग्रामीण घर में नल के जरिए साफ और सुरक्षित पीने का पानी पहुँचाना है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2019 को की थी।

नमामि गंगे मिशन - ₹3,100 करोड़

- गंगा नदी की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए यह निरंतर निवेश आवश्यक है।
  - → प्रदूषण नियंत्रण: इस राशि का बड़ा हिस्सा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के निर्माण और पुराने घाटों के जीर्णोद्धार में उपयोग किया जाता है।
  - → पारिस्थितिक संतुलन: नदी में जलीय जीवन (जैसे डॉल्फिन) के संरक्षण और किनारों पर वनीकरण के लिए भी यह फंड महत्वपूर्ण है।

❑ नमामि गंगे मिशन के बारे में:-

- नमामि गंगे मिशन भारत सरकार द्वारा जून 2014 में शुरू किया गया एक 'फ्लैगशिप प्रोग्राम' है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी पवित्र नदी गंगा के प्रदूषण को कम करना और उसका कायाकल्प करना है। इसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) और इसके राज्य समकक्ष संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- मिशन के मुख्य स्तंभ (Pillars):- इस मिशन को सफल बनाने के लिए आठ प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है:
  - → सीवेज उपचार बुनियादी ढांचा: शहरों से निकलने वाले गंदे पानी को नदी में गिरने से पहले साफ करना।
  - → नदी तटीय विकास: घाटों और श्मशान घाटों का निर्माण और आधुनिकीकरण।
  - → नदी की सतह की सफाई: तैरते हुए कचरे और प्लास्टिक को मशीनों द्वारा हटाना।
  - → जैव विविधता: लुप्तप्राय जलीय प्रजातियों (जैसे गंगा डॉल्फिन) का संरक्षण।
  - → वनीकरण: नदी के किनारों पर पेड़ लगाकर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना।
  - → जन जागरूकता: लोगों को गंगा की स्वच्छता के प्रति जागरूक करना।
  - → औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी: फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषित पानी की सख्त जांच।
  - → गंगा ग्राम: नदी के किनारे बसे गाँवों को 'खुले में शौच मुक्त' (ODF) बनाना और कचरा प्रबंधन।

03 यंत्र इंडिया लिमिटेड (YIL) को मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जे को मंजूरी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 फरवरी, 2026 को आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) के निगमीकरण के बाद गठित यंत्र इंडिया लिमिटेड (YIL) को मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा देने की मंजूरी दी है। यह कंपनी, जो कार्बन फाइबर, बख्तरबंद वाहनों और गोला-बारूद बनाती है, महज 4 साल में एक लाभकारी रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (DPSU) बन गई है। यह दर्जा उसे बिना सरकारी मंजूरी के ₹500 करोड़ तक का पूंजीगत व्यय करने की वित्तीय स्वायत्तता देता है।

❑ यंत्र इंडिया लिमिटेड (YIL) के बारे में :-

- यंत्र इंडिया लिमिटेड उन सात नई सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों (DPSUs) में से एक है, जिन्हें 2021 में भंग किए गए OFB से बनाया गया था। इसका मुख्यालय नागपुर में है और यह मुख्य रूप से विशेषज्ञता रखती है:
  - → सैन्य ग्रेड के कंपोनेंट्स और पुर्जों का निर्माण।
  - → हथियार प्रणालियों के लिए फोर्जिंग और कास्टिंग।
  - → गोला-बारूद के हार्डवेयर घटकों की आपूर्ति।

❑ मिनीरत्न श्रेणी-I दर्जा मिलने के लाभ:-

- यह दर्जा मिलने से YIL को अब अधिक स्वायत्तता (Autonomy) प्राप्त होगी, जिससे वे तेजी से निर्णय ले सकेंगे:
  - → वित्तीय स्वतंत्रता: कंपनी अब बिना सरकार की पूर्व अनुमति के 500 करोड़ रुपये या अपनी कुल संपत्ति (Net Worth) के बराबर (जो भी कम हो) तक का निवेश कर सकती है।
  - → संयुक्त उद्यम (Joint Ventures): विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी और नई सहायक कंपनियाँ (Subsidiaries) स्थापित करने की शक्ति बढ़ जाएगी।
  - → आधुनिकीकरण: यह दर्जा आधुनिक मशीनरी और तकनीक में निवेश को आसान बनाता है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता और गति बढ़ेगी।

❑ निगमीकरण से सफलता तक का सफर

- जब OFB का निगमीकरण किया गया था, तब मुख्य लक्ष्य कार्यकुशलता बढ़ाना और इन्हें आत्मनिर्भर बनाना था। YIL ने पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में बेहतर प्रदर्शन, समय पर डिलीवरी और निर्यात (Exports) पर ध्यान केंद्रित करके अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत किया है।
- नोट :- मिनीरत्न का दर्जा केवल उन कंपनियों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले तीन वर्षों से लगातार लाभ कमाया हो और जिनकी नेट वर्थ सकारात्मक (Positive) हो।

04 'वरिष्ठ बजट' (Elderly Budget)

केरल ने हाल ही में अपने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में देश का पहला 'वरिष्ठ बजट' (Elderly Budget) पेश कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। 29 जनवरी 2026 को वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल द्वारा प्रस्तुत यह बजट वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को केंद्रित करने वाला भारत का पहला समर्पित दस्तावेज है।

❑ मुख्य विशेषताएं:-

➲ प्रमुख आंकड़े और वित्तीय प्रावधान -

- कुल आवंटन: बुजुर्गों के कल्याण के लिए कुल ₹46,236.52 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- बजट का हिस्सा: यह राशि केरल के कुल बजट परिव्यय (Outlay) का लगभग 19.07% है।
- पेंशन: बजट का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 68%) पेंशन पर खर्च होगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर ₹2,000 प्रति माह कर दिया गया है।

➲ प्रमुख योजनाएं और पहल -

- स्वास्थ्य देखभाल: 'मिसिंग मिडल' के लिए बीमा: गरीबी रेखा से ऊपर लेकिन बीमा कवरेज से बाहर के परिवारों के लिए ₹50 करोड़ का आवंटन।

→ मेनोपॉज़ क्लिनिक: जिला अस्पतालों में वरिष्ठ महिलाओं के लिए विशेष क्लीनिकों की स्थापना।

→ न्यूमोकोकल टीकाकरण: 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान।

- केयर इकोनॉमी (Care Economy): रिटायरमेंट होम्स: आधुनिक और विनियमित रिटायरमेंट होम बनाने के लिए ₹30 करोड़ आवंटित।
  → स्वयंसेवक सेवा: अकेले रहने वाले बुजुर्गों की मदद के लिए 'ऑन-कॉल' स्वयंसेवकों का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म।
  → वयोमित्रम योजना: इसे सभी नगरपालिकाओं और पंचायतों तक विस्तारित किया गया है ताकि घर-घर दवाएं और जांच पहुंचाई जा सके।
- बुजुर्ग-अनुकूल बुनियादी ढांचा: स्थानीय निकायों को पार्कों और पैदल रास्तों जैसे 'एज-फ्रेंडली' पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए विशेष अनुदान।

➲ **यह क्यों महत्वपूर्ण है?**

- केरल में बुजुर्गों की जनसंख्या भारत में सबसे तेजी से बढ़ रही है (लगभग 18.7%)। इस बजट का उद्देश्य केवल कल्याणकारी सहायता देना नहीं, बल्कि बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य प्रणाली को भविष्य के लिए तैयार करना है।

05 2026-31 के लिए 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें

16वें वित्त आयोग (16th Finance Commission) का गठन भारत सरकार द्वारा 31 दिसंबर, 2023 को किया गया था। यह आयोग 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की 5 साल की अवधि के लिए अपनी सिफारिशें लागू करेगा। इस आयोग की अध्यक्षता नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया कर रहे हैं। आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 17 नवंबर, 2025 को राष्ट्रपति को सौंपी थी, और इसकी मुख्य सिफारिशों को 1 फरवरी, 2026 के केंद्रीय बजट के साथ संसद में प्रस्तुत किया गया।

❑ रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

- करों का हस्तांतरण (Tax Devolution): आयोग ने विभाज्य पूल (Divisible Pool) में राज्यों की हिस्सेदारी को 41% पर बनाए रखने की सिफारिश की है। यह वही हिस्सा है जो 15वें वित्त आयोग द्वारा तय किया गया था।
  → उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 17.61% हिस्सेदारी
  → बिहार को दूसरा सबसे अधिक 9.95% हिस्सेदारी
  → सर्वाधिक GDP वाले तीन राज्यों में तेलंगाना (2.17%), कर्नाटक (4.13%) और हरियाणा (1.36%) का हिस्सेदारी
- हस्तांतरण के मानदंड (Horizontal Devolution): राज्यों के बीच धन बांटने के लिए एक नया मानदंड "GDP में योगदान" (10%) जोड़ा गया है। अन्य मानदंडों में आय की दूरी (Income Distance), जनसंख्या (2011 की जनगणना), और जनसांख्यिकीय प्रदर्शन शामिल हैं।
- राजकोषीय रोडमैप (Fiscal Roadmap): केंद्र को 2030-31 तक अपने राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को 3.5% तक लाने की सलाह दी गई है।
  → राज्यों के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा GSDP का 3% निर्धारित की गई है।
- स्थानीय निकायों को अनुदान (Local Body Grants): ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए अगले पांच वर्षों के लिए लगभग ₹7.9 लाख करोड़ के अनुदान की सिफारिश की गई है। इसमें ग्रामीण निकायों को 60% और शहरी निकायों को 40% हिस्सा मिलेगा।
- आपदा प्रबंधन (Disaster Management): राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (SDRF) और शमन निधि (SDMF) के लिए कुल ₹2.04 लाख करोड़ के कॉर्पस की सिफारिश की गई है।
- विशेष नोट: 16वें वित्त आयोग ने "ऑफ-बजट उधारी" (Off-budget borrowings) को पूरी तरह बंद करने और उन्हें पारदर्शी तरीके से राज्य बजट में शामिल करने पर कड़ा रुख अपनाया है।

❑ वित्त आयोग के बारे में-

- वित्त आयोग (Finance Commission) भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक और अर्ध-न्यायिक निकाय है।
- इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल (या आवश्यकतानुसार पहले) में किया जाता है।
- इसका प्राथमिक कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण (वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल) और राज्यों को सहायता अनुदान की सिफारिश करना है।
- इसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं।
- अनुच्छेद 281 केंद्र सरकार द्वारा वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखने की प्रक्रिया से संबंधित है।

❑ वर्तमान आयोग की संरचना -

- अध्यक्ष - डॉ. अरविंद पनगढ़िया
- पूर्णकालिक सदस्य - श्री अजय नारायण झा, श्रीमती ऐनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉ. मनोज पांडा
- अंशकालिक सदस्य - डॉ. सौम्य कांति घोष
- सचिव - श्री ऋत्विक रंजनम पाण्डेय

06 वॉलमार्ट (Walmart) 'ट्रिलियन-डॉलर क्लब' में शामिल होने वाली पहली पारंपरिक रिटेल कंपनी बनी

फरवरी 2026 में वॉलमार्ट (Walmart) ने इतिहास रचते हुए $1 ट्रिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन (बाजार पूंजीकरण) के आंकड़े को पार कर लिया है और इस तरह वह प्रमुख वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के वर्चस्व वाले 'ट्रिलियन-डॉलर क्लब' में शामिल होने वाली पहली पारंपरिक रिटेल कंपनी बन गई है। आमतौर पर इस एलीट क्लब में केवल बड़ी टेक कंपनियों (जैसे Apple, Microsoft, Nvidia) का ही दबदबा रहा है।

❑ सफलता के मुख्य स्तंभ :-

- ई-कॉमर्स में भारी निवेश: वॉलमार्ट ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहद मजबूत किया है, जिससे उसने अमेजन जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर दी है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI): सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस में AI के इस्तेमाल ने कंपनी की कार्यक्षमता (efficiency) को काफी बढ़ा दिया है।
- बदलता ग्राहक वर्ग: महंगाई के दौर में भी वॉलमार्ट न केवल अपने पुराने ग्राहकों को बनाए रखने में सफल रहा, बल्कि उसने बेहतर सुविधाओं के जरिए उच्च आय वाले ग्राहकों को भी अपनी ओर आकर्षित किया।
- Nasdaq में लिस्टिंग: हाल ही में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से हटकर टेक-फ्रेंडली Nasdaq में शामिल होना भी एक बड़ा रणनीतिक बदलाव था।

❑ वॉलमार्ट के बारे में -

- वॉलमार्ट (Walmart) दुनिया की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय रिटेल कंपनी है, जिसे 1962 में सैम वाल्टन द्वारा स्थापित किया गया था।
- इसका मुख्यालय बेंटनविले, अर्कांसस (USA) में है।
- वर्तमान में वॉलमार्ट 19 देशों में लगभग 10,500 से अधिक स्टोर्स और क्लब संचालित करता है।
- 2018 में वॉलमार्ट ने भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट की बहुमत हिस्सेदारी (लगभग 77%) खरीद ली थी, जो भारत के रिटेल बाजार में उसकी सबसे बड़ी उपस्थिति है।

07 Axis Bank ने लॉन्च 'रूफटॉप सोलर फाइनेंस' (Rooftop Solar Finance)

Axis Bank ने हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए एक विशेष 'रूफटॉप सोलर फाइनेंस' समाधान लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे व्यवसायों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि वे अपने बिजली के बिलों में कटौती कर सकें और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकें।

❑ एक्सिस बैंक रूफटॉप सोलर फाइनेंस की मुख्य विशेषताएँ:-

- ऋण राशि (Loan Amount): MSME ग्राहक ₹10 लाख से ₹2 करोड़ तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
- बिना जमानत ऋण (Collateral-Free): योग्य व्यवसायों को इस ऋण के लिए कोई अतिरिक्त संपत्ति गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती।
- लचीली अवधि (Flexible Tenure): ऋण चुकाने के लिए 4 से 7 साल तक का समय दिया जाता है।
- व्यापक नेटवर्क: यह सुविधा बैंक की देश भर में फैली शाखाओं के माध्यम से उपलब्ध है।
- पारदर्शिता और सहयोग: एक्सिस बैंक ने प्रमुख उपकरणों के निर्माताओं (OEMs) और एक टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ साझेदारी की है, जिससे ग्राहकों को सिस्टम की लागत और बिजली की संभावित बचत का सटीक अनुमान मिल सके।

❑ यह MSMEs के लिए क्यों फायदेमंद है?

- लागत में कमी: बिजली के महंगे बिलों से राहत मिलती है, जिससे व्यवसाय की परिचालन लागत (Operating Costs) कम होती है।
- कार्यशील पूंजी पर दबाव नहीं: आसान किस्तों (EMIs) के कारण व्यवसाय के दैनिक खर्चों या कैश फ्लो पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता।
- स्थायित्व (Sustainability): यह व्यवसायों को "ग्रीन एनर्जी" की ओर ले जाता है, जो भविष्य के लिए एक स्मार्ट निवेश है।

08 कोटक महिंद्रा बैंक ने देश का पहला पूर्णतः डिजिटल FPI लाइसेंस जारी किया

महिंद्रा बैंक फरवरी 2026 में भारत का पहला कस्टोडियन (Custodian) बन गया है जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों (e-signatures) का उपयोग करके विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) लाइसेंस जारी करने और ऑनबोर्डिंग की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है।

मुख्य बिंदु

- डिजिटल ऑनबोर्डिंग: कोटक महिंद्रा बैंक अब डिजिटल हस्ताक्षर (e-signatures) के आधार पर FPI लाइसेंस जारी करने वाला देश का पहला कस्टोडियन बन गया है। पहले इसके लिए भौतिक दस्तावेजों और स्याही वाले हस्ताक्षरों की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था।
- सेबी (SEBI) का समर्थन: यह कदम सेबी के उस विजन का हिस्सा है जिसके तहत विदेशी निवेशकों के लिए भारत में प्रवेश की बाधाओं को कम करना है।
- समय की बचत: जहाँ पहले इस प्रक्रिया में हफ़्तों लग जाते थे, अब यह काम बहुत कम समय में और बिना किसी कागजी कार्रवाई के पूरा हो सकेगा।
- पहला लाइसेंस: बैंक ने इस नई व्यवस्था के तहत अपने पहले दो FPI लाइसेंस पहले ही जारी कर दिए हैं।
- ग्लोबल स्टैंडर्ड: यह व्यवस्था भारत के बैंकिंग सिस्टम को विकसित देशों के बराबर लाकर खड़ा करती है, जिससे विदेशी फंड्स का भारत आना और भी आसान हो जाएगा।
- महत्व:- यह उपलब्धि भारत को विदेशी निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक और "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" (Ease of Doing Business) के मामले में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाती है।

09 उत्तर प्रदेश बजट 2026-27

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 11 फरवरी, 2026 को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। इस बजट का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की ओर ले जाना और 'विकसित यूपी' के विजन को साकार करना है।

❑ बजट की मुख्य विशेषताएं और प्रमुख घोषणाएं -

➲ बजट का आकार और वित्तीय स्थिति

- कुल बजट का आकार: ₹9,12,696.35 करोड़ (पिछले वर्ष से लगभग 12.2 - 12.9% अधिक)।
- पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure): ₹1.78 लाख करोड़ (कुल बजट का 19.5%), जो बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित है।
- राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit): GSDP का 3% अनुमानित है, जो वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है।
- GSDP वृद्धि: राज्य की सकल घरेलू उत्पाद दर 13.4% रहने का अनुमान है।

➲ प्रमुख क्षेत्रों के लिए आवंटन

क्षेत्र	आवंटन का प्रतिशत	मुख्य फोकस
शिक्षा	12.4%	स्मार्ट स्कूल, नए विश्वविद्यालय और टैबलेट वितरण।
कृषि	9-12%	मुफ्त बिजली, एग्री-एक्सपोर्ट हब और सौर पंप।
स्वास्थ्य	6%	मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों में ट्रामा सेंटर।
बुनियादी ढांचा	22-25%	एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल और हवाई अड्डे।

➲ युवाओं और शिक्षा के लिए घोषणाएं

- स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना: 50 लाख (5 मिलियन) टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का लक्ष्य।
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना: युवा उद्यमियों को ₹5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण।
- नए संस्थान: 16 नए मेडिकल कॉलेज और 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव।

➲ महिला कल्याण और सामाजिक सुरक्षा

- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना: बेटी के विवाह हेतु अनुदान राशि को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया गया है।
- विशेष स्कूटी योजना: मेधावी छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए ₹400 करोड़ का प्रावधान।
- सेफ सिटी परियोजना: CCTV नेटवर्क और महिला सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार।

➲ बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी

- नॉर्थईस्ट कॉरिडोर: गोरखपुर को सहारनपुर से जोड़ने वाले हाई-स्पीड कॉरिडोर के लिए ₹34,000 करोड़।
- जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट: इसे 5 रनवे तक विस्तारित करने की योजना।
- मेट्रो रेल: आगरा, कानपुर और वाराणसी मेट्रो परियोजनाओं के लिए विशेष बजटीय प्रावधान।

➲ कृषि और किसान कल्याण

- निजी नलकूप: किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की सुविधा जारी रहेगी।
- गन्ना मूल्य: गन्ना मूल्य में ₹30 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।
- एग्री एक्सपोर्ट हब: कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए हब बनाए जाएंगे।

➲ आर्थिक उपलब्धियां

- गरीबी: दावा किया गया है कि राज्य में लगभग 6 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं।
- बेरोजगारी: राज्य की बेरोजगारी दर घटकर 2.24% रह गई है।
- प्रति व्यक्ति आय: 2025-26 के अंत तक इसके ₹1,20,000 तक पहुँचने की उम्मीद है।

विशेष नोट: यह बजट बुनियादी ढांचे (Infrastructure) और पूंजीगत व्यय पर भारी निवेश के माध्यम से औद्योगिक विकास को गति देने की रणनीति पर आधारित है।

10 CPI का आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 हुआ

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने फरवरी 2026 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) की नई श्रृंखला जारी कर दी है, जिसमें आधार वर्ष 2012 से बढ़ाकर 2024=100 निर्धारित किया गया है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के सांख्यिकीय ढांचे में एक ऐतिहासिक बदलाव को दर्शाती है। यह संशोधन मुद्रास्फीति के मापन में अधिक व्यापकता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है।

❑ नई CPI श्रृंखला (आधार वर्ष 2024) की मुख्य विशेषताएं:

- HCES 2023-24 पर आधारित: नए बास्केट और वस्तुओं के भार (Weights) को हाल ही में संपन्न हुए 'घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण' (HCES) के आधार पर तैयार किया गया है।
- बास्केट का विस्तार: वस्तुओं और सेवाओं की संख्या 299 से बढ़ाकर 358 कर दी गई है।
  - → माल (Goods): 259 से बढ़कर 308
  - → सेवाएं (Services): 40 से बढ़कर 50
- खाद्य वस्तुओं के भार में कमी: 'एंजेल के नियम' (Engel's Law) का पालन करते हुए, खाद्य और पेय पदार्थों का वेटेज 45.86% से घटाकर 36.75% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब भोजन की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का कुल महंगाई दर पर असर पहले से कम होगा।
- आवास (Housing) में सुधार: पहली बार इस सूचकांक में ग्रामीण आवास किराया (Rural House Rent) को शामिल किया गया है, जो पहले केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित था।
- अंतरराष्ट्रीय मानक: भारत ने अब COICOP 2018 (Classification of Individual Consumption According to Purpose) ढांचे को अपना लिया है, जिससे भारतीय महंगाई दर की तुलना वैश्विक मानकों से आसानी से की जा सकेगी।

EDU TERIA Telegram Channel
link : https://eduteria.live

➲ **नई और पुरानी श्रृंखला का तुलनात्मक विश्लेषण**

मानक	पुरानी श्रृंखला (2012)	नई श्रृंखला (2024)
वस्तुओं की कुल संख्या	299	358
खाद्य और पेय पदार्थ का भार	45.86%	36.75%
आवास (Housing) का भार	10.07%	17.67%
वर्गीकरण	6 मुख्य समूह	12 प्रभाग
आधुनिक वस्तुएं	शामिल नहीं थीं	OTT

➲ **इस बदलाव का महत्व -**

- सटीक मुद्रास्फीति: यह सूचकांक अब यह बेहतर तरीके से दिखाएगा कि एक औसत भारतीय परिवार आज वास्तव में अपना पैसा कहाँ खर्च कर रहा है।
- RBI के लिए सहायक: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अब महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों पर अधिक सटीक निर्णय ले सकेगा।
- अंतरराष्ट्रीय मानक: भारत ने अब संयुक्त राष्ट्र के COICOP 2018 मानकों को अपना लिया है, जिससे हमारे आंकड़े वैश्विक स्तर पर तुलनीय हो गए हैं।
- ताज़ा आंकड़ा: नई श्रृंखला के तहत जनवरी 2026 की पहली खुदरा मुद्रास्फीति दर 2.75% दर्ज की गई है।

11 एक लाख करोड़ रुपये के शहरी चुनौती कोष (UCF) को मंत्रीमंडल की स्वीकृति

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी बुनियादी ढांचे को आधुनिक और बेहतर बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के शहरी चुनौती कोष (Urban Challenge Fund -UCF) को मंजूरी दी है, जो 2025-26 से 2030-31 तक चलेगा। इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक अनुदान-आधारित मॉडल के बजाय बाजार-आधारित, निजी भागीदारी (PPP) और सुधार-संचालित शहरी परियोजनाओं को बढ़ावा देना है।

मुख्य बिंदु

- वित्तीय सहायता: केंद्र सरकार परियोजना लागत का 25% देगी, जबकि शेष 50% या उससे अधिक हिस्सा नगर निगम बॉन्ड, बैंक ऋण या PPP के माध्यम से जुटाया जाएगा।
- नोडल मंत्रालय: आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय।
- लक्ष्य: लचीले, उत्पादक, समावेशी और जलवायु के प्रति संवेदनशील शहरों का निर्माण करना।
- छोटे शहरों के लिए विशेष: पूर्वोत्तर/पहाड़ी राज्यों और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले छोटे निकायों के लिए 5,000 करोड़ रुपये की 'ऋण चुकौती गारंटी योजना' का प्रावधान है।
- फोकस क्षेत्र: शहरी गतिशीलता, जल और स्वच्छता, और आर्थिक विकास केंद्र के रूप में शहरों का कायापलट।

यह योजना स्मार्ट सिटी मिशन के बाद शहरों के कायाकल्प की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो शहरों को आर्थिक विकास का मुख्य चालक बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है।

12 SBI दस लाख करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी बनी

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने फरवरी 2026 में 10 लाख करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन (M-Cap) को पार कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह पहला सरकारी (PSU) बैंक है जिसने इस जादुई आंकड़े को छुआ है, जो भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती को दर्शाता है।

मुख्य बिंदु

- SBI यह मुकाम हासिल करने वाली भारत की छठी कंपनी बनी है। इस क्लब में शामिल अन्य दिग्गज कंपनियां ये हैं:
  - → रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries)
  - → HDFC बैंक (HDFC Bank)
  - → भारती एयरटेल (Bharti Airtel)
  - → टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS)
  - → ICICI बैंक (ICICI Bank)
- SBI के शेयरों में आई इस जबरदस्त तेजी के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:
  - → शानदार Q3 नतीजे: बैंक ने दिसंबर 2026 तिमाही (Q3 FY26) में अब तक का सबसे अधिक ₹21,028 करोड़ का शुद्ध लाभ (Net Profit) दर्ज किया।
  - → बेहतर एसेट क्वालिटी: बैंक का 'ग्रॉस एनपीए' (GNPA) घटकर 1.57% पर आ गया है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है।
  - → बड़ा बिजनेस माइलस्टोन: इसी दौरान SBI का कुल बिजनेस (डिपॉजिट + एडवांस) भी 100 लाख करोड़ (₹100 trillion) के पार निकल गया है।

❑ वर्तमान स्थिति:

- फरवरी 2026 के ताजा आंकड़ों के अनुसार, SBI ने मार्केट वैल्यू के मामले में TCS को भी पीछे छोड़ दिया है और अब यह रिलायंस, HDFC बैंक और भारती एयरटेल के बाद भारत की चौथी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है।

13 "भारत की पहली CBDC आधारित PDS पहल

फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में भारत की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का शुभारंभ किया। यह पहल वास्तव में भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे और खाद्य सुरक्षा प्रणाली के एकीकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।

❑ मुख्य विशेषताएं और लाभ:-

- बिचौलियों का अंत: CBDC (ई-रुपया) आधारित भुगतान प्रणाली से लाभार्थियों को सीधे लाभ मिलेगा, जिससे भ्रष्टाचार और 'लीकेज' की गुंजाइश खत्म हो जाएगी।
- सटीक लक्ष्यीकरण: यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि सरकारी सब्सिडी का उपयोग केवल उसी उद्देश्य (राशन खरीदने) के लिए हो जिसके लिए वह दी गई है।

- वित्तीय समावेशन: इसके माध्यम से उन लोगों तक भी बैंकिंग सेवाओं जैसी सुविधाएं पहुंचेंगी जिनके पास पारंपरिक बैंक खाते नहीं हैं, क्योंकि CBDC डिजिटल वॉलेट के माध्यम से काम करता है।
- पारदर्शिता और सुरक्षा: ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होने के कारण, हर लेनदेन सुरक्षित और ट्रैक करने योग्य होता है।

❑ भविष्य की राह:

- सहकारिता मंत्रालय और RBI का यह साझा प्रयास 'सहकार से समृद्धि' के मंत्र को तकनीक के साथ जोड़ता है। गांधीनगर का यह पायलट प्रोजेक्ट सफल होने पर इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा प्रणाली को और भी पारदर्शी बना देगा।

14 शहरी चुनौती कोष (Urban Challenge Fund - UCF)

❑ चर्चा में क्यों?

अर्बन चैलेंज फंड (UCF) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे बजट 2025-26 में घोषित किया गया और हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। यह फंड अनुदान-आधारित मॉडल से हटकर बाजार-संबद्ध, सुधार-संचालित और परिणाम-उन्मुख विकास पर केंद्रित है, जिससे 5 वर्षों में ₹4 लाख करोड़ का कुल निवेश आने की उम्मीद है।

❑ मुख्य विशेषताएँ और संरचना -

- कुल परिव्यय (Corpus): केंद्र सरकार द्वारा ₹1,00,000 करोड़ (1 लाख करोड़) की सहायता।
- अवधि: वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक (जरूरत पड़ने पर 2033-34 तक विस्तार संभव)।
- नोडल मंत्रालय: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)।
- निवेश उत्प्रेरक: उम्मीद है कि यह ₹1 लाख करोड़ का फंड कुल मिलाकर ₹4 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करेगा।

❑ वित्तपोषण मॉडल (25:50:25 फॉर्मूला)

- यह फंड एक विशिष्ट वित्तीय संरचना पर आधारित है:
  - → केंद्रीय सहायता: परियोजना लागत का 25%।
  - → बाजार ऋण/निजी निवेश: कम से कम 50% हिस्सा नगर निगम बॉण्ड, बैंक ऋण, या पीपीपी (PPP) के माध्यम से जुटाना होगा।
  - → राज्य/यूएलबी हिस्सा: शेष 25% राज्य सरकार या शहरी स्थानीय निकाय (ULB) स्वयं देंगे।

❑ प्रमुख फोकस क्षेत्र

- इस योजना के तहत मुख्य रूप से इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है:
  - → सतत परिवहन: इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार, मेट्रो कनेक्टिविटी और पैदल चलने योग्य सड़कों का निर्माण।
  - → अपशिष्ट प्रबंधन: 'वेस्ट टू वेल्थ' मॉडल पर आधारित कचरा निपटान प्रणाली।
  - → जल सुरक्षा: 24x7 पेयजल आपूर्ति और जल संचयन (Water Harvesting) संरचनाएं।
  - → डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर: स्मार्ट गवर्नेंस और डेटा-आधारित शहरी प्रबंधन।

❑ अपेक्षित प्रभाव

- जीवन सुगमता (Ease of Living): बेहतर सुविधाओं से नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
- आर्थिक विकास: शहरी बुनियादी ढांचे में निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और जीडीपी में शहरों का योगदान बढ़ेगा।
- जलवायु अनुकूलन: यह फंड शहरों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों (जैसे शहरी बाढ़ या गर्मी) से निपटने के लिए तैयार करेगा।

15 मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का आधार वर्ष (Base Year) अब 2022-23

❑ चर्चा में क्यों?

भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय (DGCI&S) ने फरवरी 2026 में मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स (Merchandise Trade Indices) के आधार वर्ष (Base Year) को 2012-13 से बदलकर 2022-23 कर दिया है।

❑ मुख्य बिंदु और सुधार:

- विशेषज्ञ समिति: यह संशोधन भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) के प्रोफेसर नचिकेता चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता वाली कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर किया गया है।
- व्यापक कवरेज: नई श्रृंखला में उन वस्तुओं (Commodities) को शामिल किया गया है जिनका पिछले दशक में व्यापारिक महत्व बढ़ा है, जबकि पुरानी वस्तुओं के भार (Weightage) को पुनर्गठित किया गया है।
- अंतरराष्ट्रीय मानक: यह नया सूचकांक अब संयुक्त राष्ट्र के SITC (Standard International Trade Classification) और BEC (Broad Economic Categories) के साथ बेहतर तालमेल रखता है।
- डेटा की आवृत्ति: अब निर्यात और आयात के सूचकांक मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक आधार पर उपलब्ध होंगे। इसमें भारत के शीर्ष 20 व्यापारिक भागीदारों के लिए द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सूचकांक भी शामिल हैं।

❑ महत्व:

- सटीक नीति निर्धारण: नीति निर्माताओं को अब निर्यात-आयात के प्रदर्शन और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के बारे में अधिक वास्तविक जानकारी मिलेगी।
- व्यापार की शर्तें (Terms of Trade): यह बदलाव भारत की क्रय शक्ति (Purchasing Power) और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कीमतों के उतार-चढ़ाव को समझने में मदद करेगा।
- GDP गणना में सहायक: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) इन सूचकांकों का उपयोग वास्तविक निर्यात और आयात की गणना (Deflators के रूप में) के लिए करता है।

16 "पावरग्रिड की वित्तीय स्वायत्तता में विस्तार: CCEA ने निवेश सीमा को ₹5,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹7,500 करोड़ किया"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने पावरग्रिड (POWERGRID) को बड़ी राहत देते हुए सहायक कंपनियों में प्रति परियोजना इक्विटी निवेश सीमा को बढ़ाकर ₹7,500 करोड़ कर दिया है। यह कदम बिजली पारेषण (Transmission) अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने और नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा।

❑ प्रमुख बदलाव और वित्तीय सीमाएँ

- इक्विटी निवेश में वृद्धि: किसी भी सहायक कंपनी (Subsidiary) या संयुक्त उद्यम (Joint Venture) में निवेश की सीमा को ₹5000 करोड़ से बढ़ाकर ₹7500 करोड़ कर दिया गया है।
- कुल निवेश सीमा: किसी भी वित्तीय वर्ष में सभी सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में कुल निवेश की सीमा को नेटवर्थ के 15% से बढ़ाकर 30% (अधिकतम ₹25,000 करोड़) कर दिया गया है।
- नवरत्न/महारत्न स्वायत्तता: पावरग्रिड एक महारत्न कंपनी है, और इस निर्णय से इसे अन्य महारत्न कंपनियों की तुलना में अधिक लचीलापन प्राप्त हुआ है।

❑ महत्व:-

- नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy): भारत 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता का लक्ष्य रख रहा है। पावरग्रिड को मिली यह छूट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC) परियोजनाओं के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण में सहायक होगी।
- ग्रिड आधुनिकीकरण: 'वन नेशन, वन ग्रिड, वन फ्रीक्वेंसी' के लक्ष्य को मजबूत करने के लिए हाई-वोल्टेज लाइनों और स्मार्ट ग्रिड में भारी निवेश की आवश्यकता है, जिसे यह वित्तीय शक्ति सुगम बनाएगी।
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: निवेश सीमा बढ़ने से अब कंपनी को बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बार-बार केंद्र सरकार से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे परियोजनाओं में होने वाली देरी कम होगी।
- प्रतिस्पर्धा: यह कदम पावरग्रिड को निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने और वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में मदद करेगा।

❑ पावरग्रिड के बारे में-

- स्थापना: 1989
- मुख्यालय: गुरुग्राम
- कार्य: अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (Inter-State Transmission System) का विकास और संचालन। यह भारत में बिजली के कुल पारेषण का लगभग 45% हिस्सा संभालती है।

17 ओड़िशा में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 'हाई - सिक्योरिटी डाटा सेंटर' स्थापित

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा ओडिशा के भुवनेश्वर में एक अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। यह वित्तीय सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है।

❑ मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य:-

- डेटा संप्रभुता (Data Sovereignty): यह सेंटर भारतीय वित्तीय डेटा को सुरक्षित रखने और उसे देश के भीतर ही प्रोसेस करने में मदद करेगा, जिससे बाहरी साइबर हमलों का खतरा कम होगा।
- उन्नत साइबर सुरक्षा: यहाँ बैंकिंग क्षेत्र के लिए नए खतरों (Cyber Threats) की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए शोध और प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- डिजास्टर रिकवरी (Disaster Recovery): यह डेटा सेंटर आपदा के समय बैंकिंग सेवाओं को बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए एक बैकअप की तरह कार्य करेगा।
- ट्रेनिंग हब: यह केवल एक स्टोरेज सेंटर नहीं है, बल्कि यहाँ बैंकिंग अधिकारियों और विशेषज्ञों को साइबर सुरक्षा की बारीकियों में प्रशिक्षित किया जाएगा।

❑ महत्व:-

- बढ़ते डिजिटल लेनदेन: UPI और डिजिटल पेमेंट के बढ़ने से डेटा का वॉल्यूम तेजी से बढ़ा है, जिसे संभालने के लिए उच्च स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है।
- साइबर हमलों से सुरक्षा: वित्तीय संस्थानों पर वैश्विक स्तर पर बढ़ते रैंसमवेयर और फिशिंग हमलों के बीच यह सेंटर 'सुरक्षा कवच' का काम करेगा।
- तकनीकी आत्मनिर्भरता: यह सेंटर क्लाउड कंप्यूटिंग और क्रिटिकल डेटा प्रबंधन में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा।
- डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI): भारत के 'इंडिया स्टैक' और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को वैश्विक स्तर पर सुरक्षित और विश्वसनीय बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है।

❑ भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के बारे में -

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) भारत का केंद्रीय बैंक और सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना 'भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934' के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी।
- 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है।
- इसका केंद्रीय कार्यालय मुंबई में स्थित है।
- यह देश में बैंक नोट जारी करने, मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने, मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने और भारत सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है।
- वर्तमान में गवर्नर:- श्री संजय मल्होत्रा
- डिप्टी गवर्नर:-
  - → श्री टी. रबी शंकर
  - → श्री स्वामीनाथन जे
  - → श्री शिरीष चंद्र मुर्मू
  - → पूनम गुप्ता

18 केंद्रीय बजट 2026-27

भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2026 को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। यह उनका रिकॉर्ड नौवां बजट था, जो 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए "तीन स्तंभों: सशक्तिकरण, नवाचार और समावेशिता" पर आधारित है।

मुख्य बिंदु

समावेशी विकास (Leaving No One Behind)

- बजट का प्राथमिक उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। इसमें चार प्रमुख वर्गों—गरीब, महिलाएं, युवा और किसान (GYAN)—पर विशेष ध्यान दिया गया है।
  - → गरीब: आवास और खाद्यान्न सुरक्षा के माध्यम से बुनियादी जरूरतों की पूर्ति।
  - → युवा: कौशल विकास और नए 'यूनिवर्सिटी टाउनशिप' के जरिए रोजगार सृजन।
  - → अन्नदाता (किसान): डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) और प्राकृतिक खेती के माध्यम से कृषि आय में वृद्धि।
  - → नारी शक्ति: उद्यमिता और स्वास्थ्य (जैसे सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण) के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण।

बुनियादी ढांचा और पूंजीगत व्यय (Infrastructure as a Growth Engine)

- बजट की एक और प्रमुख थीम "कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स" है। सरकार के अनुसार बुनियादी ढांचे पर निवेश करने से एक 'मल्टीप्लायर इफेक्ट' (Multiplier Effect) पैदा होता है।
  - → पूंजीगत व्यय (Capex): ₹12.2 लाख करोड़ का निवेश सीधे तौर पर सीमेंट, स्टील और निर्माण क्षेत्रों में नौकरियों के अवसर पैदा करता है।
  - → लॉजिस्टिक्स: माल ढुलाई की लागत को कम करने के लिए रेलवे और बंदरगाहों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है।

आत्मनिर्भरता और नवाचार (Atmanirbharta & Innovation)

- बजट 2026-27 "अनुसंधान और विकास" (R&D) को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की थीम पर आधारित है।
  - → अनुसंधान: नवाचार के लिए ₹1 लाख करोड़ का कोष स्थापित करना, जो निजी क्षेत्र को शोध के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है।
  - → सेमीकंडक्टर और स्पेस: भारत को इन रणनीतिक क्षेत्रों में ग्लोबल लीडर बनाने के लिए बजट में भारी आवंटन किया गया है।
  - → ग्रीन एनर्जी: 'नेट जीरो 2070' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सौर ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen) को बढ़ावा देना।

सरलीकरण और सुशासन (Simplification & Good Governance)

- इस बजट की एक महत्वपूर्ण उप-थीम "ईज ऑफ लिविंग" और "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" है।
  - → कर सुधार: नए 'आयकर अधिनियम 2025' के माध्यम से कर प्रक्रियाओं को सरल बनाना और मुकदमों (Litigations) को कम करना।
  - → डिजिटल इंडिया: सरकारी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाना ताकि भ्रष्टाचार कम हो और दक्षता बढ़े।

हरित विकास (Green Growth)

- बजट की यह थीम पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाती है।
  - → रूफटॉप सोलराइजेशन: 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य।
  - → ई-वाहन (EV) इकोसिस्टम: चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए विशेष प्रोत्साहन।

❑ बजट 2026-27 के प्रमुख बिंदु:-

➲ मुख्य आर्थिक आंकड़े (Macroeconomic Indicators)

- सरकार ने राजकोषीय मजबूती और निरंतर विकास के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया है।
  - → कुल व्यय: ₹53,47,315 करोड़ (पिछले वर्ष से 7.7% अधिक)।
  - → राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit): जीडीपी का 4.3% लक्ष्य रखा गया है (2025-26 में यह 4.4% था)।
  - → जीडीपी विकास दर: 2026-27 के लिए 10% रहने का अनुमान है।
  - → पूंजीगत व्यय (Capex): इसे बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है, जो बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

➲ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर (Taxation)

- टैक्स के मोर्चे पर मध्यम वर्ग के लिए राहत और प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर जोर दिया गया है।
  - → आयकर स्लैब (Income Tax): बजट 2025 में घोषित नई कर व्यवस्था के स्लैब को बरकरार रखा गया है। ₹12 लाख तक की आय पर कोई प्रभावी कर नहीं है।
  - → नया आयकर अधिनियम 2025: यह घोषणा की गई है कि नया सरल आयकर अधिनियम अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा।
  - → TCS में कटौती: विदेश यात्रा (LRS), शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए टीसीएस (TCS) की दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है।
  - → STT में वृद्धि: वायदा और विकल्प (F&O) ट्रेडिंग पर प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) की दरों में वृद्धि की गई है।

➲ प्रमुख क्षेत्रों के लिए घोषणाएं :-

- कृषि और ग्रामीण विकास
  - → विकसित भारत ग्राम (Vikasit Bharat G Ram G) योजना: ग्रामीण विकास के लिए ₹1.51 लाख करोड़ का आवंटन।
  - → उच्च मूल्य वाली कृषि: नारियल, काजू, कोको, चंदन और अखरोट जैसी नकदी फसलों के लिए विशेष प्रोत्साहन।
  - → मत्स्य पालन: तटीय क्षेत्रों में 500 जलाशयों के विकास और मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने का प्रस्ताव।
- विनिर्माण और MSME
  - → SME ग्रोथ फंड: उच्च क्षमता वाले MSMEs के लिए ₹10,000 करोड़ का फंड।

→ सेमीकंडक्टर मिशन 2.0: घरेलू चिप निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ₹40,000 करोड़ आवंटित।

→ कंटेनर विनिर्माण: भारत को वैश्विक रसद हब बनाने के लिए ₹10,000 करोड़ की योजना।

- शिक्षा और कौशल विकास

→ यूनिवर्सिटी टाउनशिप: औद्योगिक और रसद गलियारों (Logistics Corridors) में 5 नए विश्वविद्यालय टाउनशिप विकसित किए जाएंगे।

→ Biopharma SHAKTI: घरेलू बायोलॉजिक्स उत्पादन के लिए ₹10,000 करोड़ का आवंटन।

➲ **बजट 2026-27 का लेखा-जोखा** -

क्षेत्र	प्रमुख आवंटन / घोषणा
बुनियादी ढांचा	₹12.2 लाख करोड़ (Capex)
रक्षा	₹7.85 लाख करोड़
ग्रामीण विकास	₹2.73 लाख करोड़
शिक्षा	₹1.39 लाख करोड़
स्वास्थ्य	₹1.05 लाख करोड़

➲ **निष्कर्ष**

- बजट 2026-27 एक "सुधारवादी और विकासोन्मुखी" बजट है। यह न केवल बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश के माध्यम से विकास को गति देता है, बल्कि कर प्रक्रियाओं को सरल बनाकर 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और 'ईज ऑफ लिविंग' को भी बढ़ावा देता है।

19 एशिया आर्थिक संवाद (AED) 2026

एशिया आर्थिक संवाद (Asia Economic Dialogue - AED) 2026 का आयोजन 26 से 28 फरवरी, 2026 तक पुणे, महाराष्ट्र में किया गया। यह इस महत्वपूर्ण भू-आर्थिक (Geoeconomics) सम्मेलन का सातवां संस्करण था।

मुख्य बिंदु

- आयोजक: यह विदेश मंत्रालय (MEA) और पुणे इंटरनेशनल सेंटर (PIC) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक 'ट्रैक 1.5' संवाद है।
- विषय (Theme): "वैश्वीकरण से परे भू-अर्थशास्त्र: टैरिफ, तकनीक और रणनीतिक गठबंधन" (Geoeconomics Beyond Globalisation: Tariffs, Technologies and Strategic Alignments)।
- सहभागी देश: इसमें भारत के अलावा भूटान, श्रीलंका, सिंगापुर, ताइवान, केन्या, ऑस्ट्रेलिया, इज़राइल और नॉर्वे सहित कुल 9 देशों के लगभग 45 से अधिक वक्ताओं ने हिस्सा लिया।
- चर्चा के विषय: मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर (विशेषकर इंडिया-एशिया चिप कॉरिडोर), रक्षा निर्माण और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री भू-अर्थशास्त्र पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- नई पहल: इस वर्ष पहली बार सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health) को आर्थिक लचीलेपन के एक स्तंभ के रूप में चर्चा में शामिल किया गया।
- सांस्कृतिक कार्यक्रम: इस संवाद के साथ-साथ 'पलाश 2026' नामक कला और संस्कृति कार्यक्रम और एक 'क्राफ्ट एक्सपो' का भी आयोजन किया गया।

महत्व

- विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सम्मेलन के दौरान इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान युग में तकनीक (विशेषकर AI और सेमीकंडक्टर) और महत्वपूर्ण खनिज केवल विकास के साधन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय शक्ति के उपकरण बन गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि "रैखिक वैश्वीकरण" (Linear Globalisation) का दौर अब पीछे छूट गया है और अब आर्थिक निर्णय सुरक्षा और राजनीति पर अधिक आधारित हैं।

20 आर्थिक घटनाक्रम (To The Point)

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया।

→ वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमन ने 9 वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया।

→ केंद्रीय बजट 2026-27 में विनिर्माण, अवसंरचना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया। साथ ही सरल कर और सीमा शुल्क का प्रस्ताव भी रखा गया है।

→ बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र को अबतक के सर्वाधिक 7.85 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

- वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के अनुसार वर्तमान वित्त वर्ष में वास्तविक GDP वृद्धि 7.4% और नॉमिनल GDP वृद्धि 8% रहने का अनुमान जताया गया है।
- केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत को वैश्विक बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए 'बायोफार्मा शक्ति' योजना के तहत 5 वर्षों में ₹10,000 करोड़ का आवंटन किया गया है।
- बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹3,47,589.76 करोड़ का ऐतिहासिक और अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है।

→ यह पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 (लगभग ₹3.17 लाख करोड़) के मुकाबले ₹30,694.74 करोड़ अधिक है।

- आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 बिहार 13.1 प्रतिशत की विकास दर के साथ देश में दूसरे स्थान पर है, जो राष्ट्रीय औसत (7.3%) से कहीं अधिक है।

→ राज्य की प्रति व्यक्ति आय अब बढ़कर 76490 रुपये हो गई है।

- केंद्रीय बजट 2026-27 में ग्रामीण जल सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जल जीवन मिशन (JJM) के लिए ₹67,670 करोड़ का आवंटन किया गया है।
- नमामि गंगे मिशन II के लिए बजट 2026-27 में ₹3,100 करोड़ का आवंटन किया गया है।
- 2026-31 के लिए 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट जारी।

→ उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 17.61% हिस्सा दिया गया।

→ बिहार को दूसरा सबसे अधिक हिस्सा 9.95% हिस्सा दिया गया।

→ सर्वाधिक GDP वाले तीन राज्यों में तेलंगना (2.17%) , कर्नाटक (4.13%) और हरियाणा (1.36%) हिस्सा दिया गया है।

- वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में ऊन उत्पादन करने वाले शीर्ष राज्यों में राजस्थान पहले स्थान पर है।
- राजस्थान का अलवर जिला केंद्र सरकार की '2047 तक सभी के लिए बीमा' योजना के तहत् 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला जिला बना।
- एशियाई विकास बैंक ने असम में बाढ़ प्रबंधन के लिए 182 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026-27 के लिए 9.13 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें परिव्यय में 12.2% की वृद्धि हुई है।
- उत्तर प्रदेश ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया, जिसका लक्ष्य निवेश-आधारित विकास के साथ 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है।
- आरबीआई ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना में संशोधन करने, फसल चक्रों को मानकीकृत करने, ऋण अवधि को छह साल तक बढ़ाने और ऋण सीमा को खेती की लागत के अनुरूप बनाने के लिए मसौदा जारी किया है।
- इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) ने एक ऑनलाइन मृत्यु दावा निपटान पोर्टल लॉन्च किया है।
  → यह परिवारों को बैंक जाए बिना 15 लाख रुपये तक के दावों का 15 दिनों के भीतर डिजिटल रूप से निपटारा करने की सुविधा देता है।
- भारत सरकार ने हाल ही में मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का बेस ईयर 2012-13 से बदलकर 2022-23 कर दिया।
- फरवरी 2026 में SBI ने घरेलू मांग में मजबूती के चलते चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में देश की जी.डी.पी वृद्धि दर 8.1 % रहने की संभावना जताई।

NOT FOR SALE

पर्यावरण पारिस्थितिकी

01 केरल के कंथल्लूर-मरायूर में खोजी गई सुगंधित ऑर्किड की प्रजाति "डिप्लोज़ेंट्रम पैपिलोसम"

केरल के इडुक्की जिले के उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्र कंथल्लूर-मरायूर में शोधकर्ताओं ने ऑर्किड की एक नई प्रजाति "डिप्लोज़ेंट्रम पैपिलोसम" (Diplozentrum papillosum) की खोज की है। यह प्रजाति पश्चिमी घाट के दक्षिणी क्षेत्र में पाई गई, जो अपनी विशिष्ट गुलाबी-सफेद सुगंधित फूलों के साथ चट्टानों और पेड़ों पर उगती है, जो पश्चिमी घाट की जैव विविधता को और समृद्ध करती है।

❑ खोज का वैज्ञानिक और पारिस्थितिक महत्व :-

- दुर्लभ वर्गीकरण: Diplozentrum जीनस (वंश) के बारे में खास बात यह है कि यह बहुत छोटा समूह है। इस नई प्रजाति का मिलना यह दर्शाता है कि उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों (High-altitude zones) में अभी भी ऐसी कई प्रजातियाँ मौजूद हो सकती हैं जो विज्ञान की नज़रों से ओझल हैं।
- अनुकूलन क्षमता: इसका एपिफाइटिक (पेड़ों पर) और लिथोफाइटिक (चट्टानों पर) दोनों रूपों में पाया जाना इसकी मजबूत उत्तरजीविता (Survival) क्षमताओं को दर्शाता है। यह कठोर वातावरण और बदलती जलवायु में खुद को ढालने की अद्भुत क्षमता रखता है।
- परागण संकेतक: चूँकि इसके फूल सुगंधित होते हैं, यह इस बात का संकेत है कि यह विशिष्ट स्थानीय कीटों (Pollinators) को आकर्षित करता है, जो उस क्षेत्र के खाद्य जाल (Food web) का एक अनिवार्य हिस्सा हैं।

❑ पश्चिमी घाट: एक 'हॉटस्पॉट' के रूप में :-

- पश्चिमी घाट दुनिया के आठ 'सबसे महत्वपूर्ण जैव-विविधता हॉटस्पॉट' में से एक है। कंथल्लूर-मरायूर जैसे ठंडे और ऊँचाई वाले क्षेत्रों में ऑर्किड की उपस्थिति उस क्षेत्र की वायु की शुद्धता और नमी के सही संतुलन का प्रमाण है, क्योंकि ऑर्किड पर्यावरण में होने वाले छोटे से बदलाव के प्रति भी बहुत संवेदनशील होते हैं।

❑ पश्चिमी घाट के बारे में -

- पश्चिमी घाट (Western Ghats), जिसे 'सह्याद्रि' पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक और पारिस्थितिक धरोहरों में से एक है।
- यह श्रृंखला भारत के पश्चिमी तट के समानांतर लगभग 1,600 किलोमीटर लंबी है।
  - → विस्तार: यह उत्तर में तापी नदी (गुजरात/महाराष्ट्र सीमा) से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैली हुई है।
  - → राज्य: यह 6 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु।
  - → ऊँचाई: इसकी औसत ऊँचाई लगभग 1,200 मीटर है। इसकी सबसे ऊँची चोटी अनामुडी (Anamudi) है, जो केरल में स्थित है।
- पश्चिमी घाट को दुनिया के 8 सबसे महत्वपूर्ण 'बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट' में गिना जाता है।
  - → स्थानिक प्रजातियाँ (Endemic Species): यहाँ पौधों और जानवरों की ऐसी हज़ारों प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलतीं (जैसे- नीलगिरी तहर और लॉयन-टेल्ड मकाक)।
  - → विश्व धरोहर: 2012 में, UNESCO ने पश्चिमी घाट के 39 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था।
- पश्चिमी घाट को 'भारत का जल मीनार' कहा जाता है क्योंकि:
  - → नदियों का उद्गम: दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी यहीं से निकलती हैं।
  - → मानसून पर प्रभाव: यह अरब सागर से आने वाली नमी वाली मानसूनी हवाओं को रोककर भारत के पश्चिमी तट पर भारी वर्षा कराता है।
- पश्चिमी घाट एक निरंतर श्रृंखला में इसे पार करने के लिए कुछ प्राकृतिक मार्ग या दर्रे हैं:
  - → थाल घाट: मुंबई को नासिक से जोड़ता है।
  - → भोर घाट: मुंबई को पुणे से जोड़ता है।
  - → पाल घाट: कोयंबटूर (तमिलनाडु) को पलक्कड़ (केरल) से जोड़ता है।
- पश्चिम घाट इतनी समृद्ध होने के बावजूद, मानवीय हस्तक्षेप के कारण खतरे में है:
  - → गाडगिल और कस्तूरीरंगन समितियाँ: भारत सरकार ने पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए इन समितियों का गठन किया था, जिन्होंने इसके पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों (ESA) की रक्षा के लिए सख्त सुझाव दिए थे।
  - → खतरे: अवैध खनन, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ भूस्खलन जैसी घटनाएँ बढ़ गई हैं।

02 'इबू बैरन' (Ibu Baron)

❑ चर्चा में क्यों?

इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप के घने जंगलों में खोजी गई एक विशाल मादा रेटिकुलेटेड अजगर 'इबू बैरन' (Ibu Baron) को अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा 7.22 मीटर (23 फीट 8 इंच) की लंबाई के साथ दुनिया का सबसे लंबा मापा गया सांप माना जा रहा है।

❑ 'इबू बैरन' की मुख्य विशेषताएँ:-

- लंबाई और वजन: 7.22 मीटर (लगभग 23.7 फीट) की लंबाई और 96.5 किलोग्राम का वजन इसे एक असाधारण जीव बनाता है। तुलना के लिए, यह एक सामान्य मिनी बस जितनी लंबी है।

- प्रजाति: जालीदार अजगर दुनिया के सबसे लंबे सांपों में से एक माने जाते हैं, लेकिन जंगली अवस्था में इस आकार तक पहुँचना दुर्लभ है।
- खोज का समय और स्थान: इसे 2025 के अंत में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप (मारोस क्षेत्र) में खोजा गया था।

❑ **खोज का महत्व :-**

- यह रिकॉर्ड न केवल 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में दर्ज हुआ है, बल्कि वन्यजीव प्रेमियों और वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुलावेसी का पारिस्थितिकी तंत्र अपनी जैव विविधता (Biodiversity) के लिए जाना जाता है, और इबू बैरन जैसे शिकारी का वहां मौजूद होना यह दर्शाता है कि वहां का खाद्य जाल (Food Web) अभी भी काफी मजबूत है।

❑ **सुलावेसी द्वीप के बारे में :-**

- सुलावेसी, जिसे पहले सेलिबीज़ (Celebes) के नाम से जाना जाता था, इंडोनेशिया का एक प्रमुख, के (K)-आकार का द्वीप है।
- यह इंडोनेशिया के बड़े सुन्दा द्वीप समूह का हिस्सा है, जो बोर्नियो और मालूकू द्वीप के बीच स्थित है और अपने पहाड़ी भूभाग, घने वर्षावनों, अनूठी संस्कृति (जैसे तोराजा) और गोताखोरी (diving) स्थलों के लिए प्रसिद्ध है।
- यह दुनिया के 11वें सबसे बड़े द्वीप के रूप में अपनी अनूठी जैव विविधता के लिए जाना जाता है।
- मकासर (दक्षिणी सुलावेसी) सबसे बड़ा शहर और बंदरगाह है।
- यहाँ 67,800 साल पुरानी दुनिया की सबसे पुरानी गुफा कला (cave art) पाई गई है।
- नोट :- 'इबू बैरन' नाम में 'इबू' (Ibu) का अर्थ इंडोनेशियाई भाषा में 'माँ' या 'महिला' होता है, जो इसकी मादा पहचान को सम्मान देता है।

03 राज्य-स्तरीय बर्ड एटलस (State-level Bird Atlas)

❑ **चर्चा में क्यों?**

फरवरी 2026 में, गोवा, केरल के बाद भारत का दूसरा राज्य बन गया जिसने अपना व्यापक राज्य-स्तरीय पक्षी एटलस जारी किया। इसे गोवा के 9वें पक्षी महोत्सव के दौरान लॉन्च किया गया था।

मुख्य बिंदु

- हाल ही में गोवा भारत का दूसरा राज्य बना जिसने अपना व्यापक राज्य-स्तरीय पक्षी एटलस जारी किया। केरल भारत का पहला राज्य था जिसने राज्य-स्तरीय पक्षी एटलस जारी किया था।
- केरल बर्ड एटलस (KBA), भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा राज्य-स्तरीय पक्षी एटलस है। इसमें 25,000 से अधिक चेकलिस्ट का उपयोग किया गया है।
- राज्य-स्तरीय बर्ड एटलस पक्षियों की प्रजातियों, उनकी संख्या और वितरण का एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक मानचित्रण (Mapping) है।
- यह किसी विशेष राज्य के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पक्षियों की उपस्थिति का डेटा तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- मैसूर, कोयंबटूर और हैदराबाद जैसे शहरों ने भी अपने स्थानीय स्तर के एटलस तैयार किए हैं।

❑ **यह कैसे तैयार किया जाता है?**

- पक्षी एटलस बनाने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति का पालन किया जाता है:
  - → ग्रिड-आधारित सर्वेक्षण: पूरे राज्य को छोटे-छोटे वर्गाकार ग्रिडों (जैसे 6.6 \text{ km} \times 6.6 \text{ km}) में विभाजित किया जाता है।
  - → दोहरे मौसम का डेटा: आमतौर पर डेटा साल में दो बार एकत्र किया जाता है—गीला मौसम (मानसून) और शुष्क मौसम (शीतकाल)।
  - → नागरिक विज्ञान: इसमें पेशेवर पक्षीविदों के साथ-साथ आम स्वयंसेवक और 'बर्ड वॉचर्स' भी eBird जैसे ऐप्स के माध्यम से डेटा जुटाने में मदद करते हैं।

❑ **बर्ड एटलस का महत्व -**

- संरक्षण योजना: यह नीति निर्माताओं को यह समझने में मदद करता है कि किन क्षेत्रों को 'संरक्षित क्षेत्र' घोषित करने की आवश्यकता है।
- जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: समय के साथ पक्षियों के वितरण में आने वाले बदलावों से पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का पता चलता है।
- दुर्लभ प्रजातियों की पहचान: इसके माध्यम से 'अति दुर्लभ' प्रजातियों की पहचान की जाती है, जो उनके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है।
- स्थानीय जागरूकता: यह स्थानीय समुदायों को उनके क्षेत्र की जैव विविधता के प्रति जागरूक बनाता है।

04 केरल में ड्रैगनफ्लाई की नई प्रजाति लिरियोथेमिस कैरलेंसिस (Lyriothemis keralensis) की खोज

❑ **चर्चा में क्यों?**

हाल ही में शोधकर्ताओं ने केरल के एर्नाकुलम (कोठामंगलम) के निचले तटीय इलाकों में ड्रैगनफ्लाई की एक नई प्रजाति लिरियोथेमिस कैरलेसिस (Lyriothemis keralensis) की पहचान की है, जिसे 'स्लेंडर बॉम्बार्डियर' भी कहा जाता है।

मुख्य बिंदु

- इसे 2013 से देखा जा रहा था, लेकिन पहले इसे Lyriothemis acigastra (जो पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है) समझा जा रहा था।
- यह एक छोटी ड्रैगनफ्लाई है, जिसमें नर चमकीले गहरे लाल और मादाएं पीले रंग की होती हैं, जिन पर काले निशान होते हैं।
- इसमें नर का पेट अधिक पतला (Slender) और विशिष्ट गुदा उपांग होता हैं।
  - → यह मुख्य रूप से मानसून (मई-अगस्त) के दौरान रबर और अनानास के बागानों के पास छायादार जल निकायों में पाई जाती है।
- यह खोज सिद्ध करती है कि जैव विविधता संरक्षित क्षेत्रों के बाहर भी मौजूद है और यह प्रजाति मानव-संशोधित लैंडस्केप में रहने के लिए अनुकूलित है।
- यह नई प्रजाति लिबेलुलिडे (Libellulidae) परिवार से संबंधित है, जो केरल के तटीय पारिस्थितिक तंत्र में पाई गई है।

- यह Lyriothemis वंश से संबंधित है। इस वंश की ड्रैगनफ्लाई अक्सर पेड़ों के कोटरों (Tree holes) में जमा पानी में प्रजनन करने के लिए जानी जाती हैं।

05 उत्तराखण्ड के दारमा घाटी के उच्च हिमालयी क्षेत्र में दिखा दुर्लभ "हिम तेंदुआ" और विलुप्तप्राय "स्नो कॉक"

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में दारमा घाटी के उच्च हिमालयी क्षेत्र (लगभग 10,000 फीट से अधिक) में 'हिडन हिमालयाज' की टीम ने दुर्लभ हिम तेंदुए और विलुप्ति की कगार पर खड़े स्नो कॉक को अपने कैमरे में कैद किया है। ये तस्वीरें इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है।

❑ हिम तेंदुआ (Snow Leopard) के बारे में -

- हिमालय के ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों का रहस्यमयी शिकारी, हिम तेंदुआ (Snow Leopard), जिसे "पहाड़ों का भूत" (Ghost of the Mountains) भी कहा जाता है, अपनी खूबसूरती और फुर्ती के लिए जाना जाता है।

➲ शारीरिक विशेषताएँ

- हिम तेंदुआ ठंडे वातावरण में रहने के लिए पूरी तरह अनुकूलित होता है।
- इसकी खाल मोटी और सफेद-धूसर होती है, जिस पर काले धब्बे होते हैं। यह इसे बर्फ और चट्टानों के बीच छिपने में मदद करती है।
- इनकी पूंछ शरीर के बराबर लंबी (करीब 3 फीट) होती है। यह चलते समय संतुलन बनाने और सोते समय शरीर को गर्म रखने के लिए ओढ़ने के काम आती है।
- इनके पंजे चौड़े होते हैं जो "स्नो-शूज़" की तरह काम करते हैं, जिससे ये गहरी बर्फ में धंसते नहीं हैं।

➲ आवास और विस्तार

- यह मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह आमतौर पर 3,000 से 4,500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है।
- भारत, नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया और रूस सहित 12 देशों में इनका निवास है।
- लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में ये देखे जाते हैं। लद्दाख को दुनिया की 'हिम तेंदुआ राजधानी' कहा जाता है।

➲ स्वभाव और आहार

- ये बहुत ही शर्मीले होते हैं और इंसानों की नजरों से दूर अकेले रहना पसंद करते हैं।
- ये मुख्य रूप से भरल (Blue Sheep), आईबेक्स (Ibex) और छोटे जीवों जैसे खरगोश और मर्मोट का शिकार करते हैं।

➲ संरक्षण की स्थिति (Conservation Status)

- हिम तेंदुए जलवायु परिवर्तन, अवैध शिकार और प्राकृतिक आवासों में कमी के कारण विलुप्ति के खतरे का सामना कर रहे हैं।
- IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें 'संवेदनशील' (Vulnerable) श्रेणी में रखा गया है।
- हर साल 23 अक्टूबर को 'अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस' मनाया जाता है।

❑ "स्नो कॉक" (Snowcock) के बारे में-

- "स्नो कॉक", जिसे हिम तीतर या तिब्बती हिममुर्ग (Tetraogallus tibetanus) भी कहा जाता है, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक दुर्लभ पक्षी प्रजाति है। यह फैसेनिडे (Phasianidae) परिवार का सदस्य है, जो अपनी लंबी पूंछ और मजबूत पैरों के कारण ढलानों पर रहने के लिए अनुकूलित है।

➲ मुख्य प्रजातियाँ

भारत और आसपास के क्षेत्रों में इसकी दो प्रमुख प्रजातियां मिलती हैं:

→ हिमालयन स्नोकॉक (Himalayan Snowcock): यह थोड़े भूरे और स्लेटी रंग का होता है और पश्चिमी हिमालय में आम है।

→ तिब्बती स्नोकॉक (Tibetan Snowcock): यह आकार में थोड़ा छोटा होता है और इसके गले पर सफेद रंग का स्पष्ट निशान होता है।

➲ आवास (Habit)

- ये पक्षी 3,000 से 6,000 मीटर की ऊंचाई पर, पथरीले ढलानों और घास के मैदानों में रहते हैं।
- इन्हें ठंडी जलवायु और बर्फ के बीच रहना पसंद है। जब भारी बर्फबारी होती है, तभी ये थोड़ा नीचे की ओर आते हैं।

➲ व्यवहार और खान-पान

- ये पक्षी उड़ने के बजाय ढलानों पर दौड़ना ज्यादा पसंद करते हैं। खतरा महसूस होने पर ये नीचे की ओर तेजी से ग्लाइड (glide) करते हैं।
- ये पूरी तरह शाकाहारी होते हैं और जड़ों, कंदों, बीजों और काई (moss) को खाते हैं।
- इनकी आवाज काफी तेज और सीटी जैसी होती है, जिसे पहाड़ों में दूर तक सुना जा सकता है।

➲ खास पहचान

- इनका शरीर भारी होता है। इनके पंखों का रंग पत्थरों और बर्फ से इतना मिलता-जुलता होता है कि इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है।

❑ दरमा घाटी के बारे में -

- दारमा घाटी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक बेहद खूबसूरत, शांत और कम प्रसिद्ध हिमालयी घाटी है, जो पंचाचूली पर्वत श्रृंखला की छाया में बसी है। इसकी ऊंचाई लगभग 3000-3600 मीटर है।
- यह धारचूला के करीब भारत-चीन/नेपाल सीमा के पास स्थित है, जो ट्रेकिंग, रोमांच और स्थानीय संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है।
  → यहाँ लगभग 12-13 पारंपरिक गाँव हैं, जो अपनी अनूठी परंपराओं और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाने जाते हैं।
- पंचाचूली पर्वत श्रृंखला, दंतु और नाग्लिंग गाँव आदि यहां की प्रमुख पर्यटन स्थल हैं।

06 भागलपुर के अगरपुट-कुरपट वेटलैंड में पहली बार दिखा 'हाइब्रिड रीफ हेरॉन'

बिहार के भागलपुर में गंगा तटीय क्षेत्र के अगरपुट-कुरपट वेटलैंड में पहली बार दुर्लभ 'हाइब्रिड रीफ हेरॉन' (Hybrid Reef Heron) पक्षी देखा गया है। एशियन वॉटरबर्ड सेंसस (AWC) 2026 के दौरान इस अद्भुत प्रजाति के देखे जाने की पुष्टि हुई, जो सफेद और स्लेटी रंग का मिश्रण है और आमतौर पर तटीय इलाकों में पाया जाता है।

❑ 'हाइब्रिड रीफ हेरॉन' (Western Reef Heron) के बारे में-

- 'हाइब्रिड रीफ हेरॉन' मुख्य रूप से पश्चिमी रीफ बगुला और लिटिल इग्रेट के क्रॉस-ब्रीडिंग से उत्पन्न एक दुर्लभ पक्षी है, जो भूमध्यसागरीय और अफ्रीकी तटों के पास देखा जाता है।
- यह मिश्रित विशेषताएं दर्शाता है, जैसे गहरे पैरों के साथ मटमैला या मिश्रित रंग का पंख और सामान्य से अलग चोंच, जो इसे एक अनूठा संकर बनाता है।
- ये अक्सर 'धुंधले' सफेद या स्लेटी रंग के हो सकते हैं। कभी-कभी सफेद पंखों पर नीले-स्लेटी धब्बे दिखाई देते हैं।
  - → वेस्टर्न रीफ हेरॉन की चोंच थोड़ी मोटी और मुड़ी हुई होती है, जबकि लिटिल एग्रेट की चोंच सीधी और काली होती है। हाइब्रिड पक्षी में इन दोनों का मिश्रण दिखाई दे सकता है।
  - → इनके पंजों का रंग अक्सर पीला या नारंगी-पीला होता है, जो लिटिल एग्रेट की मुख्य पहचान है।

07 भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने तटीय जल से समुद्री कृमि की दो नई प्रजातियों की खोज की

❑ चर्चा में क्यों?

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) के शोधकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में दीघा और बांकीपुर के प्रदूषित तटीय क्षेत्रों में समुद्री कृमियों की दो नई प्रजातियों - नामालीकास्टिस सोलेनोटोग्नाथा और नेरीस धृतिया (Namalycastis solenotognatha And Nereis dhritiae) की खोज की है।

❑ खोज के मुख्य विवरण:

- प्रजातियां: खोजे गए दोनों जीव पॉलीकीट (Polychaetes) श्रेणी के हैं, जिन्हें आमतौर पर 'ब्रिसल वर्म्स' (Bristle worms) कहा जाता है।
  - → Namalycastis solenotognatha: यह प्रजाति अपनी विशिष्ट शारीरिक बनावट के लिए जानी जाती है।
  - → Nereis dhritiae: इस प्रजाति का नाम ZSI की वर्तमान निदेशक डॉ. धृति बनर्जी के सम्मान में रखा गया है।
- स्थान: यह खोज दीघा और बांकीपुट, पूर्व मेदिनीपुर (पश्चिम बंगाल) के तटीय क्षेत्रों में हुई।
- विशेषता: ये कीड़े अत्यधिक प्रदूषित, सल्फाइड-युक्त, और सड़ती हुई मैंग्रोव लकड़ी या मिट्टी के बीच जीवित रह सकते हैं।
- प्रकाशन: यह शोध 'जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री' में प्रकाशित किया गया था, जिसमें ZSI और मेक्सिको के शोधकर्ता शामिल थे।

❑ ये समुद्री कृमि (Polychaetes) क्यों महत्वपूर्ण हैं?

- पारिस्थितिक संकेतक (Bio-indicators): ये जीव पर्यावरण के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हैं। चूंकि ये प्रदूषित क्षेत्रों में पाए गए हैं, इसलिए ये वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद कर सकते हैं कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र प्रदूषण से कैसे निपट रहा है।
- खाद्य श्रृंखला: ये कृमि समुद्री खाद्य जाल (Food web) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो मछलियों और अन्य समुद्री जीवों के लिए भोजन का स्रोत बनते हैं।
- मिट्टी का पोषण: ये समुद्र तल की तलछट (Sediment) में रहकर उसे उपजाऊ बनाने और पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में मदद करते हैं।

यह खोज उन तटीय आवासों के लचीलेपन को उजागर करती है जो मानवीय गतिविधियों के कारण गंभीर पर्यावरणीय तनाव का सामना कर रहे हैं।

08 'लेइओगैलाथिया समुद्रगिरि', नामक स्क्वाट लॉबस्टर

❑ चर्चा में क्यों?

भारतीय शोधकर्ताओं ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप के पास 360 मीटर की गहराई में लेइओगैलाथिया समुद्रगिरि (Leiogalathea samudragiri) नामक स्क्वाट लॉबस्टर की एक नई प्रजाति खोजी है। यह खोज भारत सरकार के Deep Ocean Mission (समुद्रयान कार्यक्रम) के तहत महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

मुख्य बिंदु

- इस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम 'लेहओगैलाथिया समुद्रगिरि' (Lehogaulatheas samudragiri) रखा गया है। इसका नाम 'समुद्रगिरि' पर्वत के नाम पर है, जहाँ इसे खोजा गया था।
- यह खोज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)-NBFGR (नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज) के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है।
- यह खोज अरब सागर में, विशेष रूप से लक्षद्वीप के कम-अध्ययनित गहरे समुद्री प्रवाल-भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र में जैव-विविधता की समृद्धि को दर्शाती है।
- गहरे समुद्र की प्रजातियाँ समुद्री खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को समझने में मदद करती हैं।
- नई प्रजातियों की पहचान से उस क्षेत्र के संरक्षण प्रयासों को मजबूती मिलती है।

❑ स्क्वाट लॉबस्टर (Squat Lobster) के बारे में -

- स्क्वाट लॉबस्टर वास्तव में सामान्य लॉबस्टर (झींगा) नहीं हैं, बल्कि ये 'एनामुरा' (Anomura) समूह से संबंधित हैं, जिसमें 'हर्मिट क्रैब' (Hermit Crabs) भी आते हैं।
- अन्य प्रजातियों के विपरीत, इसकी खोल (shell) पर चिकनी और लगातार धारियाँ होती हैं, जो इसे अनोखा बनाती हैं।
  - → इनके शरीर का पिछला हिस्सा मुड़ा हुआ होता है और इनके पास लंबे, चिमटे जैसे हाथ (Chelipeds) होते हैं।
- ये आमतौर पर गहरे समुद्र में चट्टानों और समुद्री पर्वतों की दरारों में रहते हैं।

09 टैट्राटेनियम पैकाडे

❑ चर्चा में क्यों?

हाल ही में केरल के इडुक्की जिले में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के उच्च ऊंचाई वाले घास के मैदानों में टैट्राटेनियम पैकाडे (Tetrataenium paikadae) नामक एक नई पौधे की प्रजाति खोजी गई है। यह एपियासी (Apiaceae/गाजर) कुल का पौधा है, जिसे इसके फल में अद्वितीय तेल नलिकाओं के आधार पर पहचाना गया।

❑ मुख्य विशेषताएँ:

- खोजकर्ता: 'देवगिरी सेंट जोसेफ कॉलेज' के शोधकर्ता सी. रेखा, एम. के. प्रशांत और टी.पी. अश्विनदास, ने डॉ. के. एम. मनुदेव के मार्गदर्शन में इसका खोज किया।
- स्थान: केरल के इडुक्की जिले में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के उच्च ऊंचाई वाले घास के मैदान (High-altitude grasslands) में जिन्हें अक्सर 'शोला-घास के मैदान' कहा जाता है।
- नामकरण: इस पौधे का नाम पूर्व प्रिंसिपल रेव. फादर जोसेफ पैकाडा के सम्मान में रखा गया है।
- विशेषताएँ: यह 30-80 सेमी ऊँचा, घने, सख्त बालों वाले तने, अंडाकार पत्तियां और सफेद फूलों वाला पौधा है।
- पुष्पन: यह मानसून के दौरान (जुलाई से सितंबर) फूलता है और अक्टूबर-नवंबर में फल देता है।
- वैज्ञानिक महत्व: यह प्रजाति अपने फलों में तेल नलिकाओं (oil ducts) की विशिष्ट संरचना और संख्या के कारण भिन्न है, जिसका वर्णन नॉर्डिक जर्नल ऑफ बॉटनी में किया गया है।

❑ एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान

- एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल के इडुक्की जिले में मुन्नार के पास स्थित है, जो अपनी लुप्तप्राय प्रजाति नीलगिरी तहर (Nilgiri Tahr) के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह 97 वर्ग किमी में फैला, 1978 में स्थापित केरल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है।

➲ मुख्य आकर्षण:

- नीलगिरी तहर: यह पहाड़ पर रहने वाली बकरियों की एक दुर्लभ प्रजाति का सबसे बड़ा प्राकृतिक आवास है।
- अनामुडी चोटी: यह दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी है, जो लगभग 2695 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है।
- नीलाकुरिंजी फूल: यहाँ हर 12 साल में खिलने वाले नीले फूल (Neelakurinji) पहाड़ियों को रंग देते हैं।
- प्राकृतिक विविधता: यह पार्क हरी-भरी पहाड़ियों, शोला घास के मैदानों और गहरे खड्डों के लिए प्रसिद्ध है।
- नदियाँ: मुथिरापुझा, थलयार और पेरिवर की सहायक नदियाँ इसी क्षेत्र से होकर बहती हैं।
- अन्य आकर्षण: यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में फर्नारियम (Fernarium), लक्कम जलप्रपात, चाय संग्रहालय और पोथामेडु व्यू पॉइंट शामिल हैं।

10 पिस्टल श्रिम्प की एक नई प्रजाति "अल्फियस मधुसूदनई"

❑ चर्चा में क्यों?

कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (CUSAT) के औद्योगिक मत्स्यपालन विभाग के शोधकर्ताओं ने कोच्चि के बैकवाटर में पिस्टल श्रिम्प की एक नई प्रजाति की पहचान की है। इस प्रजाति का नाम अल्फियस मधुसूदनई रखा गया है और यह अल्फेइडे कुल से संबंधित है।

मुख्य बिंदु

- इसकी खोज केरल के कोच्चि बैकवाटर्स में की गई है, जो अपनी अनूठी मैंग्रोव और मुहाना पारिस्थितिकी के लिए जाना जाता है।
- इस नई प्रजाति का नाम प्रसिद्ध समुद्री जीवविज्ञानी और केरल मत्स्य पालन और समुद्री अध्ययन विश्वविद्यालय (KUFOS) के पूर्व कुलपति प्रोफेसर मधुसूदन कुरुप के सम्मान में रखा गया है।

❑ विशेषताएँ:

- पिस्टल श्रिम्प, जिन्हें 'स्नैपिंग श्रिम्प' (Snapping Shrimp) भी कहा जाता है, अपनी अद्भुत क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं:
  - → शारीरिक संरचना: यह 'अल्फीडे' (Alpheidae) परिवार से संबंधित है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका बड़ा और शक्तिशाली पंजा है, जो एक पिस्टल (बंदूक) की तरह काम करता है।
  - → ध्वनि का प्रभाव: जब यह अपने पंजे को तेजी से बंद करता है, तो पानी में एक 'कैविटेशन बबल' (Cavitation bubble) बनता है। यह बुलबुला फूटते समय इतनी तेज ध्वनि (लगभग 210 डेसिबल) और गर्मी पैदा करता है जो छोटे शिकार को बेहोश करने के लिए काफी होती है।
  - → आवास: यह आमतौर पर उथले समुद्री पानी और कोरल रीफ (मूंगा चट्टानों) के आसपास पाया जाता है।

❑ पारिस्थितिक महत्व:-

- पिस्टल श्रिम्प अक्सर 'गोबी मछली' (Goby fish) के साथ सहजीवन (Symbiosis) में रहते हैं। श्रिम्प बिल खोदता है, जबकि कम दृष्टि वाला होने के कारण वह गोबी मछली की चेतावनी पर निर्भर रहता है।
- नोट: भारत के समुद्री क्षेत्रों में इस तरह की नई प्रजातियों का मिलना यह दर्शाता है कि हमारे तटीय पारिस्थित तंत्र में अभी भी कई अनछुए रहस्य मौजूद हैं।

11 चमेली को नुकसान पहुँचाने वाली ब्लॉसम मिज की एक नये प्रजाति 'Contarinia icardiflores' की खोज

हाल ही में वैज्ञानिकों ने चमेली (Jasmine) के फूलों को गंभीर नुकसान पहुँचाने वाली ब्लॉसम मिज (Blossom Midge) की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसे 'Contarinia icardiflores' नाम दिया गया है।

मुख्य बिंदु

- पुणे स्थित ICAR-पुष्पविज्ञान अनुसंधान निदेशालय (DFR) के वैज्ञानिकों ने इस खोज को अंजाम दिया है।
- वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. डी. एम. फिराके के नेतृत्व में खोजी गई यह प्रजाति Jasminum sambac (अरबी चमेली) की कलियों में विकसित होकर उन्हें नष्ट कर देती है। जिससे फूलों की गुणवत्ता और उत्पादन में भारी गिरावट आती है।
- यह कीट चमेली के पौधों निम्न प्रक्रिया के तहत् नुकसान पहुंचाता है:
  - → कलियों का विकृत होना: इसके लार्वा फूल की कलियों के अंदरूनी हिस्सों को खाते हैं, जिससे कलियां फूलने से पहले ही सूख जाती हैं या अजीब आकार की हो जाती हैं।
  - → रंग में बदलाव: संक्रमित कलियां अक्सर गुलाबी या बैंगनी रंग की हो जाती हैं और समय से पहले गिर जाती हैं।

→ आर्थिक नुकसान: चमेली का उपयोग इत्र (Perfume) और तेल निकालने के लिए किया जाता है। इस कीट के कारण फूलों की खुशबू और तेल की मात्रा कम हो जाती है, जिससे किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान होता है।

- खोज का वैज्ञानिक महत्व:
  - → इस नई प्रजाति की पहचान से अब वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों को इसके लिए विशिष्ट कीटनाशक या जैविक नियंत्रण (Biological Control) के तरीके विकसित करने में मदद मिलेगी।
  - → इससे पहले ब्लॉसम मिज की अन्य प्रजातियों के साथ इसे भ्रमित किया जाता था, लेकिन सटीक पहचान होने से अब इसके जीवन चक्र (Life Cycle) को समझकर इसे रोकना आसान होगा।

❑ चमेली (Jasmine) के बारे में -

- अपनी मनमोहक सुगंध और सफेद फूलों के लिए प्रसिद्ध एक लोकप्रिय सुगंधित पौधा है, जो गर्मियों में खिलता है।
- यह जैस्मीनम (Jasminum) प्रजाति का, ओलेसी (Oleaceae) कुल का एक पौधा है, जिसका उपयोग इत्र, सुगंधित चाय, और सजावट में होता है।
- यह पौधा अपने औषधीय गुणों (जैसे दर्द और तनाव कम करना) के लिए भी जाना जाता है।
- दुनिया भर में इसकी 200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में मुख्य रूप से 'मोतिया', 'मोगरा' और 'जूही' प्रसिद्ध हैं।
- यह एक बारहमासी लता (creeper) या झाड़ीदार पौधा है। इसके लिए गर्म और समशीतोष्ण जलवायु सबसे उपयुक्त होती है।

12 भारत और नेपाल में वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता के लिए समझौता

- भारत और नेपाल ने हाल ही में नई दिल्ली में वन, वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दोनों देशों के बीच साझा पारिस्थितिकी तंत्र और सीमा पार वन्यजीवों के आवागमन को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

❑ समझौते के मुख्य उद्देश्य:

- ट्रांसबाउंड्री सहयोग: भारत और नेपाल के बीच लगभग 1,751 किलोमीटर की खुली सीमा है। यह समझौता वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (भारत) और चितवन नेशनल पार्क (नेपाल) जैसे साझा वन्यजीव गलियारों (Corridors) के संरक्षण पर केंद्रित है।
- प्रमुख प्रजातियों का संरक्षण: इस MoU के तहत मुख्य रूप से बाघ (Tiger), हाथी (Elephant), एक सींग वाला गैंडा (Rhinoceros), हिम तेंदुआ (Snow Leopard), गंगा डॉल्फिन और गिद्धों के संरक्षण के लिए विशेष रणनीतियां बनाई जाएंगी।
- वन्यजीव अपराध पर रोक: सीमा पार होने वाली अवैध शिकार (Poaching) और वन्यजीव तस्करी को रोकने के लिए दोनों देश खुफिया जानकारी साझा करेंगे और प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता बढ़ाएंगे।

❑ महत्वपूर्ण पहलू

- परिदृश्य-स्तरीय रणनीति: इसमें केवल एक विशेष क्षेत्र नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिक परिदृश्य (Landscape-level) के आधार पर संरक्षण योजनाएं विकसित की जाएंगी।
- ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर: जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट क्षेत्रों में 'स्मार्ट ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर' को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना रहे।
- जलवायु कार्रवाई: वनों के प्रबंधन के जरिए जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं (Best Practices) का आदान-प्रदान किया जाएगा।
- नोट: 16 मार्च 2026 को दुधवा टाइगर रिजर्व में एक बैठक हुई जिसमें भारत, नेपाल और भूटान ने मिलकर छोटी जंगली बिल्लियों (Small Wild Cats) के संरक्षण के लिए एक साझा नेटवर्क बनाने पर भी सहमति जताई है।

13 पर्यावरण पारिस्थितिकी (To The Point)

- केरल के इडुक्की जिले के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र कंथल्लूर में ऑर्किड की नई प्रजाति 'डिप्लोसेंट्रम पैपिलोसम' की खोज की गई।
- इंडोनेशिया के सुलावेसी से मिले 7.22 मीटर लंबे 'इबू बैरन' नामक साँप को विश्व के सबसे लंबे सांप के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई है।
- गोवा, केरल के बाद पक्षियों के दस्तावेजीकरण और जैव विविधता संरक्षण हेतु व्यापक राज्य-स्तरीय बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दुसरा राज्य बन गया।
- बिहार के राजवाही में साठ एकड़ में डॉल्फिन -घड़ियाल संरक्षण केंद्र बनाने की योजना है।
- उत्तराखण्ड के पिथौरागढ़ जिले की दारमा घाटी में लगभग 10,000 फीट से अधिक की ऊँचाई पर 'हिडन हिमालयाज' की टीम ने दुर्लभ हिम तेंदुए और विलुप्ति की कगार पर खड़े 'स्नो कॉक' को कैमरे में कैद किया है।
- भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) के शोधकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में दीघा और बांकीपुर के प्रदूषित तटीय क्षेत्रों में समुद्री कृमियों (पॉलीकीट) की दो नई प्रजातियों—Namalycastis solenotognatha और Nereis dhritiae की खोज की है।
- भारतीय शोधकर्ताओ ने हाल ही में लक्ष्यद्वीप के तट पर समुद्री क्षेत्र में स्क्वाट लॉबस्टर की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसका वैज्ञानिक नाम 'लेइओगैलाथिया समुद्रगिरि' है।
- शोधकर्ताओं की एक टीम ने हाल ही में केरल के इडुक्की जिले में स्थित पश्चिमी घाट के उच्च ऊंचाई वाले घास के मैदानों में टेट्राटेनियम पैकाडे नामक एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की है।
- हाल ही में 'कूनो नेशनल पार्क' में दक्षिण अफ्रीका से लाई गई चीता 'गामिनी' ने चार शावकों को जन्म दिया।
- हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा केरल के कोच्चि बैकवाटर में "अल्फियस मधुसूदनई" नामक पिस्टल श्रिम्प की एक नई प्रजाति की खोज की गई है।
- हाल ही में ICAR के वैज्ञानिकों ने चमेली की खेती को नुकसान पहुँचाने वाले एक कीट 'Contrarinia icardiflores' की खोज की।

नियुक्ति

01 निवेदिता दुबे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की पहली महिला सदस्य बनीं

❑ चर्चा में क्यों?

निवेदिता दुबे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य बन गई हैं। यह नियुक्ति भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र में नेतृत्व और लैंगिक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। 30 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, वह नीति निर्माण, औद्योगिक संबंधों और कार्यबल आधुनिकीकरण के लिए जिम्मेदार होंगी।

मुख्य बिंदु

- निवेदिता दुबे ने मानव संसाधन सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) बोर्ड में दूसरा सबसे बड़ा पद है। इसके साथ ही वह AAI के बोर्ड में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं।
- उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1995 में AAI में प्रबंधन प्रशिक्षु (Management Trainee) के रूप में की थी।
- AAI बोर्ड में सदस्य (मानव संसाधन) के रूप में वह नीति निर्माण, कार्मिक प्रबंधन, औद्योगिक संबंधों और संगठन के प्रशासन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
- उनकी नियुक्ति को भारत में महिलाओं और युवाओं के लिये एक प्रेरणादायक उपलब्धि के रूप में व्यापक रूप से सराहा जा रहा है, विशेष रूप से विमानन क्षेत्र में, जहाँ ऐतिहासिक रूप से वरिष्ठ शासन स्तरों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व सीमित रहा है।

❑ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के बारे में:-

- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) एक वैधानिक निकाय है, जो भारत में नागरिक उड्डयन अवसंरचना के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन के लिये उत्तरदायी है।
- इसकी स्थापना 1 अप्रैल, 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली में स्थित है।

02 मणिपुर में युमनाम खेमचंद सिंह के नेतृत्व में नयी सरकार का गठन

❑ चर्चा में क्यों?

युमनाम खेमचंद सिंह (Yumnam Khemchand Singh) ने हाल ही में मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्य में लगभग एक साल से लागू राष्ट्रपति शासन के हटने के बाद उन्होंने 4 फरवरी 2026 को कार्यभार संभाला।

मुख्य बिंदु

- युमनाम खेमचंद सिंह (भाजपा) इंफाल पश्चिम की सिंगजामेई (Singjamei) विधानसभा सीट से विधायक हैं।
- राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने इन्हें मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
- बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू था, जो युमनाम खेमचंद सिंह के नियुक्ति के साथ ही समाप्त हो गया।
- सरकार ने समावेशी शासन के लिए दो उपमुख्यमंत्री नियुक्त किए हैं:
  - → नेमचा किपगेन (Nemcha Kipgen): ये कुकी-ज़ो समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं और राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री हैं।
  - → लोसी दिखो (Losii Dikho): ये नागा पीपल्स फ्रंट (NPF) के नेता हैं और नागा समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं।

❑ पृष्ठभूमि और राजनीतिक सफर:-

- अनुभव: खेमचंद सिंह पहले मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष (Speaker) रह चुके हैं और पिछली एन. बीरेन सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री (शिक्षा और ग्रामीण विकास) के पद पर थे।
- उद्देश्य: उन्हें एक "उदारवादी मैतेई नेता" के रूप में देखा जा रहा है, जिनकी जिम्मेदारी राज्य के विभिन्न समुदायों (मैतेई, कुकी और नागा) के बीच विश्वास बहाल करना और शांति स्थापित करना है।

03 पुर्तगाल में एंटोनियो जोस सेगुरो ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता

फरवरी, 2026 को हुए पुर्तगाल के राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर में सोशलिस्ट पार्टी के एंटोनियो जोस सेगुरो (António José Seguro) ने एक शानदार जीत दर्ज की है।

मुख्य बिंदु

- एंटोनियो जोस सेगुरो को कुल 66.7% वोट मिले, जिससे उन्होंने अपनी जीत सुनिश्चित की।
- उन्होंने दूर-दराज़ (far-right) चेगा (Chega) पार्टी के नेता आंद्रे वेंचुरा को हराया, जिन्हें 33.3% वोट प्राप्त हुए।
- यह पुर्तगाल के लोकतांत्रिक इतिहास में केवल दूसरा अवसर था जब राष्ट्रपति का फैसला दूसरे दौर के मतदान के जरिए हुआ।
- 63 वर्षीय सेगुरो अब निवर्तमान रूढ़िवादी राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल मार्च 2026 में समाप्त हो रहा है।

❑ पुर्तगाल के बारे में:-

- पुर्तगाल, आधिकारिक तौर पर पुर्तगाली गणराज्य, दक्षिणी यूरोप में इबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित देश है। लिस्बन
- इसकी राजधानी लिस्बन है जो यहां का सबसे बड़ा शहर है।
- पुर्तगाल अपनी शानदार तटरेखा, भूमध्यसागरीय जलवायु, पुर्तगाली संस्कृति, और 1986 से यूरोपीय संघ (EU) का सदस्य होने के लिए जाना जाता है।
- पुर्तगाली नाविकों ने विश्वभर में अन्वेषण किया, और 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की।
- गोवा 1961 तक पुर्तगाली शासन के अधीन था।

04 थन्या नाथन सी. केरल की पहली पूर्ण दृष्टिहीन महिला न्यायाधीश बनीं।

24 वर्षीय थन्या नाथन सी. (Thanya Nathan C.) केरल न्यायिक सेवा में 100% पूर्ण दृष्टिहीनता (blindness) के साथ नियुक्त होने वाली राज्य की पहली महिला न्यायाधीश बनीं।

मुख्य बिंदु

- थन्या नाथन केरल के कन्नूर जिले के मंगद की रहने वाली हैं।
  - → ये केरल की पहली और भारत की चुनिंदा दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीशों में से एक हैं।
  - → कन्नूर यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई पूरी की और अपनी कड़ी मेहनत व तकनीक का इस्तेमाल किया।
  - → उन्होंने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा 2025 में विकलांग श्रेणी (Benchmark Disabilities) में प्रथम रैंक प्राप्त की।
  - → जन्म से ही दृष्टिहीन थान्या ने ब्रेल लिपि (Braille) और स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर की मदद से यह मुकाम हासिल किया।
  - → उनकी इस शानदार सफलता को न्यायपालिका में समावेशिता (Inclusion) की दिशा में एक बड़ी मिसाल माना जा रहा है।

05 "मिया अमोर मोटली" लगातार तीसरी बार बारबाडोस की प्रधानमंत्री बनीं

फरवरी 2026 में हुए आम चुनावों में मिया अमोर मोटली की पार्टी, बारबाडोस लेबर पार्टी (BLP) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार तीसरी बार क्लीन स्वीप किया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस ऐतिहासिक जीत पर उन्हें बधाई दी और दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई।

मुख्य बिंदु

- मिया मोटली की पार्टी ने हाउस ऑफ असेंबली की सभी 30 सीटों पर जीत दर्ज की। यह लगातार तीसरी बार है जब उन्होंने विपक्ष का पूरी तरह सूपड़ा साफ कर दिया है।
  - → वह लगातार तीसरी बार बारबाडोस की प्रधानमंत्री बनी हैं।
  - → विपक्षी डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी (DLP) के नेता राल्फ थोर्न (Ralph Thorne) अपनी सीट भी नहीं बचा सके।
  - → मिया मोटली को जलवायु परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सुधारों (Bridgetown Initiative) पर उनके मुखर रुख के लिए वैश्विक स्तर पर काफी सराहा जाता है।

❑ बारबाडोस के बारे में -

- बारबाडोस, दक्षिण-पूर्वी कैरेबियन सागर में स्थित एक छोटा, स्वतंत्र द्वीप राष्ट्र है।
- यह लेसर एंटिल्स का सबसे पूर्वी द्वीप है, जो सेंट लूसिया और सेंट विंसेंट के पास है।
- इसकी राजधानी ब्रिजटाउन है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है।
- बारबाडोस 30 नवंबर 1966 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ और अब एक संसदीय गणराज्य है।
- बारबाडोस कैरिबियन समुदाय (CARICOM) का हिस्सा है, जिसका गठन 1973 में किया गया था।

06 जोस मारिया बाल्काजर (José María Balcázar) पेरू के नये अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त हुए

पेरू की कांग्रेस ने फरवरी 2026 में वामपंथी सांसद और पूर्व न्यायाधीश जोस मारिया बाल्काजर (José María Balcázar) को देश का नया अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया है। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद हटाए गए दक्षिणपंथी नेता जोस जेरी (José Jerí) की जगह ली है।

मुख्य बिंदु

- पेरू के कांग्रेस में मतदान के बाद उन्हें 60 वोटों के साथ राष्ट्रपति चुना गया, जहाँ उन्होंने मारिकार्मेन अल्वा को हराया।
- जोस मारिया बाल्काजर, जोस जेरी की पदच्युति के बाद एक दशक में पेरू के नौवें राष्ट्रपति बने हैं।
- 83 वर्षीय बाल्काजर अब तक के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं, जो अप्रैल के आम चुनाव तक पद पर रहेंगे।
- उन्होंने डेनिस मिरालेस को अपना प्रधानमंत्री (Prime Minister) नियुक्त किया है।

❑ पेरू के बारे में -

- पेरू, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित एक विविध और ऐतिहासिक देश है, जिसकी राजधानी लीमा है।
- यह उत्तर में इक्वाडोर और कोलंबिया, पूर्व में ब्राज़ील, दक्षिण-पूर्व में बोलीविया, दक्षिण में चिली और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है।
- यह अपनी प्राचीन इंका सभ्यता, विश्व प्रसिद्ध माचू पिचू (Machu Picchu), एंडीज़ पर्वतमाला और अमेज़ॅन वर्षावन के लिए जाना जाता है।
- यहाँ की मुख्य भाषाएँ स्पेनिश और क्वेशुआ हैं, और यहाँ की मुद्रा 'सोल' (Sol) है।

❑ महत्व तथ्य :-

- पेरू इंका साम्राज्य का केंद्र था, जो कोलंबस के आगमन से पहले अमेरिका का सबसे बड़ा साम्राज्य था।
- माचू पिचू (Machu Picchu) को "इंकाओं का खोया हुआ शहर" कहा जाता है, यह दुनिया के सात अजूबों में से एक है। यह एंडीज पर्वतमाला की चोटी पर स्थित एक शानदार पुरातात्विक स्थल है।
- यहाँ इंका सभ्यता से भी पहले की कई संस्कृतियाँ (जैसे नाज़्का और मोचे) फल-फूल चुकी थीं। नाज़्का लाइन्स (Nazca Lines) आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य हैं।
- दुनिया की सबसे ऊँची नौगम्य (navigable) झील 'टिटिकाका' भी पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है।
- विकुना (Vicuña) पेरू का राष्ट्रीय पशु है।

07 तारिक रहमान, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने

बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, जिससे मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत लगभग 18 महीनों की अनिश्चितता के बाद बांग्लादेश के लिए यह एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत है।

मुख्य बिंदु

- तारिक रहमान ने 17 फरवरी, 2026 को बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पद की शपथ दिलाई।
- इनके साथ 25 कैबिनेट मंत्रियों और 24 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की है।
- भारत की ओर से इस शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्री शामिल हुए।
- इनकी पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने फरवरी 2026 में हुए आम चुनावों में भारी बहुमत (300 में से 209 सीटें) हासिल की।
  - → शेख हसीना के इस्तीफे और डॉ. मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के कार्यकाल के बाद यह देश में पहली निर्वाचित सरकार है।
  - → ये पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पुत्र रहमान 17 साल लंदन में रहने के बाद दिसंबर में देश लौटे हैं।
- रहमान 1991 के बाद से बांग्लादेश के पहले पुरुष प्रधानमंत्री बने हैं (इससे पहले खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच ही सत्ता का हस्तांतरण होता रहा था)।

❑ **भारत-बांग्लादेश संबंध:-**

- भारत और बांग्लादेश के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान में फरवरी 2026 के आम चुनावों के बाद, जहाँ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) सत्ता में लौटी है, द्विपक्षीय संबंधों में एक नया 'रणनीतिक पुनर्संतुलन' (Strategic Recalibration) देखा जा रहा है।

मुख्य बिंदु

- फरवरी 2026 के चुनावों में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली BNP की जीत के बाद भारत ने "व्यावहारिक और हित-आधारित" दृष्टिकोण अपनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई सरकार को बधाई देते हुए संबंधों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है।
  - → पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत में रहना और उनके संभावित प्रत्यर्पण (Extradition) की मांग दोनों देशों के बीच एक संवेदनशील कूटनीतिक मुद्दा बन सकती है।

➲ **सहयोग और विवाद के प्रमुख क्षेत्र -**

- आर्थिक और कनेक्टिविटी सहयोग
  - → सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार: बांग्लादेश, भारतीय उपमहाद्वीप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है (द्विपक्षीय व्यापार लगभग $13 बिलियन)।
  - → रुपये में व्यापार: जुलाई 2023 से दोनों देशों ने व्यापार के निपटान के लिए भारतीय रुपये (INR) का उपयोग शुरू किया है।
  - → प्रमुख प्रोजेक्ट्स:
    - ♦ मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट: ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग का बड़ा उदाहरण।
    - ♦ भारत-बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन: नुमालीगढ़ रिफाइनरी (असम) से बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति।
    - ♦ कनेक्टिविटी: अखौरा-अगरतला रेल लिंक और चटगाँव व मोंगला बंदरगाहों का भारत द्वारा ट्रांजिट उपयोग।
- प्रमुख चुनौतियां और विवाद
  - → नदी जल साझाकरण: 54 नदियाँ साझा हैं। तीस्ता नदी जल विवाद अभी भी अनसुलझा है। साथ ही, गंगा जल संधि (1996) दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाली है, जिसके नवीनीकरण पर चर्चा महत्वपूर्ण है।
  - → सीमा प्रबंधन: 4,096 किमी लंबी सीमा (भारत की सबसे लंबी भूमि सीमा) पर पशु तस्करी, घुसपैठ और फेक करेंसी जैसी चुनौतियां बनी रहती हैं।
  - → चीन का बढ़ता प्रभाव: बांग्लादेश में चीन का बढ़ता निवेश (BRI के तहत) भारत के लिए रणनीतिक चिंता का विषय है।
  - → अल्पसंख्यक सुरक्षा: बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के दौरान हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा भारत के लिए चिंता का केंद्र रहा है।
- सामरिक महत्व (Geopolitical Significance)
  - → Neighbourhood First Policy: भारत की 'पड़ोसी पहले' की नीति में बांग्लादेश एक मुख्य स्तंभ है।
  - → पूर्वोत्तर की सुरक्षा: भारत के 'चिकन नेक' (सिक्किम के पास का संकीर्ण गलियारा) की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश का सहयोग अनिवार्य है।
  - → आतंकवाद विरोधी सहयोग: उग्रवादी समूहों को शरण न देने की बांग्लादेश की नीति भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रही है।

08 रॉब जेटन, नीदरलैंड के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने।

38 वर्षीय रॉब जेटन (Rob Jetten) फरवरी 2026 में नीदरलैंड के सबसे कम उम्र के और पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री बने। मध्यमार्गी-उदारवादी पार्टी D66 के नेता जेटन ने 2025 के चुनाव जीतने के बाद तीन-दलीय गठबंधन सरकार का नेतृत्व संभाला। वे पूर्व में जलवायु और ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं।

मुख्य बिंदु

- हेग (The Hague) स्थित हुइस टेन बॉश पैलेस (Huis ten Bosch Palace) में राजा विलेम-अलेक्जेंडर ने नीदरलैंड्स के इतिहास के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री रॉब जेटन को नई सरकार हेतु पद की शपथ दिलाई।
- जेटन, नीदरलैंड्स के पहले समलैंगिक (Openly Gay) प्रधानमंत्री भी हैं, जो डच राजनीति में सामाजिक समावेशिता के एक नए अध्याय को दर्शाता है।
- वे तीन दलों के अल्पमत गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें उनकी मध्यमार्गी पार्टी डेमोक्रेट्स 66 (D66), मध्य-दक्षिणपंथी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक अपील (CDA) और उदारवादी पीपल्स पार्टी फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी (VVD) शामिल है। निचली सदन की 150 सीटों में से इस गठबंधन के पास कुल 66 सीटें हैं।

❑ नीदरलैंड के बारे में -

- नीदरलैंड, उत्तर-पश्चिमी यूरोप में स्थित एक विकसित देश है, जिसे हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है।
- यह देश उत्तर में समुद्र से, दक्षिण में बेल्जियम और पूर्व में जर्मनी से घिरा है।
- एम्स्टर्डम , नीदरलैंड की आधिकारिक राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, जबकि सरकार और शाही परिवार द हेग में रहते हैं।
- नीदरलैंड की मुद्रा 'यूरो' है ।
- नीदरलैंड अपनी ऐतिहासिक पवन चक्कियों (Windmills), नहरों, ट्यूलिप के खेतों और लकड़ी के जूतों (मोजरी) के लिए प्रसिद्ध है।
  - → 'नीदरलैंड' का अर्थ 'निचली भूमि' है, क्योंकि यहाँ का काफी हिस्सा समुद्र तल से नीचे है।

09 निधि छिब्बर को मिला नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार

छत्तीसगढ़ कैडर की 1994 बैच की वरिष्ठ IAS अधिकारी निधि छिब्बर ने 26 फरवरी 2026 से नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है।

मुख्य बिंदु

- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने एक अधिसूचना जारी कर नीति आयोग (NITI Aayog) के CEO पद का अतिरिक्त प्रभार निधि छिब्बर को सौंपा है।
- निधि, इस पद पर बीवीआर सुब्रह्मण्यम का स्थान लेंगी, जिनका तीन साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है।
  - → नीति आयोग में आने से पहले, उन्होंने सीबीएसई (CBSE) की अध्यक्ष और भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।
- CEO नीति-निर्माण एवं योजना प्रक्रिया की देखरेख, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने, केंद्र के मंत्रालयों तथा राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करने और राष्ट्रीय विकास पहलों के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने के लिये उत्तरदायी होता है।

❑ नीति आयोग के बारे में -

- नीति आयोग (NITI Aayog - National Institution for Transforming India) भारत सरकार का प्रमुख 'थिंक टैंक' है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। यह योजना आयोग का प्रतिस्थापन है।

मुख्य बिंदु

- अध्यक्ष: प्रधानमंत्री (वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी)।
- उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त (वर्तमान: सुमन बेरी)।
- शासी परिषद (Governing Council): सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल।
- मुख्य उद्देश्य: राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ नीति निर्माण, सतत विकास लक्ष्य (SDG) प्राप्त करना, और सहकारी व प्रतिस्पर्धी संघवाद (Cooperative & Competitive Federalism) को बढ़ावा देना।
- कार्य: नीति और कार्यक्रम रूपरेखा तैयार करना, ज्ञान व नवाचार केंद्र के रूप में कार्य करना, और विकास की निगरानी व मूल्यांकन।

10 नियुक्ति (To The Point)

- एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया ने ईस्टर्न एयर के कमांडिंग-इन-चीफ का पद संभाला।
- पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने हाल ही में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ नेमचा किपगेन और लोसी दिखो ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
- बैडमिंटन खिलाड़ी सोराया अघाई हाजियाघा, ईरान की पहली महिला बनीं जिन्हें इटली के मिलान में आयोजित 145वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) सत्र के दौरान सदस्य के रूप में चुना गया।
- दिल्ली सरकार ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके शिखर धवन को आगामी दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया।
- बुल्गारिया की राष्ट्रपति इलियाना योतोवा ने केंद्रीय बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी एंड्री ग्युरोव को इस वर्ष अप्रैल में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव तक अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है।
- मिया अमोर मोटली ने फरवरी 2026 में बारबाडोस की प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दीपक गुप्ता को GAIL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति 1 मार्च 2026 से 28 फावरी 2028 तक प्रभावी रहेगी।
- बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने 17 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में पद की शपथ ली।
  - → राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने तारिक रहमान को शपथ दिलाई।
  - → लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
- हर्षरन कौर त्रेहन, पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की निदेशक नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी।
- माइक्रासॉफ्ट ने भारतीय मूल की वरिष्ठ टेक लीडर आशा शर्मा को माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का कार्यकारी उपाध्यक्ष और CEO नियुक्त किया है।
- IIT मद्रास के प्रोफेसर बी. रविंद्रन को संयुक्त राष्ट्र के कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल में नियुक्त किया गया है।
- महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है।

EDU TERIA Telegram Channel
link : https://eduteria.live

खेल घटनाक्रम

01 ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026

❑ चर्चा में क्यों?

वर्ष 2026 के पहले ग्रैंड स्लेम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन का समापन कार्लोस अल्काराज़ (पुरुष एकल) तथा एलेना रिबाकिना (महिला एकल) की जीत के साथ हुआ।

मुख्य बिंदु

- स्पेन के कार्लोस अल्काराज़ ने फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर वर्ष 2026 के ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता।
- यह अल्काराज़ का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब और कुल मिलाकर उनका सातवाँ ग्रैंड स्लैम एकल खिताब था।
- कार्लोस अल्काराज़ ने मात्र 22 वर्ष की उम्र में अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर 'करियर ग्रैंड स्लैम' (सभी चार प्रमुख खिताब जीतना) पूरा किया। वह ऐसा करने वाले इतिहास के सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं।
- कज़ाखस्तान की एलेना रिबाकिना ने बेलारूस की आर्यना सबालेंका को हराकर महिला एकल खिताब अपने नाम किया।
- यह रिबाकिना का दूसरा ग्रैंड स्लैम एकल खिताब और पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब था, जिससे शीर्ष खिलाड़ी के रूप में उनकी क्षमता का प्रदर्शन हुआ।
- यह टूर्नामेंट मेलबर्न पार्क के हार्ड कोर्ट्स में आयोजित हुआ, जिसमें विश्व भर के शीर्ष टेनिस खिलाड़ियों ने भाग लिया।
- इस वर्ष कुल पुरस्कार राशि रिकॉर्ड 111.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर रखी गई थी।

❑ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के विजेताओं की सूची -

श्रेणी	विजेता	उपविजेता
पुरुष एकल	कार्लोस अल्काराज़ (स्पेन)	नोवाक जोकोविच (सर्बिया)
महिला एकल	एलेना रिबाकिना (कजाकिस्तान)	आर्यना सबालेंका (बेलारूस)
पुरुष युगल	सी. हैरिसन (USA) एवं एन. स्कुप्स्की (UK)	जे. कुबलर एवं एम. पोलमैन्स
महिला युगल	एलिस मर्टेंस (बेल्जियम) एवं झांग शुआई (चीन)	ए. दानिलिना एवं ए. क्रूनिक
मिश्रित युगल	ओलिविया गैडेकी एवं जॉन पीयर्स (ऑस्ट्रेलिया)	के. म्लादेनोविक एवं एम. गुइनार्ड

❑ आस्ट्रेलियन ओपन के बारे में -

- स्थापना: 1905 (इसे पहले 'ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप' कहा जाता था)।
- कोर्ट का प्रकार: हार्ड कोर्ट (1988 से पहले यह ग्रास कोर्ट पर खेला जाता था)।
- उपनाम: इसे 'हैप्पी स्लैम' (Happy Slam) भी कहा जाता है।
- स्थान: मेलबर्न पार्क, मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया)।
- आयोजन समय: हर साल जनवरी (सीजन का पहला ग्रैंड स्लैम)।

02 देविका सिहाग ने थाईलैंड मास्टर्स 2026 का महिला एकल खिताब जीता

भारत की युवा शटलर देविका सिहाग ने फरवरी 2026 में बैंकॉक में आयोजित थाईलैंड मास्टर्स 2026 (BWF Super 300) का महिला एकल खिताब जीत कर इतिहास रच दिया।

मुख्य बिंदु

- फाइनल में देविका का सामना मलेशिया की गोह जिन वेई (Goh Jin Wei) से था। देविका 21-8, 6-3 से आगे चल रही थीं, तभी विपक्षी खिलाड़ी चोट (हैमस्ट्रिंग इंजरी) के कारण मैच से हट गईं और देविका को विजेता घोषित किया गया।
- इस टूर्नामेंट की कुल इनामी राशि $250,000 थी।
- साइना नेहवाल और पी.वी. सिंधु के बाद देविका सिहाग Super 300 खिताब जीतने वाली केवल तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं।
- यह 2026 में किसी भी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी द्वारा जीता गया पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब है।
- टूर्नामेंट के दौरान देविका ने शानदार खेल दिखाते हुए शीर्ष वरीयता प्राप्त थाईलैंड की सुपनिदा कटेथोंग (Supanida Katethong) को भी हराया।
- 20 वर्षीय देविका हरियाणा की रहने वाली हैं और प्रकाश पादुकोण-द्रविड़ सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस (बेंगलुरु) में ट्रेनिंग करती हैं।
- थाईलैंड मास्टर्स 2026 के पुरुष एकल का खिताब इंडोनेशिया के मोहम्मद जाकी उबैदिल्लाह (Moh. Zaki Ubaidillah) ने अपने नाम किया।

❑ थाईलैंड मास्टर्स 2026 के सभी विजेताओं की सूची :-

कैटेगरी	विजेता (Champion)	देश
महिला एकल	देविका सिहाग	भारत
पुरुष एकल	जाकी उबैदिल्लाह	इंडोनेशिया
पुरुष युगल	लियो रोली कारनांडो और बगास मौलाना	इंडोनेशिया
महिला युगल	अमल्लिया सहाया प्रितीवी और सिती फादिया सिल्वा रामधंती	इंडोनेशिया
मिश्रित युगल	अदनान मौलाना और इंदा चह्या सारी जमील	इंडोनेशिया

03 एशियाई राइफल और पिस्टल निशानेबाजी चैंपियनशिप 2026

एशियाई राइफल और पिस्टल निशानेबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हाल ही में भारत के नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। भारतीय निशानेबाजों ने इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया।

मुख्य बिंदु

- तिथि: 2 फरवरी से 14 फरवरी, 2026 तक।
- स्थान: डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज, नई दिल्ली, भारत।
- आयोजक: नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI)।
- प्रतिभागी: एशिया के लगभग 20 देशों के 300 से अधिक निशानेबाजों ने हिस्सा लिया।
- शीर्ष विजेता: भारत ने कुल 94 पदक (51 स्वर्ण, 23 रजत और 20 कांस्य) जीतकर महाद्वीप में अपना दबदबा साबित किया।

❑ मुख्य आकर्षण और उपलब्धियां :-

- विश्व रिकॉर्ड: ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन (3P) स्पर्धा में 362.0 के स्कोर के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता।
- अद्रियान कर्मकार ने जूनियर वर्ग में विश्व रिकॉर्ड स्थापित करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया।
- क्लीन स्वीप: भारत ने 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में क्लीन स्वीप किया (स्वर्ण: अमनप्रीत सिंह, रजत: गुरप्रीत सिंह, कांस्य: अंकुर गोयल)।
- 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पुरुषों के वर्ग में भी भारत ने तीनों पदक (स्वर्ण, रजत, कांस्य) जीते।
- महिला वर्ग में प्रदर्शन: ईशा सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में व्यक्तिगत स्वर्ण जीता।
- मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कड़ी टक्कर के बाद रजत पदक हासिल किया।
- सिफ्ट कौर समरा ने 50 मीटर राइफल प्रोन में रजत पदक जीता और टीम स्पर्धा में स्वर्ण हासिल किया।

❑ अन्य सितारे:

- इलावेनिल वलारिवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता।
- अनीश भानवाला ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में कांस्य पदक जीता।

04 महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026

❑ चर्चा में क्यों?

महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का चौथा सीजन 9 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक आयोजित किया गया। इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए दूसरा खिताब अपने नाम किया।

❑ WPL 2026 से जुड़ी मुख्य जानकारियां :-

- चैंपियन: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)
- रनर-अप: दिल्ली कैपिटल्स (DC)
- फाइनल स्कोर: फाइनल में RCB ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर ट्रॉफी जीती। दिल्ली कैपिटल्स ने 203/4 रन बनाए थे, जिसे RCB ने 19.4 ओवर में 204/4 रन बनाकर हासिल कर लिया।

❑ टूर्नामेंट का विवरण:-

विवरण	जानकारी
तारीख	9 जनवरी – 5 फरवरी 2026
टीमें	5 (MI, RCB, DC, GG, UPW)
कुल मैच	22 (20 लीग + एलिमिनेटर + फाइनल)
स्थान	नवी मुंबई (डीवाई पाटिल स्टेडियम) और वडोदरा (कोटंबी स्टेडियम)

❑ अवॉर्ड्स की लिस्ट:

- प्लेयर ऑफ द मैच: स्मृति मंधाना
- ऑरेंज कैप (सर्वाधिक रन): स्मृति मंधाना (377 रन)
- पर्पल कैप (सर्वाधिक विकेट): सोफी डिवाइन (17 विकेट)

❑ मेगा ऑक्शन की सबसे महंगी खिलाड़ी -

- सीजन से पहले नवंबर 2025 में हुए मेगा ऑक्शन में कई खिलाड़ियों पर बड़ी बोलियां लगीं:

→ दीप्ति शर्मा: ₹3.20 करोड़ (यूपी वॉरियर्स) — सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी।

→ एमेलिया केर: ₹3.00 करोड़ (मुंबई इंडियंस) — सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी।

- शिखा पांडे: ₹2.40 करोड़ (यूपी वॉरियर्स)।

05 भारत छठी बार अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का विजेता

आईसीसी अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का आयोजन, भारत के जीत के साथ हाल ही में संपन्न हुआ है। यह टूर्नामेंट का 16वां संस्करण था, जिसकी मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया ने संयुक्त रूप से की। भारत ने जिम्बाब्वे के हरारे में खेले गए फाइनल में इंग्लैंड को हराकर छठी बार अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है।

❑ 2026 फाइनल की मुख्य विशेषताएं -

- इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम का नेतृत्व आयुष म्हात्रे ने किया।
- 14 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने फाइनल में केवल 80 गेंदों पर 175 रनों की तूफानी पारी खेली। यह किसी भी अंडर-19 विश्व कप फाइनल का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है।
- भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से मात दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 411/9 का विशाल स्कोर बनाया, जिसके जवाब में इंग्लैंड 311 रनों पर सिमट गई।
- पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन (439 रन) के लिए वैभव सूर्यवंशी को ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया।

EDU TERIA Telegram Channel
link : https://eduteria.live

❑ भारत की अब तक की 6 खिताबी जीत

वर्ष	कप्तान	उपविजेता
2000	मोहम्मद कैफ	श्रीलंका
2008	विराट कोहली	दक्षिण अफ्रीका
2012	उन्मुक्त चंद	ऑस्ट्रेलिया
2018	पृथ्वी शॉ	ऑस्ट्रेलिया
2022	यश धुल	इंग्लैंड
2026	आयुष म्हात्रे	इंग्लैंड

06 'खेलो दिल्ली-दिल्ली खेल महाकुंभ' 2026

'खेलो दिल्ली-दिल्ली खेल महाकुंभ' 2026 की शुरुआत दिल्ली को देश की 'स्पोर्ट्स कैपिटल' बनाने के उद्देश्य से की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 13 फरवरी 2026 को छत्रसाल स्टेडियम से इसका आधिकारिक उद्घाटन किया।

❑ प्रमुख विवरण-

- प्रारंभ तिथि: 13 फरवरी 2026 (यह आयोजन लगभग एक महीने तक चलेगा)।
- ब्रांड एंबेसडर: भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन।
- मैस्कॉट (शुभंकर): 'रणवीर' (Ranveer)।
- प्रतिभागी: इस आयोजन में दिल्ली के 12 जिलों से लगभग 30,000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।
- स्टेडियम: दिल्ली के विभिन्न कोनों (बवाना, नजफगढ़, विकासपुरी आदि) के 17 स्टेडियमों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है।

❑ शुरुआती चरण में 7 प्रमुख खेलों को शामिल किया गया है:

1. कबड्डी
2. फुटबॉल
3. एथलेटिक्स
4. कुश्ती
5. बास्केटबॉल
6. वॉलीबॉल
7. स्क्वैश

❑ पुरस्कार और प्रोत्साहन राशि

सरकार ने विजेताओं के लिए भारी पुरस्कार राशि की घोषणा की है:
टीम इवेंट्स:

→ स्वर्ण (Gold): ₹1,75,000
→ रजत (Silver): ₹1,51,000
→ कांस्य (Bronze): ₹1,31,000

व्यक्तिगत स्पर्धाएं:

→ स्वर्ण: ₹11,000
→ रजत: ₹9,000
→ कांस्य: ₹7,000

नोट :- एथलेटिक्स जैसी स्पर्धाएं 19 फरवरी से शुरू होकर 15 मार्च 2026 तक अलग-अलग वेन्यू पर चल रही हैं। इस महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को खोजना और उन्हें एक पेशेवर मंच प्रदान करना है।

07 अबू धाबी (UAE) में आयोजित "ओपन मास्टर्स गेम्स 2026" के पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर

अबू धाबी (UAE) में आयोजित ओपन मास्टर्स गेम्स 2026 (6 से 15 फरवरी) में भारतीय एथलीटों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए दुनिया भर में तिरंगा लहराया है। भारत इस वैश्विक प्रतियोगिता की पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा।

मुख्य बिंदु

- पदक तालिका में भारत का स्थान
  → भारत ने कुल 142 पदक जीतकर प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारत द्वारा जीते गए पदक विवरण:-
    - स्वर्ण (Gold): 48
    - रजत (Silver): 52
    - कांस्य (Bronze): 42
  → भारत UAE के बाद दूसरे स्थान पर रहा, प्रतियोगिता में ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया क्रमश: तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर रहे।
- व्यक्तिगत शानदार प्रदर्शन
  → हैमर थ्रो (एथलेटिक्स): किशोरकुमार चंदीरा मोगन ने 30+ आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में मोहम्मद अंसार ने कांस्य पदक हासिल किया।
  → बैडमिंटन: पुणे के अनुभवी खिलाड़ी राज सिंह ने कुल तीन पदक जीते:
    - 60+ पुरुष युगल: रजत (धनंजय देशपांडे के साथ)
    - 60+ मिश्रित युगल: कांस्य (रेखा धुपड़ के साथ)
    - 45+ पुरुष युगल: कांस्य (प्रताप मेकाला के साथ)
  → इस प्रतियोगिता में 30 से लेकर 90 वर्ष तक की आयु के भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें जालंधर के विकास महाजन जैसे अनुभवी एथलीट भी शामिल थे।
- प्रतियोगिता की विशेषताएं
  → यह पश्चिम एशिया में आयोजित होने वाला अपनी तरह का पहला मल्टी-स्पोर्ट्स मास्टर्स इवेंट था।
  → इसमें योग्यता (Qualification) की कोई बाध्यता नहीं थी, जिससे भारत के एक बड़े दल को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला।
  → प्रतियोगिता में फुटबॉल और बास्केटबॉल से लेकर ऊंट दौड़ (Camel Racing) जैसे 38 विभिन्न खेलों को शामिल किया गया था।

08 अंतरराष्ट्रीय मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप (IMACC) 2026

❑ चर्चा में क्यों?

भारतीय सेना ने 18 से 23 फरवरी 2026 तक पूर्वी हिमालय की तलहटी (अरुणाचल प्रदेश) में पहली बार अंतरराष्ट्रीय मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप (IMACC) 2026 का आयोजन किया। इस अनूठी प्रतियोगिता में भारत सहित 7 मित्र देशों के सैनिकों ने हिस्सा लिया, जिसमें भारतीय सेना की टीम विजयी रही।

❑ मुख्य बिंदु:

- स्थान: आयोजन के लिए अरुणाचल प्रदेश स्थित पूर्वी हिमालय में विशेष रूप से एक 'एडवेंचर विलेज' विकसित किया गया था।
- उद्देश्य: सैनिकों की शारीरिक फिटनेस, मानसिक सहनशीलता, नेतृत्व क्षमता और टीम वर्क का परीक्षण करना रहा।
- प्रतियोगिता: इसमें ड्यूथलॉन (दौड़+साइकिलिंग) और ट्रायाथलॉन (तैराकी+साइकिलिंग+दौड़) जैसे कठिन पहाड़ी चुनौतियों पर आधारित इवेंट्स शामिल थे।
- प्रतिभागी: सात देशों (भूटान, ब्राजील, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, सऊदी अरब) की टीमों के अलावा, भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, भारतीय तटरक्षक बल (ICG) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) ने भाग लिया।
- महत्व: यह आयोजन 'खेल के माध्यम से मित्रता' (Friendship through Sport) के दर्शन के तहत भारत की रक्षा कूटनीति को बढ़ावा देता है।

09 छठी राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026

❑ चर्चा में क्यों?

छठी राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप, जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले के शिबनोट (प्रेम नगर) में 19-22 फरवरी 2026 तक चेनाब नदी पर आयोजित की गई। इस क्षेत्र में यह आयोजन 'साहसिक पर्यटन' (Adventure Tourism) को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

मुख्य बिंदु

- यह चार दिवसीय कार्यक्रम जम्मू पर्यटन निदेशालय (Directorate of Tourism Jammu) और डोडा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।
- इस चैंपियनशिप को "द अल्टीमेट रिवर बैटल" (The Ultimate River Battle) नाम दिया गया।
- इस आयोजन का उद्देश्य साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना और देश भर की शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करना था।
- इसमें देश भर की 13 से अधिक टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें विशेष रूप से BSF (सीमा सुरक्षा बल) ने मैराथन और स्प्रिंट (पुरुष/महिला) दोनों में शीर्ष स्थान हासिल किया।
- इस बार की चैंपियनशिप में तीन महिला टीमों की भागीदारी रही, जो राष्ट्रीय स्तर की राफ्टिंग में महिलाओं की बढ़ती रुचि और समावेशिता को दर्शाती है।

10 मिलानो-कॉर्टिना, शीतकालीन ओलंपिक 2026

❑ चर्चा में क्यों?

इटली में आयोजित मिलानो-कॉर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक (6-22 फरवरी 2026) में नार्वे ने 18 स्वर्ण, 12 रजत और 11 कांस्य सहित कुल 41 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया।

❑ मुख्य विवरण:

- संस्करण: यह 25वां शीतकालीन ओलंपिक (25th Winter Olympics) था।
- उद्घाटन समारोह: मिलान के प्रतिष्ठित सैन सिरो स्टेडियम (San Siro Stadium) में 6 फरवरी को आयोजित किया गया।
- नया खेल: 'स्की माउंटेनियरिंग' (Ski Mountaineering) को पहली बार ओलंपिक पदक स्पर्धा के रूप में शामिल किया गया।
- समापन समारोह: वेरोना के प्राचीन वेरोना एरिना (Verona Arena) में 22 फरवरी को संपन्न हुआ।
- लैंगिक समानता: इन खेलों में महिलाओं की भागीदारी 47% रही, जो शीतकालीन ओलंपिक के इतिहास में अब तक की सर्वाधिक है।

❑ शुभंकर (Mascot) और थीम

- शुभंकर: 'टीना' (Tina) और 'मिलो' (Milo)। ये दो 'स्टोट्स' (Stoats - एक प्रकार का नेवला) हैं, जिनके नाम मेजबान शहरों (कॉर्टिना के लिए टीना और मिलान के लिए मिलो) से प्रेरित हैं।
- थीम: इस बार की थीम "अरमोनिया" (Armonia) यानी सद्भाव (Harmony) रखी गई थी।

❑ पदक तालिका (Medal Tally) - शीर्ष 5 देश

- नॉर्वे ने एक बार फिर शीतकालीन खेलों में अपना दबदबा कायम रखा।

रैंक	देश	स्वर्ण पदक	कुल पदक
1	नॉर्वे	18	41
2	अमेरिका	12	33
3	नीदरलैंड	10	20
4	इटली	10	30
5	जर्मनी	8	26

- विशेष: अमेरिका ने 1980 के "मिरेकल ऑन आइस" के बाद पहली बार पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा।

❑ भारत की भागीदारी

- भारत का प्रतिनिधित्व दो मुख्य एथलीटों ने किया:
  - → आरिफ मोहम्मद खान: अल्पाइन स्कीइंग (Alpine Skiing - Slalom) में। वे उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक भी थे।
  - → स्टांजिन लुंडुप: लद्दाख के इस खिलाड़ी ने क्रॉस-कंट्री स्कीइंग (10km Interval Start Free) में हिस्सा लिया।
- नोट: पैरालंपिक शीतकालीन खेल (Paralympic Winter Games) 6 मार्च से 15 मार्च, 2026 तक आयोजित होंगे।

11 अर्जेंटीना के टेनिस खिलाड़ी 'टोमस मार्टिन एचेवेरी' ने अपना पहला ATP टूर खिताब जीता

अर्जेंटीना के 26 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी टोमस मार्टिन एचेवेरी (Tomás Martín Etcheverry) ने ब्राजील में आयोजित एटीपी 500 रियो ओपन 2026 (Rio Open) जीतकर अपना पहला ATP टूर खिताब हासिल किया है। उन्होंने फाइनल में चिली के अलेजांद्रो ताबिलो को 3-6, 7-6(3), 6-4 से हराया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ वह विश्व रैंकिंग में 33वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

❑ ATP के बारे में:-

- ATP (Association of Tennis Professionals) टूर खिताब पुरुषों के पेशेवर टेनिस में सबसे प्रतिष्ठित उपलब्धियों में से एक हैं।
- ATP टूर के अंतर्गत विभिन्न स्तरों के टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं, जिनमें जीतने पर अलग-अलग रैंकिंग अंक मिलते हैं:
  - → Grand Slams (2000 अंक): ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन। (हालांकि ये ITF द्वारा संचालित हैं, लेकिन ATP रैंकिंग में इनका सबसे अधिक महत्व है)।
  - → ATP Finals (अधिकतम 1500 अंक): सीजन के अंत में शीर्ष 8 खिलाड़ियों के बीच होने वाला टूर्नामेंट।
  - → ATP Masters 1000 (1000 अंक): साल में 9 ऐसे टूर्नामेंट होते हैं (जैसे इंडियन वेल्स, मियामी, मैड्रिड)।
  - → ATP 500 और ATP 250: ये क्रमशः 500 और 250 रैंकिंग अंक प्रदान करते हैं।

12 खेल घटनाक्रम (To The Point)

- स्पेन के युवा टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज ने आस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब दिग्गज टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को हरा कर जीता।
- नई दिल्ली में आयोजित एशियाई राइफल/पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारतीय निशानेबाज विश्व चैंपियन सम्राट राणा और विश्व कप फाइनलिस्ट सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता।
- भारत व श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में ICC पुरुष टी-20 विश्व कप 2026 की शुरुआत हुई।
- भारत ने नेपाल में आयोजित SAFF अंडर-19 महिला चैम्पियनशिप के फाइनल में बांग्लादेश को हराकर खिताब जीता।
- सेना ने 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैम्पियनशिप संतोष ट्राफी के फाइनल में केरल को 1-0 से हराकर खिताब जीता।
- झारखंड की महिला टीम ने झुंझुनूं में खेले गए पैरा थ्रोबॉल राष्ट्रीय महासंघ कप 2026 के फाइनल में राजस्थान को हराकर पदक जीता।
- भारत के तेजस्विन शंकर ने चीन के तियानजिन में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की हेप्टाथलॉन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।
- नई दिल्ली में आयोजित एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता।
- दिल्ली में 'खेलो इंडिया' की तर्ज पर शुरू हुए 'खेलो दिल्ली-दिल्ली खेल महाकुंभ' का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मशाल जलाकर शुभारंभ किया।
- नई दिल्ली में आयोजित एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीनियर राइफल और पिस्टल स्पर्धाओं में कुल 33 पदक (13 स्वर्ण, 11 रजत और 9 कांस्य) जीते।
- ओपन मास्टर्स गेम्स, अबू धाबी 2026 में पुरुषों के हैमर थ्रो में भारत के किशोरकुमार चंदीरा मोगन ने स्वर्ण पदक और मोहम्मद अंसार ने 30+ आयु वर्ग में कांस्य पदक जीता।
- विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन (नार्वे) ने वीसेनहॉस में खेले गए फाइनल में फैबियानो कारुआना (जर्मनी) को हराकर 2026 का फिडे फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व चैंपियन का खिताब जीता।
- नॉर्वे के दिग्गज क्रॉस-कंट्री स्कीयर 'जोहान्स होसफ्लोट क्लेबो' ने पुरुषों की 4×7.5 किमी रिले जीत के साथ अपने करियर का 9वाँ शीतकालीन ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किया।
- अफगानिस्तानी ऑलराउंडर 'राशिद खान' हाल ही में टी 20 फार्मेट में 700 विकेट लेने पहले क्रिकेटर बने।
- मिलान-कार्टिना (इटली) में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक खेलों में अमेरिका ने महिला आइस हॉकी के फाइनल में कनाड़ा को 2-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता।
- फाइनल में 'इंडिया ए' ने 'बांग्लादेश ए' को 46 रनों से हराकर 2026 के महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब अपने नाम किया।
- इटली में सफलतापूर्वक संपन्न हुए विंटर ओलंपिक 2026 की पदक तालिका में नार्वे (कुल पदक -41) ने शीर्ष स्थान हासिल किया।
  - → पदक तालिका में दुसरे स्थान पर अमेरिका रहा।
- जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुलमर्ग में 6वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन किया।
- प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन कॉपर इवेंट 2026 का आयोजन 18-22 मार्च, 2026 मुम्बई में किया जाएगा।

पुरस्कार एवं सम्मान

01 दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड 2026

90 वर्षीय तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने साल 2026 में संगीत और कला जगत के सबसे बड़े सम्मान ग्रैमी अवार्ड (Grammy Award) को जीतकर इतिहास रच दिया है। लॉस एंजिल्स में आयोजित समारोह में उनकी ओर से यह अवार्ड रफस वेनराइट ने स्वीकार किया।

मुख्य बिंदु

- समारोह: 68वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स
- श्रेणी (Category): 'बेस्ट ऑडियो बुक, नरेशन और स्टोरीटेलिंग रिकॉर्डिंग' (Best Audio Book, Narration & Storytelling Recording)।
- विजेता एल्बम: "मेडिटेशन्स: द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा" (Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama)।
- भारतीय संगीत का योगदान: इस एल्बम में संगीत प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान और उनके बेटों (अमान और अयान अली बंगश) द्वारा दिया गया है। इसका निर्माण ग्रैमी विजेता कबीर सहगल ने किया है।
- विषय: इसमें शांति, करुणा, पर्यावरण संरक्षण (जैसे 'Water' नामक ट्रैक में) और मानवता की एकता पर विचार साझा किए गए हैं।
- प्रतिस्पर्धा: दलाई लामा ने इस श्रेणी में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस केतनजी ब्राउन जैक्सन, मशहूर होस्ट ट्रेवर नूह और मिली वनिली के फैब मोरवन जैसे बड़े नामों को पीछे छोड़ा।

❑ दलाई लामा के बारे में:

- दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे प्रतिष्ठित आध्यात्मिक गुरु और तिब्बत के राष्ट्रध्यक्ष (निर्वासित) माने जाते हैं। वर्तमान में 14वें दलाई लामा, तेनजिन ग्यात्सो, दुनिया भर में शांति, करुणा और अहिंसा के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं।
- तिब्बती परंपरा के अनुसार, दलाई लामा को 'अवलोकितेश्वर' (करुणा के बुद्ध) का अवतार माना जाता है। जब एक दलाई लामा की मृत्यु होती है, तो उनके पुनर्जन्म की खोज की जाती है।
- 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। 1959 में चीनी शासन के खिलाफ एक असफल विद्रोह के बाद, दलाई लामा को अपनी जान बचाने के लिए तिब्बत छोड़कर भागना पड़ा।
- उन्हें तिब्बत की मुक्ति के लिए अहिंसक संघर्ष और प्रकृति के संरक्षण के प्रति उनके दृष्टिकोण के लिए नोबेल शांति पुरस्कार (1989) भी प्राप्त हुआ है।

02 68वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स 2026

68वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स 2026 का आयोजन 1 फरवरी, 2026 को लॉस एंजिल्स के क्रिप्टो डॉट कॉम एरिना में हुआ। इस साल के समारोह में केंड्रिक लैमर (Kendrick Lamar) और बैड बनी (Bad Bunny) ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी और कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए।

❑ प्रमुख श्रेणियों के विजेताओं की सूची :-

- एल्बम ऑफ द ईयर - बैड बनी (Bad Bunny)
- रिकॉर्ड ऑफ द ईयर - केंड्रिक लैमर
- सॉन्ग ऑफ द ईयर - बिली आइलीश
- बेस्ट न्यू आर्टिस्ट - ओलिविया डीन
- बेस्ट पॉप वोकल एल्बम - लेडी गागा (Lady Gaga)
- बेस्ट रैप एल्बम - केंड्रिक लैमर (Kendrick Lamar)

❑ ग्रैमी 2026 के मुख्य बिंदु:-

- ऐतिहासिक जीत: बैड बनी का एल्बम 'Debí Tirar Más Fotos' एल्बम ऑफ द ईयर जीतने वाला पहला स्पैनिश भाषा का एल्बम बन गया है।
- दलाई लामा का पहला ग्रैमी: बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने अपनी ऑडियो बुक 'Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama' के लिए बेस्ट ऑडियो बुक और नरेशन कैटेगरी में अपना पहला ग्रैमी जीता।
- केंड्रिक लैमर का रिकॉर्ड: केंड्रिक लैमर अब ग्रैमी के इतिहास में सबसे ज्यादा अवॉर्ड जीतने वाले हिप-हॉप कलाकार बन गए हैं (उन्होंने जय-ज़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया)।
- भारतीय कलाकार: सितार वादक अनुष्का शंकर इस साल भी नामांकित थीं, लेकिन वे अवॉर्ड जीतने से चूक गईं।
- EGOT स्टेटस: फिल्म निर्माता स्टीवन स्पीलबर्ग ने बेस्ट म्यूजिक फिल्म (Music by John Williams) के लिए ग्रैमी जीतकर प्रतिष्ठित EGOT (एमी, ग्रैमी, ऑस्कर, टोनी) स्टेटस हासिल कर लिया।

❑ ग्रैमी अवार्ड के बारे में:-

- ग्रैमी अवार्ड्स (Grammy Awards) को संगीत की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। इसे "म्यूजिक इंडस्ट्री का ऑस्कर" भी कहा जाता है।
- यह पुरस्कार संगीतकारों, गायकों, गीतकारों और तकनीकी विशेषज्ञों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है।
- इसकी शुरुआत 1959 में हुई थी। पहला समारोह 4 मई, 1959 को आयोजित किया गया था।
- "ग्रैमी" नाम थॉमस एडिसन के आविष्कार 'ग्रामोफोन' (Gramophone) से लिया गया है।
  - → यह पुरस्कार The Recording Academy (नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज) द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

→ पंडित रविशंकर, ग्रैमी जीतने वाले पहले भारतीय (1968) हैं , उन्होंने अपने जीवनकाल में कुल 5 ग्रैमी जीते।

03 प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को 2026 का क्रैफोर्ड पुरस्कार

❑ चर्चा में क्यों?

रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने भारतीय मूल के प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन (Veerabhadran Ramanathan) को 2026 के क्रैफोर्ड पुरस्कार (Crafoord Prize) के लिए चुना है। भूविज्ञान (Geosciences) के क्षेत्र में दिए जाने वाले इस पुरस्कार को अक्सर 'जियोसाइंसेज का नोबेल' भी कहा जाता है।

मुख्य बिंदु

- रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने रामनाथन को "अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों (SLCP) और ग्रीनहाउस प्रभाव की भूमिका की वैज्ञानिक समझ को विस्तारित करने में उनके अग्रणी योगदान" के लिये चयनित किया।
- उन्होंने प्रथम बार यह प्रमाणित किया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs), जो पूर्व में केवल ओज़ोन परत के क्षरण से सबंधित माने जाते थे, प्रभावशाली ग्रीनहाउस गैसों के रूप में भी कार्य करते हैं।
- 1975 में उन्होंने यह खोज की थी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) जैसे गैसें कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में हजारों गुना अधिक गर्मी सोखती हैं। इससे दुनिया को पता चला कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए केवल CO_2 ही जिम्मेदार नहीं है।
- उनके शोध में दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र के ऊपर बने कालिख और धूल के विशाल ब्राउन मेघ की उपस्थिति को रेखांकित किया गया।
- उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि ये कण (ब्लैक कार्बन) सूर्य विकिरण को अवशोषित कर वायुमंडल को गर्म करते हैं तथा साथ-ही-साथ पृथ्वी की सतह को ठंडा करते हैं, जिससे मानसूनी प्रवृत्तियाँ प्रभावित होती हैं।
- उनके वैज्ञानिक प्रमाणों ने 'मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल' जैसी अंतरराष्ट्रीय संधियों को मजबूत बनाने में मदद की।

❑ क्रैफोर्ड पुरस्कार के बारे में -

- इसकी स्थापना 1980 में स्वीडिश उद्योगपति होल्गर क्रैफोर्ड और उनकी पत्नी अन्ना-ग्रेटा क्रैफोर्ड द्वारा की गई थी।
- यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है।
- उन वैज्ञानिक क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देना जो नोबेल पुरस्कार की श्रेणियों में नहीं आते।
- क्रैफोर्ड पुरस्कार मुख्य रूप से चार क्षेत्रों में दिया जाता है, जो चक्र (Rotation) के अनुसार हर साल बदलते रहते हैं:
  - → खगोल विज्ञान और गणित
  - → भू-विज्ञान
  - → जीव विज्ञान (मुख्य रूप से पारिस्थितिकी)
  - → पॉलीआर्थराइटिस (यह विशेष रूप से इसलिए जोड़ा गया क्योंकि होल्गर क्रैफोर्ड स्वयं इस बीमारी से पीड़ित थे)।

04 विंग्स इंडिया 2026 पुरस्कार: दिल्ली एयरपोर्ट सर्वश्रेष्ठ

हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित विंग्स इंडिया 2026 (Wings India 2026) में भारतीय विमानन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले हवाई अड्डों, एयरलाइनों और संस्थाओं को सम्मानित किया गया। नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने ये पुरस्कार प्रदान किए।

मुख्य बिंदु

- विंग्स इंडिया 2026 अवॉर्ड्स में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को मिला है।
- विंग्स इंडिया 2026 अवॉर्ड्स नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने FICCI और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के सहयोग से आयोजित किया था।
- इन अवॉर्ड्स में एयरपोर्ट्स, एयरलाइंस, सर्विस प्रोवाइडर्स, मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन और राज्य सरकारों में बेहतरीन प्रदर्शन को पहचान मिली।

❑ प्रमुख विजेता :-

➲ **हवाई अड्डा श्रेणी -**

- वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा - दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड
- सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा (>25 MPPA) - केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु
- सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा (10–25 MPPA) - पुणे हवाई अड्डा
- सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा (5–10 MPPA) - लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड
- सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा (<5 MPPA) - वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर
- RCS/UDAN के तहत सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा - होलोंगी हवाई अड्डा ईटानगर

➲ **एयरलाइन और कनेक्टिविटी श्रेणी -**

- सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन (घरेलू कनेक्टिविटी): एयर इंडिया एक्सप्रेस
- सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन (क्षेत्रीय/UDAN कनेक्टिविटी): स्टार एयर (घोड़ावत एंटरप्राइजेज)
- सर्वश्रेष्ठ विमानन सेवा प्रदाता: इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (IndiGo)
- सर्वश्रेष्ठ NSOP (फिक्स्ड विंग): इंडो पैसिफिक एविएशन (JetSetGo की सहायक कंपनी)
- सर्वश्रेष्ठ NSOP (हेलीकॉप्टर): पवन हंस लिमिटेड

➲ **अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार**

- आत्मनिर्भर भारत में सर्वश्रेष्ठ योगदानकर्ता: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)
- सर्वश्रेष्ठ इकोसिस्टम एक्सेलेरेटर: बोइंग इंडिया (Boeing India)
- कार्गो सेवाएं: एयर इंडिया लिमिटेड और WFS (बेंगलुरु) को संयुक्त रूप से।

- ड्रोन श्रेणी: आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड (सर्वश्रेष्ठ ड्रोन) और कार्बन लाइट प्राइवेट लिमिटेड (सर्वश्रेष्ठ घटक निर्माता)।
- राज्यों में सम्मान: आंध्र प्रदेश (विमानन के लिए समर्पित विजन), तेलंगाना और उत्तराखंड (विमानन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए)।

- नोट :- दिल्ली एयरपोर्ट को न केवल सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया, बल्कि इसे 'सस्टेनेबिलिटी चैंपियन' का पुरस्कार भी मिला।

05 भूटान की राजमाता को उपेंद्र नाथ ब्रह्मा 'मानवता के सिपाही' पुरस्कार 2025

❑ चर्चा में क्यों?

भूटान की महारानी ग्याल्युम आशी दोरजी वांगमो वांगचुक को 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा 'मानवता के सिपाही' पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह उनके द्वारा समाज सेवा और साहित्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों का एक शानदार प्रमाण है।

❑ उपेंद्र नाथ ब्रह्मा 'मानवता के सिपाही' पुरस्कार

- उद्देश्य: यह पुरस्कार बोडो समुदाय के महान नेता 'बोडोफा' उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की स्मृति में दिया जाता है। यह उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने मानवता, शांति और सामाजिक सुधार के लिए निस्वार्थ काम किया है।
- महत्व: यह सम्मान अक्सर उन लोगों को दिया जाता है जो हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए समर्पित होते हैं।

❑ राजमाता आशी दोरजी वांगमो वांगचुक का योगदान

- भूटान की राजमाता केवल एक शाही व्यक्तित्व ही नहीं, बल्कि एक सक्रिय समाज सुधारक और लेखिका भी हैं। उनके कार्यों के कुछ मुख्य पहलू:
  - → तरयाणा फाउंडेशन (Tarayana Foundation): उन्होंने इस संस्था की स्थापना की, जो भूटान के दूरदराज के गांवों में गरीबी कम करने, आवास की स्थिति सुधारने और बच्चों की शिक्षा के लिए काम करती है।
  - → साहित्यिक योगदान: वे एक प्रसिद्ध लेखिका हैं। उनकी किताबें, जैसे "Of Rainbows and Clouds" और "Treasures of the Thunder Dragon: A Portrait of Bhutan", भूटान की संस्कृति और इतिहास को दुनिया के सामने खूबसूरती से रखती हैं।
  - → सांस्कृतिक दूत: वे भारत और भूटान के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में एक सेतु का काम करती रही हैं।
- नोट: उपेंद्र नाथ ब्रह्मा को 'बोडोफा' (बोडो के पिता) कहा जाता है, और यह पुरस्कार भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों, विशेषकर असम और पड़ोसी देशों के बीच भाईचारे का प्रतीक माना जाता है।

06 पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार

पारादीप पोर्ट अथॉरिटी (PPA) ने स्वच्छता, स्थिरता और जनभागीदारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है।

मुख्य बिंदु

- पुरस्कार: स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 (प्रथम स्थान)
- आयोजक: पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW)
- अवार्ड समारोह: 3 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित
- प्रमुख पहल: "स्क्रैप टू स्ट्रक्चर", वेस्ट-टू-वेल्थ प्रदर्शनी, जनभागीदारी, सफाई मित्र कल्याण, और पर्यावरण अनुकूल संचालन
- उद्देश्य: स्वच्छता पखवाड़ा 2025 और 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के तहत अनुकरणीय कार्यों को मान्यता देना
- यह पुरस्कार स्वच्छता, स्थिरता और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बंदरगाह संचालन के प्रति PPA की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

❑ पारादीप पोर्ट (Paradip Port) के बारे में -

- यह ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित भारत का एक प्रमुख, प्राकृतिक और गहरे पानी का बंदरगाह है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1962 में ओडिशा सरकार द्वारा की गई थी।
- वर्ष 1965 में भारत सरकार ने बंदरगाह का स्वामित्व एवं प्रबंधन ओडिशा सरकार से ले लिया।
- 18 अप्रैल 1966 को भारत सरकार द्वारा पारादीप बंदरगाह को भारत का 8वाँ प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया।
- इस पोर्ट्रेट का प्रबंधन पारादीप पोर्ट ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।
  - → पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के तहत एक स्वत्व निगम है।
  - → यह बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में 145.38 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) से अधिक कार्गो को संभालकर भारत का शीर्ष कार्गो-हैंडलिंग प्रमुख बंदरगाह बन गया है।

07 रूबल नागी को प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचर प्राइज 2026

❑ चर्चा में क्यों?

भारतीय शिक्षिका और कलाकार रूबल नागी (Rouble Nagi) ने दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 में प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीता है। उन्हें 139 देशों के 5,000 से अधिक नामांकनों में से चुना गया और 10 लाख डॉलर की इनामी राशि से सम्मानित किया गया है।

मुख्य बिंदु

- सम्मान का कारण: उन्हें उनके अभिनव प्रोजेक्ट 'लिविंग वॉल्स ऑफ लर्निंग' (Living Walls of Learning) के लिए सम्मानित किया गया है।
  - → इसके तहत उन्होंने झुग्गी-झोपड़ियों और ग्रामीण इलाकों की दीवारों को इंटरैक्टिव मानचित्रों और कलाकृतियों में बदलकर उन्हें 'ओपन-एयर क्लासरूम' का रूप दिया है।

- प्रभाव: पिछले दो दशकों में उनकी संस्था 'रुबल नागी आर्ट फाउंडेशन' ने भारत भर में 800 से अधिक शैक्षिक केंद्र स्थापित किए हैं और लगभग 10 लाख बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने में मदद की है।
- भविष्य की योजना: रुबल नागी ने घोषणा की है कि वह इस पुरस्कार राशि का उपयोग वंचित युवाओं के लिए एक मुफ्त व्यावसायिक संस्थान (Vocational Institute) और डिजिटल साक्षरता केंद्र खोलने के लिए करेंगी।
- नोट :- रुबल नागी यह पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय हैं। उनसे पहले 2020 में महाराष्ट्र के रंजीतसिंह डिसले ने यह सम्मान प्राप्त किया था।

08 चांग-क्रैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड 2026

हाल ही में पुडुचेरी के दो वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञों को मोतियाबिंद से होने वाली अंधता और दृष्टि विकलांगता के विरुद्ध उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित चांग-क्रैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड 2026 से सम्मानित किया जाएगा।

❑ महत्व:-

- वैश्विक पहचान: यह अवॉर्ड 'अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मोइयाबिंद एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी' (ASCRS) द्वारा दिया जाता है, जो इसे एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि बनाता है।
- अंधता के खिलाफ जंग: भारत में मोतियाबिंद अंधता का एक प्रमुख कारण है। इन विशेषज्ञों का कार्य न केवल मरीजों की आंखों की रोशनी लौटाता है, बल्कि उन्हें एक आत्मनिर्भर जीवन भी प्रदान करता है।
- प्रेरणा: पुडुचेरी के इन डॉक्टरों की सेवा यह दर्शाती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद समर्पण और कौशल के साथ वैश्विक प्रभाव डाला जा सकता है।

❑ मोतियाबिंद (Cataract) क्या है?

- मोतियाबिंद आंखों के प्राकृतिक लेंस के धुंधला हो जाने की स्थिति है। यह आमतौर पर उम्र के साथ होता है, लेकिन सही समय पर सर्जरी के माध्यम से इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है।

विशेषता	सामान्य आंख	मोतियाबिंद वाली आंख
लेंस	पूरी तरह पारदर्शी	धुंधला या अपारदर्शी
दृष्टि	स्पष्ट और साफ	धुंधली या बादलों जैसी
उपचार	आवश्यकता नहीं	सर्जरी (लेंस प्रत्यारोपण)

09 बी बी सी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर 2025

हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को वर्ष 2025 में खेल जगत में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और उपलब्धियों के लिए नई दिल्ली में आयोजित एक प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह में BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया।

मुख्य बिंदु

- स्मृति मंधाना को उनके लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन तथा विशेष रूप से वर्ष 2025 महिला विश्व कप में भारत की ऐतिहासिक जीत में उनकी अहम भूमिका के लिये यह सम्मान प्राप्त हुआ।
- इनके साथ ही शतरंज की प्रतिभा दिव्या देशमुख को FIDE महिला विश्व कप में उनकी ऐतिहासिक जीत के लिए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया।
  - → दिव्या देशमुख ने महज 20 साल की उम्र में FIDE महिला विश्व कप में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी।
- प्रीति पाल को वर्ष 2024 पेरिस पैरालंपिक में दो कांस्य पदक जीतने के लिये पैरा-स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर का खिताब मिला।
- अनुभवी निशानेबाज़ अंजलि भागवत को उनके पथप्रदर्शक करियर के लिये लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।
- विजेताओं का चयन एक प्रतिष्ठित जूरी द्वारा किया गया, जिसमें लिएंडर पेस, दीपा मलिक और अंजू बॉबी जॉर्ज जैसी खेल हस्तियाँ शामिल थीं।
- यह पुरस्कार समारोह भारतीय महिला खिलाड़ियों की उत्कृष्टता और प्रभाव को सम्मानित करता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनके योगदान को रेखांकित करता है तथा भावी पीढ़ियों को प्रेरित करता है।

❑ बीबीसी के बारे में:-

- बीबीसी (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन) यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय प्रसारक और दुनिया के सबसे पुराने, बड़े और प्रतिष्ठित मीडिया संगठनों में से एक है।
- 18 अक्टूबर 1922 को स्थापित यह संस्था लंदन से संचालित होती है और टीवी, रेडियो और ऑनलाइन के माध्यम से 40 से अधिक भाषाओं में निष्पक्ष समाचार और मनोरंजन प्रदान करती है।

10 "भव्य भारत भूषण पुरस्कार" (2026)

❑ चर्चा में क्यों?

ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव द्वारा शुरू किया गया "भव्य भारत भूषण पुरस्कार" (2026) विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय निर्माण और उत्कृष्ट योगदान देने वाले दिग्गजों को सम्मानित करने वाला एक नया पुरस्कार है। यह पुरस्कार, रक्षा मंत्री द्वारा कोयंबटूर के ईशा योग केंद्र में महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रदान किया गया।

❑ 2026 के प्रमुख पुरस्कार प्राप्तकर्ता:

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: नम्बी नारायणन, किरण कुमार
- खेल: साइना नेहवाल
- कला एवं संस्कृति: एन. राजम (वायलिन वादक), अलार्मेल वल्ली (नृत्यांगना), विक्रम संपत (इतिहासकार)
- विशेष सम्मान (सशस्त्र बल): एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा, लेफ्टिनेंट जनरल एवीएस राठी, वाइस एडमिरल आरवी गोखले (ऑपरेशन सिंदूर के लिए)

❑ सद्गुरु जग्गी वासुदेव के बारे में

- सद्गुरु जग्गी वासुदेव एक प्रसिद्ध भारतीय आध्यात्मिक गुरु, योगी और लेखक हैं। वे ईशा फाउंडेशन (Isha Foundation) के संस्थापक हैं, जो दुनिया भर में योग और सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों का संचालन करता है।

➲ योगदान:-

- ईशा फाउंडेशन और योग
  - → स्थापना: उन्होंने 1992 में कोयंबटूर (तमिलनाडु) के पास 'ईशा फाउंडेशन' की स्थापना की। यह एक गैर-लाभकारी संस्था है।
  - → ईशा योग: वे 'ईशा योग' के माध्यम से लोगों को ध्यान और आंतरिक शांति की शिक्षा देते हैं। उनका मुख्य कार्यक्रम 'इनर इंजीनियरिंग' (Inner Engineering) के नाम से जाना जाता है।
  - → आदियोगी प्रतिमा: उन्होंने कोयंबटूर में भगवान शिव की 112 फीट ऊंची 'आदियोगी' प्रतिमा स्थापित की है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्द्धप्रतिमा (Bust Sculpture) माना जाता है।
- प्रमुख सामाजिक और पर्यावरणीय अभियान
- सद्गुरु अपने आध्यात्मिक कार्यों के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काफी सक्रिय रहते हैं:
  - → मिट्टी बचाओ (Save Soil): यह एक वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य के प्रति लोगों और सरकारों को जागरूक करना है।
  - → कावेरी कॉलिंग (Kaveri Calling): कावेरी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का अभियान चलाया।
  - → रैली फॉर रिवर्स (Rally for Rivers): भारत की नदियों के संरक्षण के लिए उन्होंने पूरे देश में जागरूकता पैदा की।
- लेखन और विचार
- सद्गुरु अपनी तार्किक और आधुनिक शैली में जटिल आध्यात्मिक विषयों को समझाने के लिए जाने जाते हैं।
- उनकी पुस्तक 'Inner Engineering: A Yogi's Guide to Joy' न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्टसेलर सूची में रही है।
- वे विश्व आर्थिक मंच (WEF) और संयुक्त राष्ट्र (UN) जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी अपने विचार साझा करते हैं।

11 आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल, वसई (पालघर)

❑ चर्चा में क्यों?

महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई (पापड़ी) में स्थित 16वीं शताब्दी के आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल (Our Lady of Grace Cathedral) को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2025 यूनेस्को एशिया-प्रशांत पुरस्कारों में 'मेरिट पुरस्कार' (Award of Merit) से सम्मानित किया गया है।

मुख्य बिंदु

- पुरस्कार मिलने का कारण:16वीं शताब्दी के इस पुर्तगाली कैथेड्रल को पारंपरिक शिल्प कौशल का उपयोग करके स्थानीय समुदाय के सहयोग से किए गए उत्कृष्ट जीर्णोद्धार के लिए यह सम्मान मिला है।
- ऐतिहासिक महत्व: वसई के पापड़ी गांव में स्थित यह कैथेड्रल लगभग 475 वर्ष पुराना है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी (लगभग 1550 ईस्वी) में पुर्तगाली शासन के दौरान किया गया था।
- स्थापत्य शैली: यह चर्च भारत में पुर्तगाली औपनिवेशिक वास्तुकला (Portuguese colonial architecture) का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसकी संरचना पत्थर और मिट्टी के गारे से बनी है, जिसमें आधुनिक सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया था।
- सामुदायिक प्रयास: इस संरक्षण परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे पूरी तरह से स्थानीय समुदाय (Parish members) द्वारा वित्तपोषित किया गया था। इसमें लगभग ₹4.5 करोड़ का खर्च आया, जो दान के माध्यम से जुटाया गया।
- संरक्षण तकनीक: इसे बिना सीमेंट का उपयोग किए, पारंपरिक चूना-आधारित तरीकों और कारीगरी से नवीनीकृत किया गया।
- विशेष रूप से चर्च के आंतरिक भाग (liturgical elements) पर हाथ से की गई नक्काशी को उसके मूल स्वरूप में वापस लाया गया।
  - → परियोजना का नेतृत्व संरक्षण विशेषज्ञ ऐन्सले लुईस द्वारा किया गया।

❑ यूनेस्को पुरस्कार 2025 के बारे में

- यूनेस्को एशिया-प्रशांत पुरस्कार (UNESCO Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation) निजी संस्थाओं और समुदायों द्वारा विरासत संरचनाओं के संरक्षण के प्रयासों को मान्यता देते हैं।
  - → Award of Merit अवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल, वसई (भारत) को प्राप्त हुआ।
  - → Award of Distinction सिहांग वेअरहाऊस (चीन) और इवामी गिन्झान लाइब्रेरी (जापान) को मिला।

12 मणिपुरी फिल्म 'Boong' (बूंग) को सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का BAFTA अवार्ड

फरवरी 2026 में लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में आयोजित 79वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स (BAFTA) में मणिपुरी फिल्म 'Boong' (बूंग) ने सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का बाफ्टा पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया।

मुख्य बिंदु

- ऐतिहासिक जीत: 'Boong' यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। इसे 'बेस्ट चिल्ड्रेन्स एंड फैमिली फिल्म' (Best Children's & Family Film) श्रेणी में सम्मानित किया गया।
- प्रतिस्पर्धा: इस फिल्म ने 'Lilo & Stitch', 'Zootropolis 2' और 'Arco' जैसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय फिल्मों को पछाड़कर यह खिताब अपने नाम किया।
- निर्देशक और निर्माता: इस फिल्म का निर्देशन लक्ष्मिप्रिया देवी (Lakshmipriya Devi) ने किया है। इसे फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी की कंपनी 'एक्सेल एंटरटेनमेंट' (Excel Entertainment) के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया गया है।

- कहानी का सार: फिल्म की कहानी एक छोटे लड़के 'बूंग' के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी मां को उपहार देने के लिए अपने खोए हुए पिता को खोजने की कोशिश करता है।
- शांति का संदेश: पुरस्कार स्वीकार करते समय निर्देशक लक्ष्मिप्रिया देवी ने एक भावुक भाषण दिया और मणिपुर में शांति बहाली की प्रार्थना की।

❑ BAFTA 2026 के अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार:-

- 79वें बाफ्टा (BAFTA) फिल्म अवॉर्ड्स 2026 में फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनदर' (One Battle After Another) का दबदबा रहा, जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित कुल 6 पुरस्कार अपने नाम किए।

➲ मुख्य विजेताओं की सूची (BAFTA 2026)

श्रेणी (Category)	विजेता (Winner)
सर्वश्रेष्ठ फिल्म	वन बैटल आफ्टर अनदर (One Battle After Another)
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक	पॉल थॉमस एंडरसन (वन बैटल आफ्टर अनदर)
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता	रॉबर्ट आरामयो (फिल्म: आई स्वियर)
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री	जेसी बकले (फिल्म: हैमनेट)
सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता	शॉन पेन (वन बैटल आफ्टर अनदर)
सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री	वुनमी मोसाकू (फिल्म: सिनर्स)
बेस्ट चिल्ड्रन्स एंड फैमिली फिल्म	बूंग (Boong) - भारतीय फिल्म (मणिपुरी)
आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म	हैमनेट (Hamnet)
सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म	ज़ूट्रोपोलिस 2 (Zootropolis 2)
सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री	मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन (Mr. Nobody Against Putin)

❑ बाफ्टा (BAFTA) के बारे में

- बाफ्टा (BAFTA) का पूरा नाम ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स (British Academy of Film and Television Arts) है।
- यह एक विश्व प्रसिद्ध संस्था है जो फिल्म, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करती है।
- इसे अक्सर "ब्रिटिश ऑस्कर" भी कहा जाता है क्योंकि इसका महत्व और प्रतिष्ठा अमेरिकी ऑस्कर पुरस्कारों के समान मानी जाती है।
  - → इसकी स्थापना 1947 में 'ब्रिटिश फिल्म एकेडमी' के रूप में हुई थी। बाद में 1976 में इसका नाम बदलकर BAFTA कर दिया गया।
  - → पुरस्कार स्वरूप विजेताओं को एक 'सुनहरा मुखौटा' (Golden Mask) दिया जाता है, जिसे प्रसिद्ध मूर्तिकार मित्ज़ी कनिफ (Mitzi Cunliffe) ने डिजाइन किया था।

13 'स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल'

❑ चर्चा में क्यों?

हाल ही में इजरायली संसद (नेसेट) द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल' (Speaker of the Knesset Medal) से सम्मानित करने के कारण यह चर्चा में बना हुआ है। यह इजराइल की संसद (नेसेट) द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च संसदीय सम्मान है।

मुख्य बिंदु

- प्रथम वैश्विक प्राप्तकर्ता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पदक को प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले वैश्विक नेता बने हैं।
- प्रदाता: यह सम्मान इजराइली संसद के स्पीकर अमीर ओहाना (Amir Ohana) द्वारा प्रदान किया गया।
- उद्देश्य: यह पदक उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने इजराइल राज्य, यहूदी लोगों और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए असाधारण योगदान दिया हो। पीएम मोदी को यह भारत-इजराइल रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के उनके प्रयासों के लिए दिया गया।

❑ पदक की बनावट:

- यह मेडल गोल्ड-प्लेटेड ब्रोंज (सोने की परत चढ़ा हुआ कांस्य) से बना है।
- इसके एक तरफ इजराइल का राजकीय प्रतीक और नेसेट भवन बना है, जबकि दूसरी तरफ नेसेट का सदन (Plenum) दर्शाया गया है।
- इस पर बाइबल की एक आयत (Psalms 8:6) अंकित है: "Hast crowned him with glory and honor" (उसे महिमा और सम्मान का ताज पहनाया है)।

❑ ऐतिहासिक महत्व

- पीएम मोदी दुनिया के उन गिने-चुने नेताओं में शामिल हो गए हैं जिन्हें इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हैं। 2018 में उन्हें फिलिस्तीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन' भी मिल चुका है।

14 पुरस्कार एवं सम्मान (To The Point)

- तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को "ग्रैमी अवॉर्ड 2026" प्रदान किया गया।
  - → लॉस एंजिलिस में आयोजित 68वें ग्रैमी अवॉर्ड्स में इतिहास रचते हुए 90 वर्ष की आयु में दलाई लामा ने अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता।
  - → उनको यह सम्मान स्पोकन - वर्ड एल्बम "Meditions" के लिए मिला है।
- भारत के स्वच्छता और सतत विकास अभियान के तहत पारादीप पोर्ट प्राधिकरण ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार जीता।
- भारतीय कलाकार और शिक्षिका रुबल नागी ने दुबई में आयोजित 'वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026' में प्रतिष्ठित 'ग्लोबल टीचर प्राइज' जीता।

→ जीईएमएस एजुकेशन द्वारा प्रदत्त दस लाख डॉलर का यह पुरस्कार उन्हें दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम द्वारा प्रदान किया गया।

- इंडिया एनर्जी वीक (IEW) 2026 के दौरान, ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) ने प्रतिष्ठित 'ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर' के लिए FIPI अवॉर्ड 2025 जीता।
- भारतीय ग्रैंडमास्टर दिव्या देशमुख हाल ही में बी. बी. सी. इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 अवॉर्ड से नवाजी गयीं।
  → दिव्या देशमुख ने महज़ 20 साल की उम्र में FIDE महिला विश्व कप में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी।
- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में विक्रमोत्सव 2026 का शुभारंभ करते हुए सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर ₹1.01 करोड़ का वार्षिक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की।
- मुंबई को प्रिंस विलियम द्वारा स्थापित विश्व के सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली पर्यावरण पुरस्कार "अर्थशॉट पुरस्कार 2026" के मेजबान के रूप में घोषित किया गया।
- महाराष्ट्र के वसई में स्थित 16वीं शताब्दी के आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को पारंपरिक शिल्प कौशल और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से उत्कृष्ट जीर्णोद्धार के लिए 2025 यूनेस्को एशिया-पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट (UNESCO Asia-Pacific Award of Merit) से सम्मानित किया गया है।
- करण अदानी को 2026 मैनेजिंग इंडिया अवार्डस में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर नामित किया गया है।
- इजरायल की संसद द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल' से सम्मानित किया गया।
- मुम्बई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एशिया-प्रशांत का सर्वश्रेष्ठ प्रस्थान (डिपार्चर) हवाई अड्डा चुना गया।

NOT FOR SALE

भारत में एआई का युग और पर्यावरण संरक्षण (नवाचार से स्थिरता तक एक नई दिशा)

जलवायु परिवर्तन आज एक गंभीर वास्तविकता है, जो हमारे जीवन और आजीविका के लगभग हर पहलू को प्रभावित कर रही है। जैसे-जैसे जलवायु जोखिम बढ़ रहे हैं, अडैप्टेशन और मिटिगेशन के लिए सक्रिय और दूरदर्शी समाधानों की आवश्यकता है। भारत ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है— चाहे वह ग्रीन कवर बढ़ाना हो, अक्षय ऊर्जा का दोहन हो, उत्सर्जन में कमी लाना हो या गंभीर मौसम की चुनौतियों से निपटना हो। हाल के वर्षों में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध इस लड़ाई में एक शक्तिशाली टूल बनकर उभरा है। एआई कंप्यूटरों को डेटा से सीखने और मनुष्यों की तरह निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। इसी के भीतर डीप लर्निंग एक ऐसी पद्धति है जो बड़ी मात्रा में सूचनाओं का विश्लेषण कर कंप्यूटर की सीखने की क्षमता को और बेहतर बनाती है। एआई प्रणालियाँ जलवायु से संबंधित डेटा का विश्लेषण करती हैं और बेहतर जलवायु मॉडलिंग, अक्षय ऊर्जा उत्पादन के अनुकूलन, सतत कृषि के समाधान और आपदा प्रबंधन की मजबूती के लिए प्रभावी उत्तर प्रदान करती हैं।

समावेशी विकास को गति देने में एआई की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया गया। यह ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन रहा। पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस (जन, पर्यावरण और प्रगति) के तीन आधारभूत स्तंभों पर टिका यह सम्मेलन शासन, नवाचार और सतत विकास के क्षेत्रों में एआई की परिवर्तनकारी क्षमता पर केंद्रित था।

❑ एआई की मदद से आपदा की समय रहते चेतावनी और बचाव

उन्नत तकनीक मौसम के पैटर्न का पूर्वानुमान लगाने और प्राकृतिक आपदाओं की तैयारी करने के हमारे तरीके को नया रूप दे रही है।

➲ मौसम पूर्वानुमान की जानकारी देने वाला सिस्टम: चक्रवात और गंभीर मौसम का अंदाज़ा लगाने की तकनीक का सटीक मॉडल

भारत ने एआई असिस्टेड टूल्स की मदद से चक्रवात की भविष्यवाणी करने की अपनी क्षमता को काफी बेहतर बना लिया है:

1. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) और अन्य सरकारी संस्थाएं समुद्री तूफान (चक्रवात) की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए एडवांस्ड ड्वोरक तकनीक (एडीटी) का इस्तेमाल कर रही हैं।

/// चक्रवात की निगरानी ///

भारतीय मौसम विभाग समुद्री तूफानों (चक्रवातों) पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल करता है। तूफान कितना ताकतवर है, इसका अंदाज़ा लगाने में एडवांस्ड ड्वोरक तकनीक मदद करती है। इसके साथ ही, आईएमडी मौसम की भविष्यवाणी करने वाले यूरोपीय केंद्र (यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम-रेंज वेदर फोरकास्टिंग) से मिलने वाले एआई बेस्ड गाइडेंस का भी उपयोग करता है। ये सभी आधुनिक तकनीकें यह बताने में मदद करती हैं कि चक्रवात कब बनेगा, किस दिशा में जाएगा और वह कितना शक्तिशाली होगा।

2. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 22 पेटाफ्लॉप्स की भारी क्षमता वाले हाई-पावर कंप्यूटिंग सिस्टम (सुपरकंप्यूटर) लगाए हैं। इस सिस्टम का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा खास तौर पर एआई के कामों के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा, मौसम की भविष्यवाणी में एआई और मशीन लर्निंग रिसर्च के लिए अलग से ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स भी लगाए गए हैं। ये शक्तिशाली सिस्टम मौसम का और भी सटीक अनुमान लगाने वाले मॉडल तैयार करने में मदद करते हैं।

➲ अनुसंधान और विकास के तहत

1. भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित ट्रांसफॉर्मर-आधारित न्यूरल नेटवर्क मानसून के व्यवहार की 18 दिन पहले ही भविष्यवाणी कर सकते हैं।
2. दुनिया भर के एआई सिस्टम (जैसे GraphCast, PanguWeather, Aurora और FourCastNet) के तुलनात्मक अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि अब चक्रवात के जमीन से टकराने के 96 घंटे पहले ही उसके रास्ते का सटीक पता लगाया जा सकता है। यह तकनीक कुछ ही सेकंड्स में 200 किलोमीटर के दायरे तक की सटीक जानकारी दे देती है। इन सुधारों की वजह से लोगों को सुरक्षित निकालने की योजना बनाने और बिजली-पानी जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर को बचाने में बहुत मदद मिल रही है।
3. आईआईटी बॉम्बे ने स्पेशली अवेयर डोमेन एडाप्टेशन नेटवर्क (SpADANet) नाम का एक एआई मॉडल विकसित किया है। यह मॉडल हवाई तस्वीरों के जरिए चक्रवात और तूफानों से हुए नुकसान का सटीक अंदाजा लगाता है। इस मॉडल ने पुराने तरीकों की तुलना में 5 प्रतिशत बेहतर सटीकता हासिल की है। यह मॉडल कम डेटा होने पर भी सही परिणाम दे सकता है। यह एनडीएमए जैसी आपदा प्रबंधन एजेंसियों की बड़ी समस्याओं, जैसे—डेटा की कमी और कम कंप्यूटर पावर—को हल करता है, जिससे आपदा के समय तेजी से और भरोसेमंद तरीके से मदद पहुंचाई जा सके।
4. आईआईटी मद्रास भारत में जलवायु की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए रिलायबिलिटी एनसेंबल एवरेजिंग (आरईए) तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने 26 अलग-अलग जलवायु मॉडलों को एक साथ मिलाया और हर मॉडल को इस आधार पर नंबर दिए कि वे वर्तमान और भविष्य के मौसम को कितनी सटीकता से बताते हैं। जब भारत के चार शहरों कोयंबटूर, राजकोट, उदयपुर और सिलीगुड़ी में इनका परीक्षण

किया गया, तो पाया गया कि ज्यादातर मॉडल बारिश की सही भविष्यवाणी करने में पीछे रह गए। लेकिन, आरईए तकनीक बहुत ही भरोसेमंद नतीजे देती है, जिससे मानसून वाले इलाकों में भविष्य की योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

5. भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे में एक वर्चुअल सेंटर बनाया गया है, जो एआई आधारित एप्लिकेशन टूल्स विकसित करता है। भारतीय मौसम विभाग ने एआई और मशीन लर्निंग रिसर्च को मजबूत करने के लिए एक विशेष टीम तैयार की है। इसके साथ ही, आईएमडी ने एआई रिसर्च में सहयोग के लिए आईआईटी, एनआईटी, इसरो, डीआरडीओ और अन्य बड़े संस्थानों के साथ समझौते किए हैं। वैज्ञानिकों को वर्कशॉप और कोर्सेज के माध्यम से एआई की ट्रेनिंग दी जा रही है। आईएमडी हर साल मई के महीने में एआई और मशीन लर्निंग के बुनियादी सिद्धांतों पर एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है।

➲ भूस्खलन, बाढ़ और ग्लेशियर की निगरानी

खतरे की संभावना वाले संवेदनशील क्षेत्रों में एआई आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां पहले से ही काम कर रही हैं:

1. भारत में विकसित स्वदेशी एआई-आधारित भूस्खलन चेतावनी प्रणाली अब पहाड़ खिसकने से तीन घंटे पहले ही अलर्ट दे देती है। यह सिस्टम कम लागत वाले सेंसरों का उपयोग करता है जो मिट्टी की नमी, बारिश, नमी, तापमान और जमीन की हलचल को मापते हैं। यह सारा डेटा एक मशीन लर्निंग मॉडल को भेजा जाता है, जिसकी सटीकता 90 प्रतिशत से भी अधिक है। हिमाचल प्रदेश में 60 से अधिक स्थानों पर इसे लगाया गया है, जो जमीन में होने वाली मिलीमीटर जितनी छोटी हलचल को भी पहचान लेता है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामान से बना यह सिस्टम विदेशी तकनीक के मुकाबले बेहद सस्ता है और आपदा से निपटने में भारत की तैयारी को मजबूत करता है। इसकी मदद से भूस्खलन वाले इलाकों में समय रहते लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है।
2. इसरो द्वारा वित्तपोषित (2021-24) इंडियन लैंड डेटा एसिमिलेशन सिस्टम (आईएलडीएएस), रिमोट सेंसिंग और विशेष कंप्यूटर मॉडल्स की मदद से जमीन की स्थिति और बाढ़ के संभावित इलाकों का सटीक अनुमान लगाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसे क्षेत्रों में नदियों के बेहतर प्रबंधन के लिए भौतिक विज्ञान और एआई तकनीकों को मिलाकर बाढ़ की भविष्यवाणी करने वाले सिस्टम बनाए गए हैं। इसी क्रम में, BrahmaSATARK ब्रह्मपुत्र बेसिन के लिए बाढ़ का पूर्वानुमान देता है, जबकि GBM-CLIMPACT एक ऐसा टूलकिट है जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना बेसिन में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और जल क्षेत्र की तैयारी का आकलन करता है।

ये सभी एआई आधारित सिस्टम मिलकर खतरे की चेतावनी काफी समय पहले (लीड टाइम) देने में मदद करते हैं, जिससे लोगों को सुरक्षित निकालने की योजना बनाना आसान हो जाता है। इनकी मदद से इमारतों और बिजली-पानी जैसे बुनियादी ढांचे के नुकसान को कम किया जा सकता है और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील इलाकों में रहने वाले समुदायों को सुरक्षित रखा जा सकता है।

❑ अंतिम छोर तक जलवायु सूचना: समुदायों तक पहुँच

1. भारतीय मौसम विभाग ने पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से ग्राम पंचायत स्तर मौसम पूर्वानुमान (जीपीएलडब्ल्यूएफ) सेवा शुरू की है। यह सेवा भारत की लगभग सभी ग्राम पंचायतों को कवर करती है। इसमें एक साथ कई मौसम पूर्वानुमान मॉडलों का उपयोग किया जाता है। किसान इन भविष्यवाणियों को ई-ग्राम स्वराज, मेरी पंचायत और मौसम ग्राम जैसे ऐप्स के माध्यम से देख सकते हैं। इन सूचनाओं में तापमान, बारिश, नमी, हवा और बादलों की स्थिति की जानकारी शामिल होती है। इससे किसानों को बुवाई, कटाई और सिंचाई से जुड़े बेहतर फैसले लेने में मदद मिलती है।
2. भारत सरकार ने 27 मई, 2025 को भारत फोरकास्टिंग सिस्टम (BharatFS) लॉन्च किया है। यह पूरी तरह से भारत में विकसित मौसम पूर्वानुमान मॉडल है। यह गाँव के स्तर तक बहुत सटीक और विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। भारत-एफएस की रेज़ोल्यूशन क्षमता 6 किलोमीटर है, जो पिछले 12 किलोमीटर के मुकाबले कहीं बेहतर है। यह 10 दिन पहले ही बारिश की भविष्यवाणी कर सकता है। इससे किसानों, आपदा प्रबंधकों और आम जनता को मौसम के खतरों से निपटने और बेहतर तैयारी करने में बहुत मदद मिलती है।

❑ जलवायु और मौसम की भविष्यवाणियों के लिए नए एआई टूल्स

1. सरकार द्वारा मौसम जीपीटी (MausamGPT) नामक एक एआई चैटबॉट विकसित किया जा रहा है, जो किसानों और अन्य लोगों को जलवायु और मौसम के बारे में सलाह देगा। सरकार बारिश के पैटर्न का पूर्वानुमान लगाने और भविष्यवाणी करने के लिए एआई अनुसंधान कर रही है। एआई का उपयोग अब आग की घटनाओं, कोहरा, बिजली गिरने और गरज के साथ तूफान आने की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा रहा है। डीप लर्निंग तकनीक मौसम में बारिश की सटीक भविष्यवाणियों को बेहतर बनाने में मदद करती है।
2. एआई का उपयोग करके तटीय और समुद्र के स्तर की निगरानी भारत को जलवायु जोखिमों के लिए तैयार होने में मदद करती है। भारत की तटरेखाओं के साथ, एआई यह जाँच करता है कि बढ़ते समुद्री स्तर से कौन से क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। यह जानकारी सिटी प्लानर्स को बेहतर शहर डिजाइन करने में मदद करती है, जो इन बदलावों को झेल सकें। इसके बाद समुदाय भविष्य के खतरों से बचने के लिए खुद को तैयार और सुरक्षित कर सकते हैं।

सटीक और विस्तृत जलवायु जानकारी तक सभी की पहुँच को आसान बनाकर, भारत सामुदायिक स्तर पर संकटों से लड़ने की क्षमता को मजबूत कर रहा है।

❑ एआई-संचालित वन निगरानी और संरक्षण

1. एआई उन्नत निगरानी और मॉनिटरिंग तकनीकों के माध्यम से भारतीय वनों की रक्षा करता है। यह वन क्षेत्रों के आसपास

लगाए गए कैमरों से प्राप्त रियल-टाइम फुटेज का विश्लेषण करने के लिए मशीन विजन (एमवी) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है।

2. एआई जंगल की आग और उसका कारण बनने वाली मानवीय गतिविधियों के लिए एक मजबूत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करता है। यह आग को फैलने से पहले ही रोकने या नियंत्रित करने में मदद करता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया भर में लगने वाली 75 प्रतिशत आग के लिए इंसान ही जिम्मेदार हैं।
3. जंगल की सीमाओं पर लगाए गए एआई और मशीन विजन (एमवी) से लैस कैमरे उन जानवरों का पता लगा लेते हैं जो जंगल के बाहर भटक जाते हैं। यह मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने में मदद करता है, जो जंगल के इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा है।
4. एआई निगरानी तकनीकें संरक्षित वन क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण और पेड़ों की कटाई जैसी गतिविधियों का पता लगाती हैं।

सैटेलाइट, ड्रोन और जमीनी सेंसरों का एकीकृत नेटवर्क कंज़र्वेशन गवर्नेंस को मजबूत कर रहा है और प्राकृतिक कार्बन सिंक (जैसे जंगलों) को सुरक्षित रख रहा है।

❑ वायु एवं जल जोखिम प्रबंधन हेतु एआई आधारित नवाचार

➲ रियल-टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग:

आईआईटी कानपुर के AIRAWAT रिसर्च फाउंडेशन और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर सस्टेनेबल शहरों के लिए एआई तकनीक विकसित करने का एक समझौता किया है। यह साझेदारी शहरों की बड़ी समस्याओं जैसे—वायु गुणवत्ता, बिजली, ट्रैफिक, कचरा प्रबंधन और डिजिटल सरकारी सेवाओं को सुधारने पर काम करेगी। इसमें खास तौर पर ऐसे स्मार्ट सेंसर बनाए जाएंगे जो हवा में प्रदूषण के साथ-साथ हानिकारक कीटाणुओं (बायोएरोसोल) की भी तुरंत पहचान कर सकें। इस तकनीक का उद्देश्य शहरों को स्मार्ट, स्वस्थ और सुरक्षित बनाना है, ताकि वे जलवायु परिवर्तन के खतरों का मजबूती से सामना कर सकें। विभिन्न शहरी डेटा स्रोतों को एकीकृत करके, एआई जलवायु-अनुकूल और पर्यावरण-अनुकूल शहर बनाने में योगदान देता है।

➲ भूजल और पेयजल सुरक्षा हेतु रिस्क मैपिंग

आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने भारत के पेयजल में आर्सेनिक प्रदूषण का पता लगाने के लिए एक एआई-आधारित प्रेडिक्शन मॉडल विकसित किया है। यह तकनीक गंगा के किनारों पर रहने वाले उन लाखों लोगों की समस्या का समाधान करती है जो इस संकट से प्रभावित हैं। पर्यावरण, भूविज्ञान और मानवीय उपयोग के डेटा पर एआई एल्गोरिदम का उपयोग करते हुए, टीम ने भूजल में आर्सेनिक के डिस्ट्रीब्यूशन और उससे होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों का पूर्वानुमान लगाया है। उन्होंने डेल्टा क्षेत्र में उच्च और निम्न आर्सेनिक वाले क्षेत्रों की पहचान की है। यह मॉडल दिखाता है कि 'सरफिशियल एक्विटार्ड थिकनेस' (सतह की वह परत जो पानी के बहाव को रोकती है) और 'ग्राउंडवाटर-फेड इरिगेशन' (भूजल आधारित सिंचाई) का क्षेत्रीय स्तर पर आर्सेनिक के खतरे से गहरा संबंध है। यह ढांचा पश्चिम बंगाल जैसे आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल स्रोतों की पहचान करने में मदद करता है और बेहतर भूजल स्रोतों के चयन को सक्षम बनाकर सरकार के जल जीवन मिशन को मजबूती प्रदान करता है।

एआई पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारत के दृष्टिकोण को बदल रहा है, जो स्थायी विकास और स्वस्थ समुदायों के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है।

❑ निष्कर्ष

भारत एआई-आधारित जलवायु समाधानों में एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे बढ़ रहा है। देश ने संस्थागत नवाचार और मजबूत बहुपक्षीय साझेदारियां की हैं। भारत अब ग्राम-स्तर पर मौसम का पूर्वानुमान उपलब्ध करा रहा है, जो लगभग हर पंचायत तक पहुँचता है। स्वदेशी भारत फोरकास्टिंग सिस्टम 6 किमी के दायरे की सटीक भविष्यवाणी करता है। इसने पूरे देश में जलवायु से जुड़ी जानकारी को जन-जन के लिए सुलभ बना दिया है। भारत ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश किया है, जिसमें 22 पेटाफ्लॉप्स (PetaFLOPS) की कंप्यूटिंग क्षमता शामिल है। ये निवेश नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। भारत 2070 तक अपने नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। एआई-संचालित समाधान अक्षय ऊर्जा, पर्यावरण-अनुकूल खेती और आपदा पूर्वानुमान जैसे क्षेत्रों में मदद कर रहे हैं। ये केवल तकनीकी उपलब्धियां नहीं हैं, बल्कि जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए अनिवार्य उपकरण हैं। भारत यह साबित कर रहा है कि जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में एआई एक शक्तिशाली हथियार हो सकता है, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के संवेदनशील समुदायों के लिए।

भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0

बजट 2026 में सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम

❑ परिचय

संघ बजट 2026–27 ने भारत की प्रौद्योगिकी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक निर्णायक क्षण का संकेत दिया, जिसमें भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गई। नया चरण ऐसे समय में घरेलू सेमीकंडक्टर क्षमताओं को गहरा करने के लिए स्पष्ट नीतिगत धक्का देता है जब चिप्स हर महत्वपूर्ण डिजिटल और औद्योगिक प्रणाली का आधार हैं। आईएसएम 2.0 भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण और सामग्री उत्पादन पर केंद्रित होगा, पूर्ण स्टैक भारतीय सेमीकंडक्टर बौद्धिक संपदा डिजाइन करेगा, और घरेलू तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करेगा। वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए आईएसएम 2.0 के लिए ₹1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें उद्योग-नेतृत्व वाले अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्रों पर मजबूत जोर दिया गया है ताकि प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा मिले और भविष्य के लिए तैयार कुशल कार्यबल तैयार हो।

सेमीकंडक्टर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की रीढ़ हैं, जो कंप्यूटर, मोबाइल उपकरण, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल, रक्षा प्रणालियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शक्ति प्रदान करते हैं। भारत ने आईएसएम 1.0 के तहत अपनी सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र की पूर्ण-स्टैक मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने में स्थिर प्रगति की है, डिजाइन क्षमताओं का विस्तार किया है और देश भर में निर्माण, असेंबली तथा परीक्षण अवसंरचना को आगे बढ़ाया है। यह गति आत्मनिर्भर भारत के व्यापक दृष्टिकोण और भारत के नीति निर्माण से उत्पादन तैयारी की ओर संक्रमण को प्रतिबिंबित करती है। इन लाभों पर निर्माण करते हुए, आईएसएम 2.0 भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर नेटवर्क में विश्वसनीय और प्रतिस्पर्धी प्रतिभागी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करता है।

❑ क्षेत्रवार दृष्टिकोण: भारत का सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र

भारत धीरे-धीरे वैश्विक सेमीकंडक्टर केंद्र के रूप में उभर रहा है। बड़े पैमाने पर निवेश, विनिर्माण क्षमता का विस्तार, और SEMICON India 2025 जैसे मंच भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में बढ़ते वैश्विक विश्वास को प्रतिबिंबित करते हैं। घरेलू चिप बाजार तेजी से वृद्धि कर रहा है। उद्योग अनुमानों के अनुसार, भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार का आकार 2023 में लगभग 38 बिलियन डॉलर, 2024-2025 में 45-50 बिलियन डॉलर और 2030 तक 100-110 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। यह विस्तार 'मेक इन इंडिया' और 'मेक फॉर द वर्ल्ड' के राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर आधारित है, जो भारत को विनिर्माण आधार और वैश्विक आपूर्तिकर्ता दोनों के रूप में स्थापित कर रहा है।

इस वृद्धि की नींव दिसंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 को मंजूरी दिए जाने के साथ रखी गई। मिशन को ₹76,000 करोड़ के प्रोत्साहन ढांचे का समर्थन प्राप्त है, जो सिलिकॉन फैब्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर सुविधाओं, असेंबली तथा परीक्षण इकाइयों और चिप डिजाइन के लिए 50 प्रतिशत तक वित्तीय समर्थन प्रदान करता है। दिसंबर 2025 तक, 6 राज्यों में कुल ₹1.60 लाख करोड़ के निवेश वाले 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें सिलिकॉन निर्माण इकाइयां, सिलिकॉन कार्बाइड फैब्स, उन्नत और मेमोरी पैकेजिंग सुविधाएं, तथा विशेष असेंबली और परीक्षण अवसंरचना शामिल हैं। ये सामूहिक रूप से एक लचीला घरेलू सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र आकार दे रही हैं।

2029 तक, भारत को घरेलू अनुप्रयोगों के लगभग 70–75 प्रतिशत के लिए आवश्यक चिप्स डिजाइन और निर्माण करने की क्षमता प्राप्त करने की उम्मीद है। इस नींव पर आगे बढ़ते हुए, सेमीकॉन 2.0 के तहत अगला चरण उन्नत विनिर्माण पर केंद्रित होगा, जिसमें 3-नैनोमीटर और 2-नैनोमीटर प्रौद्योगिकी नोड्स प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित रोडमैप होगा। 2035 तक, भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष सेमीकंडक्टर राष्ट्रों में शामिल होने का लक्ष्य रखता है।

❑ मंजूर की गई सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजनाएँ

1. माइक्रॉन टेक्नोलॉजी इंक. गुजरात में ₹22,516 करोड़ के निवेश के साथ सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा स्थापित कर रही है। भारत में माइक्रॉन की सुविधा डीआरएएम और नैंड उत्पादों के लिए असेंबली और टेस्ट निर्माण को सक्षम करेगी तथा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों की मांग को पूरा करेगी। उत्पादन क्षमता लगभग 14 मिलियन इकाइयाँ प्रति सप्ताह है।
2. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (टीईपीएल) गुजरात में ₹91,526 करोड़ के निवेश के साथ सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा स्थापित कर रही है। फैब सुविधा ताइवान की पीएसएमसी के साथ तकनीकी साझेदारी में स्थापित की जाएगी। परियोजना की उत्पादन क्षमता लगभग 50,000 वेफर स्टार्ट्स प्रति माह (डब्ल्यूएसपीएम) होगी।
3. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (टीईपीएल) असम में ₹27,120 करोड़ के निवेश के साथ सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा स्थापित कर रही है। सुविधा स्वदेशी सेमीकंडक्टर पैकेजिंग तकनीकों का उपयोग करेगी तथा उत्पादन क्षमता 48 मिलियन इकाइयाँ प्रति दिन होगी।
4. सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड गुजरात में ₹7,584 करोड़ के निवेश के साथ सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा स्थापित कर रही है। सुविधा यूएसए की रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स अमेरिका इंक. और थाईलैंड की स्टार्स माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक के साथ संयुक्त उद्यम साझेदारी में स्थापित की जाएगी।
5. केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड (केटीआईएल) गुजरात में ₹3,307 करोड़ के निवेश के साथ सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा स्थापित कर रही है। सुविधा की क्षमता 6.33 मिलियन से अधिक चिप्स प्रति दिन उत्पादित करने की होगी।
6. वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड (वीएसआईपीएल) उत्तर प्रदेश में ₹3,706 करोड़ के निवेश के साथ सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा स्थापित कर रही है। उत्पादन क्षमता लगभग 20K वेफर प्रति माह/36 मिलियन चिप्स प्रति माह होगी।

7. 3डी ग्लास सॉल्यूशंस इंक. (3डीजीएस) ओडिशा में ₹1,943 करोड़ के निवेश के साथ सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा स्थापित कर रही है। प्रस्तावित स्थापित क्षमता ग्लास पैनल सब्सट्रेट उत्पादन, असेंबली और हेटेरोजीनियस इंटीग्रेशन (3डीएचआई) के लिए क्रमशः 5800 पैनल प्रति माह, 4.20 मिलियन इकाइयाँ प्रति माह और 1100 इकाइयाँ प्रति माह है।
8. सिक्सेम प्राइवेट लिमिटेड ओडिशा में ₹2,066 करोड़ के निवेश के साथ सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा स्थापित कर रही है। उत्पादन क्षमता 5,000 वेफर/माह है, और पैकेजिंग क्षमता 8 मिलियन इकाइयाँ/माह है।
9. कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीडीआईएल) पंजाब में अपनी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा का विस्तार ₹117 करोड़ के निवेश के साथ कर रही है। सुविधा उच्च-शक्ति विवेक सेमीकंडक्टर उपकरणों का निर्माण करेगी। उत्पादन क्षमता लगभग 158.38 मिलियन इकाइयाँ/वर्ष होगी।
10. एडवांस्ड सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (एएसआईपी) आंध्र प्रदेश में ₹480 करोड़ के निवेश के साथ सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा स्थापित कर रही है। सुविधा की उत्पादन क्षमता लगभग 96 मिलियन इकाइयाँ/वर्ष होगी।

ये सुविधाएं उपभोक्ता उपकरण, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, एयरोस्पेस और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों की बढ़ती चिप आवश्यकताओं को पूरा करने की उम्मीद है।

उल्लेखनीय रूप से, कई मंजूर प्रस्ताव सेमीकंडक्टर चिप्स के असेंबली, परीक्षण और पैकेजिंग के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का लाभ उठा रहे हैं। यह बदलाव भारत की गहरी प्रौद्योगिकी क्षमता की ओर बढ़ने और बाहरी प्रणालियों पर निर्भरता कम करने को प्रतिबिंबित करता है, जो वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में इसकी स्थिति को मजबूत करता है।

❑ आईएसएम के तहत योजनाएँ

1. सेमीकंडक्टर फैब्स योजना: उन्नत और परिपक्व प्रौद्योगिकी नोड्स को कवर करते हुए सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन इकाइयों की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत तक वित्तीय समर्थन प्रदान करती है।
2. डिस्प्ले फैब्स योजना: भारत में एएमओएलईडी और एलसीडी डिस्प्ले फैब्रिकेशन इकाइयों की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत तक वित्तीय समर्थन प्रदान करती है।
3. कंपाउंड सेमीकंडक्टर और एटीएमपी/ओएसएटी योजना: कंपाउंड सेमीकंडक्टर और चिप असेंबली, टेस्टिंग तथा पैकेजिंग इकाइयों को 50 प्रतिशत तक पूंजीगत सहायता प्रदान करती है।
4. डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना: ₹1,000 करोड़ के प्रावधान के साथ, चिप डिजाइन स्टार्टअप्स और एमएसएमई को आरएंडडी समर्थन तथा प्रति कंपनी ₹15 करोड़ तक के प्रोत्साहन के माध्यम से समर्थन प्रदान करती है।

❑ वर्ष 2026-27 में सेमीकंडक्टर कार्यक्रम का अपेक्षित प्रभाव

भारत का सेमीकंडक्टर कार्यक्रम वैश्विक प्रतिस्पर्धा की तीव्रता और उन्नत चिप प्रौद्योगिकियों के सीमित खिलाड़ियों में केंद्रीकरण के जवाब में पुनर्गठित किया गया है। स्थापित सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र वाले कई देश आक्रामक प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं, जिससे भारत के लिए अपनी रणनीति को परिष्कृत करना आवश्यक हो गया है। इसलिए संशोधित कार्यक्रम सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डिस्प्ले निर्माण और डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र में निवेशों के लिए वित्तीय समर्थन को मजबूत करने पर केंद्रित है।

2026-27 के लिए, भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम की कुल वित्तीय निकासी ₹8,000 करोड़ है। कार्यक्रम पूंजी निवेश को तेज करने, उच्च गुणवत्ता वाली रोजगार सृजन करने और निर्माण, पैकेजिंग तथा चिप डिजाइन में घरेलू क्षमताओं का विस्तार करने का लक्ष्य रखता है। वर्ष के लिए अनुमानित परिणाम नीचे दिए गए हैं।

आईएसएम के तहत 2026-27 के लिए अनुमानित लक्ष्य

योजना	प्रमुख संकेतक	अनुमानित लक्ष्य
संशोधित सेमीकंडक्टर फेब्स योजना (समर्थित फेब्स – 1)	वर्ष के दौरान निवेश	₹4,000 करोड़
	रोजगार सृजन	1,500 व्यक्ति
संशोधित यौगिक सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर, डिस्क्रीट फेब्स और असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग तथा पैकेजिंग (ATMP)/आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (OSAT) योजना (समर्थित इकाइयाँ – 9)	इकाइयों द्वारा वर्ष के दौरान निवेश	₹11,000 करोड़
	समर्थित इकाइयों द्वारा रोजगार सृजन	3,000 व्यक्ति
डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना (समर्थित डिजाइन कंपनियाँ – 30)	विकसित सेमीकंडक्टर आईपी कोर	10
	नियोजित सेमीकंडक्टर डिजाइन मैनपावर	200 व्यक्ति

ये परिणाम घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने, डिजाइन क्षमताओं को गहरा करने और भारत की दीर्घकालिक सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने की मजबूत दिशा को दर्शाते हैं।

❑ भारत सेमीकंडक्टर मिशन क्यों महत्वपूर्ण है ?

सेमीकंडक्टर आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण हो चुके हैं। हालांकि रोजमर्रा की जिंदगी में वे शायद ही दिखाई देते हैं, माइक्रोप्रोसेसर चुपचाप उन सिस्टमों को शक्ति प्रदान करते हैं जो समाजों को चलाते रहते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में उल्लेखित अनुसार, वे ऊर्जा नेटवर्क, वित्तीय बाजारों और दूरसंचार का आधार बनाते हैं। वे विनिर्माण इकाइयों, अस्पतालों, परिवहन प्रणालियों और उपग्रहों को सक्षम बनाते हैं। इसलिए, सेमीकंडक्टर की विश्वसनीय आपूर्ति आर्थिक स्थिरता और विभिन्न क्षेत्रों में निरंतरता के लिए आवश्यक है। हाल की वैश्विक व्यवधान इस निर्भरता को रेखांकित करते हैं। कोविड-19 महामारी ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं में गंभीर कमजोरियों को उजागर किया, जिसमें वैश्विक स्तर पर 169 से अधिक उद्योग प्रभावित हुए। उत्पादन में देरी और बढ़ती लागतों के कारण देशों में आर्थिक गतिविधियाँ धीमी पड़ गईं। इन झटकों ने कुछ ही आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता के जोखिमों को प्रकट किया। आज सेमीकंडक्टर उद्योग कुछ

ही देशों द्वारा हावी है, जिनमें ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और संयुक्त राज्य शामिल हैं। ताइवान अकेले दुनिया के 60 प्रतिशत से अधिक सेमीकंडक्टर और लगभग 90 प्रतिशत सबसे उन्नत चिप्स का उत्पादन करता है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएँ बाहरी झटकों और भू-राजनीतिक तनावों के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं। इसके जवाब में प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ अपनी रणनीतियों को पुनर्गठित कर रही हैं। संयुक्त राज्य, यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया ने घरेलू चिप विनिर्माण को मजबूत करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को विविधीकृत करने के लिए राष्ट्रीय पहलें शुरू की हैं। भारत इस वैश्विक बदलाव में खुद को एक विश्वसनीय और भरोसेमंद साझेदार के रूप में स्थापित कर रहा है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन इस क्षण का सीधा जवाब है। डिजाइन, विनिर्माण और नवाचार में घरेलू क्षमता निर्माण द्वारा, आईएसएम स्वावलंबन और तकनीकी संप्रभुता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, साथ ही अधिक लचीली वैश्विक सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में भारत की भूमिका को मजबूत करता है।इस रणनीति का मूल में सेमीकंडक्टर डिजाइन और प्रतिभा विकास पर मजबूत फोकस है, जो तकनीकी स्वावलंबन का आधार बनाते हैं।

❑ भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना

दिसंबर 2021 में अपनी शुरुआत के बाद से, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना ने क्षमता सृजन से भारत में तकनीकी गहराई की ओर संक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह योजना घरेलू नवाचार को पोषित करने, प्रारंभिक चरण की कंपनियों का समर्थन करने और एक जीवंत फैबलेस पारिस्थितिकी तंत्र की नींव रखने पर केंद्रित है। इसने शैक्षणिक अनुसंधान और उद्योग अनुप्रयोग के बीच की खाई को भी पाटा है, जिससे वैश्विक डिजाइन परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत हुई है।

➲ डीएलआई योजना के तहत प्रमुख उपलब्धियाँ (जनवरी 2026 तक):

- कार्यक्रम वर्तमान में देश भर में 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन स्टार्टअप्स का समर्थन कर रहा है।
- योजना के तहत स्टार्टअप्स ने लगभग ₹430 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंडिंग आकर्षित किया है, जो भारत के डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र में निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है
- एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन (ईडीए), राष्ट्रीय चिप डिजाइन प्लेटफॉर्म ने उच्च स्तरीय डिजाइन टूल्स तक पहुँच प्रदान की है, जिसमें लगभग 2.25 करोड़ टूल घंटे दर्ज किए गए हैं।
- लगभग 67,000 छात्र और 1,000 से अधिक स्टार्टअप इंजीनियर इन टूल्स का उपयोग चिप डिजाइन और विकास के लिए सक्रिय रूप से कर रहे हैं।
- शैक्षणिक क्षेत्र में, 122 डिजाइनों को टेप आउट किया गया है, जिसमें 56 चिप्स को मोहाली के सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में 180 nm पर बनाया गया है।
- स्टार्टअप्स ने 16 टेप आउट पूरे किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 12 nm जैसी उन्नत फाउंड्री नोड्स पर 6 चिप्स बनाए गए हैं।
- शैक्षणिक संस्थानों ने 75 पेटेंट दाखिल किए हैं, जबकि स्टार्टअप्स ने 10 पेटेंट दाखिल किए हैं, जो नवाचार और बौद्धिक संपदा सृजन की बढ़ती संस्कृति को इंगित करता है।

आगे देखते हुए, कार्यक्रम और विस्तार करने को तैयार है, जिसमें अगले चरण में कम से कम 50 फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनियों को सक्षम करने का लक्ष्य है, जो भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने की महत्वाकांक्षा को मजबूत करता है।

❑ स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर और कोर सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकियों का विकास

माइक्रोप्रोसेसर आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की आधारभूत परत बनाते हैं, जो दूरसंचार, गतिशीलता, स्वास्थ्य सेवा, उद्योग, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में उपकरणों और सिस्टमों को शक्ति प्रदान करते हैं। उनकी रणनीतिक महत्व को मानते हुए, भारत ने उन्नत प्रोसेसर डिजाइन में संप्रभु क्षमताओं का निर्माण करने के लिए केंद्रित निवेश किए हैं, जो सेमीकंडक्टर स्वावलंबन का कोर स्तंभ है।इस यात्रा का एक प्रमुख मील का पत्थर है डीएचआरयूवी64 का लॉन्च, जो सी-डैक द्वारा माइक्रोप्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम (एमडीपी) के तहत विकसित एक पूर्णतः स्वदेशी 64-बिट माइक्रोप्रोसेसर है। आधुनिक वास्तुशिल्प सिद्धांतों पर निर्मित, डीएचआरयूवी64 बेहतर दक्षता, मल्टीटास्किंग क्षमता और विश्वसनीयता प्रदान करता है, जो 5जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक ऑटोमेशन, उपभोक्ता उपकरणों और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) जैसे क्षेत्रों में तैनाती को सक्षम बनाता है। इसका विकास भारत को एक सुरक्षित, स्वदेशी प्रोसेसर प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जो आयातित चिप्स पर दीर्घकालिक निर्भरता को कम करता है—खासकर तब जब भारत वैश्विक माइक्रोप्रोसेसर उत्पादन का लगभग 20 प्रतिशत उपभोग करता है।डीएचआरयूवी64 स्वदेशी प्रोसेसर्स के बढ़ते पोर्टफोलियो पर आधारित है, जिसमें शक्ति, अजित, विक्रम और थेजस शामिल हैं, जो सामूहिक रूप से भारतीय प्रोसेसर पारिस्थितिकी तंत्र की नींव बनाते हैं। डिजिटल इंडिया आरआईएससी-वी (डीआईआर-वी) प्रोग्राम के तहत विकसित, ये प्रोसेसर ओपन-सोर्स आरआईएससी-वी वास्तुकला का लाभ उठाते हैं, जो लाइसेंस लागत को समाप्त करते हैं और शैक्षणिक, स्टार्टअप्स तथा उद्योग में सहयोगी नवाचार को सक्षम बनाते हैं। डीएचआरयूवी64 का रोलआउट, साथ ही धनुष और धनुष+ सिस्टम ऑन चिप्स वेरिएंट्स का चल रहा विकास, भारत के आरएंडडी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है, उत्पाद प्रोटोटाइपिंग को तेज करता है और घरेलू डिजाइन प्रतिभा के लिए अवसरों का विस्तार करता है।साथ ही, ये पहल माइक्रोप्रोसेसर को केवल घटकों के रूप में नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल संप्रभुता के रणनीतिक सक्षमकर्ताओं के रूप में स्थापित करती हैं—नवाचार का समर्थन करती हैं, महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित करती हैं और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में देश की दीर्घकालिक महत्वाकांक्षाओं को मजबूत करती हैं।

❑ सेमीकंडक्टर प्रतिभा पाइपलाइन का विकास

एक मजबूत सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही लोगों पर निर्भर करता है जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इसलिए भारत ने डिजाइन, विनिर्माण और उन्नत पैकेजिंग में बड़ी, कुशल और उद्योग-तैयार प्रतिभा आधार बनाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। जोर चिप प्रौद्योगिकियों को प्रारंभिक जोखिम, व्यावहारिक प्रशिक्षण और विकसित उद्योग आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर अपस्किलिंग पर है

- चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम: चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम 397 विश्वविद्यालयों और स्टार्टअप्स में नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन टूल्स तक पहुँच प्रदान करता है। इन टूल्स का उपयोग

करते हुए, 46 से अधिक विश्वविद्यालयों के चिप डिजाइनरों ने मोहाली के सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में 56 चिप्स डिजाइन और निर्माण किए हैं।

- ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) के तहत शैक्षणिक कार्यक्रम: मुख्यधारा इंजीनियरिंग में सेमीकंडक्टर शिक्षा को एकीकृत करने के लिए विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इनमें वीएलएसआई डिजाइन पर केंद्रित इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक, इंटीग्रेटेड सर्किट विनिर्माण में डिप्लोमा और वीएलएसआई डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी को कवर करने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में माइनर डिग्री शामिल हैं। ये कार्यक्रम उद्योग-संबंधी कौशलों से लैस स्नातक तैयार करने का लक्ष्य रखते हैं।
- एनआईईएलआईटी कलिकट में स्मार्ट लैब: एनआईईएलआईटी कलिकट में कुशल मैनपावर एडवांस्ड रिसर्च एंड ट्रेनिंग लैब सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकियों में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण का समर्थन करता है। पहल देश भर में एक लाख इंजीनियरों को लक्षित करती है, जिसमें 62,000 से अधिक इंजीनियर पहले ही प्रशिक्षित हो चुके हैं, जो राष्ट्रीय प्रतिभा पूल को काफी मजबूत कर रहा है।
- एनआईईएलआईटी कलिकट में स्मार्ट लैब: एनआईईएलआईटी कलिकट में कुशल मैनपावर एडवांस्ड रिसर्च एंड ट्रेनिंग लैब सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकियों में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण का समर्थन करता है। पहल देश भर में एक लाख इंजीनियरों को लक्षित करती है, जिसमें 62,000 से अधिक इंजीनियर पहले ही प्रशिक्षित हो चुके हैं, जो राष्ट्रीय प्रतिभा पूल को काफी मजबूत कर रहा है।
- लैम रिसर्च के साथ उद्योग साझेदारी: नैनोफैब्रिकेशन और प्रोसेस इंजीनियरिंग में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम लैम रिसर्च के साथ लागू किया जा रहा है। फोकस (ATMP) और उन्नत पैकेजिंग सुविधाओं के लिए विशेष कौशलों का निर्माण है। कार्यक्रम अगले दस वर्षों में 60,000 प्रशिक्षित पेशेवर तैयार करने का लक्ष्य रखता है।
- फ्यूचरस्किल्स प्राइम प्रोग्राम: फ्यूचरस्किल्स प्राइम मेइटी और नास्कॉम की संयुक्त पहल है जो भारत को वैश्विक डिजिटल प्रतिभा केंद्र बनाने पर केंद्रित है। यह उभरती प्रौद्योगिकियों, जिसमें सेमीकंडक्टर शामिल हैं, में स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग पर फोकस करता है। कोर्स उद्योग इनपुट्स के साथ विकसित किए जाते हैं और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वितरित किए जाते हैं, जो लर्नर्स को कभी भी प्रशिक्षण तक पहुँच और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप मान्यता प्राप्त स्किल सर्टिफिकेट अर्जित करने की अनुमति देता है।

साथ ही, ये पहल एक मजबूत और भविष्य-तैयार सेमीकंडक्टर कार्यबल तैयार कर रही हैं, जो पूर्ण चिप मूल्य श्रृंखला में भारत को दीर्घकालिक विकास बनाए रखने के लिए तैयार कर रही हैं।

❑ निष्कर्ष

भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 पारिस्थितिकी तंत्र सृजन से पारिस्थितिकी तंत्र समेकन और वैश्विक एकीकरण की ओर निर्णायक बदलाव का प्रतीक है। विनिर्माण, डिजाइन और उन्नत कौशलों के लिए समर्थन को गहरा करके, आईएसएम 2.0 सेमीकंडक्टर को रणनीतिक राष्ट्रीय क्षमता के रूप में स्थापित करता है—आर्थिक लचीलापन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी संप्रभुता के केंद्रीय है। 2026–27 में बढ़ा बजटीय समर्थन निष्पादन को तेज करने, निजी निवेश को आकर्षित करने और पूर्ण सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में घरेलू क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है।आगे देखते हुए, आईएसएम 2.0 भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और नवाचार का विश्वसनीय केंद्र बनाने की नींव रखता है। उन्नत नोड्स के लिए स्पष्ट रोडमैप, मजबूत डिजाइन प्रोत्साहन और बढ़ती प्रतिभा पाइपलाइन के साथ, भारत बाहरी निर्भरताओं को प्रगतिशील रूप से कम करने और अधिक लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में योगदान देने के लिए तैयार है। मिशन इस प्रकार भारत की महत्वाकांक्षा को अगले दशक में दुनिया के प्रमुख सेमीकंडक्टर राष्ट्रों में शामिल होने की नींव प्रदान करता है।

विविध समसामयिकी

01 माउंट अकांकागुआ (Mount Aconcagua)

❑ चर्चा में क्यों?

अरुणाचल प्रदेश की 27 वर्षीय पर्वतारोही कबाक यानो (Kabak Yano) ने अर्जेंटीना में स्थित दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी, माउंट अकांकागुआ (22,831 फीट/6,959 मीटर) पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है।

मुख्य बिंदु

- यह कबाक यानो के 7-शिखर पर्वतारोहण अभियान (7-Summit Mountaineering Expedition) की एक महत्वपूर्ण सफलता है।
- इससे पहले, उन्होंने 2025 में अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो और यूरोप की माउंट एल्ब्रुस पर भी चढ़ाई की थी।
- यह उपलब्धि उनकी असाधारण सहनशक्ति, साहस और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है, जो अरुणाचल प्रदेश और भारत के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है।

❑ माउंट एकांकागुआ के बारे में -

- यह अर्जेंटीना के मेंडोज़ा प्रांत में, चिली की सीमा के पास स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 6,961 मीटर (22,838 फीट) है।
- "अकांकागुआ" नाम की उत्पत्ति को लेकर विवाद है। कुछ लोग इसे स्वदेशी भाषा 'क्वेचुआ' से जोड़ते हैं जिसका अर्थ "पत्थर का रक्षक" होता है।
- इसे अक्सर 'मौत का पहाड़' कहा जाता है, क्योंकि यहाँ चढ़ाई के दौरान उच्च ऊंचाई वाली बीमारियां और खराब मौसम का खतरा बना रहता है।
- दिसंबर से फरवरी (दक्षिण गोलार्द्ध में ग्रीष्म ऋतु) सबसे अच्छा समय माना जाता है।
- 1897 में स्विस पर्वतारोही मैथियास ज़ुरब्रिगेन द्वारा पहली बार इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की गई थी।

02 आदित्य पंड्या बने भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री

❑ चर्चा में क्यों?

17 वर्षीय आदित्य पंड्या, AAKA स्पेस के चंद्र आवास मिशन को पूरा करने के बाद भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं।

मुख्य बिंदु

- स्थान: यह मिशन गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित धोलावीरा के सफेद रेगिस्तान (White Desert) में आयोजित किया गया था। यहाँ की भौगोलिक स्थिति चंद्रमा की सतह से काफी मिलती-जुलती है।
- अवधि: यह एक 8-दिवसीय (1 से 8 फरवरी, 2026) सिमुलेशन मिशन था।
- प्रोटोकॉल: मिशन के दौरान आदित्य और अन्य चालक दल के सदस्यों को बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग रखा गया था, ताकि वास्तविक अंतरिक्ष मिशनों के दौरान होने वाले अलगाव और मनोवैज्ञानिक दबाव का अध्ययन किया जा सके।

❑ आदित्य की भूमिका :-

- हार्डवेयर और IoT: उन्होंने मिशन के लिए आवश्यक हार्डवेयर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) आधारित 'स्मार्ट हैबिटेट' सिस्टम को डिजाइन और विकसित करने में मदद की।
- डिजिटल ट्विन: मिशन में 'डिजिटल ट्विन' तकनीक का उपयोग किया गया था, जो वास्तविक समय में आवास की स्थिति की निगरानी करने में मदद करती है।
- प्रणाली परीक्षण: आदित्य ने स्वयं के द्वारा बनाए गए एयर-क्वालिटी सेंसर और बायोमेट्रिक ट्रैकर्स का मिशन के दौरान वास्तविक परिस्थितियों में परीक्षण किया।

❑ AAKA Space Studio के बारे में

- यह ISRO द्वारा पंजीकृत एक 'स्पेस ट्यूटर' (Space Tutor) संस्था है जो ग्रहों के एनालॉग अनुसंधान (Planetary Analog Research) और अंतरिक्ष वास्तुकला पर काम करती है।

❑ एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं?

- वे व्यक्ति जो पृथ्वी पर ही अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियों (जैसे अलगाव, सीमित संसाधन और कठिन वातावरण) में रहकर वैज्ञानिक प्रयोग और तकनीकी परीक्षण करते हैं, ताकि भविष्य के वास्तविक अंतरिक्ष मिशनों की तैयारी की जा सके।

03 'म्यूजिकल रोड' (Musical Road)

❑ चर्चा में क्यों?

मुंबई कोस्टल रोड जो आधिकारिक रूप से 'धर्मवीर स्वराज रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड' के नाम से भी जाना जाता है, पर भारत का पहला 'म्यूजिकल रोड' (Musical Road) या 'मेलोडी ट्रैक' तैयार किया गया है। इसका उद्घाटन 11 फरवरी, 2026 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा किया गया।

मुख्य बिंदु

- कौन सी धुन सुनाई देती है?
  - → जब आप इस सड़क के खास हिस्से से गुजरते हैं, तो आपको ए.आर. रहमान का ऑस्कर विजेता गीत "जय हो" (Jai Ho) सुनाई देता है। यह धुन किसी लाउडस्पीकर से नहीं, बल्कि सड़क और टायरों के बीच होने वाले घर्षण से पैदा होती है।
- यह कहाँ स्थित है?
  - → यह म्यूजिकल स्ट्रेच कोस्टल रोड के उत्तर की ओर जाने वाली लेन (Northbound Lane) पर है।

→ यह नरिमन पॉइंट से वर्ली की तरफ जाते समय, कोस्टल टनल (सुरंग) से बाहर निकलते ही शुरू होता है।

→ यह लगभग 500 मीटर लंबा हिस्सा है।

- **यह काम कैसे करता है?**

सड़क की सतह पर खास अंतराल और गहराई पर 'रंबल स्ट्रिप्स' (Grooves) काटे गए हैं। जब गाड़ी के टायर इन खांचों के ऊपर से गुजरते हैं, तो होने वाले कंपन से संगीत की तरंगें पैदा होती हैं। इसे सुनने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना होगा -

→ **निश्चित गति:** इस धुन को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए आपको गाड़ी 60 से 80 किमी/घंटा की स्थिर गति पर चलानी होगी। यदि गति कम या ज्यादा होगी, तो धुन बेसुरी हो सकती है।

→ **लेन:** यह सुविधा केवल डिवाइडर के पास वाली पहली लेन में उपलब्ध है।

→ **संकेत:** सड़क पर 500 मीटर, 100 मीटर और 60 मीटर पहले ही सूचना बोर्ड लगाए गए हैं ताकि ड्राइवर अपनी गति को नियंत्रित कर सकें।

- **उद्देश्य और तकनीक**

→ **सुरक्षा:** इसका मुख्य उद्देश्य ड्राइवरों को एक निश्चित गति सीमा बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना है।

→ **तकनीक:** इसे हंगेरियन (Hungary) इंजीनियरिंग की मदद से बीएमसी (BMC) द्वारा लगभग ₹6.21 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है।

- नोट: भारत ऐसा करने वाले दुनिया का चुनिंदा देशों में शामिल हो गया। इससे पहले जापान, दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड और हंगरी जैसे देशों में ही ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया है।

04 समर्थ पोर्टल (SAMARTH Portal)

❑ चर्चा में क्यों?

बिहार के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों में 2026-27 शैक्षणिक सत्र से स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) में नामांकन, परीक्षा और रिजल्ट की प्रक्रिया समर्थ पोर्टल (SAMARTH) के माध्यम से ऑनलाइन होगी। यह कदम बिहार में उच्च शिक्षा को डिजिटल बनाने और प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है।

❑ समर्थ पोर्टल के बारे में -

- समर्थ पोर्टल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक डिजिटल पहल है। यह एक 'इन्फोर्मेशन स्टैंडर्ड एंड ऑटोमेशन इंजन' है, जिसे उच्च शिक्षण संस्थानों (Universities और Colleges) के कामकाज को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह विश्वविद्यालयों के लिए एक "ऑल-इन-वन" डिजिटल प्लेटफॉर्म है।

❑ मुख्य उद्देश्य

- समर्थ का लक्ष्य उच्च शिक्षा संस्थानों में ई-गवर्नेंस (e-Governance) को बढ़ावा देना है। इसे दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है ताकि सभी संस्थानों में एक जैसा और आधुनिक प्रबंधन सिस्टम हो।

❑ समर्थ पोर्टल के मुख्य मॉड्यूल

- यह पोर्टल किसी विश्वविद्यालय के लगभग 40 से अधिक कार्यों को संभालता है, जिन्हें मुख्य रूप से इन श्रेणियों में बांटा गया है:

→ **छात्र प्रबंधन (Student Management):** ऑनलाइन प्रवेश (Admission), परीक्षा फॉर्म भरना, एडमिट कार्ड, और डिजिटल रिजल्ट।

→ **कर्मचारी प्रबंधन (Employee Management):** शिक्षकों और स्टाफ की भर्ती, सर्विस बुक, और पेरोल (सैलरी) सिस्टम।

→ **अकादमिक कार्य:** पाठ्यक्रम (Curriculum) डिजाइन, समय-सारणी (Time-table), और छात्र उपस्थिति।

→ **प्रशासनिक कार्य:** बजट, संपदा (Asset) प्रबंधन, और इन्वेंट्री कंट्रोल।

❑ इसके बड़े लाभ

विशेषता	लाभ
पारदर्शिता	सभी डेटा ऑनलाइन होने से हेरफेर की संभावना खत्म हो जाती है।
दक्षता	कागजी कार्रवाई कम होती है और काम तेजी से होता है।
NEP 2020 का समर्थन	यह 'नेशनल एजुकेशन पॉलिसी' के डिजिटल लक्ष्यों को पूरा करता है।
एकल खिड़की	छात्रों को अलग-अलग काम के लिए अलग ऑफिस नहीं जाना पड़ता।

❑ समर्थ और CUET का संबंध

- आजकल अधिकांश केंद्रीय विश्वविद्यालयों (Central Universities) में CUET (Common University Entrance Test) के बाद काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया Samarth Portal के माध्यम से ही पूरी की जाती है। छात्र इसी पोर्टल पर अपना प्रोफाइल बनाकर कॉलेजों का चयन करते हैं।

05 सौंदला : भारत का पहला 'जाति-मुक्त' गांव

- महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले (पूर्व अहमदनगर) के सौंदला (Soundala) गांव ने फरवरी 2026 में ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर खुद को भारत का पहला 'जाति-मुक्त' गांव घोषित किया है। यह कदम संविधान के अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का अंत) की भावना को धरातल पर उतारने जैसा है।

❑ मुख्य विवरण:-

- **स्थान:** नेवासा तालुका, अहिल्यानगर (महाराष्ट्र)।
- **पहल:** सरपंच शरद बाबूराव अरगड़े के नेतृत्व में ग्रामीणों की सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित।
- **उद्देश्य:** जाति आधारित भेदभाव को पूरी तरह खत्म करना और 'मानवता' को ही सबसे बड़ा धर्म मानना।
- **नियम:** कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या सार्वजनिक रूप से जातिसूचक उपनाम (Surname) का उपयोग नहीं करेगा। उल्लंघन करने पर ग्राम पंचायत द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

- प्रगतिशील कदम: 2024 में गांव ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन और महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा पर रोक लगाई थी।

06 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजरायल दौरा

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25-26 फरवरी 2026 को इज़राइल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग के साथ आधिकारिक भेट वार्ता की। यह दौरा भारत और इज़राइल के बीच कूटनीतिक संबंधों के एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है।

❑ संबंधों का नया स्तर (Special Strategic Partnership)

- इस दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि दोनों देशों के बीच संबंधों को "Special Strategic Partnership for Peace, Innovation & Prosperity" (शांति, नवाचार और समृद्धि के लिए विशेष रणनीतिक साझेदारी) के स्तर पर ले जाना रहा। यह द्विपक्षीय संबंधों का सर्वोच्च स्तर है।

❑ महत्वपूर्ण समझौते और एमओयू (MoUs)

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज़राइल यात्रा के दौरान कुल 27 प्रमुख परिणामों की घोषणा की गई, जिनमें से 17 औपचारिक समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित क्षेत्रों के आधार पर दिया गया है:

❑ रक्षा और सुरक्षा (Defense & Security)

- यह इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ रहा।
- सह-उत्पादन और सह-विकास: दोनों देशों ने रक्षा प्रणालियों के केवल 'खरीद-बिक्री' के बजाय साथ मिलकर निर्माण (Co-development) करने के लिए एक नए 'रक्षा रोडमैप' पर हस्ताक्षर किए।
- ड्रोन तकनीक: मानवरहित हवाई वाहनों (UAVs) और एंटी-ड्रोन सिस्टम के लिए उन्नत तकनीक साझा करने पर समझौता हुआ।
- साइबर सुरक्षा: महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (Critical Infrastructure) की सुरक्षा के लिए एक 'संयुक्त साइबर कमांड सेंटर' की स्थापना का निर्णय लिया गया।

❑ अर्थव्यवस्था और फिनटेक (Economy & Fintech)

- भारत की डिजिटल ताकत और इज़राइल की वित्तीय तकनीक का मिलन।
- UPI का विस्तार: इज़राइल में भारत के UPI (Unified Payments Interface) को सक्षम करने के लिए समझौता हुआ। अब भारतीय पर्यटक और वहां रहने वाले भारतीय वहां UPI के जरिए भुगतान कर सकेंगे।
- मुक्त व्यापार समझौता (FTA): द्विपक्षीय व्यापार को $20 बिलियन तक ले जाने के उद्देश्य से 'मुक्त व्यापार समझौते' पर वार्ता को तेज करने के लिए एक निश्चित समय सीमा (Timeline) तय की गई।
- नवाचार कोष (I4F): 'इंडिया-इज़राइल इंडस्ट्रियल आरएंडडी एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड' (I4F) के बजट में वृद्धि की गई।

❑ प्रौद्योगिकी और AI (Technology & AI)

- क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज (iCET): AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए समझौता।
- सेमीकंडक्टर मिशन: इज़राइली कंपनियों द्वारा भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स लगाने के लिए प्रोत्साहन और सहयोग पर सहमति।

❑ कृषि और जल प्रबंधन (Agriculture & Water)

- विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस (Villages of Excellence): भारत के 150 और गांवों को इज़राइली तकनीक से आधुनिक बनाने के लिए अगले चरण का समझौता।
- जल संरक्षण: खारे पानी को पीने योग्य बनाने (Desalination) और ड्रिप इरिगेशन की नई तकनीकों के लिए 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की स्थापना।

❑ श्रम और कौशल विकास (Labor & Skill Development)

- श्रमिक गतिशीलता (Labor Mobility): अगले 5 वर्षों में निर्माण और स्वास्थ्य देखभाल (Nursing) के क्षेत्र में 50,000 अतिरिक्त भारतीय श्रमिकों को इज़राइल भेजने के संबंध में नए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर।
- कौशल प्रमाणन: भारतीय आईटीआई (ITI) और इज़राइली तकनीकी संस्थानों के बीच प्रमाणन को मान्यता देने पर समझौता।

❑ अंतरिक्ष और विज्ञान (Space & Science)

- ISRO-ISA सहयोग: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और इज़राइल अंतरिक्ष एजेंसी (ISA) के बीच छोटे उपग्रहों (Small Satellites) के प्रक्षेपण और पृथ्वी अवलोकन (Earth Observation) के लिए साझेदारी।

❑ संस्कृति और शिक्षा (Culture & Education)

- सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम: 2026-2029 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम का नवीनीकरण।
- अकादमिक सहयोग: प्रमुख भारतीय विश्वविद्यालयों (जैसे IITs) और इज़राइल के संस्थानों के बीच 'एप्लाइड साइंस' में संयुक्त पीएचडी प्रोग्राम शुरू करने का समझौता।

❑ ऐतिहासिक संबोधन और सम्मान

- प्रधानमंत्री मोदी ने इज़राइल की संसद 'नेसेट' (Knesset) को संबोधित किया। वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय नेता बने। इस दौरान वो नेसेट के सर्वोच्च स्पीकर सम्मान से भी सम्मानित किए जाने वाले पहले वैश्विक नेता बने। अपने संबोधन में उन्होंने आतंकवाद की निंदा की और दोनों देशों के साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर दिया।

❑ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे

- गाजा शांति योजना: पीएम मोदी ने गाजा में शांति पहल के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की।
- कनेक्टिविटी: IMEC (भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा) और I2U2 (भारत, इज़राइल, अमेरिका, यूएई) जैसे मंचों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई।

- **श्रमिक गतिशीलता:** इज़राइल में अगले 5 वर्षों में 50,000 अतिरिक्त भारतीय श्रमिकों के जाने के संबंध में नए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए।

❑ प्रतीकात्मक कार्यक्रम

- उन्होंने यैद वाशेम (Yad Vashem) होलोकॉस्ट मेमोरियल का दौरा किया।
- इज़राइल में भारतीय प्रवासियों (करीब 26,000 लोग) के साथ एक सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
- नौ वर्षों में प्रधानमंत्री का यह पहला इजरायल दौरा था, जिसे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। इस दौरे का सबसे बड़ा परिणाम यह रहा कि अब दोनों देशों के रिश्तों को 'स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप' के स्तर पर पहुंचा दिया गया है।

07 विविध समसामयिकी (To The Point)

- अरुणाचल प्रदेश के कबक यानो ने अर्जेंटीना में स्थित दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी 'माउंट अकांकागुआ' की सफलता पूर्वक चढ़ाई की।
- विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह 2026 का आयोजन 1 से 7 फरवरी को किया गया।
- एलन मस्क 800 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने।
- महिला जननांग विकृति (Female Genital Mutilations - FGM) के प्रति जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 6 फरवरी को मनाया जाता है।
- ओड़िसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी द्वारा हाल ही में अनावरित विश्वभूषण हरिचंदन की पुस्तक "ए माटी कथा कहे" और "बख्शी जगबंधु : द ग्रेट कमांडर" क्रमशः ओडिया व अंग्रेजी भाषा में लिखित हैं।
  - → 'ए माटी कथा कहे' पुस्तक में ओडिशा की संस्कृति व 1817 में हुए पाइका विद्रोह का उल्लेख है।
- तमिलनाडु सरकार ने निजी भागादारी के साथ चेन्नई और कोयंबटूर में पालतू पशु पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया।
- मुम्बई में देश का पहला म्यूजिकल रोड शहर के कोस्टल रोड के एक हिस्से पर तैयार किया हुआ।
- रक्षा मंत्रालय के क्लीयरेंस और सरकारी नियमों के कारण चर्चा में रही में रही पुस्तक 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनीः एन ऑटोबायोग्राफी' भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा है।
  - → प्रकाशक : पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया
- हाल ही में कांगड़ा जिले के पालमपुर में हिमाचल प्रदेश का पहला और देश का दूसरा टयूलिप गार्डन शुरू किया गया।
- हाल ही में नागालैंड में रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का 5वां संस्करण आयोजित हुआ।
- हाल ही में कर्नाटक के गौरीबिदानूर में अपनी तरह की पहली महिलाओं के नेतृत्व वाली इंडस्ट्रियल पार्क पहल का उद्घाटन किया गया।
- आंध्रप्रदेश विधानसभा में विधायकों की अटेंडेंस मार्क करने के लिए AI-पावर्ड फेस-रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गयी है।
- हाल ही में नागालैंड के संगतम नागा समुदाय की सर्वोच्च जनजातीय संस्था 'यूनाइटेड संगतम लिखम पुमजी' (USLP) ने अपने अधिकार क्षेत्र में पैंगोलिन के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
- राजस्थान के जैसलमेर में 6-8 मार्च 2026 तक देश का पहला जैन चादर महोत्सव आयोजित किया जाएगा।
- करूर वैश्य बैंक (KVB) और मद्रास विश्वविद्यालय ने सम्मिलित रूप से चेन्नई में दक्षिण भारत की पहली "स्वदेशी और लुप्तप्राय भाषा प्रयोगशाला" (IELLAB) का शुभारंभ किया।
- तीन दिवसीय 'राजकीय इटखोरी महोत्सव 2026' झारखण्ड के चतरा जिले में आयोजित हुआ।
- आठ वर्षीय रणवीर सचदेवा नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के वक्ता बने।
- हाल ही में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने विजय गोयल द्वारा लिखित पुस्तक 'अटल बिहारी वाजपेयी: द इटरनल स्टेट्समैन' नामक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया।
- विश्व क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सड़क सुरक्षा के वैश्विक चैम्पियन के रूप में नामित किया गया।
- नागालैंड के चुमौकेदिमा में एग्री एक्सपो साइट पर 26-27 फरवरी 2026 को पहली बार दो दिवसीय 'पूर्वोत्तर चावल महोत्सव: निम्सत के अनाज' (Grains of Heritage) का आयोजन किया गया।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन (10 करोड़) फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले राजनेता और विश्व नेता बन गए हैं।
- भारत ने 28 फरवरी को भौतिकी वैज्ञानिक सी.वी. रमन के रमन इफेक्ट (1928) की खोज की स्मृति में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया।
- वर्ष 2026 का विषय है– "विज्ञान में महिलाएँ: विकसित भारत को उत्प्रेरित करना"।
- NCERT की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' और नकारात्मक टिप्पणियों वाले अध्याय पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है।

बिहार समसामयिकी

01 बिहार बजट 2026-27

बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने 3 फरवरी, 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। यह बजट मुख्य रूप से 'सात निश्चय-3' और 'विकसित बिहार' के रोडमैप पर केंद्रित है।

❑ मुख्य बिंदु और महत्वपूर्ण आंकड़े:-

➲ **बजट का आकार और वित्तीय स्थिति**

- कुल बजट: ₹3,47,589.76 करोड़ (पिछले वर्ष की तुलना में करीब ₹30,000 करोड़ की वृद्धि)।
- राजस्व अधिशेष (Revenue Surplus): ₹1,143.19 करोड़ (GSDP का 0.09%)।
- राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit): ₹39,111.80 करोड़ (GSDP का 2.99%), जो निर्धारित 3% की सीमा के भीतर है।
- विकास दर: राज्य की आर्थिक विकास दर 14.9% रहने का अनुमान है।

➲ **प्रमुख घोषणाएं और 'सात निश्चय-3'**

सरकार ने 2025 से 2030 तक के लिए 'सात निश्चय-3' का रोडमैप पेश किया है, जिसके मुख्य लक्ष्य हैं:

- रोजगार: 2030 तक 1 करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा करना।
- प्रति व्यक्ति आय: राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य।
- महिला सशक्तिकरण: स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1.56 करोड़ महिलाओं को आर्थिक मदद। 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत सफल महिला उद्यमियों को ₹2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता।
- किसानों के लिए: 'जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि' की शुरुआत। इसके तहत किसानों को केंद्र की सहायता के अतिरिक्त ₹3,000 प्रति वर्ष राज्य सरकार देगी।

➲ **क्षेत्रवार आवंटन (Sectoral Allocation)**

- शिक्षा - ₹68,216 करोड़ सबसे अधिक आवंटन (19.6%) - हर पंचायत में मॉडल स्कूल और नए डिग्री कॉलेज।
- ग्रामीण विकास - ₹22,392 करोड़ - ग्रामीण सड़कें, आवास और रोजगार योजनाएं।
- स्वास्थ्य - ₹21,270 करोड़ - जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशियलिटी में बदलना, नए मेडिकल कॉलेज।
- समाज कल्याण - ₹7,724 करोड़ - बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाएं।
- कृषि - ₹2,525 करोड़ - सिंचाई सुविधाएं और कृषि रोडमैप-4 का कार्यान्वयन।

➲ **बजट के "5 संकल्प"**

- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बजट को 5 स्तंभों पर आधारित बताया है:
  - → ईमान (Integrity)
  - → ज्ञान (Knowledge)
  - → विज्ञान (Science)
  - → अरमान (Aspiration)
  - → सम्मान (Dignity)

➲ **आय और व्यय का विवरण (रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है)**

- आय का मुख्य स्रोत: केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा (लगभग 45.5%) और राज्य का अपना कर राजस्व (18.9%)।
- व्यय का मुख्य हिस्सा: सामाजिक सेवाएं (41.5%) और सामान्य सेवाएं (28.1%)।
- विशेष नोट: इस बजट में शिक्षक बहाली और औद्योगिक निवेश (₹50 करोड़ तक के निजी निवेश को बढ़ावा) पर भी विशेष जोर दिया गया है ताकि राज्य से पलायन को कम किया जा सके।

02 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण (2025-26)

बिहार के वित्त मंत्री द्वारा फरवरी 2026 में पेश किया गया 20वां आर्थिक सर्वेक्षण (2025-26) राज्य की अर्थव्यवस्था की एक सकारात्मक तस्वीर पेश करता है। सर्वेक्षण के अनुसार, बिहार ने विकास दर के मामले में राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ दिया है।

❑ सर्वेक्षण के मुख्य बिंदु और महत्वपूर्ण आंकड़े :-

➲ **आर्थिक विकास और GSDP**

- बिहार की अर्थव्यवस्था वर्तमान में "उच्च-वृद्धि पथ" (High-growth trajectory) पर है।
- विकास दर (2024-25): चालू कीमतों (Current Prices) पर बिहार की विकास दर 13.1% रही, जो राष्ट्रीय औसत (9.8%) से काफी अधिक है। स्थिर कीमतों (Constant Prices) पर यह 8.6% रही।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP):
  - → चालू कीमतों पर: ₹9,91,997 करोड़
  - → स्थिर कीमतों पर: ₹5,31,372 करोड़

➲ **प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income)**

- राज्य में लोगों की औसत आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

→ औसत आय: बिहार की प्रति व्यक्ति आय अब बढ़कर ₹76,490 (चालू कीमतों पर) हो गई है।

→ सर्वाधिक समृद्ध जिले: पटना (₹1,31,332), बेगूसराय और मुंगेर।

→ सबसे कम आय वाले जिले: शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी।

➲ **क्षेत्रीय योगदान (Sectoral Share)**

- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का योगदान (GSVA में) इस प्रकार है:

क्षेत्र	योगदान (%)	विकास दर
तृतीयक (Service)	54.8%	8.9%
द्वितीयक (Industry/ Construction)	26.8%	11.1%
प्राथमिक (Agriculture)	18.3%	4.1%

नोट: द्वितीयक क्षेत्र (विनिर्माण और निर्माण) में 11.1% की तेज वृद्धि बिहार के औद्योगिक सुधारों के सकारात्मक संकेत देती है।

➲ **राज्य वित्त और राजकोषीय स्थिति**

- सरकार ने राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने का प्रयास किया है।

→ कुल व्यय: ₹2,81,939 करोड़ (GSDP का 28.4%)।

→ राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit): GSDP का 4.2% रहा।

→ पूंजीगत व्यय: बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए ₹62,924 करोड़ खर्च किए गए।

→ बकाया ऋण: GSDP का 37.7% (लगभग ₹3.74 लाख करोड़)।

➲ **सामाजिक और बुनियादी ढांचा**

- कृषि: मखाना उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी देश में 85% और लीची में 83% है। दूध उत्पादन में 4.2% की वृद्धि हुई है।
- सड़क नेटवर्क: भारत के कुल सड़क नेटवर्क में बिहार की हिस्सेदारी 5.5% है।
- ऊर्जा: प्रति व्यक्ति बिजली की खपत बढ़कर 374 यूनिट (kWh) हो गई है।
- रोजगार: ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष बेरोजगारी दर केवल 3.3% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 6.9% है।

➲ **भविष्य का लक्ष्य**

- वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में लोगों की आय को दोगुना करना और 1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसके लिए "New Age Economy" पहल के तहत हर जिले में औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी।

03 बिहार 'नक्सल-मुक्त' राज्य घोषित

फरवरी 2026 में मुंगेर में अंतिम कुख्यात सशस्त्र माओवादी 'सुरेश कोड़ा' उर्फ 'मुस्तकीम' के आत्मसमर्पण के बाद बिहार को आधिकारिक रूप से नक्सल-मुक्त राज्य घोषित किया गया है।

मुख्य बिंदु

- सुरेश कोड़ा ने मुंगेर में बिहार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) के समक्ष AK-47, एके 56 और इंसास रायफल के साथ आत्मसमर्पण किया।
- कोड़ा, बिहार और झारखंड क्षेत्रों में सक्रिय एक दीर्घकालिक माओवादी कमांडर था तथा राज्य के सबसे वांछित उग्रवादियों में शामिल था। यह 25 वर्षों से फरार चल रहा था।
- राज्य की आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीति के तहत सुरेश कोड़ा को घोषित ₹3 लाख का इनाम, इसके अतिरिक्त ₹5 लाख की प्रोत्साहन राशि तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये मासिक भत्ता मिलना संभावित है।
- पिछले वर्ष 2025 में राज्य में एक भी नक्सली घटना नहीं हुई और 220 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद डीआईजी राकेश कुमार ने बिहार को नक्सल-मुक्त घोषित किया।
- यह 1970 के दशक से जारी हिंसा के अंत और 23 जिलों में वामपंथी उग्रवाद के पूरी तरह से खत्म होने का प्रतीक है।
- सशस्त्र संघर्ष की माओवादी विचारधारा में निहित नक्सलवाद दशकों तक बिहार के लिये एक प्रमुख आंतरिक सुरक्षा चुनौती रहा था , जिससे अब राहत मिली है।

❑ माओवाद/ नक्सलवाद के बारे में -

- माओवाद और नक्सलवाद भारत में व्याप्त एक हिंसक वामपंथी उग्रवाद (Left-wing Extremism) है, जो माओ त्से-तुंग की हिंसक विचारधारा से प्रेरित है और सशस्त्र विद्रोह द्वारा सत्ता पलटने का लक्ष्य रखता है।
- यह 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गाँव से शुरू हुआ, जिसके कारण इसे नक्सलवाद कहा गया।
- भारत में यह मुख्य रूप से रेड कॉरिडोर (छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र) में सक्रिय रहा।
- 2010 से पहले यह बहुत विस्तृत था, लेकिन अब सरकार की कार्रवाई के कारण यह सीमित क्षेत्रों में रह गया है।

04 ISRO, पश्चिम चंपारण और भागलपुर में अत्याधुनिक डॉप्लर वेदर रडार (DWR) स्थापित करेगा।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) हाल ही में बिहार के पश्चिम चंपारण और भागलपुर जिलों में अत्याधुनिक डॉप्लर वेदर रडार (DWR) स्थापित करेगा। ISRO के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (SAC) के निदेशक नीलेश एम. देसाई ने फरवरी 2026 में पटना में इसकी घोषणा की।

❑ मुख्य लाभ:-

- यह परियोजना बिहार मौसम सेवा केंद्र (BMSK) और ISRO के बीच पिछले तीन वर्षों से चल रहे सहयोग का हिस्सा है। इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:

→ वज्रपात की सटीक चेतावनी: बिहार में बिजली गिरने से हर साल बड़ी संख्या में जनहानि होती है। ये नए रडार 1 से 2 घंटे पहले सटीक वज्रपात की चेतावनी देने में सक्षम होंगे।

→ सटीक बाढ़ और तूफान पूर्वानुमान: चंपारण और भागलपुर के रडार बाढ़-प्रवण और तूफान-प्रवण गलियारों में कवरेज को मजबूत करेंगे। इससे बादलों की गति, हवा की गति और बारिश की तीव्रता का वास्तविक समय (Real-time) में पता लगाया जा सकेगा।

→ चक्रवात चेतावनी: विशेषज्ञों के अनुसार, सैटेलाइट डेटा और AI के साथ मिलकर ये रडार चक्रवात और आंधी की सूचना 15 दिन पहले तक देने की क्षमता विकसित करेंगे।

→ कृषि और भीड़ प्रबंधन: रडार से प्राप्त स्थानीय (Localized) डेटा किसानों को फसल सुरक्षा के लिए समय देगा। इसके अलावा, छठ पूजा जैसे बड़े आयोजनों के दौरान भीड़ नियंत्रण और वायु गुणवत्ता की निगरानी में भी इस तकनीक का उपयोग किया जा सकेगा।

❑ डॉप्लर वेदर रडार (DWR) के बारे में:-

- पारंपरिक रडार के विपरीत, डॉप्लर रडार डॉप्लर प्रभाव (Doppler Effect) पर काम करता है। यह न केवल बादलों की दूरी और स्थिति बताता है, बल्कि उनकी गति और दिशा (Velocity) को भी मापता है।
- इसका रेंज लगभग 300 से 500 किलोमीटर है। यह बारिश, हवा की दिशा, तूफान का केंद्र और वेग की निगरानी करता है।
- यह 'नाउकास्टिंग' (0-6 घंटे का अल्पकालिक पूर्वानुमान) के लिए अति महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम है।

05 बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2026

❑ चर्चा में क्यों?

बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2026 राज्य की न्यायपालिका में एक ऐतिहासिक सुधार है। यह कानून लगभग 139 साल पुराने बंगाल, आगरा और असम सिविल कोर्ट अधिनियम, 1887 का स्थान लेगा। इसका मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक काल के कानूनों को समाप्त कर वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार निचली अदालतों (Subordinate Courts) के ढांचे को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाना है।

❑ विधेयक की मुख्य विशेषताएं:

- नाम में परिवर्तन: अब तक बिहार में 1887 के अधिनियम के तहत ही अदालतों का संचालन होता था। नए विधेयक के पारित होने के बाद अब इसे आधिकारिक तौर पर 'बिहार सिविल न्यायालय अधिनियम' के रूप में जाना जाएगा।
- अदालतों का पदानुक्रम (Hierarchy): यह विधेयक राज्य में दीवानी (Civil) अदालतों के स्पष्ट ढांचे को परिभाषित करता है:
  - → जिला न्यायाधीश (District Judge) का न्यायालय
  - → अपर जिला न्यायाधीश (Additional District Judge) का न्यायालय
  - → सिविल जज (Senior Division) का न्यायालय
  - → सिविल जज (Junior Division) का न्यायालय
- वित्तीय क्षेत्राधिकार (Pecuniary Jurisdiction): नए कानून के माध्यम से कनिष्ठ (Junior) और वरिष्ठ (Senior) स्तर के न्यायाधीशों की सुनवाई करने की वित्तीय सीमा में वृद्धि की गई है। इससे बड़े मामलों का निपटारा स्थानीय स्तर पर तेजी से हो सकेगा।
- प्रशासनिक नियंत्रण: यह विधेयक स्पष्ट करता है कि राज्य की सभी सिविल अदालतें पटना उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण और अधीक्षण (Supervision) के अधीन कार्य करेंगी।

❑ संरचनात्मक परिवर्तन (एक नज़र में)

विशेषता	पुराना कानून (1887)	नया विधेयक (2026)
प्रकृति	औपनिवेशिक और संयुक्त प्रांतों के लिए	बिहार-विशिष्ट और आधुनिक
प्रासंगिकता	वर्तमान न्यायिक बोझ के लिए अपर्याप्त	समकालीन आवश्यकताओं के अनुकूल
प्रशासनिक नियंत्रण	सीमित और अस्पष्ट	विकेंद्रीकृत और अधिक प्रभावी

❑ नोट:-

- यह विधेयक बिहार विधानसभा के बजट सत्र 2026 में पारित किया गया।
- यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233-235 (अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित) के कार्यान्वयन को मजबूती प्रदान करता है।

06 बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026

❑ चर्चा में क्यों?

बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 को बिहार विधानसभा द्वारा 24 फरवरी, 2026 को पारित किया गया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों (Municipal Bodies) की निर्णय प्रक्रिया को अधिक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।

❑ इस संशोधन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

➲ सशक्त स्थायी समिति (Empowered Standing Committee) का गठन

- इस विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया में है:
  - → गुप्त मतदान: अब सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों का चयन पार्षदों द्वारा गुप्त मतदान (Secret Ballot) के माध्यम से किया जाएगा।
  - → मेयर की शक्तियों में कमी: इससे पहले, मेयर (मुख्य पार्षद) के पास समिति के सदस्यों को नामित करने का अधिकार होता था। अब इस शक्ति को विकेंद्रीकृत कर दिया गया है।
  - → पारदर्शिता: इसका उद्देश्य समिति के गठन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

➲ प्रशासनिक और भर्ती सुधार

- विधेयक के माध्यम से नगर निकायों में नियुक्तियों को लेकर भी स्पष्टता दी गई है:
  - → नगर निगमों और जिला परिषदों के ग्रुप-B और ग्रुप-C (द्वितीय और तृतीय श्रेणी) के पदों पर भर्ती अब बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) और बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) के माध्यम से की जाएगी।

→ इसका उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता लाना और भाई-भतीजावाद को समाप्त करना है।

➲ **अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान**

- अध्यादेश का स्थान: यह विधेयक 'बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2025' की जगह लेगा।
- विधिक अपील: यदि कोई व्यक्ति मुख्य नगरपालिका अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट है, तो वह 30 दिनों के भीतर जिला न्यायाधीश (District Judge) के पास अपील कर सकता है।
- सांसदों और विधायकों को छूट: लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो सदस्य नगर निकाय के पदेन सदस्य होते हैं, उन्हें सदन सत्र के दौरान नगरपालिका की बैठकों में भाग लेने से छूट दी गई है।

➲ **प्रभाव:**

- यह संशोधन बिहार के सभी 19 नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों पर लागू होगा। यह मेयर की "एकतरफा" शक्तियों को नियंत्रित करने और पार्षदों की सामूहिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

07 सोनपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रस्ताव को बिहार कैबिनेट की मंजूरी

बिहार कैबिनेट ने सारण जिले के सोनपुर (दरियापुर चंवर क्षेत्र) में 4200 एकड़ भूमि पर एक अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी दी है। इसमें बड़े विमानों के लिए लंबा रनवे शामिल है, जो उत्तर बिहार को वैश्विक कनेक्टिविटी देगा और क्षेत्र में व्यापार व पर्यटन को बढ़ावा देगा।

मुख्य बिंदु

- यह एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Greenfield International Airport) होगा, जिसका अर्थ है कि इसे पूरी तरह से नए सिरे से विकसित किया जा रहा है।
  - → इस परियोजना के लिए लगभग 4200 एकड़ (प्रारंभिक चरण) भूमि चिन्हित की गई है। इसके लिए कैबिनेट ने करीब ₹1302 करोड़ के भूमि अधिग्रहण बजट को भी स्वीकृति दी है।
  - → इसका निर्माण कार्य पूरा करने और परिचालन शुरू करने के लिए 2030 की समय सीमा तय की गई है।

❑ लाभ:-

- यह हवाई अड्डा केवल यात्रा ही नहीं, बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था के कई पहलुओं को प्रभावित करेगा:
  - → पटना एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा: वर्तमान में जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना की अपनी सीमाएं हैं। सोनपुर हवाई अड्डा एक बड़े विकल्प के रूप में उभरेगा।
  - → सोनपुर मेला और पर्यटन: विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले के पास हवाई अड्डा होने से अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी।
  - → कृषि निर्यात: बिहार के मखाना, फल (जैसे शाही लीची) और अन्य कृषि उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय निर्यात को इससे सीधा बढ़ावा मिलेगा।
  - → लॉजिस्टिक्स हब: यह उत्तर बिहार को देश के बाकी हिस्सों और विदेशों से सीधे जोड़ने वाला एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स केंद्र बनेगा।

08 बिहार कैंसर कॉन्क्लेव 2026

❑ चर्चा में क्यों?

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 फरवरी 2026 को पटना के बुद्ध मार्ग स्थित होटल ताज सिटी सेंटर में दो दिवसीय 'बिहार कैंसर कॉन्क्लेव 2026' का उद्घाटन किया। इस दो दिवसीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बिहार में कैंसर देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और विशेषज्ञों के बीच नवीनतम चिकित्सा पद्धतियों को साझा करना था।

मुख्य बिंदु

- इसका आयोजन पारस हेल्थ (Paras Health), पटना के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मेदांता और अन्य प्रमुख चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञों ने भी सहभागिता की।
- इस कार्यक्रम में देश भर के 200 से अधिक प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने कैंसर के निदान, उपचार, और जागरूकता बढ़ाने संबंधित निम्न बिंदुओं पर चर्चा किया -
  - → नवीनतम उपचार तकनीक: कैंसर के निदान (Diagnosis) और उपचार के लिए नवीनतम रोबोटिक सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी और सटीक दवा (Precision Medicine) पर मंथन।
  - → मल्टीडिसिप्लिनरी केयर: मरीजों को एक ही छत के नीचे विभिन्न विभागों (सर्जरी, ऑन्कोलॉजी, रेडियोलॉजी) का संयुक्त परामर्श मिलना।
  - → जन जागरूकता: बिहार में कैंसर के प्रति व्याप्त भ्रांतियों को दूर करना और लोगों को स्क्रीनिंग के लिए प्रोत्साहित करना।
  - → प्रिवेंशन (बचाव): विशेषज्ञों ने बताया कि 30 से 40% कैंसर को तंबाकू और शराब के सेवन से बचकर रोका जा सकता है।

❑ बिहार के लिए महत्व:

- बिहार जैसे राज्य में जहाँ कैंसर के मरीजों की संख्या अधिक है, यह कॉन्क्लेव निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है:
  - → स्थानीय उपचार: बिहार के मरीजों को अब उच्च स्तरीय इलाज के लिए दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
  - → स्क्रीनिंग सुविधाओं का विस्तार: राज्य में सर्वाइकल, ब्रेस्ट और ओरल कैंसर की शुरुआती जांच (Screening) के लिए विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया गया।
  - → सरकारी सहयोग: मुख्यमंत्री की उपस्थिति यह दर्शाती है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, विशेषकर कैंसर केयर में निवेश को प्राथमिकता दे रही है।
- नोट: विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में विशेष रूप से महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, जिनके लिए नियमित स्क्रीनिंग ही बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है।

EDU TERIA Telegram Channel
link : https://eduteria.live

09 कंबोडिया सरकार की पर्यटन गतिविधियों में मदद करेगा बिहार

बिहार सरकार और कंबोडिया के पर्यटन विभाग के बीच हाल ही में बौद्ध सर्किट को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष वर्चुअल बैठक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक) आयोजित की गई, यह बैठक दोनों क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित रही।

❑ चर्चा के मुख्य बिंदु:-

- इस वर्चुअल बैठक में बिहार के पर्यटन सचिव निलेश रामचंद्र देवरे और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने कंबोडियाई प्रतिनिधियों के साथ कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा की, जो इस प्रकार हैं:-
  - → विशेष भ्रमण योजना: कंबोडियाई पर्यटकों के लिए 10 से 30 दिनों की विशेष यात्रा योजना (Itinerary) तैयार की गई है, जिसमें बोधगया, राजगीर, नालंदा, वैशाली और केसरिया जैसे प्रमुख बौद्ध स्थलों को शामिल किया गया है।
  - → संयुक्त ब्रांडिंग (Joint Branding): 'अंकोरवाट से बोधगया' (Angkor Wat to Bodhgaya) जैसी साझा ब्रांडिंग पहल का प्रस्ताव रखा गया है ताकि दोनों देशों के पर्यटन स्थलों को एक साथ प्रमोट किया जा सके।
  - → बोधगया में कंबोडियन रेस्टोरेंट: कंबोडिया से आने वाले पर्यटकों की सुविधा और उनकी संस्कृति के सम्मान में बोधगया में एक समर्पित कंबोडियन रेस्टोरेंट खोलने की योजना है।
  - → आधारभूत संरचना का विकास: बैठक में बिहार में चल रहे प्रमुख प्रोजेक्ट्स जैसे—केसरिया में स्तूपों की प्रतिकृति, वैशाली में 'सम्यक स्तूप', और पटना में 'पाटलिपुत्र करुणा स्तूप' के बारे में जानकारी साझा की गई।
  - → 'बिहार को जानो' (Know Bihar) पहल: कंबोडियाई नागरिकों को बिहार की समृद्ध विरासत से परिचित कराने के लिए एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने पर सहमति बनी है।

❑ रणनीतिक महत्व:-

- कंबोडिया की लगभग 18 मिलियन की आबादी में से अधिकांश बौद्ध अनुयायी हैं। बिहार सरकार का लक्ष्य इस बड़े बाजार को आकर्षित करना है ताकि राज्य में आध्यात्मिक पर्यटन (Spiritual Tourism) और राजस्व में वृद्धि हो सके।

❑ बौद्ध सर्किट के बारे में:-

- बौद्ध सर्किट (Buddhist Circuit) भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं से जुड़े पवित्र स्थलों का एक प्रमुख पर्यटन मार्ग है, जो मुख्य रूप से भारत (बिहार, यूपी) और नेपाल में स्थित है। यह स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित किया गया है, जिसमें 8 प्रमुख स्थान शामिल हैं।

❑ बौद्ध सर्किट के मुख्य आकर्षण और स्थल:

- बोधगया (बिहार): जहाँ बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ; महाबोधि मंदिर यहाँ का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।
- राजगीर (बिहार): यहाँ बुद्ध ने कई वर्ष बिताए और उपदेश दिए।
- नालंदा (बिहार): प्राचीन बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र।
- वैशाली (बिहार): बुद्ध ने यहाँ अपना अंतिम उपदेश दिया।
- सारनाथ (यूपी): वाराणसी के पास, जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 'धम्मचक्कपवत्तन सुत्त' दिया था।
- कुशीनगर (यूपी): वह स्थान जहाँ भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ।
- श्रावस्ती (यूपी): यहाँ बुद्ध ने सबसे अधिक समय व्यतीत किया था।
- लुम्बिनी (नेपाल): भगवान बुद्ध का जन्मस्थान।

10 बिहार की पहली 'ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी' को अंतिम रूप देने में जुटा 'BREDA'

बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (BREDA) बिहार में जीरो कार्बन उत्सर्जन और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली 'ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी' (2025-2030) को अंतिम रूप देने में जुटी है। इस नीति का उद्देश्य 2030 तक हरित हाइड्रोजन उत्पादन बढ़ाना, निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए कर रियायतें, बिजली शुल्क में छूट और 'व्हाइट केटेगरी' का दर्जा देना है।

मुख्य बिंदु

- नीति के मुख्य लक्ष्य
  - → उत्पादन क्षमता: बिहार सरकार ने वर्ष 2030 तक सालाना 0.25 मिलियन मीट्रिक टन (MTPA) ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया उत्पादन का लक्ष्य रखा है।
  - → अक्षय ऊर्जा विस्तार: इसे राज्य की नई 'अक्षय ऊर्जा नीति 2025' के साथ जोड़ा गया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 24 GW (गीगावाट) सौर और अन्य हरित ऊर्जा क्षमता हासिल करना है।
- प्रमुख प्रोत्साहन और रियायतें

  निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इस ड्राफ्ट पॉलिसी में कई बड़े लाभ दिए गए हैं:
  - → SGST प्रतिपूर्ति: ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी सामग्री पर चुकाए गए राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) की 100% वापसी (5 वर्षों के लिए)।
  - → बिजली शुल्क में छूट: 15-20 वर्षों के लिए बिजली शुल्क (Electricity Duty) और ट्रांसमिशन शुल्क (Wheeling Charges) में पूर्ण छूट।
  - → सिंगल विंडो क्लीयरेंस: ब्रेडा (BREDA) नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी, जो 60 दिनों के भीतर सभी आवश्यक स्वीकृतियां सुनिश्चित करेगी।
  - → 'व्हाइट कैटेगरी' का दर्जा: इन परियोजनाओं को बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 'सहमति पत्र' (NOC) लेने की जरूरत नहीं होगी, जिससे व्यापार में सुगमता आएगी।
- औद्योगिक क्लस्टर और हब
  - → नीति के तहत बिहार में 'ग्रीन हाइड्रोजन हब' और 'इंडस्ट्रियल वैली' विकसित करने की योजना है।
  - → शुरुआत में इसका उपयोग उर्वरक (Fertilizer) संयंत्रों और रिफाइनरियों (जैसे बरौनी) में किया जाएगा, जहाँ वर्तमान में 'ग्रे हाइड्रोजन' का उपयोग होता है।

→ भविष्य में इसे भारी परिवहन और अन्य उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग करने की योजना है।

- पर्यावरणीय और आर्थिक महत्व
  - → शून्य कार्बन उत्सर्जन: यह नीति बिहार के 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के विजन का हिस्सा है।
  - → रोजगार सृजन: सरकार का अनुमान है कि अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में आने वाले इन बदलावों से राज्य में लगभग 50,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- नोट:- यह नीति केंद्र सरकार के 'नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन' के अनुरूप है। बिहार उन चुनिंदा राज्यों (जैसे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र) की सूची में शामिल होने जा रहा है जिनकी अपनी स्वतंत्र हाइड्रोजन नीति है।

❑ BREDA के बारे में:-

- बिहार में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (BREDA - ब्रेडा) की स्थापना वर्ष 1987 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई थी।
- यह राज्य में सौर, पवन और बायोमास जैसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करने और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार एक प्रमुख सरकारी एजेंसी है।
- यह बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करती है।

11 'जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना'

❑ चर्चा में क्यों?

बिहार विधानसभा में हाल ही में पेश किए गए 'बिहार बजट 2026-27' में 'जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना' की घोषणा वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा की गई। यह योजना किसानों को केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त राज्य से 3,000 रुपये सालाना प्रदान करेगी।

मुख्य बिंदु

- यह योजना केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ क्रियान्वित होगी।
- पहले किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत प्रतिवर्ष 6,000 रुपये (तीन किस्तों में 2,000–2,000) मिलते थे। अब बिहार सरकार इसके ऊपर 3,000 रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त देगी, इस तरह पात्र किसानों को कुल 9,000 रुपये सालाना मिलेंगे।
- अतिरिक्त 3,000 रुपये की राशि भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में जाएगी।
- इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो पहले से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पंजीकृत और पात्र लाभार्थी हैं।
- योजना का उद्देश्य राज्य के छोटे और सीमांत किसानों की आय में बढ़ोतरी कर उन्हें अधिक सशक्त और आर्थिक रूप से स्थिर बनाना है।
- सरकार ने इसे जननायक कर्पूरी ठाकुर की स्मृति और किसान-समर्थक राजनीति के प्रतीक के रूप में शुरू किया है।
- नोट:- 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' औपचारिक रूप से 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शुरू की गई थी।

❑ जननायक कर्पूरी ठाकुर (24 जनवरी 1924 – 17 फरवरी 1988) के बारे में:-

- जन्म: समस्तीपुर के पितौंझिया (अब कर्पूरीग्राम) में एक साधारण नाई परिवार में।
- उपनाम: जनता के बीच अत्यधिक लोकप्रियता के कारण उन्हें 'जननायक' कहा जाता था।
- राजनीतिक करियर: बिहार के दूसरे उपमुख्यमंत्री (1967) और दो बार मुख्यमंत्री (1970-71, 1977-79) रहे।
- इनके द्वारा लिए गए क्रांतिकारी निर्णय:
  - → आरक्षण: पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर जातियों के लिए शिक्षा व नौकरियों में 26% आरक्षण लागू किया।
  - → शिक्षा: बिहार में मैट्रिक तक की शिक्षा मुफ्त कर दी।
  - → भाषा: उर्दू को बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया।
  - → शराबबंदी: बिहार में शराब पर प्रतिबंध लागू किया।
- सम्मान: 26 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया।

12 एशियन वॉटरबर्ड सेंसस 2026 (Asian Waterbird Census - AWC) 2026

एशियन वॉटरबर्ड सेंसस 2026 के तहत बिहार की आर्द्रभूमियों (wetlands) में पक्षियों की गणना 18 जनवरी से 8 फरवरी 2026 के बीच की गई, जिसमें 119 प्रजातियों के 18,050 से अधिक पक्षी पाए गए। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय (CUSB) की टीम ने रोहतास के इंद्रपुरी बैराज, गया के हरदिया डैम और गंगा नदी के विभिन्न घाटों पर पक्षियों के सबसे समृद्ध आवासों की पहचान की।

मुख्य बिंदु

- गया के अहियापुर झील और टिकारी क्षेत्र के वेटलैंड्स में प्रवासी पक्षियों की अच्छी उपस्थिति देखने को मिली।
- रोहतास और औरंगाबाद के बीच सोन नदी पर स्थित इंद्रपुरी बैराज, इस साल के सर्वेक्षण में सबसे समृद्ध स्थल रहा। यहाँ 66 प्रजातियों के कुल 7,829 पक्षी मिले। सोन नदी के इस क्षेत्र में विदेशी पक्षियों का जमावड़ा अधिक देखा गया।
- बांका और जमुई
  - → ओढ़नी डैम (Odhni Dam): यहाँ बार-हेडेड गूज (कलहंस) की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में भारी वृद्धि हुई (50 से बढ़कर लगभग 200) है। इसके अलावा, यहाँ पहली बार 'ब्राउन हेडेड गीज' देखा गया।
  - → चंदन डैम: यहाँ भी प्रवासी पक्षियों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है।
- भागलपुर में गंगा नदी (सुल्तानगंज से कहलगांव के बीच) के दियारा क्षेत्रों में गणना की गई। यहाँ इंडियन स्कीमर (Indian Skimmer) और ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क (गरुड़) की उपस्थिति दर्ज की गई, जो पारिस्थितिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है।

- उत्तर बिहार
  - → सुपौल और कोसी क्षेत्र: कोसी के जलग्रहण क्षेत्रों में 'सिल्ली' (Lesser Whistling Teal) की संख्या सबसे अधिक पाई गई।
  - → बेगूसराय (कांवर झील): एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील (Ox-bow lake) होने के नाते यहाँ मध्य एशिया से आए पक्षियों की विविधता देखी गई।

❑ **बिहार के लिए गणना का महत्व:**

- इकोटूरिज्म: बांका के ओढ़नी डैम और गया के जलाशयों को पक्षी पर्यटन (Bird Tourism) के केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है।
- संरक्षण: यह डेटा राज्य सरकार को आर्द्रभूमियों के संरक्षण और शिकार रोकने की नीतियां बनाने में मदद करेगा।
- जलवायु संकेत: प्रवासी पक्षियों की बदलती संख्या यह संकेत देती है कि बिहार की आर्द्रभूमियों का जल स्तर और भोजन की उपलब्धता (मछली, शैवाल) कैसी है।

13 बिहार समसामयिकी (To The Point)

- केंद्र सरकार ने 2026-27 के लिए बिहार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में रिकॉर्ड 1.51 लाख करोड़ आवंटित किए हैं।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार देश के कुल सड़क नेटवर्क में बिहार की भागीदारी मात्र 5.5% है।
  - → राष्ट्रीय राजमार्ग के मामले में बिहार की भागीदारी मात्र 4.2% रही।
  - → बिहार के कुल 57 राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई 6389 किमी है।
  - → बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग - NH 27 'ईस्ट- वेस्ट कॉरिडोर' है, जिसकी बिहार में लंबाई 483 किमी है।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बिजली खपत वाले जिलें हैं-
  - → पटना (6969 करोड़ यूनिट)
  - → गयाजी (2505 करोड़ यूनिट)
  - → मुजफ्फपुर (1807 करोड़ यूनिट)
- आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार पटना सबसे समृद्ध और शिवहर सबसे गरीब जिला है।
- बिहार के तीन सबसे समृद्ध जिले :-
  - → पटना-(131332 रुपये)
  - → बेगुसराय - (61566 रुपये)
  - → मुंगेर - (54469 रुपये)
- बिहार के तीन सबसे गरीब जिले:-
  - → शिवहर (18980 रुपये)
  - → अररिया (19795 रुपये)
  - → सीतामढ़ी (21448 रुपये)
- सीवान के सुरैला ताल को पक्षी अभयारण्य बनाने की सिफारिश की गई।
  - → गोपालगंज-सीवान में मिले दुर्लभ पोचार्ड, नदी टिटहरी और भारतीय तंबु कछुआ। यह राज्य के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
- बिहार के भागलपुर (अगरपुट - कुरपट वेटलैंड) में पहली बार दिखा हाइब्रिड पक्षी 'रीफ हेरॉन' ।
- बिहार के सभी विश्वविधालयों में नए शुरू होने वाले सत्र से छात्रों का नामांकन समर्थ पोर्टल (SAMARTH) के माध्यम से होगा।
- हाल ही में बिहार से दीघा के मालदा आम, शाहाबाद का सोनाचूर चावल, मुंगेर का टिपिया धान, समस्तीपुर के बहुआ आम को जी आई टैग प्रदान करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया।
- ISRO, बिहार के पश्चिम चंपारण और भागलपुर जिलों में अत्याधुनिक डॉप्लर वेदर रडार (DWR) स्थापित करेगा।
- बिहार, भारत विस्तार (Bharat VISTAAR) लोगो (Logo) अपनाने वाला पहला राज्य बना।
- बिहार के आठ बांध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाएंगें। जिसमें शामिल हैं-

1. दुर्गावती जलाशय	2. वाल्मीकिनगर बराज
3. गंगाजी राजगृह जलाशय	4. खड़गपुर झील
5. कुंडघाट जलाशय	6. गरही (अपर किउल) जलाशय
7. मोरवे जलाशय	8. ओढ़नी डैम - फुलवरिया डैम

- बिहार कैबिनेट ने सोनपुर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका निर्माण 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को बिहार सरकार ने 50 लाख का सम्मान राशि प्रदान किया।

अभ्यास प्रश्न

1. किस देश की यूनिवर्सिटी ने ग्रीन हाइड्रोजन और क्लीन एनर्जी रिसर्च के लिए 19 इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (IITs) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया है?

(A) नीदरलैंड्स (B) जर्मनी
(C) फ्रांस (D) डेनमार्क

2. भारत और USA ने किस तारीख को एक अंतरिम व्यापार समझौता (ITA) के ढांचे (फ्रेमवर्क) पर सहमत हुए?

(A) 5 फरवरी, 2026 (B) 7 फरवरी, 2026
(C) 10 फरवरी, 2026 (D) 12 फरवरी, 2026

3. भारत का फ्लैगशिप डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), अब कितने देशों में चालू है?

(A) 6 देश (B) 8 देश
(C) 10 देश (D) 12 देश

4. स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज 'कृष्णा' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मितकैडेट प्रशिक्षण जहाज है।
2. इसका निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोच्ची शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है।
3. यह जहाज आपदा राहत (HADR) कार्यों में भी सक्षम है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 2 (B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3 (D) 1, 2 और 3

5. वी.ओ. चिदंबरनार (VOC) पोर्ट पर लगाए गए एडवांस्ड एंटी-ड्रोन सिस्टम की असरदार रेंज क्या है?

(A) 2 किलोमीटर (B) 3 किलोमीटर
(C) 5 किलोमीटर (D) 7 किलोमीटर

6. किस फाउंडेशन ने फ्री ऑनलाइन कोचिंग देने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया है?

(A) वेदांतु फाउंडेशन
(B) फिजिक्स वाला (PW) फाउंडेशन
(C) बायजू फाउंडेशन
(D) अनएकेडमी फाउंडेशन

7. 39 वां भारत अंतरराष्ट्रीय मेला 2026 कहां आयोजित किया जा रहा है?

(A) मुंबई (B) चेन्नई
(C) कोलकाता (D) नई दिल्ली

8. किस मिनिस्ट्री ने eSankhyiki पोर्टल पर 'MCP Server' का बीटा संस्करण लॉन्च किया?

(A) मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (MoSPI)
(B) मिनिस्ट्री ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
(C) मिनिस्ट्री ऑफ़ कम्युनिकेशंस
(D) मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस

9. भारत और अरब राज्यों के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई थी?

(A) मुंबई (B) नई दिल्ली
(C) दुबई (D) रियाद

10. 114 और राफेल फाइटर जेट की खरीद को मंजूरी मिलने के बाद भारत के पास कुल राफेल फाइटर जेट फ्लीट में कितने जेट होंगे?

(A) 152 जेट (B) 164 जेट
(C) 176 जेट (D) 188 जेट

11. डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस के संदर्भ में 'VoicERA' का मुख्य उद्देश्य क्या है?

(A) किसानों को मौसम की जानकारी प्रदान करना।
(B) फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा मैन्युअल डेटा प्रविष्टि के बोझ को कम करना।
(C) सरकारी दफ्तरों में वॉयस बायोमेट्रिक्स के जरिए हाजिरी लगाना।
(D) रक्षा क्षेत्र में एन्क्रिप्टेड वॉयस संचार प्रदान करना।

12. गगनयान मिशन के लिए ड्रोग पैराशूट (Drogue Parachute) का हालिया सफल परीक्षण कहाँ किया गया?

(A) श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश (B) चंडीगढ़, पंजाब
(C) बेंगलुरु, कर्नाटक (D) पोखरण, राजस्थान

13. USGBC LEED लिस्ट 2025 में, कौन सा देश 26,645,737 GSM LEED-सर्टिफाइड स्पेस के साथ लिस्ट में टॉप पर रहा?

(A) इंडिया (B) कनाडा
(C) मेनलैंड चाइना (D) साउथ कोरिया

NOT FOR SALE

14. USGBC LEED लिस्ट 2025 में इंडिया की क्या पोजीशन थी?
(A) पहला (B) दूसरा
(C) तीसरा (D) चौथा

15. दवा की सुरक्षा और गुणवत्ता को मज़बूत करने के लिए किन तीन एंटिटीज़ ने इंडियन फार्माकोपिया कमीशन (IPC) के साथ MoU साइन किए?
(A) GSPC, QCI, HITES (B) WHO, FDA, GSPC
(C) QCI, NDMA, HITES (D) GSPC, NDMA, WHO

16. भारत और किस देश ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ़ इंटेंट पर साइन किए?
(A) फ्रांस (B) जर्मनी
(C) ग्रीस (D) इटली

17. नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में, 127 इकॉनमी में भारत का रैंक क्या था?
(A) 40वां (B) 45वां
(C) 50वां (D) 55वां

18. सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है?
(A) जयपुर, राजस्थान (B) फरीदाबाद, हरियाणा
(C) भोपाल, मध्य प्रदेश (D) अहमदाबाद, गुजरात

19. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (CPI) 2025 में भारत की बेहतर रैंकिंग क्या थी?
(A) 86वां (B) 89वां
(C) 91वां (D) 95वां

20. विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (IPO) डेटा के अनुसार 2024 में भारत ने R&D पर कितना खर्च किया?
(A) USD 65.73 बिलियन (B) USD 70.73 बिलियन
(C) USD 75.73 बिलियन (D) USD 80.73 बिलियन

21. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स – फरवरी 2026 में, भारत की रैंकिंग क्या थी?
(A) 70वीं (B) 75वीं
(C) 80वीं (D) 85वीं

22. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत के पासपोर्ट में कितने गंतव्यों के पास वीजा-मुक्त या वीजा-ऑन-अराइवल पहुंच है?
(A) 48 गंतव्यों (B) 52 गंतव्यों
(C) 56 गंतव्यों (D) 60 गंतव्यों

23. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आरबीआई द्वारा अपनी छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति में रेपो दर क्या तय की गई थी?
(A) 5.00% (B) 5.15%
(C) 5.50% (D) 5.35%

24. कौन सा बैंक पूरी तरह से डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर (FPI) लाइसेंस जारी करने वाला भारत का पहला कस्टोडियन बना?
(A) HDFC बैंक (B) ICICI बैंक
(C) कोटक महिंद्रा बैंकब (D) एक्सिस बैंक

25. वित्त वर्ष 2025 में भारत के बैंकिंग क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी प्रवाह कितना था?
(A) USD 98 मिलियन (B) USD 115 मिलियन
(C) USD 135 मिलियन (D) USD 150 मिलियन

26. बैंक ऑफ़ बड़ौदा की किस क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली ब्रांच ने ब्रेल-इनेबल्ड प्रीमियर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया?
(A) SBI कार्ड (B) BOBCARD लिमिटेड
(C) HDFC बैंक कार्ड (D) ICICI बैंक कार्ड

27. EximPe को RBI से किस लाइसेंस के लिए मंज़ूरी मिली, ताकि इंटरनेशनल मर्चेंट्स भारतीय कस्टमर्स से पेमेंट ले सकें?
(A) पेमेंट एग्रीगेटर (PA)
(B) पेमेंट एग्रीगेटर-क्रॉस बॉर्डर (PA-CB)
(C) डिजिटल पेमेंट लाइसेंस
(D) इंटरनेशनल पेमेंट लाइसेंस

28. वित्तीय वर्ष 2026-27 में मूडीज़ का भारत के लिए अनुमानित GDP ग्रोथ रेट क्या है?
(A) 5.8% (B) 6.0%
(C) 6.4% (D) 6.8%

29. नेशनल शिपबिल्डिंग प्रोग्राम के लिए एक कंसोर्टियम बनाने के लिए किन दो इंडियन डिफेंस PSUs ने MoU साइन किया?
(A) GRSE और HAL (B) GRSE और HSL
(C) HSL और HAL (D) GRSE और कोचीन शिपयार्ड

30. 145वें IOC सेशन के दौरान ईरान की पहली महिला IOC मेंबर कौन चुनी गईं?
(A) सोराया अघाई हाजियाघा (B) नसीम इश्तियाक
(C) ज़हरा नेमाती (D) आयनाज़ घनबरज़ादेह

31. ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया?
(A) चीन (B) यूनाइटेड किंगडम
(C) संयुक्त राज्य अमेरिका (D) जापान

32. लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) की जीत के बाद जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनीं?
(A) युरिको कोइके (B) साने ताकाइची
(C) हिरोको ओटा (D) सेइको नोडा

33. RBI ने आर. विजय आनंद को किस बैंक का MD और CEO नियुक्त करने की मंज़ूरी दी?
(A) सिटी यूनियन बैंक (B) फ़ेडरल बैंक
(C) साउथ इंडियन बैंक (D) करूर वैश्य बैंक

34. हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा रेखांकित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए 'MANAV' दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत किया गया है। MANAV के पूर्ण रूप में 'N' किसे दर्शाता है?
(A) नई तकनीक (B) नेटवर्क सुरक्षा
(C) राष्ट्रीय संप्रभुता (D) न्यूरल नेटवर्क

35. पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एंबेसडर किसे नियुक्त किया गया था?
(A) विराट कोहली (B) रोहित शर्मा
(C) शिखर धवन (D) MS धोनी

36. बुल्गारिया ने केयरटेकर सरकार को लीड करने के लिए किस व्यक्ति को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया?
(A) रोसेन ज़ेलियाज़कोव (B) एंड्री ग्युरोव
(C) किरिल पेटकोव (D) एसेन वासिलेव

37. CA प्रसन्ना कुमार D को 2026-27 के लिए किस संगठन का अध्यक्ष चुना गया?
(A) CII (B) NASSCOM
(C) ICAI (D) FICCI

38. GAIL (इंडिया) लिमिटेड का नया CMD किसे नियुक्त किया गया?
(A) संदीप कुमार गुप्ता (B) दीपक गुप्ता
(C) राजेश गुप्ता (D) अरुण गुप्ता

39. भारत ने ओडिशा में किस इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया?
(A) अग्नि-1 (B) अग्नि-2
(C) अग्नि-3 (D) अग्नि-5

40. अग्नि-3 मिसाइल की रेंज क्या है?
(A) 2,000–2,500 किलोमीटर (B) 2,500–3,000 किलोमीटर
(C) 3,000–3,500 किलोमीटर (D) 3,500–4,000 किलोमीटर

41. चंद्रयान-4 मिशन के लिए ISRO ने कौन सी लैंडर साइट की पहचान की?
(A) टाइको क्रेटर (B) मॉन्स माउटन-4
(C) मारे ट्रैंक्विलिटैटिस (D) ओशनस प्रोसेलरम

42. आदित्य पांड्या किस उम्र में भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग एस्ट्रोनॉट बने?
(A) 15 साल (B) 16 साल
(C) 17 साल (D) 18 साल

43. सैटेलाइट बस एज़ ए सर्विस (SBaaS) पहल के लिए IN-SPACe ने किन तीन भारतीय प्राइवेट स्टार्टअप को चुना?
(A) स्काईरूट, एस्ट्रोम और अज़िस्टा
(B) एस्ट्रोम, अज़िस्टा और ध्रुव स्पेस
(C) स्काईरूट, ध्रुव स्पेस और अज़िस्टा
(D) एस्ट्रोम, स्काईरूट और ध्रुव स्पेस

44. विंग्स इंडिया 2026 में किस राज्य ने "एविएशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य" पुरस्कार जीता?
(A) हिमाचल प्रदेश (B) उत्तराखंड
(C) केरल (D) गुजरात

45. बंगाल की खाड़ी के इकोसिस्टम में कौन सी नई समुद्री कीड़े की प्रजाति खोजी गई?
(A) पॉलीकीट्स (नेरीडिडे परिवार)
(B) ओलिगोकीट्स
(C) लीचेस
(D) फ्लैटवर्म

46. केरल के तटीय इलाकों में कौन सी नई ड्रैगनफ्लाई प्रजाति खोजी गई?
(A) एशना ग्रैंडिस (B) लिरियोथेमिस केरालेसिस
(C) पैंटाला फ्लेवेसेंस (D) गोम्फस वल्गेटिसिमस

47. इंडिया की अंडर-19 मेन्स क्रिकेट टीम ने रिकॉर्ड कितने ICC U19 मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल जीते?
(A) चौथा टाइटल (B) पांचवां टाइटल
(C) छठा टाइटल (D) सातवां टाइटल

48. U19 वर्ल्ड कप फाइनल में वैभव सूर्यवंशी का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर क्या था?
(A) 150 रन (B) 160 रन
(C) 175 रन (D) 180 रन

49. इंडिया की अंडर-17 विमेंस फुटबॉल टीम ने SAFF U-19 विमेंस चैंपियनशिप फाइनल में किस देश को 4-0 से हराया?
(A) नेपाल (B) श्रीलंका
(C) बांग्लादेश (D) भूटान

50. कौन सा राज्य भारत का दूसरा राज्य बन गया है जिसने स्टेट-लेवल बर्ड एटलस पब्लिश किया है?
(A) महाराष्ट्र (B) गुजरात
(C) गोवा (D) कर्नाटक

51. असम में PM मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बने किस छह लेन के पुल का उद्घाटन किया?
(A) जोगीगोपा ब्रिज (B कुमार भास्कर वर्मा सेतु
(C) बोगीबील ब्रिज (D) दूसरा सिलचर ब्रिज

NOT FOR SALE

52. स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 (FoF 2.0) का कुल बजट कितना है?

(A) Rs 5,000 करोड़ (B) Rs 8,000 करोड़
(C) Rs 10,000 करोड़ (D) Rs 15,000 करोड़

53. CCEA ने कितने किलोमीटर के रेलवे मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी?

(A) 250 km (B) 300 km
(C) 389 km (D) 450 km

54. किस यूनिवर्सिटी ने टेलीकॉम और साइबर सिक्योरिटी कोलेबोरेशन के लिए C-DOT के साथ MoU साइन किया?

(A) गुजरात यूनिवर्सिटी (B) राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी (RRU)
(C) दिल्ली यूनिवर्सिटी (D) IIT बॉम्बे

55. किस केंद्रीय मंत्री ने 'माई भारत बजट क्वेस्ट 2026' लॉन्च किया?

(A) डॉ. जितेंद्र सिंह (B) डॉ. मनसुख मंडाविया
(C) राजनाथ सिंह (D) अमित शाह

56. इंडियन आर्मी की कोणार्क कोर ने पोखरण में किस मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया?

(A) ब्रह्मोस (B) स्ट्रेला-10 VSHORADS
(C) आकाश-3 (D) एस्ट्रा

57. भारत के पहले भारत रत्न डॉ बाबासाहेब अंबेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां हुआ था?

(A) गुजरात (B) कर्नाटक
(C) महाराष्ट्र (D) गोवा

58. PM RAHAT स्कीम के तहत हर विक्टिम के लिए मैक्सिमम कैशलेस ट्रीटमेंट अमाउंट कितना है?

(A) Rs 50,000 (B) Rs 75,000
(C) Rs 1 लाख (D) Rs 1.5 लाख

59. फरवरी 2026 में तारिक रहमान किस देश के प्रधानमंत्री बने?

(A) नेपाल (B) श्रीलंका
(C) बांग्लादेश (D) मालदीव

60. ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत के पहले अंडरवाटर ट्विन ट्यूब रोड-कम-रेल टनल प्रोजेक्ट की लागत क्या है?

(A) Rs 10,000 करोड़ (B) Rs 15,000 करोड़
(C) Rs 18,662 करोड़ (D) Rs 20,000 करोड़

61. पश्चिम बंगाल की किस योजना को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है?

(A) कृषक बंधु योजना (B) माटिर सृष्टि योजना
(C) सुफला बांग्ला योजना (D) उत्कर्ष बांग्ला

62. द्वितीय भारत-एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 का विषय क्या है?

(A) सभी के लिए एआई (B) लोग, ग्रह और प्रगति
(C) डिजिटल इंडिया (D) भारत में निर्मित

63. दिल्ली में एशियन राइफल/पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में इंडिया ने कितने मेडल जीते?

(A) 70 मेडल (B) 82 मेडल
(C) 94 मेडल (D) 105 मेडल

64. सूर्योदय क्षेत्रों को वित्तपोषित करने के लिए एसबीआई द्वारा शुरू किए गए उत्कृष्टता केंद्र का नाम क्या है?

(A) एसबीआई इनोवेट (B) एसबीआई चक्र
(C) एसबीआई विजन (D) एसबीआई फ्यूचर

65. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फरवरी 2026 में 'मिलन-2026' (MILAN-2026) नौसेना अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया?

(A) मुंबई (B) कोच्चि
(C) विशाखापत्तनम (D) चेन्नई

66. फरवरी 2026 में आयोजित पहली अधिकारिक FIDE फ्रीस्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती?

(A) विश्वनाथन आनंद (B) प्रज्ञानंद आर
(C) मैग्नस कार्लसन (D) डिंग लिरेन

67. ओपनAI के साथ टाटा ग्रुप के AI डेटा सेंटर प्रोजेक्ट के लिए निवेश की राशि क्या है?

(A) USD 3 बिलियन (B) USD 5 बिलियन
(C) USD 7 बिलियन (D) USD 10 बिलियन

68. USA के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका कोएलिशन में कितने देश शामिल हैं?

(A) 8 देश (B) 10 देश
(C) 12 देश (D) 15 देश

69. वित्त वर्ष 2029 तक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II का कुल वित्तीय आवंटन कितना है?

(A) Rs 4,000 करोड़ (B) Rs 6,839 करोड़
(C) Rs 8,000 करोड़ (D) Rs 10,000 करोड़

70. किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी ने पहला लिबर विन चैंपियंस कप 2026 जीता?

(A) आदित्य मेहता (B) पंकज आडवाणी
(C) कमल चावला (D) सौरव कोठारी

NOT FOR SALE

71. कौन सा भारतीय नेवी शिप पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और बनाया गया कैडेट ट्रेनिंग शिप था?

(A) INS विक्रमादित्य (B) INS कृष्णा
(C) INS विराट (D) INS जलाश्व

72. बायोएशिया 2026 के 23वें संस्करण का विषय क्या है?

(A) स्वास्थ्य सेवा नवाचार
(B) बायोटेक क्रांति
(C) टेकबायो अनलीशेड – एआई, ऑटोमेशन और जीवविज्ञान क्रांति
(D) डिजिटल स्वास्थ्य

73. नए साइन किए गए MoU के तहत FCI वर्ल्ड फ़ूड प्रोग्राम को कितना चावल सप्लाई करेगा?

(A) 1 लाख MT (B) 1.5 लाख MT
(C) 2 लाख MT (D) 2.5 लाख MT

74. किस प्रसिद्ध बैंकर को GIFT सिटी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया?

(A) गौतम अडानी (B) मुकेश अंबानी
(C) उदय कोटक (D) कुमार मंगलम बिड़ला

75. आंध्रप्रदेश में वारी एनर्जीज़ की बैटरी गीगाफैक्ट्री की अनुमानित उत्पादन क्षमता क्या है?

(A) 10 GWh (B) 12 GWh
(C) 16 GWh (D) 20 GWh

76. किस संस्थान ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे से धातुओं को पुनर्प्राप्त करने के लिए हरित विधि विकसित की?

(A) आईआईटी बॉम्बे (B) आईआईटी दिल्ली
(C) आईआईटी मद्रास (D) आईआईटी कानपुर

77. एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत कौन से सात नए इंटरवेंशन लॉन्च किए गए?

(A) निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा पिलर्स
(B) ट्रेड डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट सपोर्ट
(C) ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट
(D) कॉमर्स और इंडस्ट्री इनिशिएटिव

78. सेमीकंडक्टर और एयरोस्पेस सेक्टर में तमिलनाडु सरकार द्वारा साइन किए गए MoUs की कुल वैल्यू कितनी है?

(A) Rs 3,980 करोड़ (B) Rs 4,980 करोड़
(C) Rs 5,980 करोड़ (D) Rs 6,980 करोड़

79. 'गोवा समुद्री सम्मेलन' (GMC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारतीय नौसेना के तत्वावधान में आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है।
2. इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है।
3. GMC-2026 में केवल बिम्सटेक (BIMSTEC) सदस्य देशों ने भाग लिया है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 2 (B) केवल 2
(C) केवल 2 और 3 (D) 1, 2 और 3

80. फरवरी 2026 में 95 साल की उम्र में किस पूर्व अभिनेता का निधन हो गया?

(A) अल पचीनो (B) रॉबर्ट डुवैल
(C) क्लिंट ईस्टवुड (D) जैक निकोलसन

81. सुप्रीम कोर्ट की किस बेंच ने मासिक धर्म (पीरियड्स हेल्थ) को मौलिक अधिकार घोषित किया?

(A) जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना
(B) जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन
(C) जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला
(D) जस्टिस यू.यू. ललित और जस्टिस एस. रवींद्र भट

82. 13 फरवरी को किस स्वतंत्रता सेनानी की 147वीं जयंती मनाई गई?

(A) केशव चंद्र सेन (B) सरोजिनी नायडू
(C) राममोहन रॉय (D) देबेंद्रनाथ टैगोर

83. 'Puppets of India' नाम के कितने यादगार पोस्टेज स्टैम्प जारी किए गए?

(A) 4 स्टैम्प (B) 6 स्टैम्प
(C) 8 स्टैम्प (D) 10 स्टैम्प

84. पर्वतारोही कबाक यानो किस राज्य से संबंधित हैं?

(A) सिक्किम (B) उत्तराखंड
(C) अरुणाचल प्रदेश (D) हिमाचल प्रदेश

85. किस जिले में अंतिम सशस्त्र माओवादी कमांडर के आत्मसमर्पण के बाद बिहार को नक्सलवाद मुक्त राज्य घोषित किया गया?

(A) गया (B) मुंगेर
(C) जमुई (D) रोहतास

86. इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2026 की थीम क्या है?

(A) शांति के लिए भाषाएँ
(B) मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पर युवाओं की आवाज़ें
(C) कल्चरल हेरिटेज को बचाना
(D) भाषा की विविधता और समावेश

87. फरवरी 2026 में उप-राष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने कौन सी किताब रिलीज़ की थी?

(A) द सेज हू रीइमैजिन्ड हिंदुइज्म
(B) द लाइफ एंड लिगेसी ऑफ़ स्वामी विवेकानंद
(C) रामकृष्ण परमहंस: ए सेंट्स जर्नी
(D) द फिलॉसफी ऑफ़ श्री नारायण गुरु

NOT FOR SALE

88. नीति आयोग द्वारा ट्रेड वॉच क्वार्टरली (TWQ) के कितने संस्करण जारी किए गए?

(A) 4th एडिशन (B) 5th एडिशन
(C) 6th एडिशन (D) 7th एडिशन

89. TW रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट वैल्यू क्या था?

(A) USD 29.12 बिलियन (B) USD 35.5 बिलियन
(C) USD 42.1 बिलियन (D) USD 50 बिलियन

90. रुसोमा गांव किस राज्य में स्थित है जहां ऑरेंज फेस्टिवल आयोजित किया जाता है?

(A) मणिपुर (B) मिजोरम
(C) नागालैंड (D) त्रिपुरा

91. किस भारतीय राज्य ने भारत की पहली कॉम्प्रिहेंसिव ग्राफीन पॉलिसी को मंज़ूरी दी?

(A) तमिलनाडु (B) कर्नाटक
(C) केरल (D) तेलंगाना

92. अनाहत सिंह ने स्क्वैश ऑन फायर ओपन 2026 में अपना पहला पीएसए कांस्य-स्तरीय खिताब जीतने के लिए किसे हराया?

(A) सना इब्राहिम (B) सबरीना सोभी
(C) जॉर्जिना कैनेडी (D) हेले वार्ड

93. देविका सिहाग ने हाल ही में किस टूर्नामेंट में अपना पहला बीडब्ल्यूएफ सुपर 300 ताज जीता?

(A) इंडोनेशिया मास्टर्स (B) थाईलैंड मास्टर्स
(C) मलेशिया मास्टर्स (D) सिंगापुर ओपन

94. हाल ही में कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत का सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा है?

(A) राजस्थान (B) तमिलनाडु
(C) गुजरात (D) कर्नाटक

95. कौन सा स्पेस-टेक स्टार्टअप NSIL के साथ मिलकर काम करने वाला पहला प्राइवेट इंडियन सैटेलाइट ऑपरेटर बना?

(A) स्काईरूट एयरोस्पेस (B) गैलेक्सआई
(C) एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज (D) ध्रुव स्पेस

96. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए तमिलनाडु ने कुल कितना अंतरिम बजट पेश किया है?

(A) Rs 2.25 लाख करोड़ (B) Rs 2.40 लाख करोड़
(C) Rs 2.55 लाख करोड़ (D) Rs 2.75 लाख करोड़

97 बायोएशिया 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह इस वार्षिक वैश्विक शिखर सम्मेलन का 23वां संस्करण है।
2. इसका आयोजन कर्नाटक सरकार द्वारा बेंगलुरु में किया जा रहा है।
3. इस वर्ष का विषय 'टेकबायो अनलीश्ड - एआई, ऑटोमेशन और जीवन विज्ञान में क्रांतिकारी बदलाव' है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 2 (B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3 (D) 1, 2 और 3

98. मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के लिए AI बनाने के लिए किस इंडियन इंस्टीट्यूट ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप की?

(A) IIT मद्रास (B) IIT दिल्ली
(C) IIT बॉम्बे (D) IIT खड़गपुर

99. मिस्र की वैली ऑफ़ द किंग्स में कितने पुराने तमिल-ब्राह्मी शिलालेख मिले थे?

(A) 15 शिलालेख (B) 20 शिलालेख
(C) 30 शिलालेख (D) 40 शिलालेख

100. फरवरी 2026 में किस देश के प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार फिर से चुने गए?

(A) श्रीलंका (B) बारबाडोस
(C) त्रिनिदाद और टोबैगो (D) जमैका

101. हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी (CZA) की 43वीं मीटिंग की अध्यक्षता की?

(A) श्री कीर्ति वर्धन सिंह (B) श्री भूपेंद्र यादव
(C) श्री प्रल्हाद जोशी (D) श्री जी. किशन रेड्डी

102. सिंगापुर एयरशो 2026 में कौन सी इंडियन एयर फ़ोर्स टीम हिस्सा लेगी?

(A) तेजस स्क्वाड्रन
(B) सूर्य किरण टीम
(C) सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम
(D) गरुड़ कमांडो

103. NIPER, रायबरेली ने फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च को बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया?

(A) फाइजर इंडिया (B) बोहरिंगर इंगेलहेम इंडिया
(C) सन फार्मा (D) सिप्ला लिमिटेड

104. देश में बनी Td वैक्सीन हिमाचल प्रदेश के कसौली में किस इंस्टीट्यूट में लॉन्च की गई?

(A) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी
(B) इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड
(C) सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट
(D) सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया

105. भारत की डिजिटल स्किलिंग को तेज़ करने के लिए 'बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है' कैंपेन किस प्लेटफॉर्म के ज़रिए शुरू किया गया था?

(A) डिजिलॉकर
(B) स्किल इंडिया डिजिटल हब
(C) अमृतवा
(D) पी एम जी के ए वाई (PMGKAY)

106. आपदा प्रबंधन और जोखिम न्यूनीकरण (DMRR) में मिलकर किए जाने वाले कामों को मज़बूत करने के लिए किन तीन संस्थानों ने समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया?

(A) NDMA, ISRO, और CSIR-NISCPR
(B) NDMA, AcSIR, और CSIR-NISCPR
(C) नीति आयोग, AcSIR, और NDMA
(D) MHA, CSIR-NIScPR, और DRDO

107. दूसरे 'इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026' में सबसे कम उम्र के मुख्य वक्ता कौन थे?

(A) आर्यन कपूर (B) रणवीर सचदेवा
(C) रोहन मेहता (D) अनन्या सिंह

108. ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला ने 2030 तक भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है?

(A) USD 20 बिलियन (B) USD 25 बिलियन
(C) USD 35 बिलियन (D) USD 30 बिलियन

109. राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 किस निकाय द्वारा तैयार की गई है?

(A) वित्त मंत्रालय (B) भारतीय रिजर्व बैंक
(C) नीति आयोग (D) योजना आयोग

110. NMP 2.0 में, सबसे ज़्यादा टोटल मोनेटाइजेशन वैल्यू के साथ कौन सा सेक्टर सूची में सर्वोच्च पर है?

(A) रेलवे (B) बिजली
(C) कोयला (D) हाईवे, MMLP और रोपवे

111. आंध्र प्रदेश में संशोधित भारतनेट प्रोग्राम को लागू करने के लिए भारत सरकार ने कितने निधि को मंज़ूरी दी है?

(A) 1,500 करोड़ रुपये (B) 3,000 करोड़ रुपये
(C) 2,432 करोड़ रुपये (D) 2,000 करोड़ रुपये

112. टीचर ऐप 2.0 को भारती एयरटेल फाउंडेशन ने किस संगठन के साथ मिलकर बनाया है?

(A) गूगल फाउंडेशन (B) CK-12 फाउंडेशन
(C) खान एकेडमी (D) माइक्रोसॉफ्ट एजुकेशन

113. TEXMiN फाउंडेशन ने रेयर अर्थ और ज़रूरी मिनरल टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए किस देश के GIREDMET JSC के साथ ज्ञापन समझौता (MoU) पर हस्ताक्षर किया है?

(A) चीन (B) जापान
(C) रूस (D) अमेरिका

114. स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांज़िशन रिपोर्ट 2026 के अनुसार, कौन से राज्य EV अपनाने और ग्रीन हाइड्रोजन विकास में अग्रणी बने?

(A) कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु
(B) दिल्ली, हरियाणा और छत्तीसगढ़
(C) उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान
(D) महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब

115. भारत के संविधान के अनुच्छेद-3 के तहत, केरल राज्य का नाम बदलने के लिए किस विधेयक का ज़िक्र किया गया है?

(A) केरल (अमेंडमेंट) विधेयक, 2026
(B) केरल (नाम बदलने) विधेयक, 2026
(C) केरल (रीऑर्गेनाइज़ेशन) विधेयक, 2026
(D) केरल (नाम बदलने) विधेयक, 2026

116. MHA द्वारा जारी भारत की पहली 'नेशनल काउंटर-टेररिज़्म पॉलिसी और स्ट्रैटेजी' का नाम क्या है?

(A) रक्षा (B) सुरक्षा
(C) प्रहारी (D) प्रहार

117. बदले हुए भारत-फ्रांस DTAC के तहत, अगर किसी शेयरहोल्डर के पास कंपनी की कैपिटल का कम से कम 10% हिस्सा है, तो उस पर क्या टैक्स रेट लागू होगा?

(A) 10% (B) 15%
(C) 5% (D) 8%

118. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बनाए गए पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स में कितने देश शामिल हैं?

(A) 54 (B) 70
(C) 64 (D) 58

119. इंडिया-USA जॉइंट स्पेशल फोर्सेज़ एक्सरसाइज़ वज्र प्रहार का 16वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में किस जगह पर शुरू हुआ?

(A) शिमला (B) धर्मशाला
(C) मनाली (D) बकलोह

120. भारतीय सेना की अभ्यास 'अग्नि वर्षा' किस जगह पर हुई है?

(A) जैसलमेर, राजस्थान (B) पोखरण, राजस्थान
(C) बीकानेर, राजस्थान (D) जोधपुर, राजस्थान

121. IIRIS कंसल्टिंग ने किस यूनिवर्सिटी के साथ IIRIS चेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड फोरेंसिक सोसाइटी बनाने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया?

(A) नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली
(B) नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, मुंबई
(C) नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर
(D) नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, बैंगलोर

122. केंद्रिय कैबिनेट ने GIFT सिटी से शाहपुर तक कितने किलोमीटर तक मेट्रो कॉरिडोर को बढ़ाने की मंज़ूरी दी?

(A) 4.33 कि.मी (B) 2.33 कि.मी
(C) 5.33 कि.मी (D) 3.33 कि.मी

NOT FOR SALE

123. 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' नामक पुस्तक, जो हाल ही में संसद में बहस का विषय रही, किस पूर्व सेना प्रमुख का संस्मरण है?

(A) जनरल बिपिन रावत (B) जनरल एमएम नरवणे
(C) जनरल वीके सिंह (D) जनरल दलबीर सिंह सुहाग

124. ESIC ने अपना 75वां फाउंडेशन ईयर सेलिब्रेशन नई दिल्ली में किस जगह पर शुरू किया?

(A) विज्ञान भवन (B) इंडिया हैबिटेट सेंटर
(C) भारत मंडपम (D) जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम

125. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में बस्तर पंडुम उत्सव का उद्घाटन किया?

(A) रायपुर (B) जगदलपुर
(C) बिलासपुर (D) दुर्ग

126. भारत और जापान के बीच एक्सरसाइज धर्म गार्डियन का 7वां संस्करण उत्तराखंड में किस जगह पर शुरू हुआ?

(A) देहरादून (B) चौबटिया
(C) हरिद्वार (D) मसूरी

127. PMGKAY के तहत DBT के लिए CBDC-बेस्ड डिजिटल फूड करेंसी पायलट किस केंद्रशासित प्रदेश में लॉन्च किया गया था?

(A) लक्षद्वीप
(B) दादरा और नगर हवेली
(C) पुडुचेरी
(D) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

128. भारत का पहला 'स्टेट इनोवेशन मिशन' डॉ. जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में लॉन्च किया था?

(A) मणिपुर (B) असम
(C) मेघालय (D) त्रिपुरा

129. नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (NSIC) को शेड्यूल 'B' से अपग्रेड करके किस कैटेगरी के CPSE में रखा गया?

(A) शेड्यूल 'S' (B) शेड्यूल 'A'
(C) शेड्यूल 'AA' (D) शेड्यूल 'C'

130. भारत ने AI और डिजिटल सहयोग के लिए कौन-सा कॉरिडोर लॉन्च करने के लिए बिजनेस स्वीडन के साथ स्टेटमेंट ऑफ़ इंटेंट (SoI) पर हस्ताक्षर किए?

(A) SITAC (B) SIDAC
(C) INDAC (D) INSITEC

131. UIDAI ने गूगल के साथ मिलकर गूगल मैप्स पर ऑथराइज़्ड आधार सेंटर्स को दिखाया, जिसमें कितने आधार सेंटर्स शामिल थे?

(A) 40,000 (B) 50,000
(C) 60,000 (D) 70,000

132. माउंट अकोंकागुआ पर चढ़ने वाली छह सदस्यों वाली इंडियन माउंटेनियरिंग टीम किन दो संस्थान से थी?

(A) NIM उत्तरकाशी और JIM&WS पहलगाम
(B) NIM मनाली और JIM&WS श्रीनगर
(C) NIM देहरादून और JIM&WS लेह
(D) NIM शिमला और JIM&WS जम्मू

133. विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट महिलाएँ व्यवसाय और कानून 2026, का कौन सा संस्करण था?

(A) 9वां संस्करण (B) 10वां संस्करण
(C) 12वां संस्करण (D) 11वां संस्करण

134. सैपियन लैब्स की जारी ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत के युवा वयस्क (18-34 साल के) 84 देशों में से किस स्थान पर हैं?

(A) 55वां (B) 65वां
(C) 60वां (D) 70वां

135. RBI ने ओडिशा के किस शहर में अपना दूसरा बहुत सुरक्षित डेटा सेंटर लॉन्च किया?

(A) कटक (B) राउरकेला
(C) पुरी (D) भुवनेश्वर

136. एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने भारत में सस्ते घरों को बढ़ाने के लिए 'आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड' के साथ कितने रुपये के सीनियर सिक्योर्ड डेट फाइनेंसिंग पैकेज पर हस्ताक्षर किए?

(A) USD 150 मिलियन (B) USD 80 मिलियन
(C) USD 108 मिलियन (D) USD 200 मिलियन

137. IRFC ने किन दो जापानी बैंकों के कंसोर्टियम से JPY के बराबर USD 400 मिलियन का बाह्य वाणिज्यक उधार लिया?

(A) मिज़ुहो बैंक और SMBC
(B) SMBC और MUFG बैंक
(C) MUFG बैंक और नोमुरा बैंक
(D) बैंक ऑफ़ टोक्यो और SMBC

138. प्रवासी श्रमिकों की मौत के लिए बिहार सरकार द्वारा हाल ही में घोषित नई मुआवजा राशि क्या है?

(A) 2 लाख रुपये (B) 3 लाख रुपये
(C) 4 लाख रुपये (D) 5 लाख रुपये

139. एम्ब्रेयर और महिंद्रा समूह ने भारत में किस सैन्य परिवहन विमान के लिए MRO फैसिलिटी बनाने के प्लान की घोषणा की?

(A) C-130 हरक्यूलिस (B) C-17 ग्लोबमास्टर
(C) C-390 मिलेनियम (D) C-295 ट्रांसपोर्ट

NOT FOR SALE

140. ICRA ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में भारत की GDP वृद्धि लगभग कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी?

(A) 6.8% (B) 7.5%
(C) 8.0% (D) 7.2%

141. भारत के वसई कैथेड्रल को UNESCO एशिया-पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंज़र्वेशन 2025 में कौन-सा अवार्ड मिला?

(A) अवार्ड ऑफ़ डिस्टिंक्शन
(B) सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए स्पेशल रिकग्निशन
(C) हेरिटेज कॉन्टेक्स्ट में नए डिज़ाइन के लिए अवार्ड
(D) अवार्ड ऑफ़ मेरिट

142. मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने लगातार कितने साल 2025 AS बेस्ट अराइवल्स अवार्ड जीता?

(A) लगातार पहले साल (B) लगातार तीसरे साल
(C) लगातार दूसरे साल (D) लगातार चौथे साल

143. मणिपुरी फ़िल्म 'बूंग' ने सेरेमनी के किस एडिशन में बेस्ट चिल्ड्रन्स एंड फ़ैमिली फ़िल्म के लिए BAFTA अवार्ड जीता?

(A) 77वां एडिशन (B) 80वां एडिशन
(C) 81वां एडिशन (D) 79वां एडिशन

144. रॉब अर्नोल्डस एड्रियनस जेटन ने किस उम्र में नीदरलैंड्स के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली?

(A) 40 (B) 35
(C) 38 (D) 42

145. अभिनव बिंद्रा ने IOC एथलीट्स आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर कितने साल का कार्यकाल पूरा किया?

(A) छह साल (B) दस साल
(C) आठ साल (D) चार साल

146. विश्व रक्षा शो 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी?

(A) संयुक्त अरब अमीरात (B) कतर
(C) सऊदी अरब (D) ओमान

147. 24 फरवरी, 2026 को नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार दिया गया?

(A) बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम (B) निधि छिब्बर
(C) अजय साहनी (D) रामास्वामी नारायणन

148. फेसबुक ओवरसीज ने रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड (REIL) में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदा?

(A) 25% (B) 49%
(C) 20% (D) 30%

149 पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू की गई 'बांग्लार युवा साथी' कार्यक्रम बेरोज़गार युवाओं को हर महीने कितना भत्ता देती है?

(A) ₹ 1,000 (B) ₹ 2,000
(C) ₹ 1,500 (D) ₹ 2,500

150. सिक्किम के पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया?

(A) थोंडुप नामग्याल (B) त्रिलोचन पोखरेल
(C) सोनम वांगचुक (D) काज़ी लेंडुप दोरजी

151. भारत का पहला नेशनल हाउसहोल्ड इनकम सर्वे (NHIS) और ASISSE अप्रैल 2026 से शुरू होकर कितने समय तक चलने वाला है?

(A) छह महीने (B) दो साल
(C) एक साल (D) तीन साल

152. भारत की पहली LNG-डीज़ल डुअल-फ्यूल DEMU ट्रेन अहमदाबाद में किस जगह पर लॉन्च की गई?

(A) कालूपुर (B) मणिनगर
(C) साबरमती (D) चांदखेड़ा

153. विंग्स इंडिया 2026 हैदराबाद के किस एयरपोर्ट पर हुआ था?

(A) राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट
(B) बेगमपेट एयरपोर्ट
(C) शमशाबाद एयरपोर्ट
(D) हकीमपेट एयरपोर्ट

154. 31 दिसंबर, 2025 तक, गुजरात के कुल रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन भारत की कुल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का कितना प्रतिशत था?

(A) 12.50% (B) 14.75%
(C) 18.25% (D) 16.50%

155. 2026 में दूसरी भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की सह-अध्यक्षता डॉ. एस. जयशंकर और UAE के किस अधिकारी ने की थी?

(A) अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान
(B) खलीफा शाहीन अल मरार
(C) राजा अल मरज़ोकी
(D) जसीम मोहम्मद अलबुदैवी

156. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS 2020-21) के अनुसार, भारत का कुल प्रवासन दर क्या था?

(A) 22.5% (B) 35.6%
(C) 28.9% (D) 18.4%

157. इंडियन हाइवेज़ मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IHMCL) ने नेशनल हाईवे ऑपरेशन में साइबर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ तीन साल का MoU साइन किया?

(A) नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली
(B) IIT बॉम्बे
(C) नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी
(D) सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी

NOT FOR SALE

158. राष्ट्रीय युवा सांसद योजना 2.0 (NYPS 2.0) पोर्टल किस मिनिस्ट्री ने 2 फरवरी, 2026 को लॉन्च किया था?

(A) युवा मामले और खेल मंत्रालय (B) शिक्षा मंत्रालय
(C) संसदीय मामले मंत्रालय (D) कौशल विकास मंत्रालय

159. मुम्बई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (MAHSR) प्रोजेक्ट के लिए दूसरी माउंटेन टनल (MT-6) महाराष्ट्र के किस जिले में है?

(A) थाने (B) रायगढ़
(C) पुणे (D) पालघर

160. भारत-किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर-XIII का 13वां एडिशन असम में किस जगह पर किया गया?

(A) तेजपुर (B) गुवाहाटी
(C) मिसामारी (D) जोरहाट

161. NGEL और असागो इंडस्ट्रीज ने आंध्र प्रदेश में किस जगह पर भारत की पहली बड़े पैमाने पर ग्रीन यूरिया प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाने के लिए एक MoU साइन किया?

(A) विशाखापत्तनम शहर (B) पुदिमदका
(C) काकीनाडा (D) नेल्लोर

162. भारत किस विभाग के एक कार्यक्रम में BRICS सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज़ (BCIC) में शामिल हुआ?

(A) डिपार्टमेंट ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी
(B) डिपार्टमेंट ऑफ़ फार्मास्यूटिकल्स
(C) डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ़ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड
(D) डिपार्टमेंट ऑफ़ इकोनॉमिक अफेयर्स

163. माउंट अकोंकागुआ, जिसे यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाई, साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितने मीटर है?

(A) 7,200 m (B) 6,500 m
(C) 7,000 m (D) 6,960 m

164. नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी (NBA) ने किस तरह के पौधों के लिए सर्टिफिकेट ऑफ़ ओरिजिन इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी करने के लिए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया?

(A) लुप्तप्राय जंगल के पौधे (B) उगाए जाने वाले औषधीय पौधे
(C) पानी के पौधे (D) जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधे

165. एयरबस ने गुजरात के वडोदरा में किस यूनिवर्सिटी में एयरोस्पेस स्टडीज़ के लिए सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया?

(A) गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी
(B) महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी
(C) गति शक्ति विश्वविद्यालय
(D) PDPU गांधीनगर

166. भारत ने संयुक्त राष्ट्र के 'सम्मान सूची' में शामिल होकर 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में कितना भुगतान किया?

(A) USD 28.50 मिलियन (B) USD 42.10 मिलियन
(C) USD 35.18 मिलियन (D) USD 50.00 मिलियन

167. DPIIT द्वारा नोटिफाई किए गए रिवाइज्ड स्टार्टअप इंडिया फ्रेमवर्क के तहत, स्टार्टअप की एज लिमिट को इनकॉर्पोरेशन की तारीख से कितने साल तक बढ़ा दिया गया है?

(A) 15 साल (B) 25 साल
(C) 12 साल (D) 20 साल

168. इंडिया-ऑस्ट्रेलिया बिज़नेस केस स्टडीज़ कम्पेंडियम नई दिल्ली में किस इंस्टीट्यूशन में लॉन्च किया गया?

(A) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट दिल्ली
(B) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ फॉरेन ट्रेड
(C) नीति आयोग
(D) कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री

169. नाइट फ्रैंक-डेलॉइट-S रिपोर्ट के अनुसार, नई दिल्ली दुनिया भर में सबसे किफ़ायती स्टूडेंट सिटी के तौर पर किस नंबर पर है?

(A) दूसरा (B) तीसरा
(C) पाँचवाँ (D) पहला

170. भारत की GoI, नागालैंड सरकार और पूर्वी नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन (ENPO) ने फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी (FNTA) बनाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत कितने सब्जेक्ट से जुड़ी पावर ट्रांसफर की जाएँगी?

(A) 36 सब्जेक्ट (B) 52 सब्जेक्ट
(C) 46 सब्जेक्ट (D) 28 सब्जेक्ट

171. इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने अगले 5 सालों में कितनी सालाना फाइनेंसिंग के साथ एक नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क (CPF) की घोषणा की?

(A) USD 5-7 बिलियन (B) USD 8-10 बिलियन
(C) USD 12-15 बिलियन (D) USD 3-5 बिलियन

172. हाल ही में बिहार के बिहटा से जी आई टैग प्राप्त मखाना की पहली खेप किस को निर्यात की गई है?

(A) अमेरिका (B) चीन
(C) ब्रिटेन (D) श्रीलंका

173. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने किस स्पॉन्सर बैंक के साथ मिलकर इंडिया का पहला RRB को-ब्रांडेड RuPay क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया?

(A) स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (B) बैंक ऑफ़ बड़ौदा
(C) पंजाब नेशनल बैंक (D) केनरा बैंक

174. 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं जिसने राज्यों को 41% कर देने की सिफारिश की थी?

(A) निर्मला सीतारमण (B) अरविंद पनगढ़िया
(C) रघुराम राजन (D) उर्जित पटेल

NOT FOR SALE

175. राजस्थान का कौन सा जिला किस पहल के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया?

(A) अजमेर (B) उदयपुर
(C) अलवर (D) बाड़मेर

176. पाटण पक्षी अभ्यारण्य (UP) और छारी-धंड (गुजरात) को क्रमशः भारत के कितने रामसर साइट के रूप में नामित किया गया?

(A) 95वां और 96वां (B) 99वां और 100वां
(C) 97वां और 98वां (D) 93वां और 94वां

177. 68वें ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 में, 14वें दलाई लामा ने किस कैटेगरी में जीता?

(A) बेस्ट स्पोकन वर्ड एल्बम
(B) बेस्ट ऑडियो बुक, नरेशन और स्टोरीटेलिंग रिकॉर्डिंग
(C) बेस्ट वर्ल्ड म्यूज़िक एल्बम
(D) बेस्ट न्यू आर्टिस्ट

178. वीरभद्रन रामनाथन को किस संस्था ने जियोसाइंस में 2026 का क्राफ़ोर्ड प्राइज़ दिया?

(A) स्वीडन की नोबेल कमेटी
(B) रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ़ साइंसेज़
(C) स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ़ जियोसाइंसेज़
(D) इंटरनेशनल यूनियन ऑफ़ जियोडेसी एंड जियोफ़िज़िक्स

179. भारतीय शिक्षिका रुबल नागी ने किस शहर में हुए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 जीता?

(A) अबू धाबी (B) रियाद
(C) दुबई (D) दोहा

180. DRDO ने किस जगह के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (SFDR) टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया?

(A) पोखरण, राजस्थान (B) व्हीलर आइलैंड, ओडिशा
(C) चांदीपुर, ओडिशा (D) बालासोर, ओडिशा

181. दिगंतरा इंडस्ट्रीज ने सैटेलाइट्स को स्पेस डेब्रिस से बचाने के लिए किस देश की डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी (DSTA) के साथ पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया?

(A) जापान (B) ऑस्ट्रेलिया
(C) सिंगापुर (D) इज़राइल

182. सागर डिफेंस ने इंडियन नेवी को पहले दो अनमैन्ड सरफेस वेसल्स (USVs) दिए, जो कितने परसेंट से ज़्यादा देसी चीज़ों से बने थे?

(A) 50% (B) 60%
(C) 80% (D) 70%

183. BEML ने एडवांस्ड R&D के लिए IISc बेंगलुरु और किस दूसरी संगठन के साथ एक ट्रिपार्टाइट मास्टर रिसर्च एग्रीमेंट (MRA) साइन किया?

(A) सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी
(B) फाउंडेशन फॉर साइंस, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट
(C) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड
(D) नेशनल साइंस एकेडमी

184. कार्लोस अल्काराज़ ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर मेन्स सिंगल्स का खिताब जीता?

(A) जैनिक सिनर (B) राफेल नडाल
(C) नोवाक जोकोविच (D) डेनियल मेदवेदेव

185. 'भाषिणी समुदाय' के संबंध में सही कथन चुनें:

(A) इसका आयोजन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
(B) इसका उद्देश्य भारत के भाषा-आधारित AI पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना है।
(C) यह केवल अंग्रेजी भाषा के प्रचार के लिए है।
(D) इसका आयोजन मुंबई में किया जा रहा है।

186. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना दूसरा WPL टाइटल 2026 वडोदरा के किस स्टेडियम में जीता?

(A) सरदार पटेल स्टेडियम
(B) नरेंद्र मोदी स्टेडियम
(C) वडोदरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम
(D) रिलायंस स्टेडियम

187. फादर थॉमस वी. कुन्नुनकल, जो CBSE के पूर्व चेयरमैन थे, को किस साल पद्मश्री से सम्मानित किया गया था?

(A) 1968 (B) 1980
(C) 1974 (D) 1990

188. इंडिया एनर्जी वीक (IEW 2026) का चौथा संस्करण गोवा में किस संगठन के एडवांस्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हुआ था?

(A) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(B) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(C) ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(D) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

189. विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026, 2 फरवरी को किस थीम के साथ मनाया गया?

(A) आर्द्रभूमि और जैव विविधता संरक्षण
(B) आर्द्रभूमि और जलवायु कार्रवाई
(C) आर्द्रभूमि और मानवाधिकार
(D) आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान: सांस्कृतिक विरासत का जश्न

190. 4 फरवरी, 2026 को मनाया जाने वाला इंटरनेशनल डे ऑफ़ ह्यूमन फ्रेटरनिटी, साल के किस दिन को दिखाता है?

(A) 4th एनिवर्सरी (B) 8th एनिवर्सरी
(C) 6th एनिवर्सरी (D) 10th एनिवर्सरी

191. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के किस ज़िले से 'मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना' लॉन्च की?

(A) वडोदरा (B) सूरत
(C) राजकोट (D) आनंद

NOT FOR SALE

192. आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में किस जगह पर 'पिल्लू AI' लॉन्च किया, जो एक वॉइस-इनेबल्ड बिलिंग और अकाउंटिंग एजेंट है?

(A) विशाखापत्तनम (B) अमरावती
(C) विजयवाड़ा (D) तिरुपति

193. FLO बेंगलुरु ने कर्नाटक में किस जगह पर अपनी तरह का पहला महिलाओं के नेतृत्व वाला औद्योगिक पार्क शुरू किया?

(A) मैसूर (B) तुमकुर
(C) गौरीबिदानूर (D) हुबली

194. सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनीं, जिन्हें किस गवर्नर ने शपथ दिलाई?

(A) भगत सिंह कोश्यारी (B) रमेश बैस
(C) सी. विद्यासागर राव (D) आचार्य देवव्रत

195. RBI ने विनय मुरलीधर टोंस को YES बैंक के MD और CEO के तौर पर कितने साल के लिए मंजूरी दी?

(A) पाँच साल (B) दो साल
(C) चार साल (D) तीन साल

196. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन हटने के बाद युमनाम खेमचंद सिंह ने मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली?

(A) अनुच्छेद 352 (B) अनुच्छेद 370
(C) अनुच्छेद 356 (D) अनुच्छेद 360

197. टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन ने किस अधिकारी को अपना नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया, जिनका कार्यकाल 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा?

(A) अकियो टोयोडा (B) कोजी सातो
(C) केंटा कोन (D) ताकेशी उचियामाडा

198. हाल ही में किस राज्य ने गरीब परिवारों के 'मेरी रसोई' योजना की घोषणा की है?

(A) हरियाणा (B) राजस्थान
(C) पंजाब (D) दिल्ली

199. RBI ने किस अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी फर्म को फेडरल बैंक में 9.99% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी?

(A) ग्लोबल मैनेजमेंट
(B) ब्लैकस्टोन
(C) कार्लाइल ग्रुप
(D) अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट

200. वर्ल्ड कैंसर डे 2026 की थीम "यूनाइटेड बाय यूनिक" किस कैंपेन पीरियड का हिस्सा है?

(A) 2024-2026 (B) 2023-2025
(C) 2023-2025 (D) 2025-2027

NOT FOR SALE

Answer Key

1. (A)	2. (B)	3. (B)	4. (C)	5. (C)	6. (B)	7. (B)	8. (A)	9. (B)	10. (C)
11. (B)	12. (B)	13. (C)	14. (B)	15. (A)	16. (C)	17. (B)	18. (B)	19. (C)	20. (C)
21. (B)	22. (C)	23. (C)	24. (C)	25. (B)	26. (B)	27. (B)	28. (C)	29. (B)	30. (A)
31. (C)	32. (B)	33. (A)	34. (C)	35. (C)	36. (B)	37. (C)	38. (B)	39. (C)	40. (C)
41. (B)	42. (C)	43. (B)	44. (B)	45. (A)	46. (B)	47. (C)	48. (C)	49. (C)	50. (C)
51. (B)	52. (C)	53. (C)	54. (B)	55. (B)	56. (B)	57. (C)	58. (D)	59. (C)	60. (C)
61. (B)	62. (B)	63. (C)	64. (B)	65. (C)	66. (C)	67. (C)	68. (C)	69. (B)	70. (B)
71. (B)	72. (C)	73. (C)	74. (C)	75. (C)	76. (C)	77. (A)	78. (C)	79. (B)	80. (B)
81. (B)	82. (B)	83. (C)	84. (C)	85. (B)	86. (B)	87. (A)	88. (C)	89. (C)	90. (C)
91. (C)	92. (C)	93. (B)	94. (C)	95. (B)	96. (C)	97. (C)	98. (C)	99. (C)	100. (B)
101. (B)	102. (C)	103. (B)	104. (C)	105. (B)	106. (B)	107. (B)	108. (D)	109. (C)	110. (D)
111. (C)	112. (B)	113. (C)	114. (C)	115. (B)	116. (D)	117. (C)	118. (C)	119. (D)	120. (B)
121. (C)	122. (D)	123. (B)	124. (C)	125. (B)	126. (B)	127. (C)	128. (D)	129. (B)	130. (A)
131. (C)	132. (A)	133. (D)	134. (C)	135. (D)	136. (C)	137. (B)	138. (C)	139. (C)	140. (D)
141. (D)	142. (C)	143. (D)	144. (C)	145. (C)	146. (C)	147. (B)	148. (D)	149. (C)	150. (B)
151. (C)	152. (C)	153. (B)	154. (D)	155. (B)	156. (C)	157. (C)	158. (C)	159. (D)	160. (C)
161. (B)	162. (C)	163. (D)	164. (B)	165. (C)	166. (C)	167. (D)	168. (B)	169. (D)	170. (C)
171. (B)	172. (B)	173. (C)	174. (B)	175. (C)	176. (C)	177. (B)	178. (B)	179. (C)	180. (C)
181. (C)	182. (D)	183. (B)	184. (C)	185. (C)	186. (C)	187. (C)	188. (C)	189. (D)	190. (C)
191. (D)	192. (B)	193. (C)	194. (D)	195. (D)	196. (C)	197. (C)	198. (C)	199. (B)	200. (D)

Note

NOT FOR SALE